रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 20, 1973/पौष 30, 1894
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 20, 1973/PAUSA 30, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1973

आदेश

का. आ. 144.—केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के टिप्पण 3 के साथ पठित नियम 18 के उपनियम (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा :—

(क) इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रारूपों को ऐसे प्रारूपों के रूप में विहित करती है जिसमें उक्त नियम में निर्दिष्ट विवरणी —

(1) प्रत्येक सरकारी सेवक द्वारा इस आदेश के जारी होने की तारीख के पश्चात् किसी सेवा या पद पर अपनी प्रथम नियुक्ति पर, और

(2) प्रत्येक सरकारी सेवक द्वारा, जो इस आदेश के जारी होने की तारीख को सेवा में हो,

प्रस्तुत की जायेगी ।

(ख) निदेश देती है कि —

(1) किसी सरकारी सेवक की बाबत, किसी सेवा या पद पर उसकी प्रथम नियुक्ति पर, प्रथम विवरणी वैसी ही होगी जैसी कि ऐसी नियुक्ति की तारीख को हो और उस तारीख से तीन मास के भीतर प्रस्तुत कर दी जाएगी और प्रत्येक ऐसी विवरणी प्रथम के पश्चात्, प्रथम विवरणी के पश्चात् की विवरणियों की बाबत खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट तारीख को, और के भीतर प्रस्तुत कर दी जाएगी, परन्तु यदि प्रथम विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख और उस तारीख के बीच का, जिसको पश्चात्वर्ती विवरणी देय हो जाती हो, अन्तराल छह मास से कम हो तो पश्चात् कथित विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है ,

(2) प्रत्येक सरकारी सेवक, जो इस आदेश के जारी होने की तारीख को सेवा में हो, की बाबत विवरणी वैसी ही होगा जैसी 31 दिसम्बर, 1972 को हो और 31 मार्च, 1973 को ऐसी तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसको या जिसके पूर्व ऐसी विवरणी प्रस्तुत कर दी जाएगी ,

(ग) और निदेश देती है कि प्रत्येक सरकारी सेवक प्रथम के पश्चात् ऐसे वर्ष के, जिससे विवरणी संबंधित हो, ठीक अगले वर्ष के मार्च के 31 वें दिन को या उसके पूर्व पांच वर्ष के अंतराल में ऐसी विवरणी प्रस्तुत करेगा और

33 G of I/72—1

प्रत्येक ऐसी विवरणी वैसी ही होगी जैसी उक्त मार्च के 31 वें दिन से ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के दिसम्बर, के 31 वें दिन की हो , और

(घ) यह भी निदेश देती हैं कि प्रत्येक ऐसी विवरणी गुप्त दस्तावेज के रूप में बरती जाएगी और उन पर केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपबन्ध यथाशक्य लागू होंगे ।

[सं. 25/7/65-स्थापना(ए)]

बी. एस. वेंकटेश्वरण, अवर सचिव ।

अनुसूची

(नियम 18 (1) देखिए)

प्रथम नियुक्ति पर/31 दिसम्बर, 19 तक, आस्तियों और दायित्वों की विवरणी

1. सरकारी सेवक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)—

2. किस सेवा में हैं —

3. अद्यतन सेवा की कुल अवधि —

(1) अराजपत्रित रैंक में —

(2) राजपत्रित रैंक में —

4. धारित वर्तमान पद और तैनाती का स्थान —

5. पहली जनवरी, 19 से अव्यवहित पूर्ववर्ती कलेंडर वर्ष के दौरान सब-स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय—

6. घोषणा :

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 18 के उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी की बाबत संलग्न विवरणी, अर्थात् प्रारूप 1 से 5, तारीख ——— तक मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार पूर्ण, सत्य और शुद्ध हैं ।

तारीख ——— हस्ताक्षर ———

टिप्पण 1. इस विवरणी में सरकारी सेवक की या तो अपने नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में सभी आस्तियों और दायित्वों की विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी ।

टिप्पण 2. यदि सरकारी सेवक हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का सदस्य है जिसका वह तो 'कर्ता' के रूप में या सदस्य के रूप में कुटुम्ब की सम्पत्तियों में सहदायिकी अधिकार है, तो उसे ऐसी सम्पत्ति में अपने अंश के मूल्य प्ररूप सं. 1 में विवरणी में उपदर्शित करना चाहिए और जहां ऐसे अंश का निश्चित मूल्य उपदर्शित करना सम्भव ना हो वहां उसे उसका लगभग मूल्य उपदर्शित करना चाहिए । जहां आवश्यक हो वहां उपयुक्त स्पष्टीकारक टिप्पण जोड़े जा सकते हैं ।

प्ररूप सं० 1

प्रथम नियुक्ति पर/31 दिसम्बर, 19 तक, स्थावर सम्पत्ति का विवरण

(उदाहरणार्थ, भूमि, गृह, दुकान, अन्य भवन, आदि)

क्र० सं०	सम्पत्ति का विवरण	ठीक-ठीक अवस्थिति (उस जिला, खण्ड, तालुक और ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित है और उनके सुभिन्नक संख्यांक आदि भी)	भूमि का क्षेत्रफल (भूमि और भवनों की दशा में)	भूमि की प्रकृति (भू-सम्पत्ति की दशा में)	हित का विस्तार	यदि अपने नाम में नहीं है तो जिस के नाम में धारित हो उसका कथन कीजिए और सरकारी सेवक के साथ उसका यदि कोई हो, संबंध ।
1	2	3	4	5	6	7

अर्जन की तारीख	किस प्रकार अर्जित हुई है (चाहे वह क्रय, बन्धक, पट्टा, विरासत दान द्वारा या अन्यथा हुई हो) और जिस व्यक्ति/जिन व्यक्तियों से अर्जित की गई है उसका/उनके नाम, ब्योरों सहित (पता और संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों से, यदि कोई हो, उस सरकारी सेवक का संबंध) (कृपया निम्न टिप्पण 1 देखिए)	सम्पत्ति का मूल्य (निम्न टिप्पण 2 देखिए)	विहित प्राधिकारी, यदि कोई हो, की मंजूरी की विशिष्टियां	सम्पत्ति से कुल वार्षिक आय	टिप्पणियां
8	9	10	11	12	13

तारीख..... हस्ताक्षर.....

टिप्पण :—(1) स्तम्भ 9 के प्रयोजन के लिए "पट्टा" शब्द से स्थावर सम्पत्ति का वर्षानुवर्षी या एक वर्ष से अनधिक की किसी अवधि के लिए या नियत वार्षिक भाटक नियत करने वाला पट्टा अभिप्रेत होगा। तथापि, जहां स्थावर सम्पत्ति का पट्टा ऐसे व्यक्ति से अभिप्राप्त होता है जिसका सरकारी सेवक के साथ पदीय व्यवहार होता है, वहां ऐसे पट्टे को उस पट्टे की अवधि का, चाहे वह अल्पकालिक हो या दीर्घकालिक, और भाटक के संदाय की कालिकता का विचार किए बिना, इस स्तम्भ में दर्शित किया जाना चाहिए।

(2) स्तम्भ 10 में निम्नलिखित दर्शित किए जाने चाहिए—

(क) जहां सम्पत्ति क्रय, बन्धक या पट्टा द्वारा अर्जित की गई हो वहां ऐसे अर्जन के लिए संदत्त कीमत या प्रीमियम;

(ख) जहां वह पट्टा द्वारा अर्जित की गई हो, वहां उसका कुल वार्षिक भाटक भी; और

(ग) जहां अर्जन विरासत, दान या विनिमय द्वारा हुआ हो वहां इस प्रकार अर्जित की गई सम्पत्ति का लगभग मूल्य।

प्ररूप सं० 2

प्रथम नियुक्ति पर/31 दिसम्बर, 19 तक, जंगम आस्तियों का विवरण

(1) 3 मास की उपलब्धियों से अधिक का नकद और बैंक अतिशेष।

(2) निक्षेप, दिए गए उधार और विनिधान (जैसे अंश, प्रतिभूतियां, डिबेंचर, आदि)।

क्र० सं०	विवरण	कम्पनी, बैंक आदि का नाम और पता	रकम	यदि अपने नाम में नहीं है तो जिस व्यक्ति के नाम में धारित हो उसका नाम और पता और सरकारी सेवक के साथ उसका संबंध	व्युत्पन्न वार्षिक आय	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

टिप्पण 1 : स्तम्भ 7 में, विभिन्न संव्यवहारों की बाबत अभिप्राप्त मंजूरी या की गई रिपोर्ट संबंधी विशिष्टियां दी जा सकती हैं।

टिप्पण 2 : "उपलब्धियां" शब्द से सरकारी सेवक द्वारा प्राप्त वेतन और भत्ते अभिप्रेत हैं।

प्ररूप सं० 3

प्रथम नियुक्ति पर/31 दिसम्बर, 19 तक जंगम सम्पत्ति का विवरण

क्रम सं०	मदों का वर्णन	अवक्रय पर या किस्तों के आधार पर क्रय की गई वस्तुओं की दशा में, यथास्थिति, अर्जन के समय उनकी कीमत या मूल्य और/या विवरणी की तारीख तक किए गए कुल संदाय	यदि अपने नाम में न हों तो, जिस व्यक्ति के नाम हों, उसका नाम और पता तथा सरकारी सेवक के साथ उसका सम्बन्ध	किस प्रकार अर्जित की गई, अर्जन की लगभग तारीख सहित	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

टिप्पण 1 : इस प्ररूप में इन मदों की बाबत जानकारी दी जाए,—(क) उसके स्वामित्व में के जेवर (कुल मूल्य); (ख) उसके स्वामित्व में की चांदी और अन्य कीमती धातुएं तथा कीमती रत्न; जो जेवर का भाग न हों (कुल मूल्य); (ग) (i) मोटर गाड़ियां (ii) स्कूटर/मोटरसाइकिलें; (iii) रेफ्रीजरेटर (प्रशीतक) वातानुकूलक, (iv) रेडियो/रेडियोग्राम/टेलीविजन सेट और कोई अन्य ऐसी वस्तुएं जिनका मूल्य अलग-अलग 1000, रुपए से अधिक है; (घ) दैनिक प्रयोग में आने वाली, जैसे कि वस्त्र, बर्तन, पुस्तकें, चीनी के बर्तन आदि, वस्तुओं से भिन्न जंगम सम्पत्ति की उन मदों का मूल्य, जिनकी कीमत अलग-अलग 1000 रुपए से कम है, एकमुश्त रूप में ही जोड़ा जाए।

टिप्पण 2 : स्तंभ 5 में, यह उपदर्शित किया जाए कि क्या सम्पत्ति क्रय, विरासत, दान के द्वारा या अन्यथा अर्जित की गई थी ?

टिप्पण 3 : स्तंभ 6 में, विभिन्न संव्यवहारों की बाबत ली गई मंजूरी या की गई रिपोर्ट से संबंधित विशिष्टियां दी जाएं।

प्ररूप सं० 4

प्रथम नियुक्ति पर/31 दीसम्बर, 19 तक जीवन बीमा पालिसियों और भविष्य निधियों का विवरण

क्र० सं०	बीमा पालिसियां				भविष्य निधियां				
	पालिसी सं० और पालिसी की तारीख	बीमा कम्पनी का नाम	बीमाकृत रकम/ परिपक्वता की तारीख	वार्षिक प्रीमियम की रकम	भविष्य निधियों का प्रकार/सां० भ० नि०/अ० भ० नि० खाता सं०	वह अंत अतिशेष जिसकी रिपोर्ट अंत में लेखा परीक्षा/लेखा अधिकारी द्वारा की गई हो और उसके साथ ही ऐसे अतिशेष की तारीख	बाद में किए गए अंश-दान	कुल	टिप्पणियां (यदि अंत अतिशेष के बारे में कोई विवाद हो तो सरकारी सेवक के अनुसार आंकड़े भी इन स्तंभ में वर्णित किए जाने चाहिए।)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

प्ररूप सं० 5

प्रथम नियुक्ति पर/31 दिसम्बर, 19 तक ऋणों और अन्य दायित्वों का विवरण

क्रम सं०	रकम	लेनदार का नाम और पता	दायित्व उपगत करने की तारीख	संव्यवहार के ब्योरे	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

टिप्पण 1 : उधारों की उन अलग-अलग मदों को, जो तीन मास की परिलब्धियों या 1000 रुपयों, दोनों में से जो भी कम हो, से अधिक न हों सम्मिलित नहीं किया जाए।

टिप्पण 2 : स्तंभ 6 में, संक्षेप प्राधिकारी से ली गई अनुज्ञा, यदि कोई हो, या उसे दी गई रिपोर्ट के बारे में जानकारी भी दी जाए।

टिप्पण 3 : "परिलब्धियां" शब्द से सरकारी सेवक द्वारा प्राप्त किये गये वेतन और भत्ते अभिप्रेत हैं।

टिप्पण 4 : विवरण में सरकारी सेवकों को उपलब्ध विभिन्न उधार और अग्रिम धन भी जैसे कि (वेतन और यात्रा भत्ते के अग्रिम धनों से भिन्न) सवारी खरीदने के लिए अग्रिम धन, आवास का निर्माण करने के लिए अग्रिम धन, आदि, सां० भ० निधि से अग्रिम धन तथा जीवन बीमा पालिसियों और आवधिक निक्षेपों पर उधार, सम्मिलित किए जाने चाहिए।

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

New Delhi, the 6th January, 1973

ORDER

S.O. 144.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 18 of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, read with Note III thereto, the Central Government hereby—

(a) prescribes the forms specified in the Schedule to this Order, as the forms in which the return referred to in the said rule shall be submitted by—

(i) every Government servant, on his first appointment after the date of issue of this Order to any service or post, and

(ii) every Government servant who is in service on the date of issue of this order;

(b) directs that—

(i) the first return in respect of a Government servant on his first appointment to any service or post shall be as on the date of such appointment and shall be submitted within three months from that date and every such return, after the first, shall be submitted as on, and by, the date specified in clause (c) in respect of returns after the first return, provided that if the interval between the date of submission of the first return and the date on which a subsequent return is due is less than six months, the latter return need not be submitted;

(ii) the first return in respect of every Government servant who is in service on the date of issue of this order, shall be as on the 31st December, 1972 and specifies the 31st day of March, 1973, as the date on or before which such return shall be submitted;

(c) further directs that every Government servant shall submit such returns, after the first, at an interval of five years, on or before the 31st day of March of the year immediately following the year to which the return relates and every such return shall be as on the 31st day of December of the year immediately preceding the said 31st day of March; and

(d) also directs that every such return shall be handled as secret document and the provisions of rule 11 of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, shall, as far as may be, apply thereto.

[No. 25/7/65-Ests(A)]

P. S. VENKATESWARAN, Under Secy.

THE SCHEDULE

[See Rule 18(1)]

RETURN OF ASSETS AND LIABILITIES ON FIRST APPOINTMENT/AS ON THE 31ST DECEMBER, 19——

1. Name of the Government servant in full (in block letters)——————
2. Service to which he belongs——————
3. Total length of service upto date——————
   (i) in Non-gazetted rank——————
   (ii) in Gazetted rank——————
4. Present post held and place of posting——————
5. Total annual income from all sources during the Calendar year immediately preceding the 1st day of January, 19—— ——————
6. *Declaration*

I hereby declare that the return enclosed namely, Forms I to V, are complete, true and correct as on—— to the best of my knowledge and belief, in respect of information due to be furnished by me under the provisions of sub-rule (1) of rule 18 of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964.

Date——————

Signature——————

Note 1. This return shall contain particulars of all assets and liabilities of the Government servant, either in his own name or in the name of any other person.

Note 2. If a Government servant is a member of Hindu Undivided Family with co-parcenary rights in the properties of the family either as a 'Karta' or as a member, he should indicate in the return in Form No. I the value of his share in such property and where it is not possible to indicate the exact value of such share, its approximate value. Suitable explanatory notes may be added, wherever necessary.

FORM NO. I

STATEMENT OF IMMOVABLE PROPERTY ON FIRST APPOINTMENT/AS ON THE 31ST DECEMBER, 19 .

(e.g. Lands, Houses, Shops, Other Buildings, etc.)

S. No.	Description of property	Precise location (Name of District, Division, Taluk and Village in which the Property is situated and also its distinctive number, etc.)	Area of Land (in case of land and Buildings)	Nature of land (in case of landed property)	Extent of Interest	If not in own name, state in whose name held, and his/her relationship, if any, to the Govt. servant
1	2	3	4	5	6	7

Date of acquisition	How acquired ? (whether by purchase, mortgage, lease, inheritance, gift or otherwise) and name with details of person/persons from whom acquired. (address and connection of the Govt. servant, if any, with the person/persons concerned) (Please see Note 1 below)	Value of the property (see Note 2 below)	Particulars of sanction of prescribed authority, if any	Total Annual income from the property	Remarks
8	9	10	11	12	13

Date .... Signature ....

NOTE:—(1) For purpose of Column 9, the term "lease" would mean a lease of immovable property from year to year or for any term exceeding one year or reserving a yearly rent. Where, however, the lease of immovable property is obtained from a person having official dealings with the Government servant, such a lease should be shown in this Column irrespective of the term of the lease, whether it is short term or long term, and the periodicity of the payment of rent.

(2) In Column 10 should be shown—

(a) where the property has been acquired by purchase, mortgage, or lease, the price or premium paid for such acquisition;

(b) where it has been acquired by lease, the total annual rent thereof also; and

(c) where the acquisition is by inheritance, gift or exchange, the approximate value of the property so acquired

FORM NO. II

STATEMENT OF LIQUID ASSETS ON FIRST APPOINTMENT/AS ON THE 31ST DECEMBER, 19 .

(1) Cash and Bank balances exceeding 3 month's emoluments.

(2) Deposits, loans advanced and investments (such as shares, securities, debentures, etc.).

S. No.	Description	Name and address of Company, Bank, etc.	Amount	If not in own name, name and address of person in whose name held and his/her relationship with the Government servant	Annual income derived	Remarks
1	2	3	4	5	6	7

Date ..... Signature .....

NOTE 1. In column 7, particulars regarding sanctions obtained or report made in respect of the various transactions may be given.

NOTE 2. The term "emoluments" means the pay and allowances received by the Government servant.

FORM NO. III

STATEMENT OF MOVABLE PROPERTY ON FIRST APPOINTMENT/AS ON THE 31ST DECEMBER, 19 .

S. No.	Description of items	Price or value at the time of acquisition and/or the total payments made up to the date of return, as the case may be, in case of articles purchased on hire-purchase or instalment basis	If not in own name, name and address of the person in whose name and his/her relationship with the Government servant	How acquired with approximate date of acquisition	Remarks
1	2	3	4	5	6

Date ..... Signature .....

NOTE 1. In this Form information may be given regarding items like (a) jewellery owned by him (total value); (b) silver and other precious metals and precious stones owned by him not forming part of jewellery (total value); (c) (i) Motor Cars, (ii) Scooters/Motor Cycles, (iii) refrigerators/air-conditioners, (iv) radios/radiograms/television sets and any other articles, the value of which individually exceeds Rs. 1000/-, (d) value of items of movable property individually worth less than Rs. 1000/-, other than articles of daily use such as clothes, utensils, books, crockery, etc., added together as lumpsum.

NOTE 2. In column 5, may be indicated whether the property was acquired by purchase, inheritance, gift or otherwise.

NOTE 3. In column 6 particulars regarding sanction obtained or report made in respect of various transactions may be given.

FORM NO. IV

STATEMENT OF PROVIDENT FUND AND LIFE INSURANCE POLICY ON FIRST APPOINTMENT/AS ON THE 31ST DECEMBER, 19 .

	Insurance Policies				Provident Funds				
S. No.	Policy No. and date of policy	Name of Insurance Company	Sum Insured/date of maturity	Amount of annual premium	Type of Provident Funds/ G.P.F./ C.P.F. Account No.	Closing balance as last reported by the Audit/ Accounts Officer along with date of such balance	Contributions made subsequently	Total	Remarks (if there is dispute regarding closing balance the figures according to the Government servant should also be mentioned in this column.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Date ..... Signature .....

FORM NO. V

STATEMENT OF DEBTS AND OTHER LIABILITIES ON FIRST APPOINTMENT/AS ON THE 31ST DECEMBER, 19 .

S. No.	Amount	Name and Address of Creditor	Date of incurring Liability	Details of Transaction	Remarks
1	2	3	4	5	6

Date ..... Signature .....

NOTE 1. Individual items of loans not exceeding three months emoluments or Rs. 1,000/- whichever is less, need not be included.

NOTE 2. In column 6, information regarding permission, if any, obtained from or report made to the competent authority may also be given.

NOTE 3. The term "emoluments" means Pay and allowances received by the Government servant.

NOTE 4. The statement should also include various loans and advances available to Government servants like advance for purchase of conveyance, House building advance, etc. (other than advances of pay and travelling allowance), advances from the C.P. Fund, and loans on Life Insurance Policies and fixed deposits.

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1973

आदेश

का. आ. 145.—दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की सहमति से, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, कथित अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत जारी की गई और उसके साथ लगी अनुसूची में उल्लिखित भारत सरकार के गृह मंत्रालय/कार्मिक विभाग की अधिसूचनाएं (1) सं. 25/12/62-ए. वी डी-1 दिनांक 18-2-1963-(2) सं. 25/3/60-ए. वी. डी-2 दिनांक 1-4-1964, (3) सं. 25/9/64-ए. वी. डी. दिनांक 1-9-1964, (4) सं. 228/1/65, ए. वी. डी.-2 दिनांक 3-2-1965, (5) सं. 228/4/66 ए. बी. डी.-2(1) दिनांक 23-12-1966, (6) सं. 25/4/64-ए. वी. डी.-2 दिनांक 21-11-1967, (7) सं. 228/3/66-ए. वी. डी. (2) दिनांक 10-7-1970, (8) सं. 228/7/65-ए. वी. डी.-2 दिनांक 13-7-1970, (9) सं. 228/6/67-ए. वी. डी.-2 दिनांक 15-7-1970 और (10) सं. 288/11/67 (1) ए. बी. डी.-2 दिनांक 3-9-1970 में बताये गए कुछ अपराधों के अन्वेषण के लिए दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना के सदस्यों को शक्तियों और क्षेत्राधिकार का हिमाचल प्रदेश राज्य में विस्तार करती हैं :—

अनुसूची

(क) (1) भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धाराएं 124-ए, 161, 162, 163, 164, 165, 165-ए, 166, 167, 168, 169, 171-ई 171-एफ, 182, 193, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 204, 211, 218, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 263-ए, 379, 380, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 403, 406, 407, 408, 409, 411, 412, 413,, 414, 417, 418, 419, 420, 465, 466, 467, 468, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477-ए, 489-ए, 489-बी, 489-सी, 489-डी, 489-ई, 500, 502, और 505 के अधीन दण्डनीय अपराध,

(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (1947 का 2) के अधीन दण्डनीय अपराध ,

(3) भारत रक्षा अधिनियमों, 1962 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए भारत रक्षा नियमों के अधीन दण्डनीय अपराध ;

(4) आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 1947 का 18) के अधीन दण्डनीय अपराध ;

(5) विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1947 (1947 का 7) के अधीन दण्डनीय अपराध ,

(6) भारतीय डाक-घर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धाराएं 51, 52, 55 और 56 के अधीन दण्डनीय अपराध ;

(7) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धाराएं 62, 68, 116, 538, 539, 540, 541, 542, 628, 629, और 630 के अधीन दण्डनीय अपराध ;

(8) बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धाराएं 104, और 105 के अधीन दण्डनीय अपराध ,

(9) भारतीय शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 (1923 का 19) के अधीन दण्डनीय अपराध ,

(10) आवश्यक सामग्री अधिनियम 1955 (1955 का 10) की धाराएं 7 और 8 के अधीन दण्डनीय अपराध ;

(11) उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 24 की उप-धारा (1) के खंड (3) के अधीन दण्डनीय अपराध ;

(12) भारतीय बेतार टेलीग्राफ अधिनियम, 1933 के अधीन दण्डनीय अपराध ;

(13) टेलीग्राफ-तार (अवैध कब्जा) अधिनियम, 1950 (1950 का 74) के अधीन दण्डनीय अपराध ;

(14) रेलवे भंडार (अवैध कब्जा) अधिनियम, 1955 (1955 का 51) के अधीन दण्डनीय अपराध ,

(15) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 27 के अधीन दण्डनीय अपराध ;

(16) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धाराएं 132, 133, 134, 135, और 136 के अधीन दण्डनीय अपराध ,

(17) पार पत्र (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 (1920 का 34) की धारा 3 की उप-धारा (3) के साथ पठित भारतीय पार पत्र नियमावली, 1950 के नियम 6 के अधीन दण्डनीय अपराध ,

(18) विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939 (1939 का 16) की धारा 5 के अधीन दण्डनीय अपराध ,

(19) वायूयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धाराएं 6, 10, 11, और 12 के अधीन और कथित अधिनियम की धाराएं 5, 7, 8, 8-ए, या 8-बी के अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अधीन दण्डनीय अपराध ,

(20) विदेशी अधिनियम, 1946 (1946 का 31) की धारा 14 के अधीन दण्डनीय अपराध ;

(21) अफीम अधिनियम, 1878 (1878 का 1) की धारा 9 के अधीन दण्डनीय अपराध ;

(22) हानिकर औषध अधिनियम, 1930 (1930 का 2) की धाराएं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 और 21 के अधीन दण्डनीय अपराध ,

(23) आयकर अधीनियम, 1961 (1961 का 43) की धाराए 277 और 278 के अधीन दण्डनीय अपराध ,

(24) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धाराएं 9 और 17 के अधीन दण्डनीय अपराध ;

(25) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धाराएं 31 और 32 के अधीन दण्डनीय अपराध ;

(26) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराएं 128, 129, 134 और 136 के अधीन दण्डनीय अपराध और ;

(27) पारपत्र अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 12 के अधीन दण्डनीय अपराध , और

(ख) उपरोक्त उप-पैराग्राफ (क) में बताए हुए अपराधों में से किसी भी अपराध के संबंध में अथवा उससे संबंधित प्रयत्न, उकसाहट और षडयंत्र तथा वैसे ही तथ्यों से उत्पन्न हुई वैसी ही कार्यवाही के दौरान किया गया कोई अन्य अपराध ।

[सं. 288/3/71-ए. वी. डी. 2]

वी. सी. वनजानी, अवर सचिव

New Delhi, the 9th January, 1973

ORDER

S.O. 145.—In exercise of the powers conferred by sub-sub-section (1) of section 5, read with section 6, of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government, with the consent of the Government of the State of Himachal Pradesh, hereby extends to the State of Himachal Pradesh the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment for the investigation of certain offences, spcified in the notifications of the Government of India in the Ministry of Home Affairs/Department of Personnel (i) No. 25/12/62-AVD I, dated the 18th February, 1963, (ii) No. 25/3/60-AVD II, dated the 1st April, 1964 (iii) No. 25/9/64-AVD, dated the 1st September, 1964, (iv) No. 228/1/65(I)AVD II, dated the 8th February, 1965, (v) No. 228/4/66-AVD II (I), dated the 23rd December, 1966 (vi) No. 25/4/64-AVDII, dated the 21st November, 1967, (vii) No. 228/3/66-AVD (II), dated the 10th July, 1970 (viii) No. 228/7/65-AVD (II), dated the 13th July, 1970, (ix) No. 228/6/67-AVD II, dated the 15th July, 1970 and (x) No. 228/11/67-AVDH II, dated the 3rd September, 1970, issued under section 3 of the said Act, and mentioned in the Schedule hereto annexed :—

THE SCHEDULE

(a) 1. Offences punishable under sections 124A, 161, 162, 163, 164 165, 165A, 166, 167, 168, 169, 171E, 171F, 182, 193, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 204, 211, 218, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 263A, 379, 380, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 403, 406, 407, 408, 409, 411, 412, 413, 414, 417, 418, 419, 420, 465, 466, 467, 468, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477A, 489A, 489B, 489C, 489D, 489F, 500, 502, and 505 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860);

2. Offences punishable under the Prevention of Corruption Act, 1947 (2 of 1947);

3. Offences punishable under the Defence of India Act, 1962 and the Defence of India Rules framed thereunder;

4. Offences punishable under the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947);

5. Offences punishable under the Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (7 of 1947);

6. Offences punishable under sections 51, 52, 55 and 56 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898);

7. Offences punishable under sections 63, 68, 116, 538, 539, 540, 541, 542, 628, 629 and 630 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

8. Offences punishable under sections 104 and 105 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);

9. Offences punishable under the Indian Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923);

10. Offences punishable under sections 7 and 8 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955);

11. Offences punishable under clause (iii) of sub-section (i) of section 24 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951);

12. Offences punishable under the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933);

13. Offences punishable under the Telegraph Wires (Unlawful Possession) Act, 1950 (74 of 1950);

14. Offences punishable under the Railway Stores (Unlawful Possession) Act, 1955 (51 of 1955);

15. Offences punishable under section 27 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);

16. Offences punishable under sections 132, 133, 134, 135 and 136 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962);

17. Offences punishable under rule 6 of the Indian Passport Rules, 1950 read with sub-section (3) of section 3 of the Passport (Entry into India) Act, 1920 (34 of 1920);

18. Offences punishable under section 5 of the Registration of Foreigners Act, 1939 (16 of 1939);

19. Offences punishable under sections 6, 10, 11 and 12 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934) and under any rules made under sections 5, 7, 8, 8A, or 8B of the said Act;

20. Offences punishable under section 14 of the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946);

21. Offences punishable under section 9 of the Opium Act, 1878 (1 of 1878);

22. Offences punishable under sections 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 and 21 of the Dangerous Drugs Act, 1930 (2 of 1930);

23. Offences punishable under sections 277 and 278 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961);

24. Offences punishable under sections 9 and 17 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944);

25. Offences punishable under sections 31 and 32 of the Representation of the people Act, 1950 (43 of 1950);

26. Offences punishable under sections 128, 129, 134 and 136 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951);

27. Offences punishable under section 12 of the Passport Act, 1967 (15 of 1967); and

(b) attempts, abetments and conspiracies in relation to, or in connection with, any of the offences mentioned in sub-paragraph (a) and any other offence committed in the course of the same transaction arising out of the same facts.

[No. 228/3/71-AVD II]

B. C. VANJANI, Under Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1972

आदेश

का. आ. 146.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि लोक सभा के लिए निर्वाचन के लिए 7-करोलबाग (एस. सी.) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पन्ना लाल, 90, गली नं. 5, टी. हट, थान सिंह नगर, करोलबाग, नई दिल्ली लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;—

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पन्ना लाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. दिल्ली-लो. स./7/71(2)]

आदेश से,

बी. एन. भारद्वाज, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 29th December, 1972

ORDER

S.O. 146.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Panna Lal, 90, Gali No. 5, T. Hut, Than Singh Nagar, Karol Bagh, New Delhi, a contesting candidate for election to the House of the People from 7-Karol Bagh (SC) Parliamentary Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Panna Lal to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. DL-HP/7/71(2)]

By Order,

B. N. BHARDWAJ, Secy.

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1972

आदेश

का. आ. 147.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए पश्चिमी बंगाल विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 28-रायगंज निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री चक्रधर राय, ग्राम तथा डाकघर खालसी, जिला पश्चिमी दीनाजपुर, पश्चिमी बंगाल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री चक्रधर राय को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. प. बं.-वि. स./28/72(14)]

आदेश से,

ए. एन. सेन, सचिव

New Delhi, the 30th December, 1972

ORDER

S.O. 147.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Chakradhar Roy, Village & P.O. Khalsi District West Dinajpur, West Bengal, a contesting candidate for election to the West Bengal Legislative Assembly from 28-Raiganj constituency, held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Chakradhar Roy to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA/28/72(14)]

New Delhi, the 6th January, 1973

S.O. 148.—In pursuance of section 106 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby publishes the Order dated the 18th October, 1972 of the High Court of Punjab and Haryana in Election Petition No. 2 of 1972.

[No. 82/PB/2/71]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

IN THE HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA AT CHANDIGARH

CIVIL ORIGINAL SIDE

Election Petition No. 2 of 1971

S. Baldev Singh son of S. Mukand Singh resident of village Mauran, Tehsil and District Sangrur at present C/o S. Surjit Singh, Education Minister Punjab, Chandigarh. **Petitioner**

VERSUS

1. Shri Teja Singh Swatantar, M.P. 118-C, East Moti Bagh, New Delhi-7,

2. Shri Harnam Singh Chamak, Ex. M.L.A. resident of village Lohat Baddi, Tehsil Malerkotla, District Sangrur.

3. Lt. Gen. Harbax Singh, G.O.C. Retd. resident of Dhuri Gate, Sangrur.

4. Shri Mangal Sain, Municipal Commissioner. Dhuri District Sangrur. **Respondents.**

Petition under the provisions of Part VI, Chapter II, Sections 80, 81 and 101 of the Representation of People Act, 1951 praying that the election of Respondent No. 1 be declared to be void and the petitioner be declared to have been duly elected under clause (c) of the Section 98 of the Representation of Peoples Act, 1951.

The 18th October, 1972

PRESENT:

The Hon'ble Mr. Justice Gurdev Singh.

For the Petitioner.—Sh. A. S. Sarhadi, Advocate with Sh. N. S. Bhatia, Advocate.

For the Respondents.—Sh. Meja Singh Sandhu, Advocate with Shri Gurnam Singh Tir, Advocate for respondent No. 1.

JUDGMENT

The petitioner S. Baldev Singh was one of the contestants for Parliamentary seat from "12-Sangrur Parliamentary Constituency" in Punjab. As a result of the poll that took place on 5th March, 1971 he was defeated by S. Teja Singh Swatantar, respondent No. 1, by a margin of 210 votes. The votes polled by the various candidates were as follows:—

1. S. Teja Singh Swatantar	1,15,708
2. S. Baldev Singh	1,15,498
3. Lt. Gen. Harbax Singh	33,638
4. Shri Mangal Sain	2,285

The counting took place on 12th March, 1971 at Sangrur. The petitioner asked for recount but his prayer was rejected by the Returning Officer. This election petition has been preferred by Baldev Singh challenging the election of respondent Teja Singh Swatantar. Besides claiming that the election of the successful candidate was void, he prays that under Section 98(c) of the Representation of the People Act, 1951 he be declared to have been duly elected as on proper scrutiny and recount of the votes it will be found that the counting was improper and dishonest and in fact, he was the candidate by whom highest number of votes had been polled. He charged the counting staff with bias against him and the Akali Party of which he was the official candidate, dishonesty in counting of votes and breach of the rules concerning the scrutiny and counting.

Respondent No. 1, Teja Singh Swatantar, who alone contested this petition, vehemently denied these allegations and maintained that the counting was fair, impartial and in accordance with rules. Besides complaining that the allegations regarding unfair counting, illegal acceptance and wrongful rejection of votes were extremely vague, he asserted that the prayer for recount had been turned down for valid reasons and he validly declared elected.

This, in brief, is the case of the parties. Their pleadings have been noticed in detail in my order dated 24th March, 1972. They gave rise to the following issues for trial:—

1. Whether 1280 votes cast in favour of the petitioner were illegally rejected as alleged in paragraph 10 and detailed in sub-paras (A)(i) (ii) (iii), (B), (C) (i) (ii), (D) (i) (iii) and (E) (i) (ii) of paragraph 9 of the Election Petition?

2. Whether 815 votes were wrongfully accepted in favour of Respondent No. 1 as averred in sub-paras (A) (iv), (B), (C) (iii), (D) (i) (ii) (iii) and (E) (iv) of paragraph 9 of the petition?

3. Whether the Counting Assistants acted dishonestly and 430 votes, which were in fact secured by the petitioner, were wrongfully counted for the respondent as alleged in sub-paras (A) (iii), (C) (iv), (D) (iv) and (E) (iii) of paragraph 9 of the petition?

4. Whether any votes cast in favour of the petitioner were placed inside the bundles of votes earmarked for the respondent and other candidates as alleged in sub-paras (A) (iii), (C) (iv), (D) (iv) and (E) (iii) of paragraph 9 of the petition? If so, what is its effect on the result of the election?

5. If issue No. 1, 2, 3 or 4 or any parts thereof are proved, has the result of election been thereby materially affected?

6. Is the petitioner entitled to inspection, scrutiny and recount of the ballot papers and, if so, to what extent?

7. Whether the petitioner had secured majority of valid votes and is entitled to the declaration as prayed in part (a) of paragraph 23 of the petition?

8. Relief?

It may be emphasised here that there is no charge of any corrupt practice and gravamen of the petitioner's complaint is that number of his valid votes had been illegally rejected while invalid votes had been wrongfully accepted for the respondent No. 1 Teja Singh Swatantar. To substantiate these allegations the petitioner not only depended upon the oral evidence produced by him but also claimed inspection and scrutiny of the ballot papers, which form the subject matter of issue No. 6. After examining a number of witnesses in support of his case, on 8th November, 1971, the petitioner made an application (Civil Miscellaneous 41-E of 1971) praying for the opening, scrutiny, inspection and recount of the ballot papers, both rejected and accepted, relating to Dhuri, Dhanaula, Sangrur, Malerkotla, Phul and Sherpur segments of Parliamentary Constituency from which he had contested the elections. In support of this prayer it was urged that adequate material was forthcoming in the evidence., that the petitioner had examined, about the illegalities committed in the course of scrutiny and counting, illegal rejection of his votes and wrongful acceptance of the votes counted for respondent No. 1 Teja Singh Swatantar. Since the counting and scrutiny of votes had a direct bearing on the other issues framed for trial, it was considered necessary, as agreed to by the parties' counsel themselves, to dispose of issue No. 6 before dealing with other issues.

Issue No. 6

In dealing with this issue the parties took me through the entire material on record. After going through the evidence and the relevant provisions of law I disposed of this issue vide my order dated 24th March, 1972 holding that no case for wholesale scrutiny and counting of votes has been made out. It was, however, considered expedient at that stage to inspect and scrutinise only the petitioner's rejected votes relating to Sherpur segment alone. The concluding portion of my detailed order dated 24th March, 1972 runs thus:—

> "This being in my opinion the state of law, the rejection of the petitioner's votes solely on the ground that the ballot papers did not bear the signature of Presiding Officer is clearly illegal.
>
> As has been observed earlier, the petitioner has asserted that out of the votes secured by him in Sherpur segment 450 were rejected on the ground that they did not bear the signature of the Returning Officer. In view of the fact that the respondent's own witnesses admit that there was rejection of such votes, though they are silent about their number, a case for inspection and scrutiny of votes is clearly made out, even if we keep apart the petitioner's allegations and the evidence adduced by him with regard to the rejection of his votes on the ground of defective or improper marking by the voters. Issue No. 6 is, accordingly, found in petitioner's favour and the interests of justice require that the inspection and scrutiny prayed for be allowed.
>
> Since the petitioner's allegation with regard to rejection of such votes which did not bear the prescribed signature is confined to Sherpur Assembly constituency alone and the number of such votes is stated to be 450, which is more than twice the difference of votes secured by him and the returned candidates, I consider it expedient at this stage to inspect and scrutinise only the petitioner's rejected votes relating to that segment of the Parlimentary Constituency. I, accordingly direct that the rejected ballot papers of the petitioner relating to the Sherpur segment be opened for inspection and scrutiny in the first instance.
>
> Since it is not known in which of the boxes received in this Court the relevant ballot papers etc. let the Naib Tehsildar (Elections) be summoned for 7th of April, 1972, as suggested by the counsel for the parties"

Being dissatisfied with this order the contesting respondent Teja Singh Swatantar went up in appeal to the Supreme Court and their Lordships by their order dated 2nd May, 1972 in Civil Appeal No. 1139 of 1972 issued the following direction to this Court with the parties' consent:—

> "The trial Court shall direct the recount of all the rejected ballot paper of Sherpur segment of both the election petitioner as well as the returned candidate.
>
> It was urged on behalf of the appellant that the learned trial Judge has given conflicting interpretation as to the scope of sub-rule (2) of Rule 56 of the Conduct of Election Rules, 1961. It is not proper to go into that question at this stage."

In obedience to this order rejected ballot papers of both the election petitioner and of the returned candidate relating to the Sherpur segment were scrutinised and counted in open Court in presence of the Parties and their counsel on 18th July, 1972, The result thereof has been summed up in my order dated 1st August, 1972 in the following words:—

> "The scrutiny and recount of the rejected ballot papers of the Sherpur segment thus reveals that out of 1096 rejected ballot papers, only 17 claimed by

the petitioner and 7 by the respondent No. 1 were rejected. One of the rejected ballot papers of Baldev Singh was mutilated and its rejection is thus justified. The rejection, however, of 16 ballot papers of Baldev Singh and 7 of Teja Singh Swatantar, which did not bear the prescribed signature under section 83 but had the prescribed mark on them, was illegal in view of the interpretation that I have placed on rule 56 in my detailed order of 24th of March, 1972, to which reference has been made earlier. Because of this wrong view of the Returning Officer that ballot papers which did not bear the prescribed signature though they had the prescribed mark on them, could not be treated as valid, 16 votes of the petitioner Baldev Singh and 7 of the respondent Teja Singh Swatantar must be held to have been wrongfully rejected."

Relying upon this finding that 16 votes of the petitioner Baldev Singh and 7 of the contesting respondent Teja Singh Swatantar had been wrongfully rejected, it was urged on behalf of the petitioner that the rejected votes of the petitioner relating to other segments as well be inspected and recounted. That prayer was, however, rejected vide my detailed order dated 1st August, 1972.

Issues Nos. 1 to 4

Issues Nos. 1 to 4 relate to the petitioner's allegations of illegal and dishonest counting of votes relating to five segments of the Constituency, namely, Dhuri, Sherpur, Phul, Sangrur and Malerkotla. The general allegations made in paragraph 10 of the petition are that out of the rejected votes, 1280 were those that had been cast in favour of the petitioner and had been illegally rejected, and 430 votes out of the votes secured by the petitioner were illegally put in the bundles of other candidates, thereby deflating the petitioner's count. It is further alleged that 815 votes were illegally accepted for Respondent No. 1. The details of these illegalities and dishonest acts are set out in paragraph 9 of the petition. In support of this plea a large number of witnesses were examined at the trial. As their evidence is common to all the issues, issues Nos. 1 and 4 are being dealt with together. It will, however, be convenient to deal with the evidence about the counting of votes segment-wise.

Paragraph 9(A) of the petition relates to Dhuri constituency. It is alleged that out of 1013 rejected votes, 350 were those votes of the petitioner that had been illegally rejected. The voter's mark on 250 out of these votes, though not very distinct or perfect, was, however, sufficient to indicate that the voter had cast it for the petitioner, and 100 votes, though bearing the distinct marking, were rejected because of the smudging due to folding of ballot papers. According to the petitioner's allegations, out of the votes polled by him at the Dhuri constituency, 200 votes had been put in the bundles of the other candidates, and 175 were illegally counted for Respondent No. 1, though out of them 150 bore multiple markings and 25 were badly mutilated. The petitioner's witnesses examined in support of these allegations, who were present at the time of counting of votes at Dhuri segment, are Surjit Singh P.W. 9, Gursant Singh P.W. 10, Dr. Tejpal Singh P.W. 15, Raghbir Singh P.W. 22, Charanjit Singh P.W. 23, Gurbax Singh P.W. 24, and Sukhdev Chand P.W. 25.

Surjit Singh P.W. 9 was the petitioner's Counting Agent. He deposed that 350 votes of the petitioner were rejected on the ground that they were not distinctly or properly marked, and 200 votes polled in favour of the petitioner were put in the bundles of Teja Singh Swatantar, Respondent No. 1. He has stated that he had informed the petitioner when he visited the Place of counting and when the counting was going on, but it is an admitted fact that no written complaint was made to anyone about such illegal rejection on the date of the counting. In his cross-examination, the witness further conceded that except for the petitioner he never complained to anyone that the counting was not fair or legal. The witness all the same admitted that the rejected votes used to be examined by the Assistant Returning Officer sometime even with the help of magnifying glass.

Gursant Singh P.W. 10 is another Counting Agent of the petitioner. According to him, at the table at which he was working 10 or 12 votes of the petitioner were illegally rejected and he himself took exception to 10 or 15 votes that were being counted for Respondent No. 1. These votes were then taken to the Returning Officer, but he does not disclose with what result.

Dr. Tejpal Singh P.W. 15 stated that 15 or 20 votes having double markings were accepted as valid votes for Respondent No. 1 despite his objection, while some valid votes of the petitioner were rejected, by the Assistant Returning Officer on the ground that the voter's marks on those ballot papers were faint or overlapping. Even this part of his statement is of no consequence as he admitted in the next breath that these votes were not rejected in his presence. Though he asserted that 8 or 10 votes of the petitioner were put in the respondent's bundle and he brought this fact to the notice of the petitioner's Election Agent S. Surjit Singh Dhillon, but nothing came out of it and no written complaint was made. In his cross-examination, he admitted that he never complained about the conduct of Supervisor or the Counting Assistants to anyone, except S. Surjit Singh Dhillon and the petitioner's Agent Shri Gurdev Singh Advocate.

Raghbir Singh P.W. 22 deposed that his objections to 10 or 15 votes of the respondent Teja Singh Swatantar were accepted, though the marking on those votes was either incomplete or was not at the proper place, but 14 of 15 similar votes cast in favour of the petitioner were rejected.

Charanjit Singh P.W. 23 claims to have objected to 10 or 12 votes which were counted for Respondent No. 1. He alleged that 7 or 8 votes of the petitioner were wrongly rejected and in the pile of votes of Respondent No. 1 he found two valid votes of the petitioner. The witness admitted that the Agents of all the candidates were sitting at the same table and on Counting Agent of any other party objected to any vote. He further conceded that when objections were raised to ballot papers, the Counting Agents of all the parties were afforded an opportunity to see and examine the ballot paper.

Gurbax Singh P.W. 24 claims that some of the votes of Respondent No. 1 had not been properly marked, and said that 10 votes of the petitioner were rejected on the objections raised by the Agents of Respondent No. 1 as they bore double markings. Obviously, these had to be rejected.

Sukhdev Chand P.W. 25 is another Counting Agent of the petitioner, who deposed that 14 or 15 votes polled by the respondent Teja Singh Swatantar did not bear the signatures of the Presiding Officer and they were accepted despite his objection. It is further in his evidence that 5 or 7 votes polled by the petitioner were rejected as they were not properly marked, but asserted that 10 or 12 similar votes of Teja Singh Swatantar were accepted. He, however, conceded that he did not find anything wrong with any of the bundles.

This evidence does not suffice to prove the allegations contained in paragraph 9(A) of the petition.

The witnesses examined by the petitioner with regard to the counting of votes relating to Sherpur segment are Mohamad Din P.W. 19, Ahmad Ali P.W. 20 and Karnail Singh P.W. 27.

P.W. 19 Mohamad Din said that 35 or 40 votes secured by the petitioner had been wrongly rejected on the ground that they did not bear the signature of the Presiding Officer and 4 or 5 votes of the petitioner were wrongly put in another candidate's tray. In his cross-examination, he admitted that on both days the same Counting Assistants were on duty at his table. When asked why he did not ask, after the counting of first day was over, that the Counting Assistants and the Supervisor be replaced by impartial officials, the witness merely said : "It was none of my business."

P.W. 20 Ahmad Ali tells us that 10 or 15 votes, which did not bear the signatures of the Presiding Officer but were cast in favour of the petitioner, had been rejected.

Karnail Singh P.W. 27, who was the Counting Agent of the petitioner, deposed that 50 or 60 votes polled by the petitioner were rejected on the ground that those ballot papers did not bear the signatures of the Presiding Officer. He admitted that these ballot papers were examined by the Assistant Returning Officer before they were finally rejected.

As has been noticed earlier, the only allegation with regard to the votes of Sherpur segment, as set out in paragraph 9(B) of the petition, is that out of all the rejected votes of this segment, 450 were those that the petitioner had polled but they were wrongly rejected on the ground that they did not bear the signatures of the Presiding Officer. It is further urged that 200 similar unsigned votes were counted for Respondent No. 1. Under the orders of their Lordships of the Supreme Court, all the rejected votes of Sherpur segment were opened and inspected by this Court on 18th of July, 1972. This scrutiny completely falsified the allegations made by the petitioner and his witnesses, as it was found that out of 1096 rejected ballot papers, only 16 marked in favour of the petitioner and 7 in favour of the respondent Teja Singh Swatantar did not bear the signatures prescribed under section 83, but had the prescribed mark on them. This clearly demonstrates the gross exaggeration to which the petitioner and his witnesses have resorted. At the same time, it goes to show that there was no discrimination in scrutinising or dealing with the votes polled by the petitioner or the respondent Teja Singh Swantar and the counting had been fair. It is true that according to my finding the ballot papers which did not bear the prescribed signatures but had the requisite mark on them could not be rejected, but the result of the scrutiny of the ballot papers of Sherpur segment goes to show that only 16 such ballot papers of the petitioner were wrongly rejected and at the same time 7 votes of Respondent No. 1 were declared to be invalid.

I now proceed to consider the evidence relating to the counting of votes of Phul segment. It is alleged in paragraph 9(C) of the petition that out of 957 rejected votes, 120 votes of the petitioner were wrongly rejected while 150 of the Respondent No. 1 were illegally accepted, and 70 of the petitioner's votes were put in the bundles of other respondents. The witnesses examined in this connection are Jasbir Singh P.W. 13, Dr. Didar Singh P.W. 17, Harchet Singh, P.W. 26, and Harbans Singh P.W. 30.

Jasbir Singh P.W. 13 said that 150 votes of the petitioner had been wrongly rejected and about 100 votes of the respondent Teja Singh Swantar had been illegally accepted. He admitted in his cross-examination that he had kept no note of this fact and was deposing from memory.

P.W. 17 Dr. Didar Singh said that 15 or 20 votes of the respondent were accepted despite his objection, though on the same ground 10 or 15 votes cast in favour of the petitioner had been rejected. When asked in examination-in-chief if he found anything wrong the bundling the witness replied :

> "As the attitude of the Counting Assistants and Supervisors towards the petitioner was not good, I have suspicion that the bundles were not properly made."

Harchet Singh P.W. 26 is another Counting Agent of the petitioner. According to him, 10 or 15 votes of the respondent Teja Singh Swatantar had been accepted despite his objection. He, however, conceded that no vote of the petitioner was rejected.

Harbans Singh P.W. 30 tells us that 20 or 25 votes cast in favour of the petitioner were rejected on the objection that some of them bore double markings and the marks on others were faint and not at proper places. The witness admitted that the Assistant Returning Officer had himself examined those votes and declared the objections valid. The defects in the votes, to which the witness refers, obviously justified their rejection.

In the Sangrur segment, out of 898 rejected votes, according to the allegations in paragraph 9(D) of the petition, 200 votes of the petitioner were arbitrarily rejected on the ground that they had multiple markings on them, though 120 similar votes were accepted and counted for Respondent No. 1, and 20 cases of multiple voting were overlooked by the Counting Authorities and those ballot papers were counted for Respondent No. 1. Besides, 100 votes of the petitioner are alleged to have been mischieviously and maliciously put in the bundles of other respondents. In this connection, reliance is placed on the evidence of Mehma Singh P.W. 7, and Surmukh Singh P.W. 8.

Mehma Singh P.W. 7 deposed that 20 or 25 votes, which were not clearly marked, were claimed by him for the petitioner but the same were rejected. In claiming those votes for the petitioner, the witness asserted that the main portion of the marking seal was against the name of the petitioner. Thus, on his own showing it appears that the marking was not clear and without examining these ballot papers it cannot be said that they were wrongly rejected. When questioned about the bundles of votes the witness merely said that he had a suspicion that some of the bundles did not contain the correct number of votes.

Surmukh Singh P.W. 8 complains that 71 votes of the petitioner were wrongly rejected and 10 or 15 votes, which wer not distinctly marked, were wrongly counted for the respondent. When asked about the irregularities committed in making the bundles of votes, the witness, however, said : "Since I was not allowed to count such bundles, the possibility is there."

So far as Malerkotla segment is concerned, the allegations in paragraph 9(E) of the petition are that out of 844 rejected votes relating to this segment, 50 were those of the petitioner that had been wrongly rejected. It is further stated that 60 ballot papers were maliciously or dishonestly placed by the Counting Assistants in the bundles of other candidates, and 150 votes were illegally counted for Respondent No. 1. The witnesses examined by the petitioner in support of these allegations are Jasbir Singh P.W. 13, Shamshad Ali P.W. 18 and Mohammad Din P.W. 19.

Jasbir Singh P.W. 13 placed the number of the votes of the petitioner that had been illegally rejected at 100 or 150 and also stated that 100 votes of the respondent were wrongly accepted.

Shamshad Ali P.W. 18 tells us that 10 or 20 votes claimed by him for the petitioner were rejected. He, however, disclosed that on those ballot papers the marking were not complete and there just appeared a dot in front of the symbol of the petitioner. It is further in his evidence that these votes were scrutinised by the Assistant Returning Officer and he confirmed their rejection. Though a leading question was put to him to elicit if there was anything wrong with the bundles, the witness, however, said that he did not notice any irregularity.

Mohammad Din P.W. 19 is the same person who had deposed about the Sherpur segment. The result of the scrutiny, inspection and counting of votes of that segment has clearly brought out the fact that this witness is not a truthful person and no reliance can be placed upon him. So far as Malerkotla segment is concerned, his assertion that 15 or 20 votes of the petitioner were rejected either on the ground that they bore two marks or that the marking was partial and not on the symbol but away from it, does not suffice to prove that the rejection was wrongful.

It is thus evident that the allegations contained in paragraphs 9 and 10 of the petition, which forms the subject-matter of issues Nos. 1 to 4, are not substantiated. The evidence adduced in support of them is not only interested but is extremely vague and conjectural. Such like evidence can be easily procured. In dealing with the oral evidence in this case, it must be remembered that though it is alleged that persistent illegalities were being committed by the counting staff at various places where the counting was going on, not a single complaint muchless in writing was made to any authority either while the counting was going on or soon after. At some places the counting went on for two days, but curious enough despite the fact that on the first day the counting staff is alleged to have misbehaved and openly given out that they were hostile to the petitioner and the Akali Party, no complaint was made against the counting officials concerned, nor any attempt made to have the counting staff changed for the next day.

The result of the scrutiny of the rejected ballot papers relating to Sherpur segment demonstrates beyond any manner of doubt that wild allegations have been made against the counting staff and the evidence adduced in support of the same stood falsified by the result of the the scrutiny.

For all these reasons I find that issues No. 1 to 4 have not been proved and decide them against the petitioner.

Issue No. 5

Since issues Nos. 1 to 4 have been found against the petitioner, this issue does not arise.

Issue No. 6

Issue No. 6 stands disposed of by my order dated 24th of March, 1972, and the subsequent order dated 1st of August, 1972. The result of the scrutiny of the ballot papers, limited to Sherpur segment in view of the order of the Supreme Court, has been against the petitioner, as already noticed. It proved that only 16 votes of the petitioner were wrongly rejected.

Issue No. 7

In view of the fact that all the earlier issues have been found against the petitioner and the election of Respondent No. 1 has not been found to be void, the question of declaring the petitioner as duly elected does not arise.

Issue No. 8

The petitioner having failed to substantiate any of his allegations, he is not entitled to any relief.

The petition is, accordingly, dismissed with costs. Counsels' fee Rs. 500/-.

October 18, 1972. GURDEV SINGH, Judge.

वित्त मंत्रालय

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1972

का० आ० 148.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खण्ड 13 के उपखण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक से परामर्श के पश्चात्, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट निदेशकों को, उसके स्तम्भ (2) में उनके सामने विनिर्दिष्ट राष्ट्रीयकृत बैंक की प्रबंध समिति के क्रमशः सदस्यों के रूप में, 27 दिसम्बर, 1972 को प्रारम्भ होने वाली और 10 दिसम्बर, 1973 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, एतद्द्वारा नामनिर्देशित करती है।

सारणी

सदस्यों के रूप में नामनिर्देशित निदेशकों के नाम	राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम
1. श्री तारकेश्वर चक्रवर्ती 2. श्री ए० एच० इलियास 3. श्री जी० बी० नेवाल्कर	सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
1. श्री ए० आर० सुले 2. श्री जी०डी० पारिख 3. ब्रिगेडियर के० के० वर्मा	बैंक आफ इंडिया
1. श्री डी० पी० चड्ढा 2. श्री मुहम्मद अब्दुल्ला 3. श्री मदन मोहन महाजन	पंजाब नैशनल बैंक
1. श्री के० सी० चोकसी 2. श्री डी० के० देसाई 3. डा० टी०आर० एस० गोयल	बैंक आफ बड़ौदा
1. श्री एस० लक्ष्मणन 2. डा० डी० बनर्जी 3. श्री गुरसरन सिंह	यूनाइटेड कामर्शियल बैंक
1. श्री सी० एस० सुब्रमण्यम 2. श्री के० एस० आर० मलियाह 3. श्री पी० एस० राजगोपाल नायडू	कनारा बैंक
1. श्री तारा प्रसन्न दास 2. श्री के० पी० बरुआ 3. श्री कार्तिक चन्द्र पाल	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया
1. श्री टी० एच० नारायण स्वामी 2. श्री कृष्ण राज 3. श्री देवभाई प्रभुभाई पटेल	देना बैंक
1. श्री यू० पी० शेट 2. श्री स्वामीनाथ रेड्डी 3. डा० एन० सी० बिलिगिरी रंगय्या	सिन्डीकेट बैंक
1. श्री एस० बी० गोदीवाला 2. श्री के० एच० पारिख 3. श्री आर०आर० उपासनी	यूनियन बैंक आफ इण्डिया
1. श्री जे० डी० जैन 2. श्री एम० आर० राय 3. श्री एस० एन० श्रीवास्तव	इलाहाबाद बैंक
1. श्री एम० गोपालकृष्णन 2. डा० बी० नटराजन 3. श्री एम० सीताराम दास	इण्डियन बैंक
1. श्री एम० आर० कुलकर्णी 2. डा० के० एस० यावल्कर 3. डा० (श्रीमती) सुलभ ब्रह्म	बैंक आफ महाराष्ट्र
1. श्री पी० ए० कुमारदेवन 2. श्री एम० के० राजू 3. श्री एन० बी० प्रसार	इण्डियन ओवरसीज बैंक

[सं० फा० 8/11/72-बी० ओ० I]

द० म० सुकथनकर, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Banking)

New Delhi, the 27th December, 1972

S.O. 148.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (2) of clause 13 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank, hereby nominates the Directors specified in column (1) of the Table below to be respectively members of the Management Committee of the nationalised bank specified against them in column (2) thereof for the period commencing on 27th December, 1972, and ending with 10th December, 1973.

TABLE

Name of Directors nominated as members	Name of the nationalised bank
1. Shri Tarakeshwar Chakraborty 2. Shri A. H. Elias 3. Shri G. B. Newalkar.	Central Bank of India.
1. Shri A. R. Sule 2. Shri G. D. Parikh. 3. Brig. K. K. Verma.	Bank of India.
1. Shri D. P. Chadha. 2. Shri Mohamad Abdullah. 3. Shri Madan Mohan Mahajan.	Punjab National Bank.
1. Shri K. C. Chokshi. 2. Shri D. K. Desai. 3. Dr. T. R. S. Goel.	Bank of Baroda.
1. Shri S. Lakshmanan 2. Dr. D. Banerjee. 3. Shri Gursaran Singh	United Commercial Bank
1. Shri C. S. Subramaniam. 2. Shri K. S. R. Malliah. 3. Shri P. S. Rajagopal Naidu.	Canara Bank.
1. Shri Taraprasanna Das. 2. Shri K. P. Barua. 3. Shri Kartick Chandra Paul.	United Bank of India.
1. Shri T. H. Narayanaswami. 2. Shri Krishna Raj. 3. Shri Devabhai Prabhubhai Patel	Dena Bank
1. Shri U. P. Shet. 2. Shri Swaminatha Reddy 3. Dr. N. C. Billigiri Rangaiah.	Syndicate Bank.
1. Shri S. B. Godiwalla. 2. Shri K. H. Parikh 3. Shri R. R. Upasani.	Union Bank of India.
1. Shri J. D. Jain. 2. Shri M. R. Roy. 3. Shri S. N. Srivastava.	Allahabad Bank.
1. Shri M. Gopalkrishnan. 2. Dr. B. Natarajan. 3. Shri Seetharama Dos.	Indian Bank.
1. Shri M. R. Kulkarni. 2. Dr. K. S. Yawalkar. 3. Dr. (Mrs.) Sulabha Brahme.	Bank of Maharashtra.
1. Shri P. A. Kumaradevan. 2. Shri M. K. Raju. 3. Shri N. B. Prasad.	Indian Overseas Bank.

[No. F. 8/11/72-BOI]

D. M. SUKTHANKAR, Director

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1973

का० आ० 149.—रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसरण में दिसम्बर 1972 की 29 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा

इशु विभाग

देयताएं	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	4,92,35,000		सोने का सिक्का और बुलियन :—		
संचलन में नोट	4794,33,80,000		(क) भारत में रखा हुआ	182,53,11,000	
			(ख) भारत के बाहर रखा हुआ	. .	
			विदेशी प्रतिभूतियां	171,65,38,000	
जारी किये गये कुल नोट		4799,26,15,000	जोड़		354,18,49,000
			रुपये का सिक्का		20,73,21,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां		4424,34,54,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र		
कुल देयताएं		4799,26,15,000	कुल आस्तियां		4799,26,15,000

तारीख 3 जनवरी, 1973

एस० जगन्नाथन, गवर्नर

29 दिसम्बर, 1972 को रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

देयताएं	रुपये		आस्तियां	रुपये
चुकता पूंजी		5,00,00,000	नोट	4,92,35,000
आरक्षित निधि		150,00,00,000	रुपये का सिक्का	7,47,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि		209,00,00,000	छोटा सिक्का	3,10,000
			(खरीदे और भुनाये गये बिल :—	
ष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि		45,00,00,000	(क) देशी	85,50,000
ष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि		175,00,00,000	(ख) विदेशी	. .
			(ग) सरकारी खजाना बिल	260,61,80,000
जमा राशियां :—			विदेशों में रखा हुआ बकाया*	158,89,77,0000
(क) सरकारी			निवेश**	409,25,27,000
			ऋण और अग्रिम	
(i) केंद्रीय सरकार	64,03,25,000		(i) केंद्रीय सरकार को	
(ii) राज्य सरकारें	10,96,06,000		(ii) राज्य सरकारों को $	79,38,15,000
(ख) बैंक			ऋण और अग्रिम :	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	297,61,05,000		(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को†	8,54,50,00
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	11,70,93,000		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को‡	297,71,76,000
(iii) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,12,21,000		(iii) दूसरों को	3,97,97,000
(iv) अन्य बैंक	53,72,000		राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं, निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश :	
			(क) ऋण और अग्रिम :	
			(i) राज्य सरकारों को	53,56,04,000
			(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	24,91,10,000
			(iii) केंद्रीय भूमिबंधक बैंकों को	. .
			(iv) कृषि पुनर्वित्त निगम को	10,00,00,000
(ग) अन्य		89,35,47,000	(ख) केंद्रीय भूमिबंधक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	11,08,56,000
			राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	
देयबिल		96,54,57,000	राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	28,92,86,000
			राष्ट्रीय औद्योगिक दीर्घकालिन क्रियाएं निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
अन्य देयताएं		358,96,71,000	(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	93,06,94,000
			(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किए गए बांडों/डिबेंचरों में निवेश	. .
			अन्य आस्तियां	69,00,83,000
	रुपये	1514,83,97,000	रुपये	1514,83,97,000

*नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि में से किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

$ राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परंतु राज्य सरकारों के अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

†रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मीयादी बिलों पर अग्रिम दिए गए शून्य रुपये शामिल हैं।

‡राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

एस० जगन्नाथन, गवर्नर

[सं० फा० 1/3/72-बी० ओ०-I]

तारीख : जनवरी, 1973।

च० व० मीरचन्दानी, अवर सचिव

RESERVE BANK OF INDIA

New Delhi, the 4th January, 1973

S.O. 149.—An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934, for the week ended the 29th day of December, 1972.

Issue Department

Liabilities	Rs.	Rs.	Assets	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	4,92,35,000		Gold Coin and Bullion:-		
Notes in circulation	4794,33,80,000		(a) Held in India	182,53,11,000	
			(b) Held outside India	..	
			Foreign Securities	171,65,38,000	
Total Notes issued		4799,26,15,000	TOTAL		354,18,49,000
			Rupee Coin		20,73,21,000
			Government of India Rupee Securities		4424,34,45,000
			Internal Bills of Exchange and other commercial Paper.		..
Total Liabilities		4799,26,15,000	Total Assets		4799,26,15,000

Dated the 3rd January 1973

S. JAGANNATHAN, Governor.

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 29th December, 1972.

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	4,92,35,00,000
		Rupee Coin	7,47,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Small Coin	3,10,000
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	209,00,00,000	Bills Purchased and Discounted :-	
		(a) Internal	5,50,000
		(b) External	..
		(c) Government Treasury Bills	260,61,80,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	45,00,00,000	Balances Held Abroad*	158,89,77,000
		Investments **	409,25,27,000
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	175,00,00,000	Loans and Advances to:-	
		(i) Central Government	..
		(ii) State Governments@	79,38,15,000
Deposits :-		Loans and Advances to:-	
(a) Government		(i) Scheduled Commercial Bankst	8,54,50,000
(i) Central Government	64,03,25,000	(ii) State Co-operative Banks‡	297,71,76,000
(ii) State Governments.	10,96,06,000	(iii) Others	3,97,97,000
		Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to:—	
(b) Banks		(i) State Governments	53,56,04,000
(i) Scheduled Commerical Banks	297,61,05,000	(ii) State Co-operative Banks	24,91,10,000
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	11,70,93,000	(iii) Central Land Mortgage Banks	..
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks.	1,12,21,000	(iv) Agricultural Refinance Corporation.	10,00,00,000
(iv) Other Banks	53,72,000	(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	11,08,56,000
		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
(c) Others	89,35,47,000	Loans and Advances to State Co-operative Banks	28,92,86,000
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.	
Bills Payable.	96,54,57,000	(a) Loans and Advances to the Development Bank	93,06,94,000
Other Liabilities.	358,96,71,000	(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	..
		Other Assets.	69,00,83,000
Rupees.	1514,83,97,000	Rupees.	1514,83,97,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Government.

†Includes Rs. Nil advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

‡Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

Dated, 3rd January, 1973.

S. JAGANNATHAN, Governor.

[No. F.1/3/72-BOI]

C. W. MIRCHANDANI, Under Secy.

(राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1972

आय-कर

का. आ. 150.—सर्व साधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संस्था, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (2) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, द्वारा अनुमोदित कर दी गई है।

संस्था

तमिलनाडु आई रिलीफ एसोसिएशन, मदुराई।

[सं. 237 (फा. सं. 203/44/72-आई. टी. ए. 2)]

(Department of Revenue & Insurance)

New Delhi, the 11th December, 1972

INCOME-TAX

S.O. 150.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Medical Research, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

INSTITUTION

TAMIL NADU EYE RELIEF ASSOCIATION, MADURAI

[No. 237/F. (No. 203/44/72-ITA-II)]

का. आ. 151.—सर्व साधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संस्था, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (2) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, द्वारा अनुमोदित की गई है।

संस्था

विज्ञान परिषद्, इलाहाबाद।

[सं. 238 (फा. सं. 203/25/72-आई. टी. ए. 2)]

टी. पी. झुनझुनवाला, उप-सचिव,

S.O. 151.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Council of Scientific and Industrial Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-taix Act, 1961.

INSTITUTION

VIJNANA PARISHAD, ALLAHABAD.

[No. 238/F. (No. 203/25/72-ITA. II)]

T. P. JHUNJHUNWALA, Deputy Secy.

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय

(कार्यालय समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

मद्रास, 14 नवम्बर, 1972

का. आ. 152.—1944 की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली के नियम 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, मद्रास के समाहर्ता कार्यालय के उन अधिकारियों को, जिनका पद केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के सहायक समाहर्ता के पद से नीचे न हो, अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के नियमों का उल्लंघन करने के कारण अधिगृहीत की गयी केवल सवारियों के सम्बन्ध में अस्थायी रूप से छोड़ देने के लिए, 1944 की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली के नियम 206(3) के अन्तर्गत, समाहर्ता की शक्तियां प्राधिकृत करता हूं।

[सं. 4/9/67-केन्द्रीय उत्पाद निर्णय]

COLLECTORATE OF CUSTOM AND CENTRAL EXCISE

(Office of the Collector of Central Excise)

Madras, the 14th November, 1972

CENTRAL EXCISE

S.O. 152.—In exercise of the powers conferred by rule 5 of the Central Excise Rules 1944, I authorise the officers not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise in the Madras Central Excise Collectorate to exercise within their respective jurisdiction the powers of the Collector under rule 206(3) of Central Excise Rules, 1944 in regard to the provisional release of conveyances only, seized for violation of the Central Excise Rules.

[No. C. No. IV/9/67/72 CX. Adj.]

मद्रास, 20 दिसम्बर, 1972

का. आ. 153.—1944 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के 5वें नियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस समाहर्ता कार्यालय की दिनांक 6-6-70 की अधिसूचना सं. 4/16/391/62 केन्द्रीय उत्पाद-1, का अधिक्रमण करके, मैं एतद्द्वारा, इस समाहर्ता कार्यालय के सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, (नवीन उत्पाद शुल्क) मुख्यालय-मद्रास, को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के 189क और 189ख, नियमों के अन्तर्गत, समाहर्ता की शक्तियों के प्रयोग करने का अधिकार प्रदान करता हूं।

[सी. सं. 4/16/391/62 केन्द्रीय उत्पाद-3]

सी. चिदाम्बरम्, समाहर्ता

Madras, 20th December, 1972

S.O. 153.—In exercise of the powers conferred on me Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of this Collectorate Notification No. IV/16/391/62-CX.I dated 6-6-1970, I hereby empower the Assistant Collector of Central Excise (New Exercises) at the Collectorate, Headquarters Office, Madras to exercise powers of the Collector under Rules 189A and 189B of the Central Excise Rules, 1944.

[C. No. IV/16/391/62 CX. III]
C. CHIDAMBARAM, Collector.

विदेश व्यापार मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1973

का. आ. 154.—मोंढक की टांग निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 6 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के विदेश व्यापार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3323, ता.

14 अगस्त 1969 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में "मुम्बई क्षेत्र (महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमण और दीव, दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों को मिला कर)" शीर्षक के अन्तर्गत क्रम सं. (6) और उससे संबंधित प्रविष्टियां निकाल दी जाएंगी तथा क्रम सं. (7) को क्रम संख्या (6) के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा ।

[सं. 6(9)/71-नि. नि. तथा नि. सं.]

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 13th January, 1973

S.O. 154.—In pursuance of rule 6 of the Export of Frog Legs (Inspection) Rules, 1965, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Foreign Trade No. S.O. 3323 dated the 14th August, 1969 namely:—

In column (2) of the Table appearing below the said notification, under the heading "Bombay Region (Covering the States of Maharashtra, Gujrat, the Union Territories of Goa, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli)". Serial No. (6) and entries relating thereto shall be deleted, and the Serial number (7) be re-numbered as Serial No. (6).

[No. 6(9)/71-EI&EP]

आदेश

का. आ. 155.—यतः निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि बीज-रहित इमली, निर्यात के पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन की जानी चाहिए;

और यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 2 के उपनियम (2) द्वारा यथाअपेक्षित निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेजा है;

अतः अब, उक्त उपनियम के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रस्तावों को उनसे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले जनसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित करती है ।

2. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों के बारे में किन्हीं आक्षेपों या सुझावों को भेजने की वांछा करने वाला कोई व्यक्ति उन्हें इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद् "वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर", 14/1 बी, इजरा स्ट्रीट (सातवीं मंजिल) कलकत्ता-1 को भेज सकेगा ।

प्रस्ताव

(1) यह अधिसूचित करना कि बीज-रहित इमली, निर्यात के पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होगी ।

(2) इस अधिसूचना के उपाबंध में दिए गए बीज-रहित इमली निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1973 के प्ररूप के अनुसार निरीक्षण के उस प्रकार को विनिर्दिष्ट करना जो ऐसी बीज-रहित इमली के निर्यात के पूर्व निरीक्षण के लिए लागू किया जाएगा ।

(3) बीज-रहित इमली श्रेणीकरण और चिन्हन नियम, 1971 के अधीन बनाए गए श्रेणी अभिधानों को बीज-रहित इमली के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देना ।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में बीज-रहित इमली के निर्यात का तब तक प्रतिषेध करना जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त चिन्ह या सील, यह उपदर्शित करते हुए कि यह उसको लागू मानक विनिर्देशों के अनुरूप है, ऐसी बीज-रहित इमली के पैकेजों या आधानों पर लगाई या चिपकाई गई न हो ।

3. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को बीस रूपए से अनधिक मूल्य की बीज-रहित इमली के उन नमूनों के समुद्र, स्थल और वायु मार्ग द्वारा निर्यात को लागू नहीं होगी ।

4. इस आदेश में, "बीज-रहित इमली" से इमली के पेड़ (टैमरिंडस इंडिकस) के पके फलों से पहले छिलके को और इसके पश्चात गूदे तथा बीजों को ढकने वाले रेशेदार पंजर को उतारने के बाद प्राप्त इमली का गूदा अभिप्रेत है ।

उपाबंध

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 के अधीन बनाए जाने वाले प्रस्तावित प्रारूप नियम ।

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:** (1) इन नियमों का नाम बीज-रहित इमली निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1973 है ।

(2) ये को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषा:** इन नियमों में बीज-रहित इमली से इमली के पेड़ (टैमरिंडस इंडिकस) के पके फलों से पहले छिलके को और उसके पश्चात् गूदे तथा बीजों को ढकने वाले रेशेदार पंजर को उतारने के बाद प्राप्त इमली का गूदा अभिप्रेत है ।

3. निर्यात से पूर्व बीज-रहित इमली के निरीक्षण की प्रक्रिया:— कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1), सामान्य श्रेणीकरण और चिन्हन नियम, 1937 और बीज-रहित इमली श्रेणीकरण और चिन्हन नियम, 1971 के उपबंध, निर्यात से पूर्व बीज-रहित इमली के निरीक्षण को यथावश्यक लागू होंगे ।

[सं. 6(13)/72-नि. नि. तथा नि. सं.]

ORDER

S.O. 155.—Whereas, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, that seedless tamarind should be subject to quality control and inspection prior to export;

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council, as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said

proposals may forward the same within thirty days of the date of publication of this order in the official Gazette to the Export Inspection Council, "World Trade Centre", 14/1B, Ezra Street (7th Floor), Calcutta-1.

PROPOSALS

(1) To notify that seedless tamarind shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) To specify the type of inspection in accordance with the draft Export of Seedless Tamarind (Inspection) Rules, 1973, set out in the Annexure to this order, as the type of inspection which shall apply to such seedless tamarind prior to export;

(3) To recognise the grade designations formulated under the seedless Tamarind Grading and Marking Rules, 1971, as the standard specifications for seedless tamarind;

(4) To prohibit the export in the course of international trade of seedless tamarind, unless a mark or seal recognised by the Central Government as indicating that it conforms to the standard specifications applicable to it has been affixed or applied to packages or containers of such seedless tamarind.

3. Nothing in this order shall apply to export by sea, land or air of samples of seedless tamarind not exceeding in value of rupees twenty to prospective buyers.

4. In this order, "seedless tamarind" means the tamarind pulp obtained from the mature fruits of *Tamarindus indicus* by removing first the rind, then the fibrous skeleton enclosing the pulp and the seeds.

ANNEXURE

Draft rules proposed to be made under section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Export of Seedless Tamarind (Inspection) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the . . .

2. **Definition.**—In these rules, "seedless tamarind" means the tamarind pulp obtained from the mature fruits of *Tamarindus induicus* by removing first the rind, then the fibrous skeleton enclosing the pulp and the seeds.

3. **Procedure of inspection of seedless tamarind prior to export.**—The provisions of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), the General Grading and Marking Rules, 1937, and the Seedless Tamarind Grading and Marking Rules, 1971, shall, so far as may be, apply to the inspection of seedless tamarind prior to export.

[No.6(13)/72-EI&EP]

का. आ. 156.—यतः निर्यात क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 8 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, बीज-रहित इमली श्रेणीकरण और चिन्हन नियम, 1971 के नियम 3 के अधीन वर्णित श्रेणी-अभिधान चिन्ह को, बीजरहित इमली के बारे में यह घोषित करने के प्रयोजन के लिए मान्यता देने का प्रस्ताव करती है कि जहां बीज-रहित इमली से भरे पैकेजों या आधानों पर विहित चिह्न लगाए गए हों, वहां ऐसे पैकेजों या आधानों में भरी बीज-रहित इमली उक्त अधिनियम की धारा 6 के खण्ड (ग) के अधीन उसे लागू मानक विनिर्देशों के अनुरूप है ।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने प्रस्ताव बनाए हैं और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) द्वारा यथाअपेक्षित निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेजा है ।

33 G of I—3.

अतः अब, उक्त उपनियम के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त प्रस्ताव को उनसे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले जनसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित करती है ।

2. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्ताव के बारे में किन्हीं आक्षेपों या सुझावों को भेजने की वांछा करने वाला कोई व्यक्ति उन्हें इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर निर्यात-निरीक्षण परिषद्, "वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर" 14/1-बी, इजरा स्ट्रीट (सातवीं मंजिल), कलकत्ता-1 को भेज सकेगा ।

स्पष्टीकरणः— इस अधिसूचना में "बीज-रहित इमली" से इमली के पेड़ (टेमरिंडस इंडिक्स) के पके फलों से पहले छिलके को और उसके पश्चात् गूदे तथा बीजों को ढकने वाले रेशेदार पंजर को उतारने के बाद प्राप्त इमली का गूदा अभिप्रेत है ।

[सं. 6(13)/72-नि. नि. तथा नि. सं.]

S.O. 156.—Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 8 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) proposes to recognise the garde designation mark described under rule 3 of the Seedless tamarind, Grading and Marking Rules, 1971 with respect to seedless tamarind, for the purpose of denoting that where packages or containers containing seedless tamarind are affixed with the prescribed labels, the seedless tamarind in such packages or containers conform to the standard specifications applicable thereto under clause (c) of Section 6 of the said Act;

And whereas, the Central Government has formulated the proposal and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposal for information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposal may forward the same within thirty days of the date of publication of this notification to the Export Inspection Council, "World Trade Centre", 14/1B, Ezra Stree (7th Floor), Calcutta-1.

Explanation: In this notification "Seedless Tamarind" means the tamarind pulp obtained from the mature fruits of *Tamarindus indicus* by removing first the rind, then the fibrous skeleton enclosing the pulp and the seeds.

[No. 6(13)/72-EI&EP]

का. आ. 157.—यतः भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए कतिपय प्रस्ताव, वैद्युत प्रयोजनों के लिए रबड़ दस्तानों का निर्यात के पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन करने के लिए, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) द्वारा यथापेक्षित भारत के राजपत्र, भाग 2-खंड 3-उप-खंड (2) में पृष्ठ 1748 से पृष्ठ 1479 पर, भारत सरकार के विदेश व्यापार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 946, तारीख 1 अप्रैल, 1972 के अधीन प्रकाशित किए गए थे ।

और यतः उक्त अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिन के भीतर तद्द्वारा संभाव्यतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे,

और यतः उक्त राजपत्र जनसाधारण को 1 अप्रैल, 1972 को उपलब्ध कर दिया गया था ,

और यतः उक्त प्रारूप पर जनसाधारण से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ,

अतः अब, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार, यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है, एतद्द्वारा—

(1) अधिसूचित करती है कि वैद्युत प्रयोजनों के लिए रबड़ दस्तानें निर्यात के पूर्व क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण के अधीन होंगे ।

(2) वैद्युत प्रयोजनों के लिए रबड़ दस्तानों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1973 के अनुसार निरीक्षण के प्रकार को ऐसे रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जो ऐसे रबड़ दस्तानों को निर्यात के पूर्व लागू किया जाएगा ।

(3) (क) ऐसे विनिर्देशों को, जो किसी आयात कर्ता देश के राष्ट्रीय मानक होंगे, वैद्युत रबड़-दस्तानों के लिए निर्यात संविदा के निर्यात कर्ता द्वारा घोषित करार पाए गए विनिर्देशों के रूप में, मान्यता देती है ।

(ख) (क) में यथावर्णित किन्हीं विनिर्देशों के अभाव में, भारतीय मानक संस्थान द्वारा वैद्युत प्रयोजनों के लिए रबड़ दस्तानों के लिए अनुमोदित विनिर्देशों को वैद्युत प्रयोजनों के लिए रबड़ दस्तानों के मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देती है ।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में वैद्युत प्रयोजनों के लिए रबड़ दस्तानों के निर्यात का तब तक प्रतिषेध करती है जब तक उसके साथ केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन मान्यताप्राप्त अभिकरणों में से किसी एक द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाणपत्र न हो कि वैद्युत प्रयोजनों के लिए ऐसे रबड़ दस्तानें निर्यात योग्य हैं ।

3. इस आदेश की कोई भी बात स्थल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा निर्यात किए गए ऐसे रबड़ दस्तानों के उन नमूनों पर लागू नहीं होगी, जिनका भावी क्रेताओं के लिए पोत-पत्तन-निःशुल्क 125 रु. से अधिक नहीं है ।

4. यह आदेश 3 फरवरी, 1973 से प्रवृत्त होगा ।

[सं. 6(17)/71-नि. नि. तथा नि. सं.]

ORDER

S.O. 157.—Whereas for the development of export trade of India certain proposals for subjecting rubber gloves for electrical purposes to quality control and inspection prior to export were published, as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, at pages 1478 to 1479 of the Gazette of India, Part II—Section 3—Sub-Section (ii), dated the 1st April, 1972, under the notification of the Government of India in the Ministry of Foreign Trade, No. S.O. 946, dated the 1st April, 1972.

And whereas objections and suggestions were invited within sixty days from the date of publication of the said notification from all persons likely to be affected thereby;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 1st April, 1972;

An whereas no objections and suggestions were received from the public on the said draft;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, being of the opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of export trade of India, hereby—

(1) notifies that rubber gloves for electrical purposes shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) specifies the eype of inspection in accordance with the Export of Rubber Gloves for Electrical Purposes (Inspection) Rules, 1973, as the type of inspection which would be applied to such rubber gloves prior to export;

(3) recognises—

(a) the specifications, which shall be a national standard of an importing country, declared by the exporter as the agreed specifications of the export contract for the electrical rubber gloves;

(b) In the absence of any specifications as mentioned in (a), the specifications approved for rubber gloves for electrical purposes by the Indian standards Institution, as the standard specifications for rubber gloves for electrical purposes;

(4) prohibits the export, in the course of international trade of the rubber gloves for electrical purposes unless the same is accompanied by a certificate issued by one of the agencies recognised by the Central Government under secion 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), to the effect that such rubber gloves for electrical purposes are exportworthy.

3. Nothing in this order shall apply to the export by land, air or sea of samples of such rubber gloves to prospective buyers the F.O.B. value of which does not exceed Rs. 125/-.

4. This Order shall come into force on the 3rd February, 1973.

[No. 6(17)/71-EI&EP]

का. आ. 158.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम वैद्युत प्रयोजनों के लिए रबड़ दस्तानों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1973 होगा ।

(2) ये 3 फरवरी 1973 को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषा:**—इन नियमों में "वैद्युत प्रयोजनों के लिए रबड़ दस्तानों" से उर्जित कंडक्टरों और उपस्करों पर काम करते समय वैद्युत धक्कों से कर्मकारों के संरक्षण के लिए उपयोग में लाए गए पूर्णतः रबड़ से बने हुए सभी प्रकार के दस्ताने अभिप्रेत होंगे ।

3. **निरीक्षण का आधार:**—वैद्युत प्रयोजनों के लिए रबड़ दस्तानों का निरीक्षण इस दृष्टि से कार्यान्वित किया जाएगा कि वे निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों और विदेशी क्रेताओं की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हों, किन्तु ऐसे विनिर्देश मान्यताप्राप्त विनिर्देशों से कम न हों ।

4. **निरीक्षण की प्रक्रिया:**—(1) वैद्युत प्रयोजनों के लिए रबड़ दस्तानों के निर्यात करने का आशय रखने वाला कोई निर्यात-कर्ता ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना देगा तथा ऐसी सूचना के साथ ऐसे निर्यात से संबंधित निर्यात संविदा में अनुबंध विनिर्देशों की घोषणा निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन मान्यताप्राप्त निरीक्षण अभिकरणों में से किसी एक को (जिसे इसमें इसके पश्चात् अभिकरण कहा गया है) नियम 3 के अनुसार निरीक्षण कार्यान्वित करने के लिए उसे समर्थ बनाने हेतु भेजेगा ।

(2) यदि निर्यात संविदा में अनुबद्ध विनिर्देश क्रेता द्वारा अनुमोदित नमूने के रूप में हो तो निर्यात-कर्ता अनुमोदित नमूना और उसके लक्षण देते हुए सबूत के साथ घोषणा अभिकरण को तदनुसार भेजेगा ।

(3) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना और घोषणा तथा उप-नियम (2) के अधीन पोषण पोतभरण की अनुसूचित तारीख से कम से कम दस दिन पहले दी जाएगी ।

(4) उप-नियम (3) के अधीन सूचना और घोषणा की प्राप्ति पर, अभिकरण नियम 3 और निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा इसके बारे में जारी किए गए अनुदेशों, यदि कोई हो, के अनुसार वैद्युत प्रयोजनों के लिए रबड़ दस्तानों का निरीक्षण करेगा ।

(5) निरीक्षण की समाप्ति पर अभिकरण तत्काल परेषण के पैकिजों को इस प्रकार यह सुनिश्चित करने के लिए सील करेगा ताकि सील-बंद माल को बिगाड़ा न जा सके ।

(6) यदि निरीक्षण के पश्चात्, अभिकरण का समाधान हो गया है कि वैद्युत प्रयोजनों के लिए रबड़ दस्तानों के परेषण नियम 3 की आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं तो वह सूचना तथा व्यौरे घोषणा की प्राप्ति के दस दिन के भीतर उप-नियम (3) के अधीन निर्यात कर्ता को निर्यात-योग्यता का प्रमाणपत्र जारी करेगा, अन्यथा निर्यातकर्ता को निरीक्षण की समाप्ति के तीन दिन के भीतर नामंजूर किए जाने के कारणों के बारे में सूचना देगा ।

5. निरीक्षण का स्थान:—इन नियमों के अधीन प्रत्येक निरीक्षण या तो (क) ऐसे उत्पादों के विनिर्माता के परिसर में, या (ख) ऐसे परिसर में, जिसमें निर्यात-कर्ता द्वारा माल प्रस्तावित किया जाता है, परन्तु उसमें प्रयोजन के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों, क्रियान्वित किया जाएगा ।

6. निरीक्षण फीस-प्रत्येक परेषण के लिए, कम से कम 50 रूपये के अधीन रहते हुए, प्रत्येक परेषण के पोतपर्यंत निःशुल्क मूल्य के प्रत्येक 100 रूपयों के लिए 30 पैसे की दर से फीस इन नियमों के अधीन निरीक्षण फीस के रूप में संदत्त की जाएगी ।

7. **अपील.**—(1) नियम 4 उप-नियम (6) के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अभिकरण के इन्कार से व्यथित कोई व्यक्ति उसके द्वारा ऐसे इंकार की संसूचना की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर ऐसे विशेषज्ञों के पैनल को अपील कर सकेगा, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए नियुक्त 3 व्यक्तियों से कम व्यक्ति न हों ।

(2) पैनल की गणपूर्ति 3 व्यक्तियों की होगी ।

(3) ऐसी अपील पर उक्त पैनल का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

[सं. 6(7)/71-नि. नि. तथा नि. सं.]

S.O. 158.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Export of Rubber gloves for Electrical Purposes (Inspection) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the 3rd February, 1973.

2. **Definition.**—In these rules, "rubber gloves for electrical purposes" shall mean all types of gloves, made wholly of rubber, used for protection to workers from electrical shocks while working on energized conductors and equipments.

3. **Basis of inspection.**—Inspection of rubber gloves for electrical purposes shall be carried out with a view to seeing that the same conform to the standard specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) and specific requirements of foreign buyers provided such specifications do not fall below the specifications so recognised.

4. **Procedure of inspection.**—(1) An exporter intending to export rubber gloves for electrical purposes shall give intimation in writing of his intention so to do and submit along with such intimation a declaration of the specifications stipulated in the export contract relating to such export to any of the Inspection Agencies (hereinafter referred to as the Agency) recognised under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), to enable it to carry out the inspection in accordance with rule 3.

(2) In case the specifications stipulated in the export contract are in the form of a sample approved by the buyer, the exporter shall accordingly submit a declaration with proof along with the approved sample and its characteristics to the Agency.

(3) Every intimation and declaration under sub-rule (1) and the declaration under sub-rule (2) shall be given not less than ten days before the scheduled date of shipment.

(4) On receipt of the intimation and declaration under sub-rule (3), the Agency shall carry out the inspection of rubber gloves for electrical purposes in accordance with rule 3 and instructions, if any, issued by the Export inspection Council in this regard.

(5) After completion of the inspection, the Agency shall immediately seal the packages in the consignment in a manner as to ensure that the sealed goods cannot be tampered with.

(6) If after inspection, the agency is satisfied that the consignments of rubber gloves for electrical purposes complies with the requirements of rule 3, it shall, within 10 days of the receipt of intimation and declaration under sub-rule (3), issue a certificate of export-worthiness to the exporter, otherwise the exporter shall be informed in writing regarding reasons for rejection, within 3 days of completion of inspection.

5. **Place of inspection.**—Every inspection under these rules shall be carried out either—

(a) at the permises of the manufacturer of such products, or,

(b) at the premises at which the goods are offered by the exporter, provided adequate facilities for the purpose exist therein.

6. **Inspection fee.**—Subject to a minimum of Rs. 50/- for each consignment, a fee at the rate of 30 paise for every 100 rupees of F.O.B. value of each consignment shall be paid as inspection fee under these rules.

7. **Appeal.**—(1) Any person aggrieved by the refusal of the Agency to issue a certificate under sub-rule (6) of rule 4, may, within 10 days of the receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of experts consisting of not less than three persons appointed for the purpose by the Central Government.

(2) The quorum of the panel shall be three.

(3) The decision of the said panel on such appeal shall be final.

[No. 6(17)/71-EI&EP]

का. आ. 159—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, वैद्युत प्रयोजनों के लिए रबड़ दस्तानों के निर्यात-पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के लिए निम्नलिखित निरीक्षण अभिकरणों को एतद्द्वारा मान्यता देती है, अर्थात् :—

(1) निर्यात निरीक्षण अभिकरण-मुंबई, "अमन चैम्बर्स" 113, महर्षि कर्वे, मुम्बई-4

(2) निर्यात निरीक्षण अभिकरण-कलकत्ता, "वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर," 14/1 बी, एजरा स्ट्रीट, कलकत्ता-1

(3) निर्यात निरीक्षण अभिकरण-मद्रास, "वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर," 123, माउंट रोड, मद्रास-6

(4) निर्यात निरीक्षण अभिकरण-दिल्ली, 13/37, प. वि. क्षेत्र, आर्यसमाज रोड, नई दिल्ली-5

(5) निर्यात निरीक्षण अभिकरण-कोचिन, मनोहर बिल्डिंग, महात्मा गांधी रोड, कोचिन-11

स्पष्टीकरण:—इस अधिसूचना में वैद्युत प्रयोजनों के लिए रबड़ दस्तानों से उर्जित कंडक्टरों और उपस्करों पर काम करते समय वैद्युत धक्कों से कर्मकारों के संरक्षण के लिए उपयोग में लाये गए पूर्णतः रबड़ से बने हुए सभी प्रकार के दस्तानों अभिप्रेत हैं।

[सं. 6(17)/71-नि. नि. तथा नि. सं.]

S.O. 159.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises the following Inspection Agencies for quality control and inspection of rubber gloves for electrical purposes prior to their export, namely:—

(1) Export Inspection Agency-Bombay, 'Aman Chambers' 113, M. Karve Road, Bombay-4.

(2) Export Inspection Agency-Calcutta, 'World Trade Centre', 14/1B, Ezra Street, Calcutta-1.

(3) Export Inspection Agency-Madras, 'World Trade Centre', 123, Mount Road, Madras-6.

(4) Export Inspection Agency-Delhi, 6B/9, Northern Extension Area, Rajinder Nagar, New Delhi-60.

(5) Export Inspection Agency-Cochin, Manohar Building, Mahatma Gandhi Road, Cochin-11.

Explanation.—In this notification "rubber gloves for electrial purposes" means all types of gloves made wholly of rubber, used for protection to workers from electrical shocks while working on energized conductors and equipments.

[No. 6(17)/71-EI&EP]

का. आ. 160.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, जूट उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1970 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम जूट उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जूट उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1970 में,

(1) नियम 9 के उपनियम (5) में, अन्त में आने वाला 'तद्नुसार' शब्द के पश्चात निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—"उपनियम (1) के अधीन प्रज्ञापन और घोषणा की प्राप्ति की तारीख से तीन दिन के भीतर प्रज्ञापित करेगा",।

(2) नियम 11 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्: "परन्तु जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं हो जाता वहां वह तीन दिनों की उक्त अवधि के अन्दर ऐसा प्रमाणपत्र देने से इंकार कर देगा और ऐसी इंकारी के कारण बताते हुए उसकी संसूचना निर्यातकर्ता को देगा।"

[सं. 6(18)/72 नि. नि. तथा नि. सं.]

S.O. 160.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Jute Products (Quality Control and Inspection) Rules, 1970 namely:—

1. (1) These rules may be called the Export of Jute Products (Quality Control & Inspection) Amendment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Export of Jute Products (Quality Control and Inspection) Rules, 1970,

(i) in sub-rule (5) of rule 9, after the word 'accordingly' occurring at the end, the following shall be inserted, namely:—

"within three days of the date of receipt of the intimation and declaration under sub-rule (1)";

(ii) In rule 11, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that where the agency is not so satisfied it shall within the said period of 3 days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter alongwith the reasons thereof".

[No. 6(18)/72-EI&EP]

का. आ. 161.—यतः निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है कि इस्पात-तार के रस्सों का निर्यात के पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाए।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे दिए गए विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) द्वारा यथाउपेक्षित निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है,

अतः अब, उक्त उपनियम के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त प्रस्तावों को उनसे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले जन साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है।

2. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव भेजने की वांछा करने वाला कोई व्यक्ति उन्हें इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद् "वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर" 14/1 बी, एजरा स्ट्रीट (सातवीं मंजिल) कलकत्ता-1 को भेज सकेगा।

प्रस्ताव

(1) अधिसूचित करना कि इस्पात-तार के रस्से निर्यात के पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगे,

(2) इस आदेश के उपाबंध में दिए गए इस्पात-तार रस्से निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1973 के प्रारूप के अनुसार निरीक्षण के उस प्रकार को विनिर्दिष्ट करना जो ऐसे इस्पात-तार के रस्सों को लागू किया जाएगा,

(3) भारतीय या अन्य राष्ट्रीय मानकों को इस्पात-तार के रस्सों के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देना,

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में, ऐसे किसी भी इस्पात-तार के रस्सों का निर्यात तब प्रतिषिद्ध करना, जब तक कि उसके साथ केन्द्रीय सरकार द्वारा, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन मान्यता प्राप्त अभिकरणों में से किसी एक द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाणपत्र न हो कि इस्पात तार के रस्से निर्यात-योग्य हैं ।

3. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेता के लिए ऐसे इस्पात-तार के रस्सों के उन नमूनों के निर्यात को लागू नहीं होगी, जिसका पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 1251 रुपये से अधिक न हो ।

4. इस आदेश में "इस्पात-तार रस्सों" से कर्षण, लपेटने, उत्तोलन, तेल-कूप बंधन या किसी अन्य सम्बंध प्रयोग के लिए प्रयुक्त, तंतु के क्रोड सहित या रहित, बटे हुए इस्पात तारों द्वारा विनिर्मित रस्से अभिप्रेत होंगे ।

उपाबंध

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम, 1963 की धारा 17 के अधीन बनाए जाने वाले प्रस्तावित नियमों का प्रारूप :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—इन नियमों का नाम इस्पात-तार के रस्से निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1973 है ।

2. **परिभाषा.**—इन नियमों में इस्पात-तार रस्सों से कर्षण, लपेटन, उत्तोलन, तेल-कूप बंधन या किसी अन्य सहबद्ध प्रयोग के लिए तंतु के क्रोड सहित या रहित, बटे हुए इस्पात-तारों द्वारा विनिर्मित रस्से अभिप्रेत होंगे ।

3. **निरीक्षण का आधार.**—इस्पात-तार के रस्सों का निरीक्षण यह देखने के लिए किया जाएगा कि वे निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विनिर्देशों (जिनको इसके पश्चात मानक विनिर्देश कहा गया है) के अनुरूप हैं ।

4. **निरीक्षण की प्रक्रिया.**—(1) इस्पात तार के रस्सों के निर्यात का आशय रखने वाला निर्यात कर्ता ऐसा करने के अपने आशय की लिखित में सूचना के साथ ऐसे निर्यात से संबंधित संविदा में करार पाए गए विनिर्देशों के बारे में घोषणा, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन मान्यताप्राप्त निरीक्षण अधिकरणों में से किसी एक को, जिसे इसमें इसके पश्चात अभिकरण के रूप में कहा गया है, देगा, ताकि वह नियम 3 के अनुसार निरीक्षण कर सके तथा साथ ही साथ निरीक्षण के लिए सूचना की एक प्रति या तो 'वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर', 14/1 बी एज्रा स्ट्रीट, कलकत्ता-1, या अमन चैम्बर्स, 113 महर्षि कर्वे रोड, मुम्बई-4 या मनोहर बिल्डिंग, महात्मा गांधी, एर्नाकुलम कोचीन-11, या 6 बी 19 उ. वि. क्षे. राजिंदर नगर, नई दिल्ली-60 पर स्थित किसी निर्यात निरीक्षण परिषद् के निकटतम कार्यालय को भेज देगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना तथा घोषणा नीभरण की अनुमानित तारीख से कम से कम 10 दिन पहले दी जाएगी । जहां कहीं भी निर्यातकर्ता तथा अभिकरण द्वारा करार पाया गया हो, इस्पात तार रस्से, पैक किए बिना, निरीक्षण के लिए तैयार रखे जाएंगे

(3) उपनियम (2) के अधीन सूचना तथा घोषणा प्राप्त होने पर अभिकरण, नियम 3 तथा निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा समय समय पर जारी किए गए निदेशों के अनुसार, निरीक्षण करेगा ।

(4) यदि निरीक्षण पर, अभिकरण की यह राय हो कि इस्पात तार के रस्से नियम 3 तथा इसके लिए निर्यात निरीक्षण परिषद्-द्वारा दिये गए आदेशों की उपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं, तो वह उपनियम (1) के अधीन सूचना तथा घोषणा की प्राप्ति की तारीख के तीन दिन के भीतर लिखित रूप में इसके अनुसार निर्यातकर्ता को सूचना देगा ।

(5) **निरीक्षण का प्रमाणपत्र.**—जब अभिकरण का समाधान हो गया है कि इस्पात-तार के रस्सों का परेषण नियम 3 की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है तो वह अपनी सील से परेषण को सील करेगा तथा निरीक्षण के पूरा हो जाने के तीन दिन के भीतर परेषण को निर्यात-योग्य घोषित करते हुए, निर्यातकर्ता के प्रमाणपत्र देगा :

परन्तु जहां अभिकरण का इस प्रकार का समाधान नहीं हुआ है, वहां तीन दिन की उक्त अवधि के भीतर ऐसा प्रमाणपत्र देने से इंकार कर देगा तथा उसके लिए कारण बताते हुए निर्यातकर्ता को इस अस्वीकृति की सूचना देगा ।

5. **निरीक्षण का स्थान.**—इन नियमों के प्रयोजनों के लिए इस्पात-तार के रस्सों का निरीक्षण केवल विनिर्माता के परिसर पर किया जाएगा ।

6. **निरीक्षण फीस.**—इन नियमों के नियम 4 के अधीन इस्पात-तार के रस्सों के निरीक्षण के लिए ऐसे प्रत्येक परिषण के पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्यक के प्रति 100 रु. के लिए 0.50 पैसे की दर से फीस, जो कम से कम 100(सौ रूपए) होगी, निरीक्षण फीस के रूप में दी जाएगी ।

7. **अपील.**—(1) नियम 4 के उपनियम (5) के अधीन अभिकरण द्वारा प्रमाणपत्र देने से इंकार कर देने से व्यथित कोई व्यक्ति उसको ऐसे इंकार की सूचना मिलने के 10 दिन के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा, इस प्रयोजन के लिए यथा गठित कम से कम तीन व्यक्तियों के विशेषों के पैनल को अपील कर सकेगा ।

(2) ऐसी अपील पर पैनल का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

[सं. 6120171-नि. नि. तथा नि. सं]

S.O. 161.—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) that steel wire ropes should be subject to quality control and inspection prior to export;

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objection or suggestion with respect to the said proposals may forward the same within thirty days of the date of publication of this order to the Export Inspection Council 'World Trade Centre' 14/1-B, Ezra Street, 7th floor, Calcutta-1.

Proposals

(1) To notify that steel wire ropes shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) To specify the type of inspection in accordance with the draft Export of Steel Wire Ropes (Inspection) Rules, 1973 set out in Annexure to this order as the type of inspection which shall be applied to such steel wire ropes;

(3) To recognise the Indian or other national standards as standard specifications for steel wire ropes;

(4) To prohibit the export, in the course of international trade, of any such steel wire ropes, unless the same are either accompanied by a certificate issued by any one of the Agencies recognised by the Central Government under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) to the effect that the steel wire ropes are export-worthy.

3. Nothing in this order shall apply to the export of samples of steel wire ropes to prospective buyers, the f.o.b. value of which does not exceed one hundred and twenty-five.

4. In this order "steel wire ropes" shall mean, ropes manufactured by standing steel wires, with or without fibre core, used for haulage, winding, hoisting, oil well drillings or for any other allied use.

ANNEXURE

Draft rules proposed to be made under section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963.

1. **Short title and commencement.**—These rules may be called the Export of Steel Wire Ropes (Inspection) Rules, 1973.

2. **Definition.**—In these rules 'steel wire ropes' shall mean, ropes manufactured by stranding steel wires, with or without fibre core, used for haulage, winding, hoisting oil well drillings or for any other allied use.

3. **Basis of Inspection.**—Inspection of Steel Wire Ropes shall be carried out with a view to seeing that the same conform to the specifications recognised by the Government under section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (hereinafter referred to as the standard specification).

4. **Procedure of Inspection.**—(1) An exporter intending to export steel wire ropes shall give intimation in writing of his intention so to do and submit along with such intimation the declaration as to the agreed specification of the export contract, to any one of the Inspection Agencies recognised under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) hereinafter referred to as the Agency, to enable it to carry out the inspection in accordance with rule 3 and shall simultaneously forward a copy of the intimation for inspection to the nearest office of the Export Inspection Council either at 'World Trade Centre', 14/1-B, Ezra Street, Calcutta-1 or at 'Aman Chambers', 113, Maharshi Karve Road, Bombay-4 or at Manohar Buildings, Mahatma Gandhi Road, Ernakulam, Cochin-11 or at 6B/9, Northern Extension Area, Rajinder Nagar, New Delhi-60.

(2) Every intimation and declaration under sub-rule (1) shall be given not less than ten days before the expected date of shipment. The consignment of steel rope wires shall be kept ready for inspection without being packed wherever agreed to by the exporter and the Agency.

(3) On receipt of the intimation and declaration under sub-rule (2), the Agency shall carry out the inspection of steel rope wires in accordance with rule 3 and the instruction in this behalf issued by the Export Inspection Council from time to time.

(4) If on inspection, the Agency is of opinion that the steel wire ropes do not comply with the requirements of rule 3 and the instructions issued in this behalf by the Export Inspection Council, it shall intimate the exporter accordingly in writing within three days of the date of receipt of the intimation and declaration under sub-rule (1).

(5) **Certificate of Inspection.**—When the Agency is satisfied that the consignment of steel wire rope complies with the requirements of rule 3, it shall seal the consignment with its seal and issue within three days of completion of inspection, a certificate to the exporter declaring that the consignment is export-worthy.

2. Provided that where the agency is not so satisfied it shall within the said period of three days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter alongwith the reasons therefor.

5. **Place of Inspection.**—Inspection of steel wire ropes for the purposes of these rules, shall be carried out only at the premises of the manufacturer.

6. **Inspection Fee.**—A fee at the rate of 50 paise for every one hundred rupees of the f.o.b. value of each such consignment, subject to a minimum of Rs. 100/- shall be paid as inspection fee for inspection of steel wire ropes under rule 4 of these rules.

7. **Appeal.**—(1) Any person aggrieved by the refusal of the Agency to issue a certificate under sub-rule (5) of rule 4, may, within ten days of the receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of experts consisting of not less than three persons, as may be constituted for the purpose by the Central Government.

(2) The decision of the panel on such appeal shall be final.

[No. 6/20/71-EI & EP]

का. आ. 162.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 358, तारीख 28 जनवरी, 1966 के साथ प्रकाशित कतीरा (गम कराया) निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम कतीरा (गम कराया) निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 है।

2. कतीरा (गम कराया) निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 में, अंकों (1) नियम 1 के उपनियम (1) और (2) में "1965" के स्थान पर "1966" अंक रखे जाएंगे,

(2) नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6. निरीक्षण फीस इन नियमों के अधीन निरीक्षण के लिए प्रभार्य फीस, कतीरा (गम कराया) के प्रत्येक 50 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 0·75 पैसे होगी, जो प्रत्येक परेषण के लिए निम्नतम 20 रु. के अधीन होगी।

[सं. 6(21)/72-नि. नि. तथा नि. सं.]

S.O. 162.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Gum Karaya (Inspection) Rules, 1965, published with the notification of the Government of India in the Late Ministry of Commerce No. S.O. 358 dated the 28th January, 1966, namely :—

1. These rules may be called the Export of Gum Karaya (Inspection) Amendment Rules 1973.

2. In the Export of Gum Karaya (Inspection) Rules, 1965,

(i) in sub-rule (1) and (2) of rule 1, for the figures "1965", the figures "1966" shall be substituted·

(ii) for rules 6, the following rule shall be substituted, namely :

"6. **Inspection fee**—The fees chargeable for inspection under these rules shall be 0.75 paise for every 50 kg. or part thereof of the Gum Karaya, subject to a minimum of Rs. 20 for each consignment.

[No. 6 (21)/72-EI&EP]

का. आ. 163.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस्पात नलियां और नलिकाकार निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1970 में और संशोधन करने के लिए, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम 'इस्पात नलिया' और नलिकाकार निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. इस्पात नलियों और नलिकाकार निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1970 के नियम 4 के उपनियम (4) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं हो पाता है, वहां वह 24 काम के घंटों की उक्त अवधि के अन्दर ऐसा प्रमाणपत्र देने से इंकार कर देगा और ऐसी इंकारी के कारण बताते हुए उसकी संसूचना निर्यातकर्ता को देगा ।"

[सं. 6(24)/72-नि. नि. तथा नि. सं.]

एम. के. बी. भटनागर, उप-निदेशक (निर्यात संवर्द्धन)

S.O. 163.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Export of Steel Tubes and Tubulars (Inspecaion) Rules, 1970, namely:

1. (1) These rules may be called the Export of 'Steel Tubes and Tubulars (Inspection) Amendment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In rule 4 of the Export of Steel Tubes and Tubulars (Inspection) Rules, 1970 to sub-rule (4) the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that where the agency is not so satisfied it shall within the said period of 24 working hours refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter alongwith the reasons therefor."

[No. 6(24)/72-EI&EP]

M. K. B. BHATNAGAR, Dy Director.

(संयुक्त-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

बम्बई, 20 जुलाई, 1972

आदेश

का. आ. 164.—सर्वश्री आर. के. इंडस्ट्रीज, चेतीपुरा पुलिस स्टेशन के पीछे, औरंगाबाद को (1) मोटाई में 5 मि. मी. से कम पी. क्यू. एम. एस. बी. पी./सी. आर. सी. ए. शीट्स (2) मोटाई में 5 मि. मी. और इससे अधिक स्किल्ड या सेमि-स्किल्ड मात्राओं वाली पी. क्यू. एम. एस. प्लेट्स के आयात के लिए लाइसेंस संख्याएं पी/ए/8025577/सी/एक्स, (2) पी/ए/8025578/सी/एक्स, (3) पी/ए/8025579/सी/एक्स सब का दिनांक 9-3-1971 मूल्य क्रमशः (1) 10,000 रु. (2) 10,667 रु. और (3) 11,333 रु. निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी किए गए थे :—

"यह लाइसेंस इस शर्त के अधीन जारी किया जाता है कि इसके अधीन आयात किए गए माल की सब मदों का उपयोग केवल लाइसेंसधारी के उस कारखाने में किया जाएगा जिसका पता उस आवेदनपत्र में दिया गया है जिसके आधार पर यह लाइसेंस जारी किया गया है, और माल का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए लाइसेंस जारी किया गया है अथवा निर्माण करने वाले दूसरे एकक के कारखाने में माल संसाधित किया जा सकता है परन्तु उसका कोई भाग दूसरी पार्टी को न तो बेचा जाएगा न दूसरी पार्टी द्वारा उपयोग किया जाएगा और न किसी दूसरे तरीके से उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी । लेकिन दूसरे के कारखाने में इस प्रकार संसाधित किए गए माल का उपयोग लाइसेंसधारी द्वारा नियंत्रित निर्माण क्रिया में किया जाएगा । लाइसेंसधारी लाइसेंस के आधार पर आयात किये गए माल के उपभोग और उपयोग का उचित लेखा निर्धारित रीति से रखेगा और उस लेखे को प्रायोजक प्राधिकारी या किसी दूसरे संम्बद्ध प्राधिकारी को ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करेगा जो उस प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाए ।"

2. उसके बाद उनको एक कारण बताओ नोटिस सं. 1/86/71/आई एंड एस/एन्फ दिनांक 31-7-71/9-8-71 यह पूछते हुए जारी किया गया था कि 15 दिनों के भीतर वे इसका कारण बताएं कि उनको प्रदान किए गए उक्त लाइसेंस इस आधार पर क्यों न रद्द कर दिए जाएं कि धारा 9, उप धारा (सी सी) की शर्तों के अनुसार उन्होंने कारखाना लगाने के स्थान की भूमि प्राप्त करने और यूनिट स्थापित करने के लिए अपेक्षित मशीनरी प्राप्त करने के लिए कोई निश्चित व्यवस्था नहीं की ।

3. पूर्वोक्त कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर में सर्वश्री आर. के. इंडस्ट्रीज औरंगाबाद ने अपने पत्र दिनांक 21-8-1971 द्वारा यह उल्लेख करते हुए विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है कि उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र औरंगाबाद में एक प्लाट प्राप्त कर लिया है और दस्ती औजारों सहित 4000 रु. के मूल्य की मशीनरी भी उनके पास है ।

4. अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अभ्यावेदन की ध्यानपूर्वक जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि सर्वश्री आर. के. इंडस्ट्रीज, औरंगाबाद ने अपने उद्योग को चालू करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए और उनके पास 4000 रु. की मशीनरी भी नहीं है और इसलिए विषयाधीन लाइसेंस जिन उद्देश्यों के लिए प्रदान किए गए हैं उनको पूरे नहीं करेंगे ।

5. पिछली कंडिका में जो कुछ कहा गया है उसको ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द कर देने चाहिएं या अप्रभावी समर्पित कर देने चाहिएं । इसलिए, अधोहस्ताक्षरी आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9 उप धारा (सी सी) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री आर. के. इंडस्ट्रीज, चेतीपुरा पुलिस स्टेशन के पीछे, औरंगाबाद को जारी किए गए लाइसेंस संख्याएं पी/ए/8025577, पी/ए/8025578 और पी/ए/8025579 सबका दिनांक 9-3-1971 मूल्य क्रमशः (1) 10,000 रु. (2) 10,667 रु. और (3) 11,333 रु. को एतद् द्वारा रद्द करता है ।

[सं. 1/86/711आई एंड एस/एन्फ./1378]

बी. सी. बनर्जी, उप मुख्य नियंत्रक.

(Office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports)

Bombay, the 20th July, 1972

ORDER

S.O. 164.—Licences Nos. PA/8025577/C/X, (2) PA/802578/C/X, (3) PA/8025579/CX all dated 9-3-1971 of the value of Rs. 10,000/- (2) Rs. 10,667/- and Rs. 11,333/- respectively for import of (1) P.Q.M.S.B.P./C.R.C.A. Sheets below 5 m.m. in thickness (2) P.Q.M.S. Plate skilled or semi skilled quantities in thickness 5 mm and above were issued to M/s. R. K. Industries, Behind Chetipura Police Station, Aurangabad subject to the conditions as under:—

"this licence is issued subject to the condition that all items of goods imported under it shall be used only in the licence holder's factory, at the address shown in the application against which the licence is issued; and for the purpose for which the licence is issued or may be processed in the factory of another manufacturing unit, but no portion thereof shall be sold to any other party or utilised or permitted to be utilised in any other manner. The goods so processed in another factory shall however, be utilised in the manufacturing process undertaken by the licencee. The licencee shall maintain a proper account of consumption and utilisation of the goods imported against the licence in the prescribed manner and produce such account to the sponsoring authority or any other concerned authority within such time as may be specified by such authority".

2. Thereafter, a show cause notice No. 1/86/71/I&S/Enf/ dated 31-7-1971/9-8-1971 was issued asking them to show cause within 15 days as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that they have not made any firm arrangement for securing land factory premises and required machinery for setting up the unit in terms of Clause 9, sub-clause (cc).

3. In response to the aforesaid show cause notice, M/s. R. K. Industries, Aurangabad had, by their letter dated 21-8-1971 furnished a detailed explanation stating that they have secured one Plot in the Industrial Area Aurangabad and also possess machineries worth Rs. 4,000/-, including hand tools.

4. The undersigned has carefully examined the said representation and has come to the conclusion that M/s. R. K. Industries, Aurangabad have not taken effective steps to start their Industry and they are also not having existing machinery worth Rs. 4,000/- and hence the licences in question will not serve the purposes for which they have been granted.

5. Having regard to what has been stated in the preceeding paragraph, the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undersigned, in exercise of the powers vested in his under Clause 9 sub-clause (cc) of the Imports (Control) Order 1955 hereby cancel the licences Nos. P/A 8025577, P/A-8025578 and P/A 8025579 all dated 9-3-1971 for Rs. 10.000/- (2) Rs. 10.667/- and Rs. 11.333/-issued in favour of M/s. R. K. Industries, Behind Chetipura Police Station, Aurangabad.

[No. 1/86/71/I&S/Enf/1378]

B. C. BANERJEE, Dy. Chief Controller.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(पेटेन्ट नियम)

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1972

का. आ. 165[301(ङ)].—यतः पेटेन्ट नियमों का प्रारूप, पेटेन्ट अधिनियम 1970 (1970 का 39) की धारा 159 की उपधारा (3) द्वारा यथापेक्षित भारत सरकार के उद्योग विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. 5246, तारीख 25 नवम्बर 1971 के साथ भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (2), तारीख 25 नवम्बर 1971 के पृष्ठ 3167 से 3226, 1 तक प्रकाशित किया गया था,

और यतः एतद्द्वारा सम्भावयतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव 25 जनवरी 1972 तक आमंत्रित किये गये थे;

और यतः पेटेन्ट नियमों का प्रारूप उक्त राजपत्र द्वारा जनता को 25 नवम्बर 1971 को उपलब्ध कर दिया गया था ,

और यतः आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के प्रयोजनार्थ उपयुक्त विनिर्दिष्ट तारीख 14 फरवरी, 1972 तक, भारत सरकार के, उद्योग विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 89 इ., तारीख 2 फरवरी, 1972, जो भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (2) तारीख 2 फरवरी, 1972 के पृष्ठ 229 पर प्रकाशित हुई थी, बढा दी गई है ।

और यतः तारीख 2 फरवरी 1972 के उक्त राजपत्र द्वारा अधिसूचना जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ,

और यतः उक्त नियम के बारे में जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया था :

अतः अब, पेटेन्ट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

पेटेन्ट नियम, 1972

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेटेन्ट नियम, 1972 ।

(2) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाए, ये नियम 1972 की अप्रैल के बीसवें दिन को प्रवृत्त होंगे :

परन्तु नियम 21, नियम 49 से लेकर 53 तक, नियम 73 तथा नियम 93 से लेकर 105 तक जिनका अधिनियम की क्रमशः धारा 12 की उपधारा (2), धारा 13 की उपधारा (2), धारा 28, धारा 68 तथा धारा 125 से लेकर 132 तक से सम्बन्ध है, उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसको उपधारा ए प्रवृत्त की जाएगी ।

2. **परिभाषाएं** : जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इन नियमों में,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है पेटेन्ट अधिनियम 1970 (1970 का 39),

(ख) "समुचित कार्यालय" से अभिप्रेत है नियम 4 में तथा विनिर्दिष्ट कार्यालय का समुचित कार्यालय ,

(ग) "वस्तु" के अन्तर्गत कोई भी पदार्थ या सामग्री और कोई भी संयंत्र, मशीनरी या साधित्र भले ही वह भूमी में लगे हों या न लगे हों,

(घ) "प्ररूप" से अभिप्रेत है द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ,

(ङ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों की अनुसूची ,

(च) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;

(छ) जो शब्द और पद इन नियमों में प्रयुक्त हैं लेकिन इनमें परिभाषित नहीं हैं उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जो इस अधिनियम में दिए गए हैं ।

3. **विहित विशिष्टियां** : इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाए, प्ररूप में अन्तर्विष्ट विशिष्टियों को, अधिनियम के सुसंगत कोई है, एतद्द्वारा विहित किया जाता है।

4. **समुचित कार्यालय** : (1) पेटेन्ट कार्यालय का समुचित कार्यालय—

(1) धारा 43, 44, 51, 52, 60, 65, 68, 125, 153 तथा 154 के अधीन कार्यवाहियों से भिन्न अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों के लिए, यथास्थिति पेटेन्ट कार्यालय का मुख्यालय या शाखा कार्यालय होगा जिसकी क्षेत्रीय सीमाओं में—

(क) पेटेन्ट के लिए आवेदक निवास करता है या उसके कारबार या अधिवास का मुख्य स्थान है, या

(ख) यदि आवेदन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम में संयुक्त रूप से दिया गया हो तो सर्वप्रथम उल्लिखित नाम वाला पेटेन्ट के लिए आवेदक जहां निवास करता है या उसके कारबार या अधिवास का मुख्य स्थान है, या

(ग) यदि भारत में आवेदक का अथवा कार्यवाही के पक्षकार का कारबार या अधिवास का कोई स्थान न हो तो पेटेन्ट के लिए उस आवेदक के अभिकर्ता का या उक्त पक्षकार का कारबार का जहां मुख्य स्थान है; तथा

(2) धारा 43, 44, 51 52, 60, 65, 68, 125, 153 तथा 154 के अधीन कार्यवाहियों के लिए पेटेन्ट कार्यालय का मुख्यालय होगा।

(2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जब तक शाखा कार्यालय धारा 74 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार स्थापित न किए जाएं तब तक के लिए अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों के लिए समुचित कार्यालय कलकत्ता के पेटेन्ट कार्यालय का मुख्यालय होगा।

5. **तामील के लिए पता**—प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो अधिनियम या इन नियमों से सम्बन्धित कार्यवाहियों से सम्बन्धित है और प्रत्येक पेटेन्टधारी भारत में तामील के लिए एक पता नियंत्रक को देगा और ऐसी कार्यवाहियां या पेटेन्ट से सम्बन्धित सभी प्रयोजनों के लिए वही पता उन कार्यवाहियों से सम्बन्धित व्यक्ति या पेटेन्टधारी का पता माना जा सकेगा। ऐसा पता न दिए जाने तक नियंत्रक पर यह बाध्यता नहीं होगी कि वह किसी भी कार्यवाही या पेटेन्ट पर कार्यवाही करे या उससे व्यौहार करे अथवा अधिनियम या इन नियमों के आधीन दी जाने के लिए अपेक्षित कोई सूचना भेजे।

6. **दस्तावेज छोड़ना तथा उनकी तामील** : (1) अधिनियम या इन नियमों के अधीन पेटेन्ट कार्यालय में या नियंत्रक अथवा किसी अन्य व्यक्ति के पास दाखिल किए जाने, छोड़े जाने या इसे दिये जाने के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित कोई आवेदन, सूचना या अन्य दस्तावेज वाहक द्वारा या डाक द्वारा समुचित कार्यालय के पते पर नियंत्रक को या उस व्यक्ति को भेजी जा सकेगी और डाक द्वारा भेजे जाने पर उन्हें उस समय दाखिल किया गया, छोड़ा गया या दिया गया समझा जाएगा जिस समय वह पत्र जिसमें वह आवेदन, सूचना या दस्तावेज है, डाक के मामूली अनुक्रम में परिदत्त कर दिया गया होता। ऐसे भेजने को साबित करने के लिए इतना साबित करना काफी होगा कि उचित पता लिखकर पत्र डाक में डाल दिया गया था।

(2) पेटेन्टधारी को, पेटेन्ट रजिस्टर में लिखे हुए उसके पते पर अथवा नियम 5 के अधीन दिए गए तामील के लिए उसके पते पर अथवा अधिनियम या इन नियमों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में किसी आवेदक या विरोधी को उस आवेदन या विरोध की सूचना में दिए गए अथवा तामील के लिए दिये गए पते पर भेजी गई किसी लिखित संसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि उस पर उचित रूप से पता लिखा गया है।

7. **फीसः**—(1) पेटेन्ट दिए जाने के लिए और तदर्थ आवेदन के लिए तथा अन्य विषयों के लिए जिनके लिए अधिनियम के अधीन फीसें दी जानी अपेक्षित हैं, दी जानेवाली फीसें प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।

(2) (क) अधिनियम के अधीन दी जानेवाली फीसें नकद दी जा सकेंगी या समुचित कार्यालय पर नियंत्रक को देय मनीआर्डर या पोस्टल आर्डर द्वारा या नियंत्रक को देय ऐसे अनुसूचित बैंक को, जो उस स्थान में स्थित हो जहां कि समुचित कार्यालय स्थित है, लिखे गए बैंक ड्राफ्ट या चैंक द्वारा फीसों को मनीआर्डर से भेजे जाने पर या ड्राफ्ट या चैंक को डाक द्वारा भेजे जाने पर यह समझा जाएगा कि फीसें उस तारीख को दी गई हैं जिस तारीख को वह मनीआर्डर या ड्राफ्ट या चैंक नियंत्रक के पास डाक के मामूली अनुक्रम में पहुंच गया होता।

(ख) जिन चैंकों या ड्राफ्टों में कमीशन की सही रकम सम्मिलित न हो उसको तथा ऐसी चैंकों को जिनके आधार पर उनमें विनिर्दिष्ट पूरी रकम, फीसों के संदाय के लिए अनुज्ञात समय के भीतर, नकद वसूल नहीं की जा सकती है, नियंत्रक के विवेक पर ही स्वीकार किया जाएगा।

(ग) अधिनियम के अधीन संदेय किन्हीं फीसों को चुकाने में स्टाम्प नहीं लिये जाएंगे।

(घ) जब किसी दस्तावेज के दाखिल किए जाने के लिए फीस दी जानी हो तो जिस तारीख को पूरी फीस दी गई हो वह तारीख उस दस्तावेज के दाखिल करने की तारीख समझी जाएगी।

(ङ) जब किसी व्यक्ति द्वारा दी गई कोई फीस नियंत्रक द्वारा अधिनियम या इन नियमों के उपबन्धों के अधीन वापस की जानी हो तब वह रकम मनीआर्डर द्वारा भेजी जा सकेगी और भेजी जानेवाली रकम में से उसके लिए देय कमीशन काट दी जाएगी।

8. **प्ररूपः**—(1) द्वितीय अनुसूची में दिए गए प्ररूपों का ऐसे फेरफारों सहित, जिनकी प्रत्येक मामले की परिस्थितियां अपेक्षा करें, उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाएगा।

(2). जहां किसी प्रयोजन के लिए कोई भी प्ररूप इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो वहां आवेदक द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी प्ररूप को ऐसे उपान्तरों और फेरफारों सहित जिनकी नियंत्रक अनुज्ञा दे, अपना सकेगा।

9. **दस्तावेज का आकार आदिः**—(1) पेटेन्ट कार्यालय को भेजे गए या उसमें छोड़े गये या नियंत्रक को अन्यथा दिए गए, शपथ-पत्रों और रेखाचित्रों को छोड़कर, सभी दस्तावेज और उनकी प्रतियां (जब तक कि नियंत्रक अन्यथा निदेश या अनुज्ञा न दे) अंग्रेजी भाषा में बड़े और सुवाच्य अक्षरों में पक्की अमिट स्याही में और पंक्तियों के बीच में काफी जगह छोड़कर केवल एक तरफ ही मजबूत सफेद कागज पर होंगी जो लगभग 33 से. मी. × 20.50 से. मी. (13"×8") या 29.7 से. मी.× 21 से. मी. 4⅔"×8⅓") का होगा और जिसमें कम से कम 4 से. मी. (डेढ़ इंच) का हाशिया उसके बाईं तरफ छूटा हुआ होगा। किसी हस्ताक्षर के सुवाच्य न होने पर या अंग्रेजी से भिन्न लिपि में लिखे होने पर उसके साथ में बड़े अक्षरों में अंग्रेजी में उसके नाम का लिप्यान्तरण भी लिखा गया होगा।

(2) यदि नियंत्रक ऐसी अपेक्षा करे तो सभी दस्तावेजों की अतिरिक्त प्रतियां समुचित कार्यालय में दाखिल की जाएंगी ।

(3) आवेदकों और अन्य व्यक्तियों के नाम और पते पूरे पूरे दिए जाएंगे और उनके साथ उनकी राष्ट्रीयता और ऐसी अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हों, जो पहचान के लिए आवश्यक हों, भी दी जाएंगी ।

10. **दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और उनका सत्यापन** :—अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों पर नीचे तारीख दी जाएगी और हस्ताक्षर किये जाएंगे तथा उनमें यह कथन होगा कि उनमें कथित तथ्य और बातें उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करनेवाले व्यक्ति की सर्वोत्तम जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं ।

अध्याय 2

पेटेन्टों के लिए आवेदन

11. **वह अवधि जिसके भीतर आवेदन करने के अधिकार का सबूत दिया जाएगा**:—जहां पेटेन्ट के लिए कोई आवेदन आविष्कार के लिए पेटेन्ट के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन करने के अधिकार के किसी समनुदेशन के आधार पर किया जाए वहां यदि आवेदन के साथ इस बात का सबूत न दिया गया हो कि आवेदन करने का अधिकार है तो आवेदक ऐसा आवेदन दाखिल करने के पश्चात् तीन मास की अवधि के भीतर ऐसा सबूत देगा ।

12. **आवेदन अभिलिखित करने का क्रम** :—किसी एक वर्ष में किए गए आवेदनों को आवली के रूप में रखा जाएगा और ऐसे दाखिल करने के वर्ष से उनकी पहचान होगी ।

13. **विदेशी आवेदनों के बारे में विवरण और बचनबन्धकता**:—(1) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन पेटेन्ट के लिए आवेदक द्वारा दाखिल किए जाने के लिए अपेक्षित विवरण और बचनबन्ध प्ररूप 4 में दिया जाएगा ।

(2) वह समय, जिसके भीतर पेटेन्ट के लिए आवेदक धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अपने द्वारा दिए जानेवाले बचनबन्ध में भारत से बाहर किसी देश में दाखिल किए गए अन्य आवेदनों की बाबत ब्यौरों की जानकारी नियंत्रक को देगा, ऐसे दाखिल की तारीख से तीन मास होगा ।

14. **विनिर्देश** :— (1) प्रत्येक विनिर्देश भले ही वह अंतिम हो या सम्पूर्ण, अविष्कार के नाम, आवेदन में दिए गए आवेदक के नाम, राष्ट्रीयता और पते के साथ आरम्भ होगा और आवेदक या उसके अभिकर्ता द्वारा उसके अंत में हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसके नीचे तारीख दी जाएगी ।

(2) अतिरिक्त के पेटेन्ट की बाबत विनिर्देश में, यथास्थिति, मुख्य पेटेन्ट के या मुख्य पेटेन्ट के आवेदन के संख्यांक का निर्देश होगा और यह स्पष्टतः कथन होगा कि आविष्कार में दिए गए या आवेदन किए गए मुख्य पेटेन्ट के विनिर्देश में दावाकृत अविष्कार में कोई सुधार या उसका उपान्तर समाविष्ट है ।

(3) जहां आविष्कार रेखाचित्रों द्वारा वर्णित किया जा सकता है वहां ऐसे रेखाचित्र नियम 16 से 19 के उपबन्धों के अनुसार तैयार किए जाएंगे और उन्हें साथ दिया जाएगा तथा उस विनिर्देश में विस्तारपूर्वक निर्दिष्ट किया जाएगा ।

परन्तु सम्पूर्ण विनिर्देश की दशा में यदि आवेदक अपनी अनंतिम विनिर्देश के साथ दिए गए रेखाचित्रों को सम्पूर्ण विनिर्देश के रेखाचित्रों के रूप में या उनके भाग के रूप में अंगीकार करना चाहता हो तो सम्पूर्ण विनिर्देश में उनको इस प्रकार निर्दिष्ट कर देना पर्याप्त होगा कि वे वही हैं जो अनंतिम विनिर्देश के साथ दिए गए हैं ।

(4) नियंत्रक की राय में जो बात आविष्कार को स्पष्ट करने के लिए विसंगत या आवश्यक है उसे शीर्षक, वर्णन, दावों अथवा रेखाचित्रों से निकाल दिया जाएगा ।

(5) ऐसे आवेदन (अभिसमय आवेदन से भिन्न) की दशा में के सिवाय जिसके साथ सम्पूर्ण विनिर्देश है, आविष्कार के कार्य की घोषणा सम्पूर्ण विनिर्देश के साथ प्ररूप 6 में या सम्पूर्ण विनिर्देश दाखिल किए जाने की तारीख से 3 मास समाप्त होने से पूर्व किसी भी समय, जैसा कि नियंत्रक प्ररूप 7 में किए गए आवेदन पर अनुज्ञात करे, दाखिल की जाएगी ।

15. **विनिर्देश में संशोधन**:—(1) आवेदक या उसके अभिकर्ता को जब कोई अनंतिम या सम्पूर्ण विनिर्देश या उसके साथ का कोई रेखाचित्र संशोधन के लिए प्राप्त हो तब यथासंभव उनमें आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे । यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त बात उन पृष्ठों को, जो एक ही दस्तावेज के रूप में हों, पुनः लिखकर अन्तर्विष्ट की जा सकेगी । उक्त दस्तावेजों में से किसी दस्तावेज में संशोधन स्लिप चिपकाकर या पाद टिप्पण लिखकर या हाशिये में लिखकर नहीं किए जाएंगे ।

(2) संशोधित दस्तावेज रद्द पृष्ठों या ऐसे चित्रों, यदि कोई हों, के सहित जिन्हें सम्यक् रूप से चिन्ह लगाकर रद्द किया गया है और जिन पर आवेदक या उसके अभिकर्ता ने आद्याक्षर कर दिए हों नियंत्रक को वापिस किए जाएंगे तथा पुनः टाइप किए गए या जोड़े गए किन्हीं पृष्ठों की और ऐसे किसी रेखाचित्र को जोड़ा गया हो या सारतः संशोधन किया गया हो, तीन तीन प्रतियां भेजी जाएंगी । संशोधन, परिवर्तनों या परिवर्तनों पर हाशिये में आवेदक या उसका अभिकर्ता आद्याक्षर करेगा ।

16. **रेखाचित्र**:—(1) नियंत्रक द्वारा की गई अपेक्षा पर दिये जाने से अन्यथा आवेदक द्वारा दिए गए रेखाचित्रों के साथ वे विनिर्देश होंगे जिनसे उनका संबंध है ।

(2) कोई भी ऐसा रेखाचित्र या रेखाकृति जो विनिर्देश के प्रेस-अक्षरों के छापे जाने के समय उसके प्रयोग के लिए विशेष उदाहरण की निर्मिति की अपेक्षा करेगा विनिर्देश में दर्शित नहीं की जाएगी ।

(3) रेखाचित्र सपाट रूप में दिए जाएंगे या इस प्रकार लपेटे जाएंगे कि उनमें सलवट न पड़ें ।

(4 रेखाचित्र की कम से कम एक प्रति प्रत्युत्पादन के लिए यथोचित होगी और उस प्रयोजन के लिए उसे ट्रेसिंग क्लाथ या पारदर्शी या अपारदर्शी पत्र अथवा पलास्टिक्स या रेशेदार कांच की बनी परत पर तैयार किया जाएगा ।

(5) फोमवाले रेखाचित्रों का उपयोग नहीं किया जाएगा ।

17. **जिस कागज पर रेखाचित्र दिए जाएंगे उसका आकार आदि**:—(1) रेखाचित्र ऐसे पत्रों पर होंगे जो ऊपर से नीचे तक 33.00 से. मी. (करीब 13 इंच) और चौड़ाई में 20.50 से. मी. या 41.00 से. मी. (8 इंच या 16 इंच) होंगे, कम चौड़े पत्र अधिमान्य होंगे । पत्रों के किनारों से 1.50 से. मी. (लगभग आध इंच) का स्पष्ट हाशिया छोड़ा जाएगा ।

(2) यदि छोटे आकार के पत्रों (33 से. मी. 20.50 से. मी.) में से किसी भी पत्र में दिखाई जा सकने वाली आकृतियों से अधिक आकृतियां हों तो ऐसे छोटे आकार वाले दो या अधिक पत्रों का

किसी बड़े आकार के पत्र के उपयोग पर अधिमान देकर उपयोग किया जाएगा । जब असाधारण रूप से बड़ी बड़ी आकृति बनानी हो तो उसे एक के बाद एक पत्र पर जारी रखा जाएगा और आवश्यकता होने पर कितने ही पत्रों का उपयोग किया जा सकेगा । आकृति को निरंतर और इस बात का ख्याल रखे बगैर कि कितने पत्रों का उपयोग किया गया है, से संख्या दी जाएगी । आकृतियां सुभिन्न रह सकें इसके लिए उनके बीच में प्रयाप्त स्थान रखा जायेगा ।

18. **रेखाचित्रों की विशिष्टियां :**

निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुसार रेखाचित्र तैयार किए जाएंगे अर्थात् :—

(क) रेखाचित्र अमिट काली स्याही से निष्पादित किए जाएंगे ।

(ख) प्रत्येक रेखा स्थिर रूप से और सम रूप से खींची जाएगी, भाली भांति स्पष्ट की जाएगी और निरन्तर एक सी मोटाई की होगी ।

(ग) खण्ड रेखाएं, प्रभाव के लिए रेखाएं या शेड के लिए रेखाएं यथा संभव कम होंगी और पास-पास नहीं खींची जाएंगी ।

(घ) शेड-रेखाएं चौड़ाई में रेखाचित्रों की साधारण रेखाओं से अत्याधिक विपरीत नहीं होंगी ।

(ङ) खण्ड और शेड ठोस काले या जलरंग (रोगन) से नहीं दिखाया जाएगा ।

(च) रेखाचित्र पर्याप्त रूप से बड़े मापमान पर होंगे ताकि आविष्कार को स्पष्टतः दिखाया जा सके और साधित्र, मशीन या अन्य बात का उसमें उतना ही भाग दर्शित जो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपेक्षित हो । यदि मापमान दिया गया हो तो उसे शब्दों में न बताकर खींच कर बताया जाएगा । रेखाचित्रों पर कोई भी लम्बाई चौड़ाई नहीं बतायी जाएगी ।

(छ) आकृतियों को पत्र की ऊपर और नीचे की स्थिति में सीधा खींचा जाएगा ।

(ज) वे निर्देश अक्षर और अंक तथा सूचक अक्षर, संकेत और अंक, जिनका उसके साथ-साथ प्रयोग किया गया हो मोटे और स्पष्ट टाइप के होंगे तथा ऊंचाई में 0.30 से. मी. (1 इंच) से कम नहीं होंगे । विभिन्न स्थितियों में उन्हीं भागों को दर्शित करने के लिए उन्हीं अक्षरों या अंकों का प्रयोग किया जाएगा जहां निर्देश अक्षर या अंक आकृति से बाहर दर्शित किए गए हों, वहां उन्हें उन भागों से जिनके प्रति उनका निर्देश हो, रेखाओं से जोड़ा जाएगा ।

19. **रेखाचित्रों के बारे में और विशिष्टियां :**

(1) रेखाचित्रों में —

(i) बांई तरफ ऊपर कोने में आवेदक का नाम दिया जाएगा ।

(2) दांयी तरफ ऊपर कोने में रेखाचित्रों के पत्रों की संख्या और प्रत्येक क्रमवर्ती संख्या दी जाएगी , तथा

(3) दांयी तरफ नीचे कोने में आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे ।

(2) रेखाचित्रों में न तो आविष्कार का नाम वर्णित होगा और न कोई अन्य वर्णनात्मक पदार्थ ।

(3) संनिर्माण संबंधी रेखाचित्रों में कोई भी वर्णनात्मक पदार्थ वर्णित नहीं होगी, किन्तु फलों-पत्रों की प्रकृति के रेखाचित्रों में वर्णनात्मक पदार्थ यह दर्शित करने के लिए वर्णित की जाएगी कि कौन सी सामग्री का प्रयोग किया गया है और आविष्कार के करने के किन रसायनों का या अन्य प्रतिक्रियाओं या ट्रीटमेंटों का प्रयोग किया गया है ।

(4) जिन रेखाचित्रों में उपकरणों की संख्या या साधित्र के एकक और उनके यांत्रिक या विद्युत अन्तः संबंध दर्शित किए गए हों और जिनमें ऐसा प्रत्येक उपकरण या एकक केवल प्रसिकात्मक रूप से दर्शित किया गया हो उनमें ऐसा वर्णनात्मक पदार्थ दिया जा सकेगा जो उन उपकरणों या एककों की अथवा उनके अन्तः संबंधों की पहचान के लिए आवश्यक हों ।

(5) कोई भी रेखाचित्र या रेखाकृति, ग्राफिक रसायन-सूत्र, विनिर्देश के वर्णनात्मक भाग में वर्णित नहीं होगा और यदि ऐसे रेखाचित्र, रेखाकृति या सूत्र को उसमें प्रयोग किया गया हो तो यदि नियंत्रक ऐसे निर्देश दे तो उसकी एक प्रति, जो उसी रीति से तैयार की गई हो जिस प्रकार कि रेखाचित्रों को किया गया था, दी जाएगी ।

20. **प्रतिमान :** (1) प्रतिमान या नमूने नियंत्रक द्वारा अपेक्षित किए जाने पर ही दिए जाएंगे ।

(2) कोई भी प्रतिमान अधिकतम लम्बाई में 12 इंच से अधिक नियंत्रक की अनुज्ञा के बिना नहीं होगा ।

(3) नमूने सुविधाजनक आयामों में बंद किए जाएंगे ।

(4) खतरनाक पदार्थ नियंत्रक के निदेश के अनुसार ही दिए जाएंगे ।

(5) प्रत्येक प्रतिमान या नमूने पर स्पष्ट रूप से और सुनिश्चित रूप से लेबल या चिन्ह ऐसे लगाया जाएगा ताकि जिस आवेदन से उसका संबंध हो, उसकी पहचान हो सके ।

अध्याय-3

आवेदनों की परीक्षा

21. **पूर्व प्रकाशन द्वारा प्रत्याशा की दशा में प्रक्रिया :** (1) यदि धारा 13 के अधीन किए गए अन्वेषण के पश्चात् नियंत्रक का यह समाधान हो जाए कि आविश्कार जहां तक उस आविश्कार का किसी सम्पूर्ण विनिर्देश वाले दावे में दावा किया गया है, उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (क) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी विनिर्देश या अन्य दस्तावेज में प्रकाशित कर दिया गया है तो नियंत्रक उसे आक्षेपों का सार आवेदक को संसूचित करेगा और आवेदक को अपने विनिर्देश में संशोधन करने का अवसर दिया जाएगा ।

(2) यदि आवेदक अपने को उपनियम (1) के अधीन नियंत्रक द्वारा संसूचित किए गए आक्षेपों में से किन्हीं आक्षेपों के लिए विरोध करता है या यदि वह अपना विनिर्देश अपने संप्रेक्षणों सहित, चाहे विनिर्देश संशोधित किया गया हो या नहीं; फिर से दाखिल करता है, तो यदि वह ऐसी अपेक्षा करे तो उसे मामले में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

(3) यदि आवेदक आक्षेपों के सार की संसूचना की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर उपनियम (2) के अधीन सुनवाई

की अपेक्षा करता है या यदि नियंत्रक ऐसा करना वांछनीय समझे तो वह चाहे आवेदक अपना आवेदन फिर से दाखिल करे या नहीं, आवेदन को ठीक करने के लिए बकाया समय या मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुनवाई के लिए तारीख नियत कर सकता है ।

(4) जब उपनियम (3) के अधीन सुनवाई नियत की जाए तो आवेदक को, इस प्रकार नियत किए जाने की कम से कम 10 दिन की सूचना, या ऐसी अल्पतर सूचना, जैसी कि नियंत्रक को मामले की परिस्थितियों में युक्ति-युक्त प्रतीत लगे, दी जाएगी और आवेदक, यथासंभव शीघ्र, नियंत्रक को अधिसूचित करेगा कि क्या वह सुनवाई में हाजिर होगा या नहीं ।

(5) आवेदक की सुनवाई के पश्चात् या यदि आवेदक हाजिर नहीं हुआ हो या उसने अधिसूचित किया हो कि उसे सुनवाई की इच्छा नहीं है तो बिना सुनवाई के, नियंत्रक विनिर्देश का ऐसा संशोधन विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात कर सकेगा जैसा वह किया जाना ठीक समझे और जब तक कि विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात संशोधन ऐसी अवधि के भीतर न किया जाए जैसा कि वह निरत करे विनिर्देश को स्वीकार करने से इन्कार कर सकेगा ।

22. **पूर्व-दावे द्वारा प्रत्याशा की दशा में प्रक्रिया.**—(1) जब यह पता चले कि अविष्कार, जहां तक उसका दावा पूर्व विनिर्देश के किसी दावे में किया गया हो, का दावा धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत आने वाले किसी अन्य पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में किया गया है वहां आवेदक को सूचित किया जाएगा और उसे अपना विनिर्देश संशोधित करने का अवसर दिया जाएगा ।

(2) यदि आवेदक के विनिर्देश अन्यथा स्वीकार किए जाने के लिए ठीक हैं और धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन कोई आपत्ति बाकी रह गई है तो नियंत्रक विनिर्देश को स्वीकार कर सकेगा और उसके प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि में आपत्ति को दूर करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(3) यदि धारा 13 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन कोई आपत्ति विनिर्देश स्वीकार किए जाने के पश्चात् आवेदक को संसूचित की जाए तो संसूचना की तारीख से दो मास की अवधि उस आपत्ति को दूर करने के लिए अनुज्ञात की जाएगी ।

23. **प्रत्याशा की दशा में सम्पूर्ण विनिर्देश में से शोधन.**—(1) यदि आवेदक किसी समय ऐसी प्रार्थना करे अथवा यदि नियंत्रक का समाधान हो जाए कि नियम 22 द्वारा विहित अवधि के अन्दर आपत्ति दूर नहीं की गई है तो आवेदक को सुनने के लिए एक तारीख नियत की जाएगा और आवेदक को कम से कम दस दिन पहले इस प्राकार नियत तारीख की सूचना दी जाएगी । आवेदक यथासंभव शीघ्र नियंत्रक को सूचित करेगा कि क्या वह सुनवाई में हाजिर होगा ।

(2) नियंत्रक आवेदक को सुनने के पश्चात् अथवा यदि आवेदक हाजिर न हुआ हो या उसने वह सुना जाना नहीं चाहता है यह सूचित किया हो तो उसे सुने बिना विनिर्देश का ऐसा संशोधन विहित या अनुज्ञात कर सकेगा जो उसके समाधानप्रद रूप में हो और यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे अन्य विनिर्देश के प्रति जैसे वह बताए, निर्देश आवेदक के विनिर्देश में कर दिए जाएं, जब तक कि संशोधन उतनी अवधि के भीतर, जो वह नियत करे, न हो जाए या उसके लिए सहमति न हो जाए ।

24. **नियम 22 और 23 में विनिर्दिष्ट अवधि को बढ़ाना.**—यदि ऐसी अवधि बढ़ाने की प्रार्थना की जाए तो नियम 22 या 23 में विर्णित अवधि बढ़ाई जा सकेगी किन्तु इस प्रकार कि इस नियम के अधीन अनुज्ञात दानों में से कुल बढ़ाई गई अवधि 6 मास से अधिक नहीं होगी ।

25. **अन्य विनिर्देश के प्रति निर्देश का परप.**—नियम 23 के अनुसरण में जब नियंत्रक निदेश दे कि किसी अन्य विनिर्देश का निर्देश आवेदक के सम्पूर्ण विनिर्देश में बढ़ाया जाएगा तो दावे के पश्चात् ऐसा निर्देश बढ़ाया जाएगा और वह निम्नलिखित प्ररूप में होगा, अर्थात —

"पेटेन्ट अधिनियम, 1970 की धारा 18(2) के अनुसरण में आवेदन संख्या — — — — — — — — — के अनुसरण में दाखिल किए गए विनिर्देश का निर्देश देने का निदेश दिया गया है ।"

26. **सशक्त अतिलंघन की दशा में प्रक्रिया.**—यदि धारा 13 या धारा 25 के उपबन्धों के अधीन किए गए अन्वेषण के फलस्वरूप नियंत्रक को यह प्रतीत से कि आवेदक के आविष्कार पर किसी अन्य पेटेन्ट के दावे के अतिलंघन की सारवान सारवान जोखिम के बिना काम नहीं किया जा सकता है तो तदनुसार आवेदक को सूचित किया जाएगा और नियम 22 में से 24 तक में उपबंधित प्रक्रियाएं, जहां तक आवश्यक हो, लागू होंगी ।

27. **अन्य पेटेन्ट के प्रति निर्देश का प्ररूप.**—जहां नियंत्रक निदेश की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन आवेदक के सम्पूर्ण विनिर्देश में अन्य पेटेन्ट का निर्देश जोड़ा जाएगा वहां ऐसा निर्देश निम्नलिखित प्ररूप में दावे के पश्चात् जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"पेटेन्ट अधिनियम, 1970 की धारा 19(1) के अनुसरण में पेटेन्ट संख्या — — — — — — — — का निर्देश देने का निदेश दिया गया है ।"

28. **धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन का प्ररूप ?**

धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन निदेश के अनुसरण में जोड़े गए निर्देश को धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन निकालने के लिए आवेदन प्ररूप 9 में किया जाएगा ।

29. **वह रीति जिसके अनुसार धारा 20(1) के अधीन दावा किया जाएगा :—**

(1) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन दावा प्ररूप 10 में किया जाएगा ।

(2) नियंत्रक के निरीक्षणार्थ मूल समनुदेशन या करार अथवा उसकी शासीकियां या नोटरी द्वारा प्रमाणित की हुई प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की जाएगी और नियंत्रक हक के ऐसे अन्य सबूत की या लिखित सहमति की मांग कर सकेगा जिसकी उसे अपेक्षा है ।

30. **वह रीति जिसके अनुसार प्रार्थना की जाएगी :**

(1) धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन प्रार्थना प्ररूप 11 में की जाएगी ।

(2) मृतक संयुक्त आवेदक के विधिक प्रतिनिधि द्वारा धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन दी गई सहमति को प्रार्थना पत्र पर पृष्ठांकित किया जाएगा ।

(3) संयुक्त आवेदक की मृत्यु का सबूत प्रार्थना के साथ में होगा, और यह साबित करने के लिए कि सहमति देने वाला व्यक्ति विधित प्रतिनिधि है, या तो मृतक की विल के प्रोबेट की प्रमाणित प्रति या

उसकी सम्पदा की बाबत प्रशासन-पत्र या अन्य कोई दस्तावेज दी जाएगी ।

31. **धारा 20(5) के अधीन आवेदन की रीति :**

(1) धारा 20 की उपधारा (5) के अधीन आवेदन प्ररूप 12 में दो प्रतियों में किया जाएगा और उसके साथ में एक कथन होगा जिसमें वे तथ्य, जिनका आवेदक आश्रय लेता हो, पूर्णरूप से दिए गए होंगे और उन निदेशों का भी कथन होगा जो वह चाहता हो ।

(2) नियंत्रक द्वारा आवेदन और कथन की एक प्रतिलिपि प्रत्येक अन्य संयुक्त आवेदक को भेजी जाएगी और आवेदन करने वाला व्यक्ति इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त संख्या में प्रतियां देगा ।

32. **सम्पूर्ण विनिर्देश के स्वीकार हो जाने पर आवेदनों का संख्यांकन :**

इस आवेदन की बाबत दाखिल किए गए सम्पूर्ण विनिर्देश के स्वीकार हो जाने पर आवेदन की एक नई संख्या (जो क्रम संख्या कहलाएगी) दी जाएगी, जो उन संख्यांकों की आवली में होगी जो भारतीय पेटेन्ट और डिजाइन अधिनियम, 1911 (1911 का 2) के अधीन पेटेन्टों पर दिए गए हैं और यही संख्यांक पेटेन्ट का संख्यांक होगा जिसे आवेदन के अनुसरण में मुद्रांकित किया जाएगा ।

33. **आवेदक विनिर्देश आदि का निरीक्षण :**

धारा 23 के अधीन सम्पूर्ण विनिर्देश की स्वीकृति के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् आवेदन का अन्तिम विनिर्देश या संपूर्ण विनिर्देशों के साथ और आवेदन के बारे में दाखिल किए गए रेखाकनों और दस्तावेजों के साथ (यदि कोई हों), निरीक्षण समुचित कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकेगा ।

अध्याय 4

पेटेन्ट देने का विरोध

34. **धारा 25(1) के अधीन समय बढ़ाने के लिए आवेदन की रीति :**

(1) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन पेटेन्ट दिये जाने के विरोध की सूचना देने के लिए समय बढ़ाने का आवेदन प्ररूप 14 में और समुचित कार्यालय में सम्पूर्ण विनिर्देश स्वीकार होने के विज्ञापन की तारीख से 4 मास के भीतर किया जाएगा और उसमें समय बढ़ाए जाने की मन्जूरी के लिए कारण दिए होंगे ।

(2) समय बढ़ाने के लिए आवेदन तीन प्रतियों में किया जाएगा ।

(3) समय बढ़ाने के लिए आवेदन की एक प्रति नियंत्रक द्वारा पेटेन्ट के लिए आवेदक को भेजी जाएगी ।

35. **विरोध की सूचना दाखिल करना :**

धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन दी गई विरोध की सूचना प्ररूप 15 में दी जाएगी और नियंत्रक को तीन प्रतियों में भेजी जाएगी ।

36. **विरोध का लिखित कथन :**

(1) विरोधी पक्षकार तीन प्रतियों में लिखित कथन भी भेजेगा जिसमें विरोधी पक्षकार के हित का स्वरूप, वे तथ्य जिन पर उसका मामला आधारित है तथा वह अनुतोष, जो वह विरोध की सूचना के साथ या विरोध की सूचना की तारीख से एक मास के भीतर लेना चाहता है, भी दिया जाएगा ।

(2) नियंत्रक, विरोधी पक्षकार द्वारा दाखिल की गई विरोध की सूचना और लिखित कथन की एक एक प्रति पेटेन्ट के लिए आवेदक को (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् आवेदक कहा गया है) भेजेगा ।

37. **उत्तर कथन दाखिल करने के लिए समय :**

यदि आवेदक विरोध का प्रति विरोध करना चाहे तो वह नियम 36 के अधीन लिखित कथन की उसे प्रतिलिपि प्राप्त होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर समुचित कार्यालय में दो प्रतियों में उत्तर कथन, जिसमें उन आधारों का पूर्ण रूप से कथन होगा जिन पर कि विरोध का प्रति-विरोध किया जा रहा है, देगा तथा विरोधी पक्षकारों को उसकी एक प्रति देगा ।

38. **विरोधी पक्षकार का साक्ष्य छोड़ने के लिए समय :**

नियम 37 के अधीन आवेदक के उत्तर कथन की प्रति दिए जाने की तारीख से एक मास के भीतर विरोधी पक्षकार समुचित कार्यालय में अपने मामले के समर्थन में दो प्रतियों में साक्ष्य छोड़ सकेगा और आवेदक को साक्ष्य की एक प्रति देगा ।

39. **वह समय जिसके भीतर आवेदक का साक्ष्य छोड़ा जाना है :**— नियम 38 के अधीन विरोधी के साक्ष्य की प्रति परिदत्त किए जाने की तारीख से एक मास के भीतर अथवा यदि विरोधी कोई साक्ष्य दाखिल न करे तो उस समय के, जिसके भीतर विरोधी का साक्ष्य छोड़ा गया होता, अवसान से एक मास के भीतर आवेदक अपने मामले के समर्थन में दो प्रतियों में साक्ष्य समुचित कार्यालय में दे सकेगा और उसकी एक प्रति विरोधी को परिदत्त करेगा ।

40. **विरोधी द्वारा उत्तर-साक्ष्य.**—नियम 39 के अधीन आवेदक के साक्ष्य की एक प्रति विरोधी को परिदत्त किए जाने की तारीख से एक मास के भीतर विरोधी दो प्रतियों में उत्तर-साक्ष्य, जो आवेदक के साक्ष्य में की बातों तक ही कड़े रूप से सीमित होगा, समुचित कार्यालय में छोड़ सकेगा तथा ऐसे साक्ष्य की एक प्रति आवेदक को परिदत्त करेगा ।

41. **नियंत्रक की इजाजत से अतिरिक्त साक्ष्य का दिया जाना.**— नियंत्रक की इजाजत या उसके निदेशों के बिना किसी भी पक्षकार द्वारा कोई भी अतिरिक्त साक्ष्य परिदत्त नहीं किया जाएगा ।

42. **दस्तावेजों का कितनी प्रतियों में दिया जाना.**—(1) विरोध के संबंध में दाखिल की गई और नियंत्रक के समाधानप्रद रूप में अधिप्रमाणित की गयी विरोध की सूचना में या किसी कथन या साक्ष्य में निर्दिष्ट भारतीय पेटेन्ट विनिर्देश से भिन्न सभी दस्तावेजों की प्रतियां जब तक नियंत्रक अन्यथा निदेशन न दे :—

(क) उस दशा में जहां वे विरोध की सूचना और लिखित कथन में निर्दिष्ट हों, तीन प्रतियों में दी जाएंगी ; और

(ख) किसी अन्य मामले में, दो प्रतियों में दी जाएंगी,

ये प्रतियां यथास्थिति, उस सूचना, कथन या साक्ष्य के साथ दी जाएंगी जिनमें वे निर्दिष्ट की गई हैं ।

(2) जहां सूचना, कथन या साक्ष्य में अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में विनिर्देश या अन्य दस्तावेज का निदेश हो तो उसका अंग्रेजी में अनुप्रमाणित अनुवाद तीन प्रतियों में दिया जाएगा ।

43. **समय का बढ़ाया जाना :**—उत्तर कथन या साक्ष्य दाखिल करने के लिए अनुज्ञात समय को बढ़ाना चाहने वाले व्यक्ति द्वारा दी गई अर्जी पर किए गए नियंत्रक के विशेष आदेश द्वारा बढ़ाए जाने के सिवाय सामान्यतः नहीं बढ़ाया जाएगा ।

परन्तु इस प्रकार अनुदत्त समय का बढ़ाना किसी भी मामले में कुल तीन मास से अधिक नहीं होगा ।

44. **सुनवाई** :—(1) साक्ष्य के, यदि कोई हो, प्रस्तुतीकरण के पूरा होने पर या ऐसे अन्य समय पर, जो नियंत्रक ठीक समझे, वह विरोधी पक्ष की सुनवाई के लिए समय नियत करेगा और ऐसी सुनवाई की पक्षकारों को दस दिन से अन्यून की सूचना देगा ।

(2) यदि कार्यवाही का कोई पक्षकार सुने जाने की इच्छा रखता हो तो नियंत्रक को प्रारूप 16 में सूचना द्वारा इत्तिला देगा ।

(3) नियंत्रक, किसी ऐसे पक्षकार को जिसने उप-नियम (2) के अधीन सूचना न दी हो, सुनने से इन्कार कर सकेगा ।

(4) यदि किसी पक्षकार का सुनवाई के समय किसी ऐसे प्रकाशन का, जो पहले से सूचना, कथन या साक्ष्य में वर्णित न हो निर्दिष्ट करने का आशय हो तो वह अपने आशय की कम से कम 5 दिन की सूचना दूसरे पक्षकार को और नियंत्रक को देगा और इसके साथ ऐसे प्रत्येक प्रकाशन के जिसको निर्दिष्ट करने का उसका आशय हो ब्यौरे देगा ।

(5) सुने जाने की इच्छा वाले पक्षकार या पक्षकारों को सुनने के पश्चात् अथवा किसी पक्षकार के सुनवाई न चाहने पर सुनवाई के बिना ही नियंत्रक विरोध का विनिश्चय करेगा और विनिश्चय की उसके कारणों सहित अधिसूचना पक्षकारों को देगा ।

45. **खर्चे का अवधारण.**—यदि आवेदक, विरोध की सूचना दी जाने के पश्चात्, नियंत्रक को यह अधिसूचना करे कि वह अपने आवेदन को अग्रसर नहीं करना चाहता तो नियंत्रक यह विनिश्चित करते समय कि विरोधी को खर्चा दिलवाया जाए या नहीं इस बात पर भी विचार करेगा कि यदि विरोधी ने नियंत्रक को विरोध की सूचना देने के पूर्व आवेदक को युक्ति-युक्त सूचना दे दी होती तो क्या विरोध रोका जा सकता था ।

46. **वह समय, जिसके भीतर धारा 27 के अधीन सम्पूर्ण विनिर्देश संशोधन किया जाएगा.**—जिस समय के भीतर कोई आवेदक धारा 27 के अधीन नियंत्रक के समाधान प्रद रूप में अपना सम्पूर्ण विनिर्देश संशोधन करेगा, वह समय नियंत्रक द्वारा ऐसे प्रज्ञापन की तारीख से छे मास होगा ।

47. **अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया.**—(1) यदि विनिर्देश नियम 46 के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर, जिसके अन्तर्गत उसका बढ़ाना भी है, जिसे नियंत्रक अनुज्ञात करे, नियंत्रक के समाधानप्रद रूप में संशोधित नहीं किया जाता है तो सुनवाई की तारीख की कम से कम दस दिन की सूचना दी जाएगी ।

(2) आवेदक यथाशक्यशीघ्र, नियंत्रक को अधिसूचित करेगा वह सुनवाई में हाजिर होगा या नहीं ।

(3) आवेदक को सुनने के पश्चात् या यदि आवेदक हाजिर नहीं हुआ है या उसने अधिसूचित कर दिया है कि वह सुने जाने की वांछा नहीं करता तो सुनवाई के बिना नियंत्रक विनिर्देश में ऐसा संशोधन विहित या अनुज्ञात कर सकेगा जो उसने समाधानप्रद रूप में किया जाना है और जब तक कि उसके आदेश की तारीख से छे मास के भीतर संशोधन न कर दिया गया हो या मान न लिया गया हो वह पेटेन्ट अनुदत्त करने से इनकार कर सकेगा ।

48. **समय का बढ़ाया जाना.**—नियम 46 या नियम 47 के उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट समय को बढ़ाने के लिए निवेदन प्ररूप 17 में किया जाएगा और उक्त नियमों में से किसी के अधीन बढ़ाया गया कुल समय छे मास से अधिक नहीं होगा ।

49. **धारा 28(2) के अधीन निवेदन की रीति.**—धारा 28 की उप-धारा (2) के अधीन निवेदन प्ररूप 18 में किया जाएगा ।

50. **धारा 28(3) के अधीन दावा करने की रीति.**—(1) धारा 28 की उपधारा (3) के अधीन दावा प्ररूप 19 में किया जाएगा और जिन परिस्थितियों के अधीन दावा किया गया है उनको उपवर्णित करते हुए एक विवरण भी साथ होगा ।

(2) किए गए दावे की और विवरण की एक प्रति नियंत्रक द्वारा पेटेन्ट के हर आवेदक को (जो दावेदार न हो) और किसी अन्य व्यक्ति को जिसे नियंत्रक हितबद्ध समझे, भेजी जाएगी और दावेदार इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त संख्या में प्रतियां देगा ।

51. **धारा 28 की उपधारा (7) के अधीन किए जाने वाले आवेदन का प्ररूप.**—(1) धारा 28 की उपधारा (7) के अधीन प्रमाणपत्र के लिए कोई आवेदन प्ररूप 20 में किया जाएगा और जिन परिस्थितियों के अधीन आवेदन किया गया है उनको उपवर्णित करते हुए एक विवरण भी उसके साथ होगा ।

(2) आवेदन की और विवरण की एक प्रति नियंत्रक द्वारा, यथा-स्थिति, हर पेटेन्टधारी को या पेटेन्ट के आवेदक को (जो आवेदक न हो) वास्तविक प्रकल्पक के रूप में वर्णित व्यक्ति को और किसी भी अन्य व्यक्ति को जिसे नियंत्रक हितबद्ध समझे, भेजी जाएगी और आवेदक इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त संख्या में प्रतियां देगा ।

52. **धारा 28 के अधीन दावे या किसी आवेदन की सुनवाई के लिए प्रक्रिया.**—विरोध की सूचना, लिखित कथन, उत्तर-कथन के दाखिल करने से, साक्ष्य के छोड़ने से तथा सुनवाई से संबंधित नियम 35 से लेकर 45 तक में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया धारा 28 के अधीन किसी दावे या आवेदन की सुनवाई को, इस उपान्तरण के अध्यधीन कि आवेदक के प्रति निदेश का अर्थ, यथास्थिति, दावा या कोई आवेदन करने वाले व्यक्ति के प्रति लगाया जाएगा, यावत्साध्य, इस प्रकार लागू होगी जैसे कि वे पेटेन्ट के अनुदान के विरोध में कार्यवाहियों को लागू होती हैं ।

53. **आविष्कर्ता का उल्लेख.**—धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन आविष्कर्ता का कोई भी उल्लेख पेटेन्ट में नियंत्रक के नाम के पश्चात् और पूर्ण विनिर्देश पर प्ररूप 3क के शीर्ष पर किया जाएगा और निम्नलिखित प्ररूप में हो सकेगा, अर्थात् :—

"पेटेन्ट अधिनियम, 1970 की धारा 28 के अर्थ में इस आविष्कार । इस आविष्कार के सारवान भाग का आविष्कर्ता
— — का — — — — —है" ।"

अध्याय 5

गोपनीयता के निदेश

54. **धारा 36(2) के अधीन पुनर्विचार के परिणाम की संसूचना:**—धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन किए गए प्रत्येक पुनर्विचार का परिणाम उक्त उपधारा के अधीन नियंत्रक को सूचना के प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर पेटेन्ट के आवेदक को लिखित में संसूचित किया जाएगा ।

55. **धारा 38 के अधीन गोपनीयता के निदेशों के प्रतिसंहरण पर समय का बढ़ाया जाना.**—धारा 38 के अधीन की जाने के लिए अपेक्षित या करने के लिए धारू प्राधिकृत किसी बात के लिए समय उस अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा जिसके लिए धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए निदेश प्रवृत्त थे ।

अध्याय 6

पेटेन्टों का मुद्रांकन

56. **पेटेन्टों का मुद्रांकन.**—(1) धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन पेटेन्ट के मुद्रांकन की प्रार्थना प्ररूप 22 में की जाएगी ।

(2) वह अवधि, जिसके भीतर पेटेन्ट के मुद्रांकन की प्रार्थना धारा 43 की उपधारा (2) के परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन की जा सकेगी, उस खण्ड में निर्दिष्ट कार्यवाहियों के अन्तिम अवधारण के पश्चात् दो मास होगी ।

(3) धारा 43 की उपधारा (3) के अधीन आवेदन प्ररूप 23 में किया जाएगा ।

57. **पेटेन्ट का प्ररूप:**—पेटेन्ट ऐसे उपान्तरणों-सहित जैसा कि हर मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हो, चतुर्थ अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट प्ररूप में दो प्रतियों में होगा और उस पर नियम 33 के अधीन आवेदन के लिए दी गई संख्या अंकित होगी ।

58. **धारा 44 के अधीन पेटेन्ट में संशोधन:**—पेटेन्ट में संशोधन के लिए धारा 44 के अधीन आवेदन प्ररूप 24 में दो प्रतियों में दिया जाएगा और उसके कथनों का सत्यापित करने वाला साक्ष्य तथा पेटेन्ट उसके साथ होंगे ।

59. **धारा 51(1) के अधीन निदेशों के लिए आवेदन करने की रीति:**—(1) धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन निदेशों के लिए आवेदन प्ररूप 25 में दो प्रतियों में दिया जाएगा और उसके साथ उन तथ्यों को, जिन पर आवेदक निर्भर करता है उपवर्णित करने वाला विवरण भी होगा ।

(2) आवेदन और विवरण की एक प्रति नियंत्रक द्वारा पेटेन्ट की प्राप्तिकर्ता या स्वत्वधारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हर अन्य व्यक्ति को भेजी जाएगी और आवेदक इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त संख्या में प्रतियां देगा ।

60. **धारा 51(2) के अधीन आवेदन की रीति:**— (1) धारा 51 की उपधारा (2) के अधीन निदेशों के लिए आवेदन प्ररूप 26 में दो-प्रतियों में किया जाएगा और उसके साथ उन तथ्यों का, जिन पर आवेदक निर्भर करता है उपवर्णन करने वाला एक विवरण भी होगा ।

(2) आवेदन और विवरण की एक प्रति नियंत्रक द्वारा व्यतिक्रमी को भेजी जाएगी ।

61. **धारा 51 के अधीन कार्यवाहियों की सुनवाई करने के लिए प्रक्रिया:**—लिखित कथन, उत्तर कथन, साक्ष्य छोड़ने तथा सुनवाई के सम्बन्ध में नियम 35 से 45 तक में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, धारा 51 के अधीन आवेदन की सुनवाई को यावत्शक्य उसी प्रकार लागू होगी जैसे वह पेटेन्ट अनुदत्त करने के लिए विरोधी पक्षकार की सुनवाई को लागू होती है ।

62. **धारा 52(2) के अधीन आवेदन की रीति:**—(1) धारा 52 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन उक्त धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट न्यायालय के आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर प्ररूप 27 में किया जाएगा और उसके साथ जिन तथ्यों पर अर्जीदार निर्भर करता है उन्हें उपवर्णित करने वाला विवरण और वह अनुतोष जिसका वह दावा करता है तथा न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति भी होगी :

परन्तु आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में लगा समय तीन मास की उक्त अवधि की गणना करते समय छोड़ दिया जाएगा ।

(2) जहां न्यायालय ने आवेदक को आविष्कार के केवल एक भाग के लिए ही पेटेन्ट की मंजूरी अनुज्ञात की है वहां मंजूर किए गए नए पेटेन्ट को संख्याओं की उसी आवलि में संख्या दी जाएगी जिस आवलि में उस दिन जिस को पेटेन्ट मंजूर किया गया है स्वीकार किए गए पूर्ण विनिर्देशों को दी गई है ।

63. **नवीकरण फीस.**—(1) यदि पेटेन्ट की अवधि तक उस पेटेन्ट को प्रवृत्त रखने की वांछा की जाए तो पेटेन्ट की तारीख से द्वितीय वर्ष के या किसी उत्तरवर्ती वर्ष के अवसान पर प्रक्रम अनुसूची में विनिर्दिष्ट नवीकरण फीस देनी होगी और वह द्वितीय वर्ष या उत्तर-वर्ती वर्ष के अवसान से पूर्व पेटेन्ट कार्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी ।

(2) नवीकरण फीस देते समय संबंधित पेटेन्ट की संख्या और वह वर्ष जिसकी बाबत फीस दी गई है, कथित किया जाएगा ।

(3) दो या अधिक वर्ष की बाबत संदेय वार्षिक नवीकरण फीस अग्रिम दी जा सकेगी ।

(4) नियंत्रक किसी पेटेन्ट की बाबत संदत्त नवीकरण फीस के जमा करने पर एक प्रमाणपत्र जारी करेगा कि फीस संदत्त कर दी गई है ।

64. **धारा 55(1) के अधीन प्रार्थना का प्ररूप:**—धारा 55 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रार्थना प्ररूप 28 में की जाएगी ।

अध्याय 7

आवेदन तथा विनिर्देश का संशोधन

65. **आवेदन या विनिर्देश का संशोधन** :—(1) किसी पेटेन्ट या संपूर्ण विनिर्देश के आवेदन के संशोधन के लिए धारा 57 के अधीन आवेदन प्ररूप 29 में किया जाएगा ।

(2) यदि उपनियम (1) के अधीन संशोधन के लिए आवेदन पेटेन्ट के लिए उस आवेदन से संबंधित है जो मंजूर नहीं किया गया है तो नियंत्रक यह अवधारित करेगा कि क्या और किन शर्तों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए संशोधन अनुज्ञात किया जाएगा ।

(3) (क) यदि उपनियम (1) के अधीन संशोधन के लिए आवेदन पूर्ण विनिर्देश की स्वीकृति के पश्चात् किया जाए तो संशोधन के लिए आवेदन और प्रस्थापित संशोधन का प्रकार नियंत्रक द्वारा राजपत्र में और आवेदक द्वारा ऐसी रीति से जो नियंत्रक प्रत्येक मामले में निर्दिष्ट करे, विज्ञापित किया जाएगा । नियंत्रक उन सभी व्यक्तियों को भी सूचित करेगा जो उसकी राय में इस मामले में हितबद्ध हों ।

(ख) संशोधन के लिए आवेदन का विरोध करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति राजपत्र में आवेदन के विज्ञापन की तारीख से तीन मास के अन्दर, अपने विरोध की सूचना दो प्रतियों में नियंत्रक को देगा ।

(ग) लिखित कथन, उत्तर कथन, साक्ष्य छोड़ने तथा सुनवाई के सम्बन्ध में नियम 36 से 45 तक में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, धारा 57 के अधीन विरोध की सुनवाई को, यावत्शक्य, उसी प्रकार लागू होगी जैसे वह पेटेन्ट अनुदत्त करने के लिए विरोधी पक्षकार की सुनवाई को लागू होती है ।

66. **संशोधित विनिर्देश आदि, तैयार करना** :—जहां नियंत्रक पेटेन्ट के या संपूर्ण विनिर्देश के आवेदन में संशोधन किया जाना अनुज्ञात करता है वहां आवेदक, यदि नियंत्रक ऐसी अपेक्षा करे और उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले समय के अन्दर इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार, यथास्थिति, संशोधित आवेदन या विनिर्देश देगा ।

67. **अनुज्ञात संशोधनों का विज्ञापन** :—संपूर्ण विनिर्देश के स्वीकार किए जाने के पश्चात् नियंत्रक द्वारा अनुज्ञात संशोधन उसके द्वारा राजपत्र में विज्ञापित किए जाएंगे ।

अध्याय 8

पेटेन्टों का प्रत्यावर्तन

68. **पेटेन्टों का प्रत्यावर्तन** :—(1) धारा 60 के अधीन पेटेन्ट के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन प्ररूप 31 में किया जाएगा ।

(2) यदि आवेदन पर और आवेदक द्वारा दिए गए साक्ष्य पर, यदि कोई हो, विचार करने पर नियंत्रक का यह समाधान हो जाए कि पेटेन्ट प्रत्यावर्तन के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बन पाया है तो वह आवेदक को तदनुसार सूचित करेगा और यदि आवेदक ऐसी सूचना की तारीख से एक मास के अन्दर मामले में सुनवाई की प्रार्थना न करे, तो नियंत्रक आवेदन नामंजूर कर देगा ।

(3) यदि आवेदक अनुज्ञात समय के अन्दर सुनवाई के लिए प्रार्थना करता है और यदि आवेदक की सुनवाई करने पर नियंत्रक का प्रथम-दृष्ट्या यह समाधान हो जाता है कि नवीकरण फीस का संदाय न करना अनाशयित था तो वह आवेदन को राजपत्र में विज्ञापित करेगा ।

69. **प्रत्यावर्तन का विरोध** :—(1) धारा 68 की उपधारा (3) के अधीन राजपत्र में आवेदन के विज्ञापन की तारीख के दो मास के अन्दर किसी भी समय कोई भी व्यक्ति उसके विरोध की सूचना प्ररूप 32 में दो प्रतियों में दे सकता है ।

(2) विरोध की सूचना की एक प्रति नियंत्रक द्वारा आवेदक को भेजी जाएगी ।

(3) लिखित कथन, उत्तर कथन, साक्ष्य छोड़ने तथा सुनवाई के सम्बन्ध में नियम 36 से 45 तक में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, धारा 60 के अधीन विरोध की सुनवाई को, यावश्यक्य उसी प्रकार लागू होगी, जैसे वह पेटेन्ट अनुदत्त करने के लिए विरोधी पक्षकार की सुनवाई को लागू होती है ।

70. **असंदत्त नवीकरण फीस का संदाय** :—(1) यदि नियंत्रक आवेदक के पक्ष में विनिश्चय करता है तो आवेदक असंदत्त नवीकरण फीस और प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त फीस आवेदन का प्रत्यावर्तन अनुज्ञात करने वाले आदेश की तारीख से एक मास के भीतर संदत्त करेगा ।

(2) नियंत्रक आवेदन पर अपने विनिश्चय को राजपत्र में विज्ञापित करेगा ।

अध्याय 9

पेटेन्टों का अभ्यर्पण

71. **पेटेन्टों का अभ्यर्पण** :—(1) धारा 68 के अधीन किसी पेटेन्टधारी द्वारा पेटेन्ट के अभ्यर्पण की प्रस्थापना की सूचना प्ररूप 33 में होगी ।

(2) नियंत्रक उपनियम (1) के अधीन दी गई प्रस्थापना की सूचना को राजपत्र में विज्ञापित करेगा ।

(3) कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, राजपत्र में सूचना के विज्ञापन की तारीख से तीन मास के भीतर नियंत्रक को उसका विरोध करने की सूचना प्ररूप 34 में दो प्रतियों में देगा ।

(4) लिखित कथन, उत्तर कथन, साक्ष्य छोड़ने तथा सुनवाई के सम्बन्ध में नियम 36 से 45 तक में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, धारा 63 के अधीन विरोधी पक्षकार की सुनवाई को, यावश्यक्य, उसी प्रकार लागू होगी जैसे वह पेटेन्ट अनुदत्त करने के लिए विरोधी पक्षकार की सुनवाई को लागू होती है ।

(5) यदि नियंत्रक पेटेन्टधारी की अभ्यर्पण की प्रस्थापना को स्वीकार कर लेता है तो वह पेटेन्टधारी को पेटेन्ट लौटाने का निदेश दे सकेगा और उस पेटेन्ट को प्राप्त करने पर नियंत्रक, आदेश द्वारा, उसे प्रतिसंहृत करेगा और पेटेन्ट के प्रतिसंहरण को राजपत्र में अधिसूचित करेगा ।

अध्याय 10

पेटेन्टों का रजिस्टर

72. **पेटेन्टों का रजिस्टर** :—(1) पेटेन्ट के मुद्रांकित होने पर नियंत्रक, उसके पेटेन्टधारी के रूप में प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और राष्ट्रिकता, आविष्कार का नाम, (जिसके अन्तर्गत धारा 5 में विनिर्दिष्ट वे प्रवर्ग भी हैं जिनसे आविष्कार सम्बन्धित है) पेटेन्ट की तारीख और उसके मुद्रांकन की तारीख तामील के लिए पेटेन्टधारी के पते सहित, पेटेन्ट के रजिस्टर में दर्ज करेगा ।

(2) नियंत्रक, प्रत्येक पेटेन्ट के बारे में नियंत्रक और न्यायालयों के समक्ष अधिनियम के अधीन की जाने वाली कार्यवाहियों से सम्बन्धित प्रविष्टियों को भी पेटेन्ट के रजिस्टर में दर्ज करेगा ।

73. **धारा 68 के अधीन दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण** :—धारा 68 के अधीन दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररूप 35 में किया जाएगा ।

74. **पेटेन्टों में हक और हित का रजिस्ट्रीकरण** :—(1) धारा 60 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन.—

(क) पेटेन्ट के या उसमें शेयर के हकदार होने वाले व्यक्ति द्वारा प्ररूप 36 में किया जाएगा ।

(ख) अन्य किसी हित के लिए बंधकदार या अनुज्ञप्तिधारी या अन्यथा हकदार होने वाले व्यक्ति द्वारा प्ररूप 37 में किया जाएगा ;

(2) धारा 69 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आवेदन.—

(क) समनुदेशक द्वारा प्ररूप 38 में,

(ख) बंधकदार या अनुज्ञप्तिधारी या अन्य पक्षकार द्वारा प्ररूप 37 में किया जाएगा ;

(3) ऐसी किसी अन्य दस्तावेज की जो दस्तावेज के अधीन फायदा प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा पेटेन्ट की स्वत्वधारिता को प्रभावित करने के लिए, तात्पर्यित है, अधिसूचना को पेटेन्ट के रजिस्टर में दर्ज करने के लिए आवेदन प्ररूप 40 में किया जाएगा ।

75. **पेटेन्ट के समनुदेशन आदि का नियंत्रक को प्रस्तुत करना** :—प्रत्येक समनुदेशन और प्रत्येक अन्य दस्तावेज, जो पेटेन्ट के संक्रामण का प्रभाव देने वाला या उसका साक्ष्य हो या ऐसे आवेदन में यथा दाखाकृत उसकी स्वत्वधारिता को प्रभावित करने वाला या उसमें हित का सृजन करने वाला हो, जब तक कि नियंत्रक अन्यथा निदेश न दे, तब तक एक आवेदन के साथ उसे प्रस्तुत की जाएगी जिसके साथ समनुदेशन या अन्य दस्तावेज की दो प्रतियां जो आवेदक या उसके अभिकर्त्ता द्वारा सत्य प्रतिलिपियों के रूप में प्रमाणित हो, भी होंगी और नियंत्रक, हक या लिखित सहमति का ऐसा अन्य सबूत मांग सकेगा जिसकी वो अपेक्षा हो।

76. **पेटेन्ट के हक या हित का रजिस्ट्रीकरण** :—धारा 69 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर नियंत्रक, यथास्थिति, पेटेन्ट में सम्बन्धित व्यक्ति के हक या उसमें उसके हित को रजिस्ट्रीकृत करेगा और रजिस्टर में निम्नलिखित प्ररूप में प्रविष्ट की जाएगी, अर्थात् —

"..... को प्राप्त आवेदन के अनुसरण में ..... एक पक्षकार और ..... अन्य पक्षकार के बीच किए गए समनुदेशन, अनुज्ञप्ति, बन्धक विलेख आदि तारीख ..... के आधार पर स्वत्वधारी, अनुज्ञप्ति-धारी, बंधकदार, आदि के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया।"

77. **नवीकरण फीस की प्रविष्टि** :—पेटेन्ट की बाबत विहित नवीकरण फीस के संदाय का प्रमाण-पत्र जारी होने पर, नियंत्रक पेटेन्टों के रजिस्टर में यह तथ्य कि फीस का संदाय कर दिया गया है और प्रमाणपत्र में यथावर्णित ऐसी फीस के संदाय की तारीख प्रविष्ट करेगा।

78. **पते में परिवर्तन** :—(1) कोई भी पेटेन्टधारी अपने नाम, राष्ट्रिकता, पते या उसको मंजूर किए गए किसी पेटेन्ट की पेटेन्टों के रजिस्टर में तामील के लिए यथा प्रविष्ट किए गए पते के परिवर्तन के लिए नियंत्रक से प्ररूप 41 में निवेदन कर सकेगा। नियंत्रक, नाम या राष्ट्रिकता के परिवर्तन के लिए निवेदन पर कोई कार्रवाई करने के पूर्व परिवर्तन के लिए ऐसे सबूत की अपेक्षा कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।

(2) यदि नियंत्रक उपनियम (1) के अधीन किए गए निवेदन को अनुज्ञात करता है, तो वह तदनुसार रजिस्टर में परिवर्तन कराएगा।

(3) यदि कोई पेटेन्टधारी भारत में तामील के लिए किसी अतिरिक्त पते की प्रविष्ट के लिए प्ररूप 42 में निवेदन करे और यदि नियंत्रक का यह समाधान हो जाए कि निवेदन को अनुज्ञात किया जाना चाहिए, तो वह रजिस्टर में तामील के लिए अतिरिक्त पते की प्रविष्टि इस शर्त के अधीन रहते हुए करा देगा कि रजिस्टर में तामील के लिए एक बार में दो से अधिक अतिरिक्त पतों की प्रविष्टि नहीं की जाएगी।

79. **पेटेन्टों के रजिस्टर का निरीक्षण और उसके लिए संदेय फीस** :—(1) पेटेन्ट कार्यालय की मुख्य शाखा में पेटेन्ट का रजिस्टर रखा जाएगा और प्रथम अनुसूची में उसके लिए विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करने पर कार्यालय-समय में निरीक्षणार्थ खुला रहेगा।

(2) रजिस्टर की एक प्रति पेटेन्ट के कार्यालय के प्रत्येक शाखा कार्यालय पर, उप-नियम (1) के अधीन रजिस्टर के निरीक्षण के लिए लागू शर्तों और उसके लिए संदेय फीस का संदाय करने पर, उपलब्ध रहेंगी।

अध्याय 11

"अधिकारों की अनुज्ञप्ति" शब्दों का पेटेन्टों पर अनिवार्य

अनुज्ञप्ति-पृष्ठांकन और प्रतिसंहरण :

80. **अनिवार्य अनुज्ञप्ति आदि के लिए आवेदन** :—धारा 84, 86, 89, 90 और 91 के अधीन आदेश के लिए नियंत्रक को किया जाने वाला आवेदन यथास्थिति, प्ररूप 43, प्ररूप 44 या प्ररूप 45 में किया जाएगा। उस दशा को छोड़कर जिसमें आवेदन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया हो, आवेदन में आवेदक के हित की प्रकृति का और अनुज्ञप्ति के उन निबन्धनों और शर्तों का जो आवेदक को स्वीकार्य हों, पूर्ण वर्णन होगा।

81. **जब प्रथमदृष्टया मामला न बनता हो** :—(1) यदि साक्ष्य पर विचार करने पर, नियंत्रक का यह समाधान हो जाए कि नियम 80 में निर्दिष्ट धाराओं में से किसी भी धारा के अधीन आदेश करने के लिए प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनता है, तो वह आवेदक को तदनुसार सूचित करेगा, और जब तक कि आवेदक मामले में सुनवाई के लिए ऐसी अधिसूचना की तारीख से एक मास के अन्दर प्रार्थना न करे, नियंत्रक आवेदन को नामंजूर कर देगा।

(2) यदि आवेदक उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञात समय के अन्दर सुनवाई के लिए प्रार्थना करता है तो नियंत्रक, आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या आवेदन पर आगे कार्यवाही की जाए अथवा उसे नामंजूर कर दिया जाए।

82. **धारा 92(2) के अधीन विरोध की सूचना** :—(1) धारा 92 की उपधारा (2) के अधीन विरोध की सूचना प्ररूप 46 में दो प्रतियों में दी जाएगी और उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन आवेदन के विज्ञापन की तारीख से दो मास के भीतर नियंत्रक को भेजी जाएगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विरोध की सूचना में अनुज्ञप्ति के वे निबन्धन और शर्तें, यदि कोई हो, होंगी जिन्हें विरोधी पक्षकार आवेदक को अनुदत्त करने के लिए तैयार हैं और उसके साथ विरोध के समर्थन में साक्ष्य होगा।

(3) विरोधी पक्षकार विरोध की सूचना और अपने साक्ष्य की एक प्रति आवेदक पर तामील करेगा और नियंत्रक को उस तारीख की सूचना देगा जिसको ऐसी तामील की गई है।

(4) नियंत्रक द्वारा विरोध की इजाजत दिए जाने या मांग किए जाने पर ही दोनों में से किसी भी पक्षकार द्वारा अतिरिक्त कथन या साक्ष्य दिया जाएगा।

(5) नियंत्रक तत्पश्चात् मामले की सुनवाई के लिए तारीख और समय नियत करेगा और पक्षकारों को ऐसी सुनवाई के लिए कम से कम दस दिन की सूचना देगा।

(6) नियम 44 के उपनियम (2) से (5) तक में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, इस नियम के अधीन सुनवाई की प्रक्रिया को, यावत्साध्य, उसी प्रकार लागू होगी, जैसे वह पेटेन्ट अनुदत्त करने के लिए विरोधी पक्षकार की सुनवाई को लागू होती है।

83. **धारा 88(2) के अधीन आदेशन की रीति**:—(1) अनुज्ञप्ति के निबन्धनों को तय करने के लिए धारा 88 की उपधारा (2) के

अधीन आवेदन प्ररूप 47 में दो प्रतियों में किया जाएगा और उसके साथ साथ अन्य पक्षकार के बीच हुई बातचीत का विवरण और अनुज्ञप्ति के उन निबन्धनों और शर्तों का कथन भी होगा जिन्हें आवेदक स्वीकार करने के लिए तैयार है।

(2) धारा 87 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (1) या उपखण्ड (2) में निर्दिष्ट उन आविष्कारों के पेटेन्टों की बाबत आवेदनों की दशा में जिनके बारे में यह समझा गया है कि वे उक्त उपधारा के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन "अधिकारों की अनुज्ञप्ति" शब्दों के रूप में अंकित हैं, पेटेन्ट शुदा वस्तु के प्रपुंज की अनुमित शुद्ध कारखाना बाह्य कीमत दर्शाने वाला एक विवरण और उसके समर्थन में साक्ष्य सहित उससे सुसंगत सभी सूचना भी आवेदन के साथ-साथ दाखिल की जाएगी।

(3) नियंत्रक, आवेदन की एक प्रति, उपनियम (2) में निर्दिष्ट विवरण, यदि कोई हो और साक्ष्य की एक प्रति अन्य पक्षकार को भेजेगा और उसे निदेश देगा कि वह उक्त प्रतियों को भेजने की तारीख से एक मास के अन्दर ऐसे निबन्धों और शर्तों वाला एक विवरण दाखिल करे जिन्हें वह स्वीकार करने के लिए तैयार है और साथ ही साथ विवरण की एक प्रति आवेदक पर तामील करेगा और आवेदक पर ऐसी तामील की तारीख नियंत्रक को संसूचित करेगा।

(4) उपनियम (2) में निर्दिष्ट पेटेन्ट की बाबत आवेदन की दशा में नियंत्रक, अन्य पक्षकार को यह भी निदेश दे सकता है कि वह उत्तर में तत्समान विवरण और उसके समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करे और कथन की एक प्रति आवेदक को तामील करे।

(5) नियंत्रक पक्षकारों के कथन या कथनों की और साक्ष्य की तामील की तारीख से एक मास के अन्दर पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देगा।

(6) नियम 44 के उपनियम (2) से (5) तक में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, इस नियम के अधीन सुनवाई की प्रक्रिया को, यावत्शक्य, उसी प्रकार लागू होगी, जैसे वह पेटेन्ट अनुदत्त करने के लिए विरोधी पक्षकार की सुनवाई को लागू होती है।

(7) नियंत्रक पेटेन्टधारी के लिए स्वामिस्व और आरक्षित अन्य पारिश्रमिक के निबन्धन तय करने के लिए कथनों पर विचार करेगा और ऐसी जांच कर सकेगा जैसी वह आवश्यक समझे।

84. धारा 88(4) के अधीन आवेदन करने की रीति: (1) पेटेन्टशुदा आविष्कार पर काम करने की अनुज्ञा के लिए धारा 88 की उपधारा (4) के अधीन आवेदक प्ररूप 48 में दो प्रतियों में किया जाएगा और उसमें आवेदन करने के कारण और वे निबन्धन होंगे जिनके अधीन वह पेटेंटधारी के साथ करार होने तक या नियंत्रक द्वारा विनिश्चय किए जाने तक, पेटेन्टशुदा आविष्कार पर कार्य करेगा। यदि नियंत्रक ऐसा निदेश दे, तो आवेदक आवेदन के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

(2) नियंत्रक, आवेदन और साक्ष्य, यदि कोई हो, की एक प्रति पेटेन्टधारी को अग्रेषित करेगा और उसे निदेश देगा कि वह एक मास से अनधिक समय के भीतर एक विवरण दे जिसमें अनुज्ञप्ति के वे निबन्धन हों जो वह अनुदत्त करने के लिए तैयार है या वे निबन्धन हों जिनके अधीन निबन्धक आवेदक को, उसके साथ करार होने तक पेटेन्टशुदा आविष्कार पर काम करने दे।

(3) नियंत्रक पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात निदेश दे सकता है कि यदि वे अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों पर परस्पर सहमत हैं तो अनुज्ञप्ति निष्पादित करें या आवेदक को ऐसे निबन्धनों पर जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, पेटेन्टशुदा आविष्कारों पर कार्य करने के लिए अनुज्ञात कर सकता है।

85. प्रतिसंहरण आदेश के विज्ञापन की रीति:

नियंत्रक, उसके द्वारा धारा 89 की उपधारा (3) के अधीन, पेटेन्ट का प्रतिसंहरण करने वाला आदेश, राजपत्र में विज्ञापित करेगा।

86. धारा 93(5) के अधीन आवेदन :

(1) अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों, जो नियंत्रक द्वारा तय की गई हों, के पुनरीक्षण के लिए धारा 93 की उपधारा (5) के अधीन आवेदन प्ररूप 49 में दो प्रतियों में किया जाएगा और उसमें उन तथ्यों, जिन पर आवेदक निर्भर करता है, और ईप्सित अनुतोष का उल्लेख होगा और इसके साथ आवेदन के समर्थन में साक्ष्य होगा।

(2) यदि नियंत्रक का यह समाधान हो जाए कि अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनता है, तो वह आवेदक को तदनुसार सूचित करेगा और जब तक कि आवेदक मामले में सुनवाई के लिए एक मास के अन्दर प्रार्थना न करे, नियंत्रक आवेदन को नामंजूर कर सकेगा।

(3) नियंत्रक, आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात यह अवधारित करेगा कि क्या आवेदन पर आगे कार्यवाही की जाए अथवा उसे नामंजूर कर दिया जाए।

87. धारा 93(5) के अधीन आवेदनों की दशा में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया :

(1) यदि नियंत्रक आवेदन पर आगे कार्यवाही अनुज्ञात करता है तो वह आवेदक को निदेश देगा कि वह आवेदन और उसके समर्थन में साक्ष्य की प्रतियां पेटेन्टधारी पर या रजिस्टर में के किसी अन्य व्यक्ति पर जो पेटेन्ट में हितबद्ध प्रतीत हो या अन्य किसी ऐसे व्यक्ति पर तामील करे जिसे उसकी राय में ऐसी प्रतियों की इस प्रकार तामील की जानी चाहिए।

(2) आवेदक नियंत्रक को उसतारीख की सूचना देगा जिसको आवेदन और साक्ष्य की प्रतियों की तामील उपनियम (1) में निर्दिष्ट पेटेन्टधारी और किन्हीं अन्य व्यक्तियों पर की गई है।

(3) पेटेन्टधारी या कोई अन्य व्यक्ति जिस पर आवेदन और साक्ष्य की प्रतियों की तामील की गई है, नियंत्रक को विरोध की सूचना प्ररूप 46 में दो प्रतियों में ऐसी तामील की तारीख से दो मास के अन्दर दे सकेगा। ऐसी सूचना में वे आधार होंगे जिन पर विरोधी पक्षकार निर्भर करता है और उसके साथ विरोध के समर्थन में साक्ष्य होगा।

(4) विरोधी पक्षकार विरोध की सूचना और अपने साक्ष्य की प्रतियां आवेदक पर तामील करेगा और नियंत्रक को उस तारीख की सूचना देगा जिसको ऐसी तामील की गई है।

(5) नियंत्रक द्वारा विशेष इजाजत दिए या मांग किए बिना दोनों में से किसी भी पक्षकार द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य या कथन दाखिल नहीं किया जाएगा।

(6) उपरोक्त कार्यवाही के पूर्ण होने पर या ऐसे अन्य समय, जो वह ठीक समझे, नियंत्रक मामले की सुनवाई के लिए तारीख और समय नियत करेगा और पक्षकारों को ऐसी सुनवाई के लिए कम से कम दस दिन की सूचना देगा।

(7) नियम 44 के उपनियम (2) से (5) तक में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, इस नियम के अधीन सुनवाई की प्रक्रिया को, यावत्शक्य,

उसी प्रकार लागू होगी, जैसे वह पेटेन्ट अनुदत्त करने के लिए विरोधी पक्षकार की सुनवाई को लागू होती है ।

(8) यदि नियंत्रक अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों को पुनरीक्षित करने का विनिश्चय करे तो वह आवेदक को मंजूर की गई अनुज्ञप्ति को ऐसी रीति से, जो वह आवश्यक समझे, संशोधित करेगा ।

अध्याय 12

वैज्ञानिक सलाहकार

88. वैज्ञानिक सलाहकारों की नामावली :

(1) नियंत्रक, धारा 115 के प्रयोजन के लिए वैज्ञानिक सलाहकारों की एक नामावली रखेगा । नामावली में वैज्ञानिक सलाहकारों के नाम और पते उनके पदाभिधान, उनकी शैक्षिक अर्हता के बारे में सूचना, उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र और उनकी तकनीकि, व्यावहारिक और अनुसंधान का अनुभव होगा ।

(2) कोई व्यक्ति, वैज्ञानिक सलाहकारों की नामावली में अपना नाम प्रविष्ट कराने के लिए तब अर्हित होगा, यदि वह निम्नलिखित अर्हताएं पूरी करता हो, अर्थात :—

(1) विज्ञान, इन्जीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिग्री

(2) कम से कम 15 वर्ष का व्यावहारिक या

(3) वह केन्द्रीय या राज्य सरकार के विज्ञानिक या तकनीकी विभाग में या किसी अन्य उपक्रम में उत्तरदायी पद पर रहा हो ।

89. वैज्ञानिक सलाहकारों की नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन की रीति:

कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपना बायोडेटा देने पर अपना नाम वैज्ञानिक सलाहकारों की नामावली में सम्मिलित कराने के लिए आवेदन कर सकता है ।

90. वैज्ञानिक सलाहकारों की नामावली में किसी अन्य व्यक्ति के नाम का समावेश:

यदि नियंत्रक की ऐसी जांच के पश्चात जैसी वह उचित समझे, यह राय हो कि ऐसे व्यक्ति का वैज्ञानिक सलाहकारों की नामावली में प्रवेश होना चाहिए, तो वह नियम 88 और 89 में किसी बात के होते हुए भी, वैज्ञानिक सलाहकारों की नामावली में किसी व्यक्ति का नाम प्रवेश कर सकता है ।

91. शिथिल करने की शक्ति :

जहां नियंत्रक की राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह, लेखबध्द किये जाने वाले कारणों पर किसी व्यक्ति के संबंध में, यदि ऐसा व्यक्ति अन्यथा हकदार हो, नियम 87 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट किसी अर्हता को शिथिल कर सकेगा ।

92. वैज्ञानिक सलाहकारों की नामावली से नामों का हटाया जाना :

नियंत्रक किसी भी व्यक्ति का नाम वैज्ञानिक सलाहकारों की नामावली से हटा सकेगा —

(क) यदि ऐसा व्यक्ति इस प्रकार हटाए जाने के लिए प्रार्थना करे या

(ख) यदि नियंत्रक का यह समाधान हो जाए कि उसका नाम गल्ती से या किसी सारवान तथ्य के दुर्व्यपदेशन या दबाने के कारण नामावली में दर्ज किया गया है : या

(ग) यदि उसे किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो और कारावास का दण्ड दिया गया हो और वह अपनी वृत्तिक हैसियत में कदाचार का दोषी हो और नियंत्रक की यह राय हो कि उसका नाम नामावली से हटा दिया जाना चाहिए ।

अध्याय 13

पेटेन्ट अभिकर्ता

93. पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में दी जाने वाली विशिष्टियां:

धारा 125 के अधीन रखे गए पेटेन्ट अभिकर्ता रजिस्टर में प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत पेटेन्ट अभिकर्ता के नाम, राष्ट्रिकता, कारबार के मुख्य स्थान का पता, शाखा कार्यालयों के पते, यदि कोई हों, अर्हताएं और रजिस्ट्रीकरण की तारीख होगी ।

94. पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन :

(1) प्रत्येक वह व्यक्ति जो एक पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने की इच्छा करे, प्ररूप 50 में दो प्रतियों में आवेदन करेगा जो कि पेटेन्ट कार्यालय के प्रधान कार्यालय में दाखिल की जाएगी ।

(2) आवेदक ऐसी अन्य जानकारी देगा जो नियंत्रक द्वारा अपेक्षित हो ।

95. पेटेन्ट अभिकर्ता के लिए अर्हक परीक्षा की विशिष्टियां :

(1) धारा 126 की उपधारा (1) के खण्ड (2) में निर्दिष्ट अर्हक परीक्षा में लिखित और मौखिक परीक्षा होगी ।

(2) लिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्नपत्र होंगे, अर्थात:—

विषय	अधिकतम अंक
प्रश्न पत्र 1 - पेटेन्ट अधिनियम और नियम	100
प्रश्न पत्र 2 - पेटेन्ट विनिर्देशों और अन्य दस्तावेजों का प्ररूपण और निर्वचन	100

(3) प्रत्येक लिखित प्रश्नपत्र और मौखिक परीक्षा के लिए अर्हत अंक क्रमशः 40 प्रतिशत और 60 प्रतिशत होंगे और अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण केवल तभी घोषित किया जाएगा जब वह कुल अंकों के 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करे ।

96. पेटेन्ट अभिकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण :

अभ्यर्थी के नियम 95 में विनिर्दिष्ट अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात और नियंत्रक जो आवश्यक समझे वह और जानकारी अभिप्राप्त करने के पश्चात, प्रथम अनुसूची में उसके लिए विनिर्दिष्ट फीस की प्राप्ति पर वह पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में अभ्यर्थी का नाम प्रवेश करेगा और उसे पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

97. पेटेन्ट अभिकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में सम्मिलित किए जाने वाले ब्यौरे:

धारा 126 की उपधारा (2) के अधीन पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के हकदार व्यक्ति द्वारा प्ररूप 50 में दो प्रतियों में दिए जाने वाले आवेदन के साथ एक विवरण होगा जिसमें 1 नवम्बर, 1966 से पूर्व पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में उसकी प्रैक्टिस के बारे में सूचना होगी और उन आवेदनों की सूची होगी जिनकी बाबत उसने उक्त तारीख से पूर्व पूर्ण निदेश दाखिल किए हों ।

98. **धारा 126(2) के अधीन पेटेन्ट अभिकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण:**

नियंत्रक, नियम 97 के अधीन किसी व्यक्ति से पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर यदि उसका समाधान हो जाए कि उक्त व्यक्ति धारा 126 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी करता है उसका नाम पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में दर्ज कर सकता है।

99. **पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए निरर्हताएं:**

कोई व्यक्ति पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का पात्र नहीं होगा, यदि वह—

(1) सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त का न्याय निर्णीत किया गया हो ;

(2) अनुन्मोचित दिवालिया हो ,

(3) उन्मोचित दिवालिया होने पर भी, उसने न्यायालय से इस बात का प्रमाण पत्र अभिप्राप्त नहीं किया है कि उसके दिवालियापन का कारण उसकी ओर से किसी अवचार के बिना ही दुर्भाग्य था ,

(4) भारत में या भारत के बाहर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास का दण्ड दिया गया है, जब तक कि जिस अपराध का उसे सिद्धदोष ठहराया गया है वह क्षमा न कर दिया गया हो या उसके द्वारा दिये गए आवेदन पर केन्द्रीय सरकार ने इस निमित्त आदेश द्वारा, निर्योग्यता हटा न दी हो ,

(5) विधि-व्यवसायी होते हुए वृत्तिक अवचार का अपराधी है।

(6) चार्टर्ड एकाउन्टेंड होते हुए उपेक्षा या अवचार का अपराधी है

100. **फीस का संदाय**

किसी व्यक्ति का नाम पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में प्रथम अनुसूची में उसके लिए विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करने पर बना रहेगा।

101. **किसी व्यक्ति का नाम पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर से काट दिया जाना :**

(1) नियंत्रक, किसी भी रजिस्ट्रीकृत पेटेन्ट अभिकर्ता का नाम—

(क) जिसने इसका अनुरोध प्राप्त हुआ हो; या

(ख) जब वह मर गया हो ; या

(ग) जब केन्द्रीय सरकार ने धारा 130 की उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति के नाम को काट दिया हो ; या

(घ) जब उसने नियम 100 में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय में उनके देय होने के तीन मास पश्चात तक व्यतिक्रम किया हो, काट सकेगा।

(2) किसी व्यक्ति का नाम पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर से काटे जाने को राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा और सम्बद्ध व्यक्ति को संसूचित किया जाएगा।

102. **पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में से हटाए गए व्यक्तियों के नामों का प्रत्यावर्तन :**

(1) पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर से हटाए गए किसी व्यक्ति के नाम के प्रत्यावर्तन के लिए धारा 130 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन ऐसे हटाए जाने की तारीख से छह मास के भीतर प्ररूप 51 में तीन प्रतियों में दिया जाएगा।

(2) यदि किसी व्यक्ति का नाम पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में प्रत्यावर्तित कर दिया गया है तो जिस तारीख को उसकी अन्तिम वार्षिक फीस देय हुई उससे एक वर्ष की अवधि तक उसका नाम उसमें रखा जाएगा।

(3) पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में किसी नाम का प्रत्यावर्तन नियंत्रक द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा और सम्बन्धित व्यक्ति को संसूचित किया जाएगा।

103. **पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में नामों आदि में परिवर्तन :**

(1) पेटेन्ट अभिकर्ता, पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में दर्ज अपने नाम, कारबार के मुख्य स्थान और शाखा कार्यालयों, यदि कोई हो, का पता या अर्हताओं में परिवर्तन के लिए प्ररूप 52 में तीन प्रति में आवेदन दे सकता है।

ऐसे आवेदन और उसके लिए प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट की प्राप्ति पर नियंत्रक, पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में आवश्यक परिवर्तन करवाएगा।

(2) पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में किया गया प्रत्येक परिवर्तन राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

104. **पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में मान्यता देने से इन्कार :**

यदि नियंत्रक की यह राय हो कि अधिनियम के अधीन जैसा कि उसकी धारा 131 की उपधारा (1) में उपबन्धित है, किसी कारबार की बाबत किसी व्यक्ति को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए तो वह अपने कारण उस व्यक्ति को संसूचित करेगा और उसे, ऐसे समय के अन्दर जैसा वह अनुज्ञात करे, यह कारण बताने का निदेश देगा कि उसे ऐसे पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में मान्यता देने से इन्कार क्यों न किया जाए और उस व्यक्ति के उत्तर पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात और उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात नियंत्रक ऐसा आदेश देगा जैसा वह ठीक समझे।

105. **अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत पेटेन्ट अभिकर्ताओं के नामों का प्रकाशन :**

पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के नामों और पतों का प्रकाशन समय-समय पर राजपत्र, समाचारपत्रों, व्यापारिक पत्रिकाओं में और ऐसी रीति में किया जाएगा जैसा नियंत्रक ठीक समझे।

अध्याय 14

प्रकीर्ण

106. **सभी सूचनाओं का पता :**

(1) इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में सभी संसूचनाएं पेटेन्टों के नियंत्रक को समुचित कार्यालय पर सम्बोधित की जाएगी।

107. **लेखन गलतियों की शुद्धि :**

धारा 73 में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज में किसी लेखन गलती के लिए अनुरोध प्ररूप 53 में दो प्रतियों में किया जाएगा और उसके साथ दस्तावेज की दो प्रतियां उपेक्षित शुद्धियों को लाल स्याही में स्पष्टतः उपदर्शित करने वाली होंगी और साथ ही जैसा कि प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट हो देय फीस होगी ।

108. **किसी गलती की प्रस्तावित शुद्धि के विज्ञापन की रीति :**

जहां नियंत्रक यह उपेक्षा करे कि प्रस्तावित शुद्धि की प्रकृति की सूचना विज्ञापित की जाए, वहां प्रस्तावित शुद्धि की प्रकृति और निवेदन करने वाला व्यक्ति प्रस्तावित शुद्धियों को दर्शित करते हुए निवेदन की प्रतियां और दस्तावेज की प्रतियां ऐसे व्यक्ति पर भी तामील करेगा जो नियंत्रक की राय में आवेदन में हितबद्ध हों ।

109. **शुद्धि करने के विरोध की रीति और समय :**

(1) कोई भी हितबद्ध व्यक्ति राजपत्र में विज्ञापन की तारीख से एक मास के भीतर किसी समय प्रस्तावित शुद्धि के विरोध के लिए प्ररूप 54 में दो प्रतियों में नियंत्रक को सूचना दे सकेगा ।

(2) विरोध की ऐसी के साथ सूचना विरोधी के हित की प्रकृति, वे तथ्य जिन पर वह निर्भर करता है और अनुतोष जो वह चाहता है को उपवर्णित करने वाला कथन दो प्रतियों में होगा ।

(3) सूचना और कथन की एक प्रति नियंत्रक द्वारा अनुरोध करने वाले व्यक्ति को भेजी जाएगी ।

(4) नियम 37 से 45 में विनिर्दिष्ट उत्तर कथन दाखिल करने, साक्ष्य छोड़ना और सुनवाई से सम्बन्धित प्रक्रिया यथासंभव, धारा 68 के अधीन विरोध की सुनवाई को उसी प्रकार लागू होगी जैसे वह पेटेन्टों के अनुदान के विरोध की सुनवाई को लागू होती है ।

110. **शुद्धियों की अधिसूचना :**

नियंत्रक, शुद्धि के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति और सुसंगत दस्तावेज में की गई शुद्धियों के विरोधी, यदि कोई हो, को अधिसूचित करेगा ।

111. **शपथ-पत्रों का प्ररूप आदि :**

(1) उन शपथ-पत्रों पर जो इस अधिनियम या इन नियमों द्वारा पेटेन्ट कार्यालय में दाखिल किए जाने के लिए या नियंत्रक को पेश किए जाने के लिए अपेक्षित हो, उस विषय या उन विषयों के शीर्षक दिए जाएंगे जिनसे वे सम्बन्धित हो, उत्तम पुरुष में लिखे जाएंगे, उनको क्रमशः संख्यांकित पैराओं में विभक्त किया जाएगा और प्रत्येक पैरा यथासम्भव एक विषय तक ही सीमित रहेगा । प्रत्येक शपथ-पत्र में, शपथ-पत्र देने वाले व्यक्ति के निवास का वर्णन और स्थान अन्तर्विष्ट होगा और देने वाले व्यक्ति का नाम और पता भी होगा और शपथ-पत्र किसी और व्यक्ति की ओर से दिया गया है, तो जिस व्यक्ति की ओर से दिया गया हो उसके नाम का भी उल्लेख होगा ।

(2) जहां एक शपथ-पत्र में दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हों, वहां उन में से हर व्यक्ति पृथक-पृथक ऐसे तथ्यों का अभिसाक्ष्य देगा जो उसकी वैयक्तिक जानकारी में हो और उन तथ्यों का पृथक पैराओं में उल्लेख किया जाएगा ।

(3) अन्तवर्ती मामलों को छोड़कर जिनमें अभिसाक्षी के विश्वास के ब्यानों को स्वीकार किया जा सकता है, शपथ-पत्र ऐसे तथ्यों तक ही सीमित रहेंगे जिन्हें अभिसाक्षी अपनी जानकारी से साबित करने में समर्थ हो परन्तु, यह तब तक जब कि उसके आधार दिए जाएं ।

(4) शपथ-पत्र की शपथ निम्नलिखित रूप में दी जाएगी :—

(क) भारत में—किसी न्यायालय या व्यक्ति के समक्ष, जो विधि द्वारा साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत हो, या अन्य किसी अधिकारी के समक्ष, जो यथा उपर्युक्त ऐसे न्यायालय द्वारा शपथ दिलाने या शपथ-पत्र लेने के लिए सशक्त किया गया हो ;

(ख) भारत से बाहर किसी देश या स्थान में—राजनयिक और कौंसलीय आफिसर (शपथ और फीस) अधिनियम, 1948 के अधीन्तर्गत ऐसे देश या स्थान के किसी राजनयिक या कौंसलिय अधिकारी के समक्ष या ऐसे देश या स्थान के नोटरी के समक्ष जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नोटरीज अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 14 के अधीन मान्यता प्राप्त हो या उस देश या स्थान के न्यायधीस या मजिस्ट्रेट के समक्ष ।

(5) वह व्यक्ति जिसके समक्ष शपथ-पत्र की शपथ ली जाए, उस तारीख का जिसको और उस स्थान का जहां पर शपथ पत्र की शपथ ली जाती है, उल्लेख करेगा और उसपर अपनी मुद्रा, यदि कोई हो, या न्यायालय की मुद्रा यदि शपथ-पत्र की शपथ न्यायालय के समक्ष ली या उस न्यायालय द्वारा समक्ष किए गए किसी अधिकारी के समक्ष ली गई हो और अन्त में अपना नाम हस्ताक्षरित करेगा और अपने पदाभिधान और पते का उल्लेख करेगा ।

(6) कोई भी शपथ-पत्र जिससे यह तात्पर्यित है कि उस पर या उसमें शपथ-पत्र लेने के लिए उपनियम (4) द्वारा प्राधिकृत किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके समक्ष शपथ-पत्र लिए जाने के परिसाक्ष्य में, मुद्रा अंकित की गई है या उसके हस्ताक्षर किए गए हैं, मुद्रा या हस्ताक्षर की या उस व्यक्ति को पदीय हैसियत की असलियत के सबूत के बिना नियंत्रक द्वारा स्वीकार किया जा सकेगा ।

(7) शपथ-पत्र को शपथ दिलाने और प्रतिसंज्ञान कराने के पूर्व उसमें के परिवर्तनों और अन्तरालेखनों को उस व्यक्ति के आद्यक्षरों द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा जिसके समक्ष शपथ-पत्र की शपथ ली गई हो ।

(8) जहां अभिसाक्षी अनपढ़, अन्धा या उस भाषा से अनभिज्ञ हो जिसमें शपथ-पत्र लिखा गया है, वहां उस व्यक्ति द्वारा जिसके समक्ष शपथ -पत्रकी शपथ ली जाए, शपथ-पत्र के अन्त में एक ऐसा प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाएगा कि उसकी उपस्थिति में अभिसाक्षी को शपथ-पत्र पढ़कर, अनुवाद कर के सुना दिया गया है या समझा दिया गया है और कि ऐसा प्रतीत होता है कि अभिसाक्षी ने उसे पूर्णतः समझ लिया है और उसने उसकी उपस्थिति में शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं या अपना चिह्न अंकित किया है ।

(9) इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी भी कार्यवाही के संबंध में नियंत्रक के समक्ष दाखिल किया गया प्रत्येक शपथ-पत्र तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन, सम्यक्तः स्टाम्पित किया जाएगा ।

112. **प्रदर्श.**—जहां विरोध में या किसी अन्य कार्यवाही में प्रदर्श दाखिल किए जाने हों, वहां प्रत्येक प्रदर्श का अंकन या प्रति, दूसरे पक्षकार को उसके निवेदन और खर्चे पर दी जाएगी, यदि प्रदर्शों की प्रतियां या उनके अंकन सुविधाजनक रूप से नहीं दिये जा सकते हों, तो मूल प्रदर्शों को नियंत्रक के पास, पहले से समय नियत करने पर हितबद्ध पक्षकार के निरीक्षण के लिए छोड़ दिया जाएगा । यदि मूल प्रदर्श पहले से ही नियंत्रक के पास न छोड़े गए हों, तो सुनवाई के समय उनको पेश किया जाएगा ।

113. **निदेश जो अन्यथा विहित न हों.**—(1)जहां इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी कार्यवाही के समुचित रूप से चलाने या पूर्ण करने के लिए, नियंत्रक की यह राय हो कि ऐसी कार्यवाहियों के किसी पक्षकार के लिए किसी कार्य का करना, किसी दस्तावेज का दाखिल करना या साक्ष्य पेश करना आवश्यक है, जिसके लिए इस अधिनियम या इन नियमों में व्यवस्था नहीं की गई है, वह लिखित सूचना द्वारा ऐसे पक्षकार से ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट कार्य करने, दस्तावेज दाखिल करने या साक्ष्य पेश करने की अपेक्षा कर सकता है ।

(2) भले ही कोई आवेदक या कार्यवाही का पक्षकार सुनवाई चाहता है अथवा नहीं नियंत्रक किसी भी समय उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर उससे यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह लिखित रूप में अपना कथन, ऐसी जानकारी, जो नियंत्रक आवश्यक समझे, देते हुए प्रस्तुत करे ।

114. **नियंत्रक द्वारा स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग.**—अधिनियम या इन नियमों के अधीन पेटेन्ट के लिए किसी आवेदक या किसी कार्यवाही के पक्षकार के प्रतिकूल स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग करने से पूर्व नियंत्रक ऐसे आवेदक या पक्षकार को ऐसी कार्यवाही की न्यूनतम दस दिन की सूचना देने के पश्चात सुनवाई करेगा ।

115. **नियंत्रक के विनिश्चयों के पुनर्विलोकन या उसके आदेशों को अपास्त करने के लिए आवेदन.**—(1) नियंत्रक की, धारा 77 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन उसके विनिश्चय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन प्ररूप 55 में दो प्रतियों में, आवेदक को ऐसे विनिश्चय की संसूचना की तारीख से एक मास भीतर या तत्पश्चात एक मास से अनधिक ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो प्ररूप 57 में अनुरोध करने पर नियंत्रक अनुज्ञात करे, प्ररूप 55 में दो प्रतियों में किया जाएगा और उसके साथ एक कथन होगा जिसमें वे कारण वर्णित होंगे जिनके आधार पर पुनर्विलोकन की ईप्सा की गई है । जहां प्रश्नगत विनिश्चय आवेदक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित हो, वहां उक्त आवेदन व कथन तीन प्रतियों में भेजा जाएगा । नियंत्रक आवेदन और कथन, प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित अन्य व्यक्ति को तुरन्त प्रेषित कर देगा ।

(2) नियंत्रक को धारा 77 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अधीन उसके द्वारा पारित एक पक्षीय आदेश को अपास्त करने के लिए आवेदन, आवेदक को ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से एक मास के भीतर या एक मास से अनधिक ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो प्ररूप 57 में अनुरोध करने पर नियंत्रक अनुज्ञात करे, प्ररूप 56 में दो प्रतियों में किया जाएगा और उसके साथ एक कथन होगा जिसमें वे कारण वर्णित होंगे जिन पर आवेदन आधारित है । जहां आदेश आवेदक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित हो, वहां आवेदन और कथन तीन प्रतियों में भेजे जाएंगे । नियंत्रक आवेदन और कथन प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित व्यक्ति को तुरन्त प्रेषित कर देगा ।

116. **प्रतिकर के संदाय की रीति.**—(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम की धारा 102 के अधीन किसी अधिष्कार या पेटेन्ट के अर्जन की बाबत प्रतिकर उस सरकार द्वारा, यदि प्रतिकर की रकम 10,000 से अधिक न हो, एक-मुश्त संदेय होगी और यदि ऐसी रकम 10,000 से अधिक हो तो उक्त 10,000 रू. से अधिक की रकम पांच समान वार्षिक किश्तों में संदेय होगी ।

(2) यदि एकमुश्त संदेय प्रतिकर या उपनियम (1) में निर्दिष्ट उसकी कोई किश्त, जिस तारीख को, यदि कोई हो, किश्त की रकम देय होती है, से तीन दिन के भीतर संदत्त नहीं की जाती, तो केन्द्रीय सरकार, उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के तुरन्त पश्चात, के दिन से गिन कर 9 प्रतिशत वार्षिक की दर पर साधारण ब्याज देने की दायी होगी ।

117. **वह प्ररूप और रीति जिसमें धारा 146(2) के अधीन अपेक्षित कथन भेजे जाने हैं.**—(1) वे कथन जो धारा 146 की उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक पेटेन्टधारी और प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भेजे जाएंगे, प्ररूप 58 में होंगे, पेटेन्टधारी या अनुज्ञप्ति धारी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित होंगे ।

(2) प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष के सम्बन्ध में उपनियम (1) में निर्दिष्ट कथन प्रत्येक वर्ष के अवसान के तीन मास के भीतर भेजे जाएंगे ।

(3) नियंत्रक, धारा 146 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन उसे प्राप्त सूचना राजपत्र और उस समाचार पत्रों और व्यापार पत्रिकाओं में, जैसी वह उचित समझे, प्रकाशित कर सकता है ।

118. **पेटेन्ट की दूसरी प्रति जारी करने के लिए आवेदन का प्ररूप:**—धारा 154 के अधीन पेटेन्ट की दूसरी प्रति जारी करने के लिए आवेदन प्ररूप 59 में होगा और उन परिस्थितियों को, जिनमें पेटेन्ट खोया या नष्ट हुआ या पेश नहीं किया जा सका है, उपवर्णित करने वाला कथन होगा, साथ में प्रथम अनुसूची में उसके लिए विनिर्दिष्ट फीस होगी ।

119. **प्रमाणित प्रतियों और प्रमाणपत्रों का देना.**—पेटेन्ट कार्यालय में रजिस्टर की किसी प्रविष्ट की प्रमाणित प्रतियां, या पेटेन्टों से, विनिर्देशों और अन्य सार्वजनिक दस्तावेजों, या वहां रखे रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों से उद्धरण, नियंत्रक द्वारा, प्ररूप 60 में उसे किए गए अनुरोध पर और प्रथम अनुसूची में उसके लिए विनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर किए जा सकेंगे ।

120. **धारा 153 के अधीन सूचना के लिए अनुरोध.**—(1) किसी पेटेन्ट या पेटेन्ट के लिए आवेदन से संबंधित निम्नलिखित विषयों के संबन्ध में सूचना के लिए अनुरोध प्ररूप 61 में किया जाएगा :—

(क) कि जब अनन्तिम विनिर्देश के पश्चात पूर्ण विनिर्देश दाखिल किया गया है या पेटेन्ट के लिए आवेदन का परित्याग कर दिया गया समझा गया हो;

(ख) कि जब संपूर्ण विनिर्देश स्वीकार कर लिया गया है या पेटेन्ट के लिए कोई आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है ,

(ग) कि जब कोई पेटेन्ट मुद्रांकित किया गया हो या जब मुद्रांकित करने का समय समाप्त हो गया हो ,

(घ) कि जब नवीकरण फीस संदत्त की गई है ,

(ङ) कि जब किसी पेटेन्ट की अवधि समाप्त हो गई हो या खत्म हो जाएगी ,

(च) कि जब रजिस्टर में कोई प्रविष्टि की गई है या ऐसी प्रविष्टि करने के लिए आवेदन किया गया है , या

(छ) कि जब रजिस्टर में किसी प्रविष्टि या राजपत्र में विज्ञापन को अन्तर्वलित करने वाला कोई आवेदन किया गया है या कार्यवाही की गई हो. यदि आवेदन या कार्यवाही की प्रकृति अनुरोध में विनिर्दिष्ट की गई है ।

(2) अपेक्षित सूचना की प्रत्येक मद के संबंध में पृथक अनुरोध किया जाएगा ।

(3) धारा 153 के अधीन किए गए अनुरोध पर संदेय फीस वह होगी जो प्रथम अनुसूची में उपवर्णित है ।

121. **अभिकरण.**—(1) इस अधिनियम और इन नियमों के प्रयोजनों के लिए किसी अभिकर्ता का प्राधिकरण प्ररूप 61 में या मुख्तारनामे के रूप में होगा ।

(2) जहां उप-नियम (1) के अधीन कोई प्राधिकरण किया गया हो इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन हुई किसी अभिकर्ता पर किसी कार्यवाही या मामले से संबंधित किसी दस्तावेज की तामील उसे इस प्रकार प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति पर तामील समझी जाएगी; किसी व्यक्ति को किसी कार्यवाही या मामले के संबंध में निर्दिष्ट सभी संसूचनाएं ऐसे अभिकर्ता को संबोधित की जा सकती हैं, और नियंत्रक के समक्ष उससे संबंधित सभी हाजिरियां ऐसे अभिकर्ता द्वारा या के द्वारा दी जा सकती हैं ।

(3) उप-नियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, नियंत्रक यदि यह आवश्यक समझता है, किसी आवेदक, विरोधी या ऐसी कार्यवाही या विषय के पक्षकार के वैयक्तिक हस्ताक्षर या उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है ।

122. **खर्चों के मापमान.**—नियंत्रक, अपने समक्ष सभी कार्यवाहियों में, नियम 46 के अधीन रहते हुए, मामले की सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जितना वह युक्तियुक्त समझे उतना खर्चा अधिनिर्णीत कर सकता है :

परन्तु, यह कि चौथी अनुसूची में दिए गए किसी विषय के संबंध में अधिनिर्णीत खर्चों की रकम उसमें विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं होगी ।

123. **साधारणतः नियंत्रक की शक्तियां.**—कोई भी दस्तावेज जिसके संशोधन के लिए अधिनियम में कोई विशेष उपबन्ध नहीं है, संशोधित किया जा सकता है और प्रक्रिया में कोई अनियमितता जो नियन्त्रक की राय में किसी व्यक्ति के हितों को अहित के बिना दूर की जा सकती है, यदि नियंत्रक ठीक समझे और उन निबन्धनों पर जो वह निर्दिष्ट करे, शुद्ध की जा सकती है ।

124. **विहित समय को बढ़ाने की शक्ति.**—इन नियमों द्वारा किसी कार्य को करने या तत्प्रधान कोई कार्यवाही करने के लिए विहित समय, नियंत्रक द्वारा यदि वह उचित समझे और उन निबन्धनों पर जो वह निर्दिष्ट करे बढ़ाया जा सकता है ।

125. **कतिपय मामलों में नियंत्रक के समक्ष सुनवाई सार्वजनिक रूप से होगी.**—जहां पेटेन्ट के लिए किसी आवेदन या पेटेन्ट से संबंधित किसी मामले से संबंधित दो या दो से अधिक पक्षकारों के मध्य किसी विवाद या पेटेन्ट के संबंध में किसी मामले की सुनवाई नियंत्रक के समक्ष संपूर्ण विनिर्देश के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् हो, विवाद की सुनवाई सार्वजनिक रूप से होगी जब तक कि नियंत्रक, विवाद के पक्षकारों, जो सुनवाई में या तो वैयक्तिक रूप से हाजिर हों या जिनका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है परामर्श के पश्चात्, अन्यथा निदेश न दे ।

126. **दी इंडियन पेटेन्ट्स एण्ड डिजाइनस रूल्स, 1933 का निरसन और संशोधन.**—दी इंडियन पेटेन्ट्स एण्ड डिजाइनस रूल्स, 1933 जहां तक पेटेन्ट्स को लागू होते हैं, एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं, अर्थात् उक्त नियम पंचम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित हो जाएंगे ।

प्रथम अनुसूची

(नियम 7 देखिये)

फीस

प्रविष्टि की संख्या	जिस पर संदेय है	पक्रम संख्या	उचित फीस
1	2	3	4
			रु० पै०
1.	अनंतिम विनिर्देश के साथ धारा 7 या 54 के अधीन पेटेन्ट के लिए आवेदन पर	1, 1क, 1ख, 1कख	20.00
2.	संपूर्ण विनिर्देश के साथ धारा 7, 54 या 135 के अधीन पेटेन्ट के लिए आवेदन पर	1, 1क, 1ख, 1कख, 2, 2क, 2ख, 2कख	50.00
3.	अनंतिम विनिर्देश के पश्चात संपूर्ण विनिर्देश दाखिल करने पर	3, 3क	30.00
4.	धारा 8 के अधीन कथन और वचनबंध करता दाखिल करने पर	4	कोई फीस नहीं
5.	धारा 9(1), 21(2) या 53(3) के अधीन समय बढ़ाने के अनुरोध पर	5	25.00 (प्रति मास)
6.	आविष्कारिता की घोषणा दाखिल करने पर	6	कोई फीस नहीं
7.	नियम 14(5) या 24 के अधीन समय बढ़ाने के आवेदन पर	7	25.00 (प्रति मास)
8.	अगली तारीख डालने के लिए आवेदन	8	30.00
9.	निर्देश खोप करने के लिए धारा 19(2) के अधीन आवेदन	9	25.00
10.	धारा 20(1) के अधीन आवेदक या संयुक्त आवेदक के रूप में कार्यवाही करने के लिए दावा	10	25.00
11.	संयुक्त आवेदक की मृत्यु होने पर धारा 20(4) के अधीन निदेशों के लिए प्रार्थना	11	25.00
12.	संयुक्त आवेदकों के बीच विवाद की स्थिति में पेटेन्ट के लिए आवेदन पर कार्यवाही करने के बारे में धारा 20(5) के अधीन निदेशों के लिए आवेदन	12	25.00
13.	धारा 22 के अधीन संपूर्ण विनिर्देश की स्वीकृति को मुल्तवी करने के लिए अनुरोध	13	30.00
14.	धारा 25(1) या 28(4) के अधीन समय बढ़ाने के लिए आवेदन	14	25.00
15.	पेटेन्ट के अनुदान के विरोध की सूचना	15	50.00
16.	यह सूचना देने पर कि नियंत्रक के समक्ष सुनवाई में हाजिर रहा जाएगा	16	50.00

1	2	3	4
17.	नियम 48 के अधीन समय बढ़ाने के लिए आवेदन	17	25.00 प्रति मास
18.	धारा 28(2) के अधीन अनुरोध पर	18	25.00
19.	धारा 28(3) के अधीन दावा	19	25.00
20.	धारा 28(7) के अधीन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन पर	20	25.00
21.	भारत से बाहर (धारा 39) पेटेन्टों के लिए आवेदन करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन पर	21	5.00
22.	धारा 43 के अधीन किसी पेटेन्ट के मुद्रांकन के लिए प्रार्थना पर	22	60.00
23.	धारा 43 (3 के अधीन किसी पेटेन्ट के मुद्रांकन के लिए प्रार्थना करने के लिए समय बढ़ाने के आवेदन पर	23	25.00 प्रति मास
24.	पेटेन्ट के संशोधन के लिए धारा 44 के अधीन आवेदन पर	24	50.00
25.	धारा 51(1) के अधीन निदेशों के लिए आवेदन पर	25	25.00
26.	धारा 51(2) के अधीन निदेशों के लिए आवेदन पर	26	25.00
27.	धारा 52(2) के अधीन पेटेन्ट के अनुदान के लिए अनुरोध पर	27	50.00
28.	धारा 55 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन किसी अतिरिक्त के पेटेन्ट को स्वतंत्र पेटेन्ट में संपरिवर्तित करने के अनुरोध पर	28	25.00
29.	पेटेन्ट के नवीकरण के लिए—		
	क. धारा 53 के अधीन, अधिनियम के अधीन अनुदत्त पेटेन्टों के—		
	पेटेन्ट की तारीख से दूसरा वर्ष समाप्त होने से पूर्व और तीसरे वर्ष की बाबत		50.00
	तीसरा वर्ष समाप्त होने से पूर्व चौथे वर्ष की बाबत		100.00
	चौथा वर्ष समाप्त होने से पूर्व पांचवें वर्ष की बाबत		200.00
	पांचवां वर्ष समाप्त होने से पूर्व छठे वर्ष की बाबत		250.00
	छठा वर्ष समाप्त होने से पूर्व सातवें वर्ष की बाबत		300.00
	सातवां वर्ष समाप्त होने से पूर्व आठवें वर्ष की बाबत		350.00
	आठवां वर्ष समाप्त होने से पूर्व नवें वर्ष की बाबत		400.00
	नवां वर्ष समाप्त होने से पूर्व दसवें वर्ष की बाबत		450.00
	दसवां वर्ष समाप्त होने से पूर्व ग्यारहवें वर्ष की बाबत		500.00
	ग्यारहवां वर्ष समाप्त होने से पूर्व बारहवें वर्ष की बाबत		550.00
	बारहवां वर्ष समाप्त होने से पूर्व तेरहवें वर्ष की बाबत		600.00
	तेरहवां वर्ष समाप्त होने से पूर्व चौदहवें वर्ष की बाबत		700.00
	ख. धारा 162(2)(ख) के अधीन, इन्डियन पेटेन्ट्स एण्ड डिजाइन्स एक्ट, 1911 (1911 का सं० 2) के अधीन अनुदत्त पेटेन्टों के—		
	चौथा वर्ष समाप्त होने से पूर्व पांचवें वर्ष की बाबत		50.00
	पांचवां वर्ष समाप्त होने से पूर्व छठे वर्ष की बाबत		50.00
	छठा वर्ष समाप्त होने से पूर्व सातवें वर्ष की बाबत		50.00
	सातवां वर्ष समाप्त होने से पूर्व आठवें वर्ष की बाबत		50.00
	आठवां वर्ष समाप्त होने से पूर्व नवें वर्ष की बाबत		100.00
	नवां वर्ष समाप्त होने से पूर्व दसवें वर्ष की बाबत		100.00
	दसवां वर्ष समाप्त होने से पूर्व ग्यारहवें वर्ष की बाबत		100.00
	ग्यारहवां वर्ष समाप्त होने से पूर्व बारहवें वर्ष की बाबत		100.00
	बारहवां वर्ष समाप्त होने से पूर्व तेरहवें वर्ष की बाबत		150.00
	तेरहवां वर्ष समाप्त होने से पूर्व चौदहवें वर्ष की बाबत		150.00
	चौदहवां वर्ष समाप्त होने से पूर्व पन्द्रहवें वर्ष की बाबत		150.00
	पन्द्रहवां वर्ष समाप्त होने से पूर्व सोलहवें वर्ष की बाबत		150.00
	टिप्पण :—दो या अधिक वर्षों की फीस का अग्रिम संदाय किया जा सकता है ।		
30.	धारा 57 के अधीन पेटेन्ट संपूर्ण विनिर्देश के लिए आवेदन के संशोधन के लिए आवेदन पर स्वीकृति के पूर्व	29	30.00
	स्वीकृति के पश्चात		60.00
	मुद्रांकन के पश्चात		100.00

1	2	3	4
31.	धारा 59 के अधीन संशोधन के आवेदन के प्रति विरोध की सूचना पर	30	50 00
32.	धारा 60 के अधीन पेटेन्ट के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन पर	31	50.00
33.	धारा 60 के अधीन पेटेन्ट के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन के प्रति विरोध की सूचना पर	32	50.00
34.	प्रत्यावर्तन पर अतिरिक्त फीस .		150.00
35.	धारा 63 के अधीन पेटेन्ट के अभ्यर्पण की प्रस्थापना की सूचना पर	33	50.00
36.	धारा 63 के अधीन पेटेन्ट के अभ्यर्पण की प्रस्थापना के विरोध की सूचना पर	34	50.00
37.	धारा 68 के अधीन पेटेन्टों के रजिस्टर में किसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन	35	
	एक पेटेन्ट की बाबत . .		25.00
	प्रत्येक अतिरिक्त पेटेन्ट की बाबत		10.00
38.	धारा 69(1) के अधीन पेटेन्ट के रजिस्टर में हकदारधारी या आंशिक हकदारधारी के नाम की प्रविष्टि के लिए आवेदन पर	36	
	एक पेटेन्ट की बाबत		25.00
	प्रत्येक अतिरिक्त पेटेन्ट के लिए .		10.00
39.	धारा 69(1) के अधीन रजिस्टर में पेटेन्टों के बन्धककर्त्ता या अनुज्ञापक के रूप में हकदारधारी व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि के लिए आवेदन पर	37	
	एक पेटेन्ट की बाबत . .		25.00
	प्रत्येक अतिरिक्त पेटेन्ट के लिए .		10.00
40.	धारा 69(2) के अधीन पेटेन्टों के रजिस्टर में पेटेन्ट या उसके किसी अंश के हकदारधारी व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि के लिए समनुदेशक के आवेदन पर	38	
	एक पेटेन्ट की बाबत		25.00
	प्रत्येक अतिरिक्त पेटेन्ट के लिए .		10.00
41.	धारा 69(2) के अधीन पेटेन्ट के बन्धक या अनुज्ञापन या अन्यथा किसी हित के हकदारधारी व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि के लिए बन्धक कर्त्ता या अनुज्ञापक या अन्य व्यक्ति द्वारा आवेदन पर	39	
	एक पेटेन्ट की बाबत . .		25.00
	प्रत्येक अतिरिक्त पेटेन्ट के लिए .		10.00
42.	पेटेन्ट के स्वामित्व को प्रभावित करने को तात्पर्यित किसी अन्य दस्तावेज की अधिसूचना की पेटेन्टों के रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए आवेदन पर [नियम 74(3))]	40	
	एक पेटेन्ट के लिए . .		25.00
	प्रत्येक अतिरिक्त पेटेन्ट के लिए .		10.00
43.	नियम 78(1) के अधीन पेटेन्टों के रजिस्टर में नाम आदि के परिवर्तन की सूचना पर	41	5.00
44.	धारा 78(3) के अधीन पेटेन्टों के रजिस्टर में एक अतिरिक्त पते की प्रविष्टि के लिए प्रार्थना पर	42	10.00
45.	धारा 84(1), 96(1) या 97(1) के अधीन अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पर	43	60.00
46.	धारा 86(1) के अधीन पेटेन्ट के पृष्ठांकन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा आवेदन पर	44	60.00
47.	धारा 89(1) के अधीन पेटेन्ट के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन पर	45	60.00
48.	धारा 92(2) और 93(5)' के अधीन आवेदन के विरोध की सूचना पर	46	50.00
49.	धारा 88(2) के अधीन अनुज्ञप्ति के निबन्धनों को तय करने के लिए आवेदन पर	47	25.00
50.	धारा 88(4) के अधीन पेटेन्टकृत आविष्कार पर कार्य करने के लिए अनुज्ञा पर	48	25.00
51.	धारा 93(5) के अधीन अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए	49	60.00
52.	नियम 94 और 97 के अधीन पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर	50	50.00
53.	नियम 94 और 97 के अधीन पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर		50.00
54.	पेटेन्ट अभिकर्त्ताओं के रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम के बने रहने के लिए :—		30.00
	(क) रजिस्ट्रीकरण की फीस के साथ संदत्त करने के लिए		

1	2	3	4
	पहले वर्ष के लिए :—		
	(i) पहली अप्रैल और 30 सितम्बर के बीच किसी समय रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की दशा में ।		30.00
	(ii) पहली अक्तूबर और अनुवर्ती 31 मार्च के बीच किसी भी समय रजिस्ट्रीकृत किसी व्यक्ति की दशा में ।		15.00
55.	पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर (नियम 102) ।	51	50.00 (धन प्रविष्टि संख्या 54 के अन्तर्गत बने रहने की फीस)
56.	पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के परिवर्तन के लिए आवेदन पर (नियम 103) ।	52	10.00
57.	धारा 78(1) के अधीन लिपिकीय गलतियों की शुद्धि के लिए प्रार्थना पर ।	53	15.00
58.	धारा 78(5) के अधीन लिपिकीय-गलतियों की शुद्धि के लिए प्रार्थना के प्रति विरोध की सूचना पर ।	54	15.00
59.	नियंत्रक के विनिश्चय के पुनर्विलोकन के लिए धारा 77(1) (च) के अधीन आवेदन पर ।	55	30.00
60.	नियंत्रक के आदेश को अपास्त करने के लिए धारा 77(1)(छ) के अधीन आवेदन पर ।	56	30.00
61.	समय बढ़ाने के लिए नियम 115 के अधीन प्रार्थना ।	57	25.00
62.	धारा 146(2) के अधीन भारत में वाणिज्यिक मापमान पर पेटेन्टकृत आविष्कार पर कार्य करने से संबंधित कथन पर ।	58	कोई फीस नहीं
63.	धारा 154 के अधीन पेटेन्ट की दूसरी प्रति के लिए आवेदन पर ।	59	50.00
64.	धारा 72 के अधीन प्रमाणित प्रतियों के लिए और धारा 147 के अधीन प्रमाणितपत्रों के लिए प्रार्थना पर ।	60	25.00
65.	दस्तावेजों की टंकित प्रतियां देने के लिए (हर 100 शब्दों या उसके भाग के लिए) ।		(25 पैसे किन्तु न्यूनतम 3 रु०)
66.	दस्तावेज की फोटो प्रतियां देने के लिए ।		
	(i) प्रत्यक्ष नेगेटिव के लिए 33.00 से०मी० 20.5 से०मी० या 13" 8-1/4" के पूरे आकार के प्रति पृष्ठ ।		4.00
	(ii) पोजिटिव प्रति के लिए 33.00 से०मी० 20.5 से०मी० या 13" 8-1/4" के पूरे आकार के प्रति पृष्ठ ।		7.00
67.	कार्यालय प्रतियों, पांडुलिपि या मुद्रित, हर एक को प्रमाणित करने के लिए ।		5.00
68.	धारा 72 के अधीन रजिस्टर के निरीक्षणार्थ प्रार्थना पर ।		5.00
69.	धारा 153 के अधीन जानकारी के लिए प्रार्थना पर ।	61	10.00
70.	पेटेन्ट अभिकर्ता या अन्य व्यक्तियों के प्राधिकरण के प्ररूप पर ।	62	कोई फीस नहीं
71.	समय बढ़ाने के लिए या लड़ी गई कार्यवाहियों में किसी अन्तर्वर्ती मामले में कोई आदेश अभिप्राप्त करने के लिए अर्जी पर, जिसके लिए अन्यथा उपबन्धित न हो ।		25.00

द्वितीय अनुसूची

प्ररूप

प्ररूपों की सूची

प्ररूप संख्या	धारा या नियम	नाम
1	2	3
1	धारा 7	जब असली तथा प्रथम आविष्कारक एकमात्र या संयुक्त आवेदक हो तो पेटेन्ट के लिए आवेदन ।
1क	धारा 7	असली तथा प्रथम आविष्कारक के समनुदेशिती या विधिक प्रतिनिधि द्वारा पेटेन्ट के लिए आवेदन ।
1ख	धारा 7 और 54	जब असली तथा प्रथम आविष्कारक एक मात्र या संयुक्त आवेदक हो तो अतिरिक्त के पेटेन्ट के लिए आवेदन ।
1कख	धारा 7 और 54	असली तथा प्रथम आविष्कारक के समनुदेशिती या विधिक प्रतिनिधि द्वारा अतिरिक्त के पेटेन्ट के लिए आवेदन ।
2	धारा 7 और 135	अभिसमय-देश में आवेदक द्वारा पेटेन्ट के लिए अभिसमय आवेदन ।
2क	धारा 7 और 135	अभिसमय देश में आवेदक के विधिक प्रतिनिधि या समनुदेशी द्वारा पेटेन्ट के लिए अभिसमय आवेदन ।
2ख	धारा 7, 54 और 135	अभिसमय देश में आवेदक द्वारा अतिरिक्त के पेटेन्ट के लिए अभिसमय आवेदन ।
2कख	धारा 7, 54 और 135	अभिसमय-देश में आवेदक के समनुदेशिती या विधिक प्रतिनिधि द्वारा अतिरिक्त के पेटेन्ट के लिए अभिसमय आवेदन ।

1	2	3
3	धारा 10	अनंतिम विनिर्देश ।
3क	धारा 10	सम्पूर्ण विनिर्देश ।
4	धारा 8	विवरण और गोपनीयता ।
5	धारा 9(1),21 (2) या 53(3)	समय बढ़ाने के लिए प्रार्थना ।
6	धारा 10(6)	आविष्कारिता के बारे में घोषणा ।
7	नियम 14(5) और 24	समय बढ़ाने के लिए आवेदन ।
8	धारा 17(1)	अगली तारीख डालने के लिए प्रार्थना ।
9	धारा 20(1)	निर्देश के लिए लोप के लिए आवेदन ।
10	धारा 20(1)	आवेदक या संयुक्त आवेदक के रूप में कार्यवाही करने का दावा ।
11	धारा 20(4)	संयुक्त आवेदक की मृत्यु होने पर पेटेन्ट के लिए आवेदन के संबंध में कार्यवाही चलाने के बारे में निदेश के लिए प्रार्थना ।
12	धारा 20(5)	संयुक्त आवेदकों के बीच विवाद की दशा में पेटेन्ट के लिए आवेदन के संबंध में कार्यवाही चलाने के बारे में निदेशों के लिए आवेदन ।
13	धारा 22	संपूर्ण विनिर्देश की स्वीकृति को मुल्तवी करने के लिए आवेदन ।
14	धारा 25(1) या 28(4)	विरोध की सूचना या पेटेन्ट में आविष्कारक के उल्लेख के लिए प्रार्थना या दावा दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन ।
15	धारा 25	पेटेन्ट अनुदत्त करने के प्रति विरोध की सूचना
16	नियम 44	सुनवाई में हाजिर होने की सूचना ।
17	नियम 48	समय बढ़ाने के लिए आवेदन ।
18	धारा 28(2)	पेटेन्ट में आविष्कारक के उल्लेख के लिए पेटेन्ट के आवेदक द्वारा प्रार्थना ।
19	धारा 28(3)	किसी व्यक्ति द्वारा उसे पेटेन्ट में आविष्कारक के रूप में उल्लिखित करने के लिए दावा ।
20	धारा 28(7)	इस बात के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कि किसी व्यक्ति का आविष्कारक के रूप में उल्लेखन किया जाए ।
21	धारा 39	भारत के बाहर पेटेन्टों के लिए आवेदन करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन ।
22	धारा 43	पेटेन्ट के मुद्रांकन के लिए आवेदन ।
23	धारा 43(3)	पेटेन्ट को मुद्रांकित करने की प्रार्थना करने की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन ।
24	धारा 44	पेटेन्ट के संशोधन के लिए आवेदन ।
25	धारा 51(1)	सहस्वामियों को निदेश देने के लिए प्रार्थना ।
26	धारा 51(2)	सहस्वामियों को उस दशा में निदेश देने के लिए आवेदन जब पेटेन्ट या प्राप्तिकर्ता या स्वत्वधारी नियंत्रक के निदेशों का पालन करने के लिए लिखत को निष्पादित करने में असफल रहे ।
27	धारा 52(2)	पेटेन्ट के प्रतिसंहरण के अर्जीदार को पेटेन्ट अनुदत्त करने के लिए प्रार्थना ।
28	धारा 52(2) परंतुक	अतिरिक्त के पेटेन्ट को स्वतन्त्र पेटेन्ट में संपरिवर्तित करने के लिए प्रार्थना ।
29	धारा 57	पेटेन्ट के लिए आवेदन या सम्पूर्ण विनिर्देश के संशोधन के लिए आवेदन ।
30	धारा 27	संशोधन के आवेदन के प्रति विरोध की सूचना ।
31	धारा 60	पेटेन्ट के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन ।
32	धारा 60	प्रत्यावर्तन के आवेदन के प्रति विरोध की सूचना ।
33	धारा 63	पेटेन्ट के अभ्यर्पण के लिए आवेदन
34	धारा 63	पेटेन्ट अभ्यर्पण की प्रस्थापना के प्रति विरोध की सूचना ।
35	धारा 68	पेटेन्टों के रजिस्टर में दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ।
36	धारा 69 (1)	पेटेन्टों के रजिस्टर में हकदार या आंशिक हकदार के नाम की प्रविष्टि के लिए आवेदन ।
37	धारा 69 (1)	पेटेन्टों के रजिस्टर में बन्धक या अनुज्ञप्ति या अन्यथा हकदार व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि के लिए आवेदन ।
38	धारा 69 (2)	पेटेन्ट या उसके अंश के हकदार व्यक्ति का नाम पेटेन्टों के रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण करने के लिए समनुदेशक द्वारा आवेदन ।
39	धारा 69 (2)	पेटन्टों के रजिस्टर में बंधक, अनुज्ञप्ति या अन्यथा के आधार पर लिखत के लिए बन्धककर्ता या अनुज्ञापक या अन्य व्यक्ति द्वारा आवेदन ।
40	धारा 69	पेटेन्टों के रजिस्टर में दस्तावेज की अधिसूचना की प्रविष्टि के लिए आवेदन ।
41	नियम 78(1)	पेटेन्टों के रजिस्टर में नाम, राष्ट्रिकता, पता या तामील के लिए पते के परिवर्तन के लिए प्रार्थना ।
42	नियम 78(3)	पेटेन्टों के रजिस्टर में तामील के लिए अतिरिक्त पते की प्रविष्टि के लिए प्रार्थना ।
43	धारा 84,96 तथा 87,97	अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन ।
44	धारा 86	पेटेन्टों के पृष्टांकन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा आवेदन ।
45	धारा 89	पेटेन्ट के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन
46	धारा 92 तथा 93(5)	धारा 92 और 93(5) के अधीन आवेदन के प्रति विरोध की सूचना ।
47	धारा 88(2)	धारा 88(2) के अधीन अनुज्ञप्ति के निबंधनों को तय करने के लिए आवेदन ।

1	2	3
48	धारा 88(4)	पेटेन्टकृत आविष्कारों पर काम करने के लिए अनुज्ञा ।
49	धारा 93(5)	अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए आवेदन ।
50	नियम 94	पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ।
51	नियम 102	पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन ।
52	नियम 103	पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर की प्रविष्टि के परिवर्तन के लिए आवेदन ।
53	धारा 78(1)	लिपिकीय गलतियों की शुद्धि के लिए आवेदन ।
54	धारा 78(5)	लिपिकीय गलती की शुद्धि के लिए प्रार्थना के प्रति विरोध की सूचना ।
55	धारा 77(1) (ख)	नियंत्रक के विनिश्चय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन ।
56	धारा 77(1) (छ)	नियंत्रक के आदेश को अपास्त करने के लिए आवेदन ।
57	नियम 115	समय बढ़ाने के लिए प्रार्थना ।
58	नियम 117	धारा 146(2) के अधीन भारत में वाणिज्यिक मापमान पर पेटेन्टकृत आविष्कार का कार्यकरण संबंधी विवरण ।
99	नियम 118	धारा 154 के अधीन पेटेन्ट की दूसरी प्रति के लिए आवेदन ।
60	नियम 119	धारा 72 के अधीन पेटेन्टों के रजिस्टर में प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतियों के लिए तथा धारा 147 के अधीन प्रमाणपत्र के लिए प्रार्थना ।
61	नियम 120	धारा 153 के अधीन पेटेन्ट को या उसके संबंध में आवेदन को प्रभावित करने वाले मामले के बारे में जानकारी के लिए प्रार्थना ।
62	नियम 121	अधिनियम (धारा 127/132) के अधीन कार्यवाही या मामले में पेटेन्ट अभिकर्ता या किसी व्यक्ति के प्राधिकरण का प्ररूप ।

प्ररूप 1

पेटेन्ट अधिनियम, 1970

जब असली और प्रथम आविष्कारक एक मात्र या संयुक्त आवेदक हो तो पेटेन्ट के लिए आवेदन ।

(धारा 7 देखिए)

फीस-पाद-टिप्पण देखिए

(तीन प्रतियों में दाखिल किया जाए तथा प्ररूप 3 पर अनन्तिम विनिर्देश को या प्ररूप 3क पर संपूर्ण विनिर्देश की तीन प्रतियां साथ भेजी जाए) ।

1. आवेदक/आवेदकों का पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए ।

2. आविष्कार का नाम लिखिए ।

3. यह बताइए कि आविष्कारक कौन है ।

4. "(और संपूर्ण विनिर्देश)" शब्दों और कोष्ठकों को काट दीजिए यदि इस प्ररूप के साथ "संपूर्ण" विनिर्देश भेजा जाए ।

मैं/हम .....
.....
एतद्द्वारा घोषित करता हूं/करते हैं :—

(i) कि .....
.....के लिए आविष्कार मेरे/हमारे कब्जे में है;

(ii) कि मैं/हम उक्त..... उसका असली और प्रथम आविष्कारक होने का दावा करता हूं/करते हैं;

(iii) कि इस आवेदन के साथ दाखिल किया गया अनन्तिम/संपूर्ण विनिर्देश (और संपूर्ण विनिर्देश) और कोई संशोधित विनिर्देश जो इस निमित्त इसके पश्चात दाखिल

(iv) कि मैं/हम विश्वास करता हूं/करते हैं कि मैं/हम पेटेन्ट अधिनियम, 1970 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए उक्त आविष्कार के लिए पेटेन्ट का/के हकदार हूं/हैं;

(v) कि इसमें कथित तथ्य और बातें मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में ठीक हैं और यह कि मुझे/हमें इस आवेदन पर पेटेन्ट अनुदत्त करने के प्रति आपत्ति का कोई विधिपूर्ण आधार नहीं है;

मैं/हम निवेदन करता हूं/करते हैं कि उक्त आविष्कार के लिए मुझे/हमें पेटेन्ट अनुदत्त किया जाए ।

मैं/हम निवेदन करता हूं/करते हैं कि इस आवेदन से संबंधित सभी सूचनाएं, अध्यपेक्षाएं और संसूचनाएं..... पर..... को भेजी जाएं ।

तारीख आज 19.....के/की.... के .....दिन

5. आवेदक/आवेदकों द्वारा या यदि आवेदक भारत से अनुपस्थित हों तो प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(हस्ताक्षर)[5].....

सेवा में,
पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय

टिप्पण :—फीस —

(क) 20/—रु० यदि इस प्ररूप के साथ अनन्तिम विनिर्देश भेजा जाए ।

(ख) 50/—रु० यदि इस प्ररूप के साथ संपूर्ण विनिर्देश भेजा जाए ।

[5] जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए ।

प्ररूप 1 क

पेटेन्ट अधिनियम, 1970

फीस-पाद टिप्पण देखिए।

असली और प्रथम आविष्कारक के समनुदेशिती या विधिक प्रतिनिधि द्वारा पेटेन्ट के लिए आवेदन।

(धारा 7 देखिए)

(तीन प्रतियों में दाखिल किया जाए तथा प्ररूप 2 पर अन्तिम विनिर्देश की या प्ररूप 3 क पर संपूर्ण विनिर्देश की तीन प्रतियां साथ भेजी जाएं)।

1. आवेदक या आवेदकों का पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए।

मैं/हम .....

.....

.....

.....

2. आविष्कारक का नाम लिखिए।

एतद्द्वारा घोषित करता हूं/करते हैं :—

(i) कि .....

.....

आविष्कार मेरे/हमारे कब्जे में है;

(ii) कि मैं/हम/उक्त .....

3. ..... का/के समनुदेशिती या विधिक प्रतिनिधि हूं/हैं, जो उसका असली और प्रथम आविष्कारक होने का दावा करता है/करते हैं और जिसका/जिनका विश्वास है कि वह/वे उसका/उसके असली और प्रथम आविष्कारक है/हैं;

3. आविष्कारक का पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए।

(iii) कि इस आवेदन के साथ दाखिल किया गया अन्तिम/संपूर्ण विनिर्देश (और संपूर्ण विनिर्देश) और कोई संशोधित विनिर्देश जो इस निमित्त इसके पश्चात् दाखिल किया जाए, उस आविष्कार का असली विनिर्देश होगा जिसके संबंध में यह आवेदन है;

4 "(और संपूर्ण विनिर्देश)" शब्दों और कोष्ठकों को काट दीजिए यदि इस प्ररूप के साथ संपूर्ण विनिर्देश भेजा जाए।

(iv) कि मैं/हम विश्वास करता हूं/करते हैं कि मैं/हम पेटेन्ट अधिनियम, 1970 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए उक्त आविष्कार के लिए पेटेन्ट का/के हकदार हूं/हैं;

5. आवेदक से/द्वारा या यदि आवेदक भारत से अनुपस्थित है/हैं तो प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(v) कि इसमें कथित तथ्य और बातें मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में ठीक हैं और यह कि मुझे/हमें इस आवेदन पर पेटेन्ट अनुदत्त करने के प्रति आपत्ति का कोई विधिपूर्ण आधार नहीं है;

मैं/हम निवेदन करता हूं/करते हैं कि उक्त आविष्कार के लिए मुझे/हमें पेटेन्ट अनुदत्त किया जाए।

मैं/हम निवेदन करता हूं/करते हैं कि इस आवेदन से संबंधित सभी सूचनाएं, अध्यपेक्षाएं और संसूचनाएं .....

.....

पर .....

.....

को भेजी जाएं।

आज 19.....के/की .....

के ..... दिन

हस्ताक्षर .....

.....

सेवा में,

पेटेन्ट नियंत्रक,

पेटेन्ट कार्यालय।

टिप्पण :—फीस :—

(क) 27 रु० यदि इस प्ररूप के साथ अन्तिम विनिर्देश भेजा जाए।

(ख) 57 रु० यदि इस प्ररूप के साथ संपूर्ण विनिर्देश भेजा जाए।

जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए।

प्ररूप 1क (पश्चात्पृष्ठ)

असली और प्रथम आविष्कारक द्वारा पृष्ठांकन

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए।

मैं/हम .....

.....

2. असली और प्रथम आविष्कारक/आविष्कारकों द्वारा/ हस्ताक्षरित किया जाएगा।

जिन्हें इस आवेदन के दूसरी ओर असली और प्रथम आविष्कारक होने के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, एतद्द्वारा घोषित करता हूं/करते हैं कि जिस/जिन आवेदक/आवेदकों ने इस आवेदन के दूसरी ओर हस्ताक्षर किए हैं, वह/वे मेरा/मेरे/ हमारे समनुदेशिती है/हैं;

तारीख, आज 19..... के/ को .....के

(हस्ताक्षर .....

दो साक्षियों के नाम और पते उनके हस्ताक्षर सहित.

1. .....

2. .....

प्ररूप 1 ख

पेटेन्ट अधिनियम, 1970

फीस-पाद टिप्पण देखिए।

जब असली और प्रथम आविष्कारक एक मात्र या संयुक्त आवेदक हों तो आतरिक्त के पेटेन्ट के लिए आवेदन

(धारा 54 देखिए)

(इसकी 3 प्रतियां तथा प्ररूप 3 पर अन्तिम विनिर्देश की या प्ररूप 3क पर संपूर्ण विनिर्देश की तीन प्रतियां साथ भेजी जाएं)

1. आवेदक या आवेदकों का पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए।

मैं/हम . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

एतद्द्वारा घोषित करता हूं/करते हैं:—

2. आविष्कार का नाम लिखिए।

(i) कि . . . .
. . . .
. . . .
. . . . के लिए आविष्कार मेरे/हमारे कब्जे में है;

3. यह बताइये कि आविष्कारक कौन है/हैं

(ii) कि मैं/हम उक्त . . . . उसका असली और प्रथम आविष्कारक होने का दावा करता हूं। करते हैं;

(iii) कि उक्त आविष्कार उस आविष्कार का एक सुधार या उपान्तरण है जिसके पेटेन्ट के लिए . . . . . .
. . . .
को आवेदन किया गया था और जिसके आवेदन की संख्या . . . . . . थी जिसके लिए मैं/हम आवेदक था/थे और जिसके लिए पेटेन्ट संख्या. . . . तारीख. . . . . अनुदत्त किया गया था और जिसका/जिसके मैं/हम पेटेन्टधारी हूं/हैं।

(iv) कि———————————— इस आवेदन के साथ दाखिल किया गया ———————————अनंतिम । संपूर्ण विनिर्देश (और संपूर्ण विनिर्देश) और कोई संशोधित विनिर्देश जो इस निमित्त इसके बाद दाखिल किया जाए उस आविष्कार का असली विनिर्देश होगा, जिसके संबंध में यह आवेदन है ;

4. "(और संपूर्ण विनिर्देश)" शब्दों और कोष्टकों को काट दीजिए यदि इस प्ररूप के साथ संपूर्ण विनिर्देश भेजा जाए।

(v) कि मैं / हम विश्वास करता हूं / करते हैं कि मैं / हम पेटेन्ट अधिनियम, 1970 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उक्त आविष्कार के लिए पेटेन्ट का / के हकदार हूं / है ;,

5. आवेदक या आवेदकों द्वारा या यदि आवेदक भारत से अनुपस्थित है / हैं तो प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।

(vi) कि इसमें कथित तथ्य और बातें मेरी / हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में ठीक हैं और यह कि मुझे / हमें इस आवेदन पर पेटेन्ट अनुदत्त करने के प्रति आपत्ति का कोई विधिपूर्ण आधार नहीं है ;

मैं / हम निवेदन करता हूं / करते हैं कि मुझे / हमें उक्त आविष्कार के लिए पेटेन्ट सं०————————के अतिरिक्त के पेटेन्ट के रूप में अनुदत्त किया जाए। पेटेन्ट आवेदन सं०——— पर अनुदत्त किया जाएगा ।

मैं / हम प्रार्थना करता हूं / करते हैं कि इस आवेदन से संबंधित सब सूचनाएं, अध्यपेक्षाएं और संसूचनाएं——————पर————————————को——————भेजी जाएं ।

तारीख, आज 19———के / की——————के——————दि

सेवा में, ——————(हस्ताक्षरित)
पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय

टिप्पण—फीस—

(क) 27 रु० यदि इस प्ररूप के साथ अनंतिम विनिर्देश भेजा जाए।

(ख) 58 रु० यदि इस प्ररूप के साथ संपूर्ण विनिर्देश भेजा जाए ।

जो लागू नहीं होता उसे काट दिजिए।

प्ररूप 1 कख

पेटेन्ट अधिनियम, 1970

फीस—पाद टिप्पण देखिए

असली और प्रथम आविष्कारक के समनुदेशिती या विधिक प्रतिनिधि द्वारा अतिरिक्त के पेटेन्ट के लिए आवेदन
(धारा 54 देखिए)
(तीन प्रतियों में दाखिल किया जाए तथा प्ररूप 3 पर अनन्तिम विनिर्देश की या प्ररूप 3क पर संपूर्ण विनिर्देश की तीन प्रतियां साथ भेजी जाएं)

1 आवेदक या आवेदकों का पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए ।

मैं / हम——————————————
एतद्द्वारा घोषित करता हूं/करते हैं:—

(i) कि——————————————के[2] लिए आविष्कार मेरे/हमारे कब्जे में है ;

2 आविष्कार का नाम लिखिए।

(ii) कि मैं/हम / उक्त 3——————————को / के समनुदेशिती या विधिक प्रतिनिधि हूं / हैं, जो उसका असली और प्रथम आविष्कारक होने का दावा करता है / करते हैं और जिसका/जिनका विश्वास है कि वहां वे उसका उसके असली और प्रथम आविष्कारक है / हैं ;

3 नाम लिखिए।

(iii) कि उक्त आविष्कार उस आविष्कार का एक सुधार या उपान्तरण है जिसके पेटेन्ट के लिए—————— को आवेदन किया गया था और जिसके आवेदन की सं०—————— थी जिसके लिए मैं/हम आवेदक था / थे

4. बताइये कि आविष्कारक कौन है/हैं ।

और जिसके लिए पेटेन्ट सं०———तारीख————अनुदत्त किया गया था और जिसका/जिसके मैं / हम पेटेन्टधारी हूं / हैं ।

(iv) कि————हम आवेदन के साथ दाखिल किया गया————अन्तिम / संपूर्ण विनिर्देश (और संपूर्ण विनिर्देश) और कोई संशोधित विनिर्देश जो इस निमित्त इसके बाद दाखिल किया जाए उस आविष्कार का असली विनिर्देश होगा जिसके संबंध में यह आवेदन है ;

5. "(और संपूर्ण विनिर्देश)" शब्द और कोष्टकों को काट दीजिए यदि इस प्ररूप के साथ "संपूर्ण विनिर्देश" भेजा जाए ।

(v) कि मैं/हम विश्वास करता हूं / करते हैं कि मैं/हम पेटेन्ट अधिनियम, 1970 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उक्त आविष्कार के लिए पेटेन्ट का /के हकदार हूं/हैं ;

(vi) कि इसमें कथित तथ्य और बातें मेरी / हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में ठीक हैं और यह कि मुझे/हमें इस आवेदन पर पेटेन्ट अनुदत्त करने के प्रति आपत्ति का कोई विधिपूर्ण आधार नहीं है ;

मैं/हम निवेदन करता हूं/करते हैं कि मुझे हमें उक्त आविष्कार के लिए पेटेन्ट सं०————के अतिरिक्त के पेटेन्ट के रूप में अनुदत्त किया जाए / पेटेन्ट आवेदन सं०————पर अनुदत्त किया जाएगा ।

मैं/हम प्रार्थना करता हूं/करते हैं कि इस आवेदन से संबंधित सब सूचनाएं, अभ्यपेक्षाएं और संसूचनाएं————पर————को भेजी जाएं ।

तारीख आज 19————के/की————के————दिन

(हस्ताक्षर)[6]————

6. आवेदक/आवेदकों द्वारा या यदि आवेदक भारत से अनुपस्थित हो तो प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं ।

सेवा में,
पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय ।

टिप्पण : फीस—

(क) 20 रु० यदि इस प्ररूप के साथ अन्तिम विनिर्देश भेजा जाए ।

(ख) 50 रु० यदि इस प्ररूप के साथ संपूर्ण विनिर्देश भेजा जाए ।

जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए।

प्ररूप 1 कल्प (पश्चात्पृष्ठ)

असली और आविष्कारक द्वारा पृष्ठांकन

1 पूरा नाम, पता राष्ट्रिकता लिखिए

मैं/हम————जिन्हें हम आवेदन के दूसरी ओर असली और प्रथम आविष्कारक होने के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, एतद्द्वारा घोषित करता हूं /करते हैं कि जिस / जिन आवेदक/आवेदकों ने इस आवेदन के दूसरी ओर हस्ताक्षर किए हैं यह/वे, मेरा/हमारे समनुदेशिती है/हैं ।

2 असली और प्रथम आविष्कारक आविष्कारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं ।

तारीख आज 19————के/की————के————दिन

(हस्ताक्षर) ————

दो साक्षियों के, उनके नाम, और पते सहित हस्ताक्षर

1. ————
2. ————

पेटेन्ट अधिनियम, 1970

प्ररूप 2

पेटेन्ट के लिए अभिसमय आवेदन

फीस 50 रुपये

(धारा 7 और 135 देखें)

(प्ररूप 3क पर संपूर्ण विनिर्देश की 3 प्रतियां साथ भेजी जाएं)

1. आवेदक या आवेदकों का (पूरा) नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए ।

मैं (या हम) [1]————एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं:—

(i) कि————[3] के लिए आविष्कार पे मेरा (या हमारा) कब्जा है,

2. आविष्कार का नाम लिखिए ।

3. उस अभिसमय देश का नाम लिखिए जहां प्रथम आवेदन किया गया था ।

(ii) कि मैंने/हमने निम्नलिखित देश या देशों और निम्नलिखित अधिकृत तारीख या तारीखों को आविष्कार या आविष्कारों के संरक्षण के लिए आवेदन किया है/किए हैं, अर्थात————[3] में————[4] को————[5] के लिए————[3] में————[4] को————[5] के लिए,

4. अभिसमय देश/देशों में प्रथम आवेदन/आवेदनों की अधिकृत तारीख/तारीखें लिखिए ।

और यह कि उक्त आवेदन या उक्त आवेदनों में से प्रत्येक उक्त आविष्कार की बाबत अभिसमय देश/देशों में प्रथम आवेदन था/ थे।

5. नाम लिखिए ।

(iii) कि इस आवेदन के साथ दाखिल किया गया संपूर्ण विनिर्देश और कोई संशोधित विनिर्देश जो इस निमित्त इसके पश्चात् दाखिल किया जाए उस आविष्कार का असली विनिर्देश होगा जिसके संबंध में यह आवेदन है,

(iv) कि मैं/हम विश्वास करता हूं/करते हैं कि मैं (हम) पेटेन्ट अधिनियम, 1970 के उपबंधों को ध्यान रखते हुए उक्त आविष्कार के पेटेन्ट के लिए हकदार हूं/हैं।

(v) कि इसमें कथितलथ्य और बातें मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास में सही हैं और यह कि मझ/हम इस आवेदन पर पेटेन्ट अनुदत्त करने के प्रति आपत्ति का कोई विधिपूर्ण आधार नहीं है ।

मैं (हम) निवेदन करता हूं/करते हैं कि अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन अभिसमय देश/देशों में ऊपर वर्णित आवेदन (आवेदनों) पर आधारित पूर्विकता के साथ उक्त आविष्कार के लिए पेटेन्ट अनुदत्त किया जाए ।

6 आवेदकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं या यदि आवेदक भारत से अनुपस्थित है। अनुपस्थित है/हैं तो किसी प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा।

मैं/हम प्रार्थना करता हूं/करते हैं कि इस आवेदन से संबंध सूचनाएं, अध्यपेक्षाएं और संसूचनाएं ———— ————को————पर भेजी जाएं ।

आज तारीख 19————के/की———— के————दिन————

(हस्ताक्षरित)[6]

सेवा में,

पेटेन्ट नियंत्रक,

पेटेन्ट कार्यालय ।

जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए ।

प्ररूप 2क

पेटेन्ट अधिनियम, 1970

फीस 50 रुपये

अभिसमय देश में आवेदक को समनुदेशिती या विधिक प्रतिनिधियों द्वारा पेटेन्ट के लिए अभिसमय आवेदन (धारा 7 और 135 देखिए)

(तीन प्रतियों में दिया जाए तथा प्ररूप 3क पर संपूर्ण विनिर्देश की तीन प्रतियां साथ भेजी जाएं)

1 आवेदक(ों) का (पूरा) नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए ।

मैं (हम)[1] ————————————————

एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं:—

2 आविष्कार का नाम लिखिए।

(i) कि————के लिए आविष्कार मेरे/हमारे कब्जे में है,

3 जिस अभिसमय देश(ों) में प्रथम आवेदन किया गया था/किए गये थे उसका नाम लिखिए।

(ii) कि आविष्कार (ों) के संरक्षण के लिए आवेदन निम्नलिखित देश या देशों में और निम्नलिखित अधिकृत तारीख या तारीखों को किया गया है या किए गये हैं, अर्थात्:—

4 अभिसमय देश(ों) में प्रथम आवेदन(ों) की अधिकृत तारीखों/तारीखें लिखिए ।

————————[5]————————[6]

————द्वारा————————[4]को

————————[3]में ।

5 आवेदकों का नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए।

————————[6] के लिए————[5]

द्वारा————————————[4] को

————————————[3] में ।

6 नाम लिखिए।

7 अभिसमय देश(ों) में आवेदक(ों) का नाम, पता, और राष्ट्रिकता लिखें।

————————————[6] के लिए

————————[5] द्वारा————[4]को

————————[3] में

और यह कि उक्त आवेदक या उक्त आवेदनों में से प्रत्येक आवेदन उक्त———— ————द्वारा सुसंगत आविष्कार की बाबत अभिसमय देश(ों) में प्रथम आवेदन था/थे ।

(iii) कि मैं/हम ————————[7] मृतक के विधिक प्रतिनिधि या समनुदेशिती हूं/हैं ।

(IV) कि इस आवेदन के साथ दाखिल किया गया संपूर्ण विनिर्देश और कोई संशोधित विनिर्देश जो इस निमित्त इसके पश्चात् फाइल किया जाय उस आविष्कार का जिसके संबन्ध में यह आवेदन है, असली विनिर्देश होगा ।

(V) कि मैं/हम विश्वास करता हूं/करते हैं कि मैं/हम पेटेन्ट अधिनियम, 1970 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए उक्त आविष्कार के लिए पेटेन्ट का/के हकदार हूं/हैं;

(VI) कि इसमें कथित तथ्य और बातें मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास से सही हैं और यह कि मुझे / हमें इस आवेदन पर पेटेन्ट अनुदत्त करने के प्रति आक्षेपों का विधिपूर्ण आधार नहीं हैं ।

8. आवेदक(ों) द्वारा या यदि आवेदक भारत से अनुपस्थित है/हैं तो प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

मैं/हम निवेदन करता हूं । करते हैं कि मुझे/हमें उक्त अविष्कार के लिए पेटेन्ट अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अधीन अभिसमय देश/देशों में ऊपर वर्णित आवेदन (ों) पर आधारित पूर्विकता से अनुदत्त किया जाएं ।

मैं/हम प्रार्थना करता हूं/करते हैं कि इस आवेदन से सम्बन्ध सब सूचनाएं, अध्यपेक्षाएं और संसूचनाएं ———— पर————————को भेजी जाएं।

तारीख आज ————————19————

के/की ————————————के————दिन

————————हस्ताक्षर

सेवा में,

पेटेन्ट नियंत्रक,

पेटेन्ट कार्यालय

जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए ।

प्ररूप 2 क (पश्चात्पृष्ठ)

अभिसमय देश में आवेदक द्वारा पृष्ठांकन

1. (पूरा) नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए।	इस आवेदन के दूसरी ओर पैरा (ii) में विनिर्दिष्ट देश (ों) में आवेदक होने का दावा करने वाले के रूप में निर्दिष्ट मैं/हम 1——————एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि जिन आवेदक/
2. अभिसमय देश (ों) में आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।	आवेदकों ने दूसरी ओर इस आवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं वह/वे मेरा/मेरे, हमारा/हमारे समनुदेशिती है/हैं।

तारीख आज 19——————के/की ——————के ——————दिन

——————(हस्ताक्षर)[2]

दो शाक्षियों के, उनके नाम और पता सहित हस्ताक्षर

1——————

2——————

प्ररूप 2ख फीस 50 रुपये

फीस 50 रुपये

प्ररूप 2ख

अतिरिक्त के पेटेन्ट के लिए अभिसमय आवेदन

(धारा 7, 54 और 135 देखिये)

(तीन प्रतियों में दिया जाए तथा प्ररूप 3क पर संपूर्ण विनिर्देश तीन की प्रतियां साथ भेजी जाएं)

1. आवेदक (ों) का (पूरा) नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिये।	मैं/हम 1—————————————— एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं :—
2. आविष्कार का नाम लिखिए	(i) कि ——————2 के लिए आविष्कार मेरे/हमारे कब्जे में हैं,
3. उस अभिसमय देश (ों) का नाम, लिखिए जिसमें प्रथम आवेदन किया गया था/किए गये थे।	(ii) कि मैंने/हमने आविष्कार या आविष्कारों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित देश या देशों में और निम्नलिखित अधिकृत तारीख या तारीखों को आवेदन किया है या किए हैं, अर्थात्:—
4. अभिसमय देश (ों) में प्रथम आवेदन (ों) की अधिकृत तारीख/तारीखें लिखिए।	——————5 के लिए——————4 को ——————3 में ——————5 के लिए ——————4 को——————3 में ——————5 के लिए ——————4 को ——————3 में
5. नाम लिखिए।	और यह कि उक्त आवेदन या उक्त आवेदनों में से प्रत्येक आवेदन उक्त आविष्कार की बाबत अभिसमय देश (ों) में प्रथम आवेदन था/थे;

(iii) कि उक्त आविष्कार उस आविष्कार में सुधार या उपान्तरण है जिसके पेटेन्ट के लिए ——————को और आवेदन संख्या —————— आवेदन किया था जिसके लिए मैं/हम आवेदक था/थे जिसके लिए —————— तारीख——————संख्यांकित पेटेन्ट अनुदत्त किया गया था और जिसका मैं/हम पेटेन्ट धारी हूं/हैं;

(iv) कि हम आवेदन के साथ दाखिल किया गया पूरा विनिर्देश और कोई संशोधित विनिर्देश जो इसके पश्चात् इस निमित्त दाखिल किया जाय उस आविष्कार का असली विनिर्देश होगा जिसके संबंध में यह आवेदन हैं ;

(v) कि मैं/हम विश्वास करते हैं कि मैं/हम पेटेन्ट अधिनियम, 1970 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए उक्त आविष्कार के पेटेन्ट के लिए हकदार हूं/हैं ;

(vi) कि इस में कथित तथ्य और बातें मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास से सही हैं और यह कि मुझे/हमें इस आवेदन पर पेटेन्ट अनुदत्त करने के प्रति आक्षेपों का विधिपूर्ण आधार नहीं हैं।

6. आवेदक (ों) द्वारा या यदि आवेदक भारत से अनुपस्थित है/हैं तो प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।	मैं/हम निवेदन करता हूं/करते हैं कि उक्त आविष्कार के लिए मुझे पेटेन्ट अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन अभिसमय देश/देशों में ऊपर वर्णित आवेदन/आवेदनों पर आधारित पूर्विकता से अनुदत्त किया जाए, यह पेटेन्ट संख्या ——————आवेदन सं० —————— पर अनुदत्त पेटेन्ट से अतिरिक्त होगा।

मैं/हम प्रार्थना करता हूं/करते हैं कि इस आवेदन से सम्बद्ध सब सूचनाएं अध्यपेक्षाएं और संसूचनाएं —————— ——————पर—————— को भेजी जाएं।

तारीख आज 19 ——————के/की —————— के ——————दिन

——————[6] (हस्ताक्षर)

सेवा में,

पेटेन्ट नियंत्रक,

पेटेन्ट कार्यालय।

जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए।

प्ररूप 2 कख

फीस 50 रुपये

पेटेन्ट अधिनियम, 1970

अभिसमय देश में आवेदक के विधिक प्रतिनिधियों पर समनुदेशिती द्वारा पेटेन्ट के अतिरिक्त के लिए अभिसमय आवेदन।

(धारा 7, 54 और 135 देखिए)

(तीन प्रतियों में दिया जाए तथा प्ररूप 3क पर संपूर्ण विनिर्देश की तीन प्रतियां साथ भेजी जाएं)

1. आवेदकों का नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए। — मैं / हम [1]———— एतद्द्वारा घोषित करता हूं/करते हैं :—

2. आविष्कार का नाम लिखिए। — (i) कि——----2 के आविष्कार पर मेरा / हमारा कब्जा है।

3. उस अभिसमय (देशों) का नाम लिखिए जिसमें प्रथम आवेदन किया गया था / किये गये थे। — (ii) कि आविष्कार या आविष्कारों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित देश(ों) में और निम्नलिखित अधिकृत तारीख / तारीखों को आवदन किया गया है या किए गए हैं अर्थात् :—

4. अभिसमय देश(ों) में आवदन(ों) की अधिकृत तारीख / तारीखें लिखिए। — --————6 के लिए-----5 द्वारा—-- ——3में———— 6 के लिए ————5द्वारा——--4को——3में,

5. आवदक(ों) का नाम पता और राष्ट्रिकता लिखिए। — और यह कि उक्त आवेदन(ों) में से प्रत्येक आवेदन उक्त आविष्कार की बाबत अभिसमय देश(ों) में प्रथम आवेदन था / थे।

6. नाम लिखिए। — (iii) कि------ 7क———मृतक।

7. अभिसमय देश(ों) में आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए — समनुदेशिती का / के मैं / हम विधिक प्रतिनिधि हूं / हैं।

(iv) कि उक्त आविष्कार उस आविष्कार में सुधार या उपान्तरण है जिसके पेटेन्ट के लिए------- को और आवेदन सं०———आवेदन किया था जिसके लिए मैं / हम आवेदक था / थे। जिसके लिए तारीख——का———-संख्यांकित पेटेंट अनुदत्त किया गया था और जिसका मैं / हम पेटेन्टधारी हूं / हैं।

(v) कि इस आवेदन के साथ दाखिल किया गया संपूर्ण विनिर्देश और कोई संशोधित विनिर्देश जो इसके साथ पश्चात् इस निमित्त दाखिल किया जाए, उस आविष्कार का असली विनिर्देश है या जिसके संबंध में यह आवेदन है;

(vi) कि मैं / हम विश्वास करते हैं कि मैं / हम पेटेन्ट अधिनियम 1970 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए उक्त आविष्कार में पेटेन्ट के लिए हकदार हूं / हैं।

(vii) कि इस में कथित तथ्य और बातें मेरे / हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास से सही हैं और यह कि मुझे / हमें इस आवेदन पर पेटेन्ट अनुदत्त करने के प्रति आक्षेपों का विधिपूर्ण आधार नहीं है।

8. आवेदक(ों) द्वारा या यदि आवेदक भारत से अनुपस्थित है। तो प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाए — मैं / हम निवेदन करता हूं / करते हैं कि उक्त आविष्कार के लिए मुझे पेटेन्ट अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन अभिसमय देश / देशों में ऊपरवर्णित आवेदन / आवेदनों पर आधारित पूर्विकता से अनुदत्त किया जाए, यह पेटेन्ट सं०------आवेदन सं०---- पर अनुदत्त पेटेन्ट से अतिरिक्त होगा। मैं / हम प्रार्थना करता हूं। करते हैं कि इस आवेदन से सम्बद्ध सब सूचनाएं, अध्यपेक्षाएं और संसूचनाएं ——--पर------को भेजी जाएं

तारीख 19------के / की------

के——————-दिन

————8 (हस्ताक्षर)

सेवा में

पेटेन्ट नियंत्रक

पेटेन्ट कार्यालय

प्ररूप 2कख (पश्चातपृष्ठ)

अभिसमय देश में आवेदक द्वारा पृष्ठांकन

1. पूरा नाम पता और राष्ट्रिकता लिखिए। — इस आवेदक के दूसरी ओर पैरा (ii) में विनिर्दिष्ट देश (ों) में आवेदक होने का दावा करने वाले के रूप में निर्दिष्ट मैं / हम----- एतद्द्वारा घोषणा करता हूं / करते हैं कि जिन आवेदक(ों) ने दूसरी ओर इस आवेदन पर

2. अभिसमय देश(ों) — हस्ताक्षर किए हैं वह / वे मेरा / मेरे / हमारा / हमारे समनुदेशिती है / हैं।

2. अभिसमय देश(ों) में आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए। — तारीख 19-----के / की------ के------के-दिन दिन।

———--- हस्ताक्षर

दो साक्षियों के उनके नाम और पता सहित हस्ताक्षर

1. ------------------

2. ------------------

पेटेन्ट अधिनियम 1970 अनंतिम विनिर्देश

प्रपत्र 3

कोई फीस नहीं

पेटेन्ट अधिनियम 1970 अन्तिम विनिर्देश
(धारा 10 देखिए)

(प्रपत्र सं० 1 1क, ख, या 1 कख में आवेदन के साथ तीन प्रतियों में भेजा जाए)

1. नाम लिखिए जैसा कि आवेदन पत्र में है। — 1. ---------------------

2. आवेदक(कों) का पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए जैसा कि आवेदन पत्र में हैं। — 2. ----------------------

3. यहां आविष्कार के स्वरूप का वर्णन आरम्भ करें। विनिर्देश अगर कागज के केवल एक ओर उसकी बाईं तरफ डेढ़ इंच या 4 से० मी० का हाशिया छोड़कर उसी आकार के कागज पर जारी रहना चाहिए। — (3) निम्नलिखित विनिर्दिष्ट में इस आविष्कार का स्वरूप वर्णित है :-

विनिर्देश और उसकी दो प्रतियां पर अन्त में हस्ताक्षर तथा इस प्रकार से तारीख देनी चाहिए :-

"तारीख आज 19-----------के / की .... के---दिन"

कर

प्रपत्र 3 क

फीस 30 रुपये।

पेटेन्ट अधिनियम, 1970

जबकि आवेदन के साथ अन्तिम विनिर्देश लगा हो।

संपूर्ण विनिर्देश
(धारा 10 देखिये)

कोई फीस नहीं जबकि आवेदन के साथ यह प्रपत्र भेजा गया हो।

(प्रपत्र सं० 2, 2क, 2ख या 2कख में आवेदन के साथ तीन प्रतियों या यदि अन्तिम विनिर्देश उसके साथ न हो तो प्रपत्र सं० 1, 1क, 1ख या 1कख में आवेदन के साथ भेजे जायें) जब एक या अधिक आवेदनों के साथ एक या अधिक अन्तिम विनिर्देश लगाये गये हों तो उसकी (उसकी) संख्या और तारीख लिखिये।

1. नाम लिखिये जैसा कि आवेदन पत्र में हैं।

2. आवेदक या आवेदकों का (पूरा) नाम, पता और राष्ट्रियकता लिखिये जैसा कि आवेदन पत्र में हैं।

संख्या	तारीख
(1)-----------	-----------
(2)-----------	-----------
(3)-----------	-----------

3. यहां आविष्कार का पूर्ण वर्णन आरम्भ कीजिये। विनिर्देश की रचना कागज के केवल एक ओर उसकी बाईं तरफ डेढ़ इंच या 4 सें० मी० का हाशिया छोड़कर उसी आकार के कागज पर होनी चाहिये। संपूर्ण विनिर्देश के पश्चात "मैं / हम दावा करते हैं" शब्द होने चाहिये जिनके बाद क्रमवर्तीरूप से संख्या किये दावा या दावे दिये जाने चाहिये। विनिर्देश और उसकी दो प्रतियां अंत में हस्ताक्षरित और इस प्रकार दिनांकित होनी चाहिये :—

(निम्नलिखित विनिर्देश विशिष्टतया इस आविष्कार के स्वरूप को और उस रीति को जिसमें यह क्रियान्वित किया जाना है वर्णित और अभिनिश्चित करता है।

तारीख आज 19---------के/की---------------के---------दिन

प्रपत्र 4

कोई फीस नहीं

पेटेन्ट अधिनियम, 1970

धारा 8 के अधीन विवरण और वचनबन्धकता।

(नियम 13 देखिये)

1. आवेदकों का नाम और पता राष्ट्रियकता बताइये — मैं/हम-------------------1 जिसने (जिन्होंने----------------2 से सम्बद्ध अपने आविष्कार के लिये

2. आविष्कार का नाम बताइये। — पैटेन्ट के लिये आवेदन संख्या ------ -----------तारीख ---------किया है, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं :—

3 उस व्यक्ति का जिसकी मार्फत आवेदक दावा करता है या उस व्यक्ति का जो आवेदक(कों) से हक प्राप्त करता है नाम, राष्ट्रियकता और पता बताइये। — (i) कि एकाकी/संयुक्त रूप में------ ---------3 के जिसकी मार्फत हम उक्त आवेदन करने के हक का दावा करते हैं जो उक्त आविष्कार में मुझ से/हमसे हक प्राप्त करते हैं मैंने/हमने --------------- निम्नलिखित देशों में उसी आविष्कार के लिये पेटेन्ट(टों) के लिये आवेदन किया है, किये हैं ;

4. उस देश, संख्या और तारीख को बताइये जिसमें पेटेन्ट के लिये तदनुरूप आवेदन भारत के बाहर दाखिल किया गया है। — (क) ------------------- 4
(ख)------------------- 4
(ग)------------------- 4

(ii) कि उक्त आवेदन स्वीकार, अस्वीकार, परित्य परित्यक्त, वापिस कर लिया गया है : लिये गये हैं।

(iii) कि ऐसे आवेदन(नों) पर निम्नलिखित पेटेन्ट अनुदत्त किया गया है/किये गये हैं।

5. पेटेन्टों तथा देश(शों) की संख्या और अधिकृत तारीख बताइये। — (क) ---------------- 5
(ख) ---------------- 5
(ग) ---------------- 5

(iv) कि आवेदन में हक--------- --को समनुदेशित कर दिये हैं।

(v) कि मैं/हम वचन करता हूं/करते हैं हैं कि मेरे/हमारे ऊपर वर्णित आवेदन के संबंध में दाखिल किये गये पूर्ण विनिर्देश के प्रतिग्रहण की अवस्था तक में/हम उन पेटेन्टों के आवेदनों सम्बन्धी ब्योरों से, जो उसी या सारतः उसी आविष्कार के लिये समय समय पर भारत के बाहर किये गये हैं ।

6. समनुदेशिती का/के नाम और पता बताइये ।

ऐसे आवेदन दाखिल करने की तारीख से तीन मास के भीतर नियंत्रक को समय-समय पर लिखित रूप में अवगत कराता रहूंगा/कराते रहेंगे;

7. आवेदक(कों) उस (उन) से प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता के हस्ताक्षर ।

(vi) कि इसमें कथित तथ्य और बातें मेरे/हमारे ज्ञान, जानकारी और विश्वास में सत्य हैं ।

तारीख आज 19————के/की ————के ————दिन

———— 6(हस्ताक्षर)

सेवा में,
पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय

जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिये ।

प्ररूप 5

पेटेन्ट अधिनियम, 1970
धारा 9(1) के अधीन समय बढ़ाने के लिये प्रार्थना

फीस 25रु० प्रतिमास

(धारा 9(1)/21(2) और 53(3) देखिये)

1. नाम,पता और राष्ट्रिकता बताइये ।

मैं/हम 1————

————

एतद्द्वारा———— मास का समय बढ़ाने के लिये प्रार्थना करता हूं/करते हैं ।

2. उन शब्दों को काट दीजिये जो लागू न होते हैं ।

2(क)———— के आवेदन सं०————की बाबत संपूर्ण विनिर्देश के लिये धारा 9(1) के अधीन

(ख) ———— के मेरे/हमारे आवेदन सं०————की मंजरी के लिये दाखिल करने के लिये धारा 21(2) के अधीन

(ग)———— वर्ष के लिये पेटेन्ट सं०———— तारीख———— पर नवीकरण फीस संदत्त करने के लिये धारा 53(3) के अधीन,

इस आवेदन को करने के निम्नलिखित कारण हैं :—

3. आवेदक (कों) या उसके (उन के) प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किये जायें।

भारत में तामील के लिये मेरा/हमारा पता निम्नलिखित है :—

————

————

तारीख आज 19————के/की ————के ————दिन

3(हस्ताक्षर) ————

सेवा में,
पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय।

पेटेन्ट अधिनियम, 1970

प्ररूप 6

आविष्कारिता के बारे में घोषणा

फीस कोई नहीं

(नियम 14(5) देखिए)

1. आवेदक(कों) का/के नाम लिखिए

मैं/हम 1———— एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे आवेदन संख्या ————

2. आविष्कारक का या हर आविष्कारक का नाम, पता और राष्ट्रियता बताइए

तारीख ———— के अनुसरण में दाखिल किए गए पूर्ण विनिर्देश में व्यक्त आविष्कार का/के असली और प्रथम आविष्कारक———— है/हैं;

2. ————
————
————
————

3. इसे न भरा जाए, यदि 2 पर आविष्कारक का/के नाम वाला /वाले आवेदक है या हैं, यदि अधिकार वैसा है/हैं जैसा कि आवेदन पत्र में उल्लिखित किया गया है।

और यह कि मेरा/हमारा आविष्कार के पेटेन्ट के लिए आवेदन करने का अधिकार निम्न प्रकार है/हैं :—
————
————
————

तारीख आज 19————के/की————

4. आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

के———— दिन

4(हस्ताक्षर) ————

————

अभिसमय आवेदन की दशा के सिवाय, यदि ऊपर 2 पर आविष्कारक के रूप में लिखित किसी व्यक्ति का नाम, आवेदन में या आवेदनों में से किसी में इस प्रकार नहीं लिखा जाता है, तो उसे निम्नलिखित कथन पर हस्ताक्षर करने होंगे ।

मैं उपरोक्त घोषणा में निर्दिष्ट आविष्कार के उल्लिखत आवेदन (ों) के अनुसरण में दाखिल किए गए पूर्ण विनिर्देश में सम्मिलित किए जाने की अनुमति देता हूं।

5. आविष्कारक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए। (हस्ताक्षर) 5 ——————

सेवा में,

पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय

जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए।

प्ररूप 7

फीस 25 रु० प्रतिमास

पेटेन्ट अधिनियम, 1970

समय बढ़ाने के लिए आवेदन

(नियम 14(5) और 24 देखिए)

पेटेन्ट के लिए या——————के तारीख ——————के पेटेन्ट सं० ——————के लिए आवेदन

1. नाम पता और राष्ट्रकता बताइए। मैं/हम 1——————एतद्द्वारा —————— मास(ों) का (की) समय बढ़ाने के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं :—

2. आवेदक/आवेदकों या उसका या उनके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किए जाए।

(क) नियम 14(5) के अधीन आविष्कारिता की घोषणा दाखिल करने के लिए;

(ख) धारा 13 (1) (ख) या धारा 19(1) के अधीन आपत्ति को हटाने के लिए;

(ग) विनिर्देश के संशोधन का निर्देश के अन्तः स्थापन का करार अधिसूचित करने के लिए।

तारीख. आज 19——————के/की ——————के ——————दिन

सेवा में,

पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय

जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए।

प्ररूप 8

फीस 30 रुपये

पेटेन्ट अधिनियम, 1970

अगली तारीख डालने के लिए प्रार्थना

(धारा 17(1) देखिए)

मैं/हम ——————एतद्द्वारा प्रार्थना करता हूं/करते हैं कि 19—————— के/की —————— के—————— दिन को दाखिल किया गया आवेदन संख्या ——————निम्नलिखित तारीख पर किया गया समझा जाए, अर्थात् :—

19 ——————के/की —————— के ——————को।

तारीख आज 19 ——————के/की—————— के —————— दिन

1. आवेदकों या प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए। हस्ताक्षर के नीचे आवेदकों का पता और राष्ट्रिकता भी लिखिए।

——————1 (हस्ताक्षर)
——————
——————
——————

सेवा में,

पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय।

प्ररूप 9

फीस 25 रुपये

पेटेन्ट अधिनियम, 1970

निर्देश के लोप के लिए धारा 19(2) के अधीन आवेदन।

(नियम 28 देखिये)

1. आवेदकों का पूरा नाम और पता लिखिए। मैं/हम 1 ——————
——————
——————

एतद्द्वारा पेटेन्ट सं०——————के निर्देश के लोप के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं, जो धारा 19(1) के अधीन निर्देश के अनुसरण में मेरे या हमारे पेटेन्ट सं० —————— (के लिए आवेदन) के संपूर्ण विनिर्देश में अन्तः स्थापित किया गया है।

इस आवेदक के समर्थन में जिन तथ्यों पर निर्भर किया गया है, वे ये हैं :—
——————
——————
——————

तारीख आज 19 ——————के/की —————— के ——————दिन

2. आवेदक/आवेदकों या उसके या उनके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए। (हस्ताक्षरी) 2 ——————
——————
——————

सेवा में,

पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय।

जो लागू नहीं होता, उसे काट दीजिए।

प्ररूप 10

फीस 25 रु०

पेटेन्ट अधिनियम, 1970

अग्र

आवेदक या संयुक्त-आवेदक के रूप में कार्यवाही करने के लिए धारा 20(1) के अधीन दावा

1. दावेदारों का नाम, पता और राष्ट्रिकता बताइए। मैं/हम 1 ——————
——————

एतद्द्वारा निवेदन करता हूं/करते हैं कि ——————
—————— द्वारा

2. पेटेन्ट के लिए आवेदक। आवेदकों का नाम बताइऐ।	2 किए गए आवेदन सं०————— तारीख ——— ———
3. उस व्यक्ति/उन व्यक्तियों का पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए जिसके/जिनके नाम में आवेदन पर कार्यवाही चलाने का निवेदन किया गया है	3 के नाम में कार्यवाही आगे चलाई जाए। मैं/हम दावा करता हूं/करते हैं कि 4————— ————————— के आधार पर पेटेन्ट के लिए आवेदक (आवेदकों) के रूप में कार्यवाही चलाने के लिए हकदार हूं/हैं।
4. ऐसे दस्तावेज की तारीख और उसके पक्षकारों की विशिष्टियां दीजिए और यह दीजिए कि यहां किया गया दावा किस प्रकार सिद्ध किया गया है।	और जिसके सबूत में मैं/हम आवेदन के के साथ 5——————— प्रेषित करता हूं/करते हैं। भारत में तामील के लिए मेरा/हमारा पता निम्नलिखित हैं :
5. दस्तावेज के स्वरूप के बारे में बताइए (प्रतिलिपि)	
	तारीख आज 19 ————————के/की———————के———————दिन
6. दावेदार/दावेदारों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।	हस्ताक्षर[6] ————————————
7. आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रिकता बताइए।	मैं/हम[7] ——————————— उपर्युक्त प्रार्थना की सहमति देता हूं/देते हैं।
8. आवेदक/आवेदकों या प्राधिकृत अधिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।	(हस्ताक्षर)[8] ——————— सेवा में, पेटेन्ट नियंत्रक, पेटेन्ट कार्यालय।

जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए।

प्ररूप 11 — पेटेन्ट अधिनियम, 1970

फीस 25 रु०

संयुक्त आवेदक की मृत्यु होने की दशा में पेटेन्ट के आवेदन पर कार्यवाही चलाने के बारे में धारा 20(4) के अधीन निदेशों के लिए प्रार्थना।

(नियम 30 देखिए)

1. आवेदक/आवेदकों का नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए।	मैं/हम[1] ————————— जिसने/जिन्होंने —————————
2. मृतक का नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए।	के साथ संयुक्त रूप से पेटेन्ट सं० ————————तारीख———— के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा घोषित करता हूं/करते हैं कि उक्त[2] ———————— की मर गया है।
	मैं/हम निवेदन करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे नाम में आवेदन पर कार्यवाही चलाने के लिए समर्थ बनाने वाले निदेशों के लिए आदेश किया जाए।
	मैं/हम निवेदन करता हूं/करते हैं कि————— ————— मृतक के विधिक प्रतिनिधि(यों) ने उपर्युक्त प्रार्थना पर सम्मति दे दी है। मृतक की मृत्यु का सबूत और मेरे/हमारे प्राधिकार का सबूत इसके साथ प्रस्तुत है।
	भारत में तामील करने के लिए मेरा/हमारा पता निम्नलिखित है :— ——————————— ———————————
	तारीख आज 19 ————————के/की ——————के——————दिन —————————— (हस्ताक्षर)[3]
3. आवेदकों या अभिकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।	सेवा में, पेटेन्ट नियंत्रक, पेटेन्ट कार्यालय।
	विधिक प्रतिनिधि द्वारा पृष्ठांकन ——————————— ———————————मृतक का/के
4. नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए।	विधिक प्रतिनिधि मैं/हम[4] ——————— ——————————एतद्द्वारा अपनी सम्मति देता हूं/देते हैं कि पेटेन्ट सं० ——————— तारीख ——— के लिये आवेदन पर कार्यवाही केवल इसके आवेदकों के नाम या नामों में ही चलाई जाए।
	तारीख आज 19 ——————————के/की ——————— के ———————दिन
5. विधिक प्रतिनिधि (यों) द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।	————————— (हस्ताक्षर)[5]

जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए।

प्ररूप 12 — पेटेन्ट अधिनियम, 1970

फीस 25 रु०

संयुक्त आवेदकों में विवाद होने की दशा में पेटेन्ट के लिए आवेदन पर कार्यवाही चलाने की बाबत धारा 20(5) के बाबत धारा 20(5) के अधीन, निदेशों के लिए आवेदन।

(नियम 31 देखिए)

जिन तथ्यों पर आवेदक आश्रित है और निर्देश वह चाहता है कि विवरण की दो प्रतियों के साथ दो प्रतियों में भेजा जाए।

1. नाम और पता लिखिए	मैं[1] ——————————— ———————————
2. अन्य आवेदक (कों) का नाम और पता लिखिए।	जो[2] ——————————————के साथ पेटेन्ट संख्या ———————— के लिए आवेदन में संयुक्त आवेदक हूं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि हमारे बीच में विवाद उत्पन् हो गया है और मैं निवेदन करता हूं कि नियंत्रक ऐसे निदेश देने वाला एक आदेश करे जिससे आवेदन पर आगे कार्यवाही चलायी जा सके।

3. आवेदकों या प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।	विवादास्पद मामलों की विशिष्टियां उपाबद्ध विवरण में दी गई हैं।
	भारत में तामील के लिए मेरा पता निम्नलिखित है:—

तारीख, आज 19———के/की ———के———दिन

(हस्ताक्षर)[3] ———

सेवा में,

पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय

जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए।

प्ररूप 13 — पेटेन्ट अधिनियम, 1970

फीस 30 रु०

संपूर्ण विनिर्देश की स्वीकृति को मुल्तवी करने के लिए आवेदन

(धारा 22 का परन्तुक देखिए)

मैं/हम एतद्द्वारा पेटेन्ट सं० ——— का तारीख———के आवेदन के अनुसरण में दाखिल संपूर्ण विनिर्देश की स्वीकृति को उस तारीख तक, जो संपूर्ण विनिर्देश दाखिल करने की तारीख——— मास के अवसान के पश्चात् की न हो, मुल्तवी करने के लिए प्रार्थना करता हूं/करते हैं।

तारीख, आज 19———के/की ———के ———दिन

आवेदक या आवेदकों या उसके/उनके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।	(हस्ताक्षर) ———

सेवा में,

पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय।

जो लागू नहीं होता, उसे काट दीजिए।

प्ररूप 14 — पेटेन्ट अधिनियम, 1970

फीस 25 रु०

धारा 15(1) या धारा 28(4) के अधीन समय बढ़ाने के लिए आवेदन।

(नियम 24 देखिए)

(तीन प्रतियों में दाखिल किए जाएं)

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए।	मैं/हम[1] ——— (क) पेटेन्ट सं०——— का——— ता०———के लिए आवेदन को बाबत विरोध की सूचना देने के लिए धारा 25(1) के अधीन (ख) आवेदन सं० ——— ता० की बाबत धारा 28(2) के अधीन प्रार्थना करने के लिए या धारा 28(3) के अधीन दावा करने के लिए धारा 28(4) के अधीन एक मास का समय बढ़ाने के लिए एतद्द्वारा आवेदन करता हूं/करते हैं। यह आवेदन करने के निम्नलिखित कारण हैं: —
2. आवेदक(कों) या प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।	भारत में तामील के लिए मेरा/हमारे पता निम्नलिखित है:

तारीख, आज 19 ———के/की———के ———दिन

(हस्ताक्षर)[2] ———

सेवा में,

पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय।

जो लागू नहीं होता, उसे काट दीजिये।

प्ररूप 15 — पेटेन्ट अधिनियम, 1970

फीस 50 रुपये

पेटेन्ट अनुदत्त करने के प्रति विरोध की सूचना धारा 25 के अधीन

(नियम 35 देखिए)

(तीन प्रतियों में दाखिल की जाएगी)

1. (पूरा) नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए।	मैं/हम[1]——— [2]द्वारा किए गए आवेदन संख्या——— पर पेटेन्ट अनुदत्त करने के प्रति———[3] आधार पर विरोध की एतद्द्वारा सूचना देता हूं/देते हैं।
2. पेटेन्ट के आवेदक का (पूरा) नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए।	भारत में तामील के लिए मेरा/हमारा पता है:- ———
3. विरोध के आधारों को लिखिए।	———
4. विरोधी पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए और यदि विरोधी पक्षकार भारत से अनुपस्थित हो तो प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा।	तारीख आज 19———के/की——— के———दिन ———[4] (हस्ताक्षर)

सेवा में,

पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय

जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए।

प्ररूप 16 — पेटेन्ट अधिनियम, 1970

फीस 50 रुपये

नियंत्रक के समक्ष सुनवाई में हाजिर होने की सूचना

(नियम 44(2) देखिए)

1. नाम और पता लिखिए।	मैं/हम[1]———एतद्द्वारा सूचना देता हूं/देते है कि———[2] के
2. विशिष्टियां (अर्थात आवेदन या पेटेन्ट की संख्या पक्षकारों के नाम और कार्यवाहियों का स्वरूप) लिखिए।	निर्देश में———के लिए नियत सुनवाई में स्वयं हाजिर हो

जाऊंगा, हो जाएंगे या मेरी/हमारी ओर से कोई व्यक्ति हाजिर हो जाएगा ।

तारीख आज 19———के/की———
———के———दिन

3. सूचना देने वाले पक्षकार द्वारा या प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं। ———(हस्ताक्षर)[3]

सेवा में,
पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय ।

जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए।

प्ररूप 17 — पेटेन्ट अधिनियम, 1970

फीस प्रति मास 25 रुपये — नियम 48 के अधीन समय बढ़ाने के लिए आवेदन

पेटेन्ट संख्या———का तारीख———
———के लिए आवेदन

1. नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए। — मैं/हम———[1] नियम 46 के अधीन संपूर्ण विनिर्देश में संशोधन प्रस्तुत करने या नियम 47(3) के अधीन संशोधन करने या संपूर्ण विनिर्देश की सहमति को अधिसूचित करने के लिए——— मास का समय बढ़ाने के लिए एतद्‌द्वारा आवेदन करता हूं/करते हैं।

2. आवेदक(कों) या उसके/उनके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाए। — तारीख आज 19———के/की
———के———दिन
———(हस्ताक्षर)[2]

सेवा में,
पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय।

जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए ।

प्ररूप 18 — पेटेन्ट अधिनियम, 1970

फीस 25 रुपये — धारा 28(2) के अधीन प्रार्थना (नियम 49 देखिए)

1. पेटेन्ट के लिए आवेदक या आवेदकों का पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता बताइए। — मैं/हम [1]———
———
जिन्होंने 19———को

2. आविष्कार का नाम बताइए। — एक आविष्कार के लिए जिसका नाम[2]
———
है, पेटेन्ट सं०———का——— तारीख———के लिए आवेदन किया है, और———

3. यदि वह/वे आवेदक न हों, तो आविष्कारक(कों) का/के नाम, पता और राष्ट्रिकता बताइए। — मैं/हम 3———
———
एतद्‌द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं

4. आविष्कार (कों) का नाम लिखिए। — कि उक्त 4———
पेटेन्ट सं० ———का
——— तारीख
के लिए आवेदन सं० आविष्कार के आविष्कारक हैं और मैं/हम एतद्‌द्वारा निवेदन करता हूं/करते हैं कि उक्त श्री 4———
———का धारा 28 के अधीन ऐसा/ऐसे आविष्कारक के रूप में उल्लेख किया जाए। उन परिस्थितियों को उपवर्णित करने वाला एक विवरण, जिनको, हमने इस आवेदन के औचित्य का आधार माना है, संलग्न है ।

भारत में तामील के लिए मेरा/हमारा पता निम्नलिखित है:—
———
———

तारीख आज 19———के/की———के———दिन

5. प्रार्थना करने वाले सभी व्यक्तियों या प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए। — (हस्ताक्षर)[5] ———

सेवा में,
पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय ।

जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए ।

प्ररूप 19 — पेटेन्ट अधिनियम, 1970

फीस 25 रु० — धारा 28(3) (नियम 50 देखिए) के अधीन दावा

1. दावेदार का पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता बताइए। — मैं/हम [1] ———
———
एतद्‌द्वारा घोषित करता हूं/करते हैं कि

2. पेटेन्ट के लिए आवेदक या आवेदकों का नाम और पता लिखिए। — मैं/हम ———
———[2]
नामक आविष्कार का आविष्कारक हूं/हैं जिसके संबंध में ———
19———
———
द्वारा पेटेन्ट के लिए आवेदन सं०———
———किया गया था और मैं/हम एतद्‌द्वारा दावा करता हूं/करते हैं कि अधिनियम की धारा 28(3) के अधीन ऐसे आविष्कारक के रूप में मेरा/हमारा उल्लेख किया जाए ।

पेटेन्ट नियम, 1972 के नियम 50 द्वारा यथा अपेक्षित उन परिस्थितियों को उपवर्णित करने वाला एक विवरण जिन के अधीन यह दावा किया गया है, उसकी एक प्रति या प्रतियों सहित संलग्न है।

3. दावेदार(रों) या प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

भारत में तामील के लिए मेरा/हमारा पता निम्नलिखित है :—

————————————

————————————

तारीख 19 ————के/की ————को————दिन

(हस्ताक्षर) 3 ————————

सेवा में,

पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय।

जो लागू नहीं होता, उसे काट दीजिये।

प्ररूप 20 — पेटेन्ट अधिनियम, 1970

फीस 25 रु० — धारा 28(7) के अधीन आवेदन (नियम 51 देखिए)

1. इस आवेदन को करनेवाले व्यक्ति या व्यक्तियों का पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता बताइए।

मैं/हम 1———————— एतद्द्वारा घोषित करता हूं/करते हैं कि ———————— की धारा 28 के अधीन उस आविष्कार का, जो पेटेन्ट सं०————का तारीख 19————के लिए आवेदन ————————

2. आविष्कारक के रूप में उल्लिखित व्यक्ति का नाम लिखिए।

————————————

मैं आविष्कारक के रूप में उल्लेख नहीं करता चाहिए था और मैं/हम एतद्द्वारा उस आशय के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं।

नियम 51 द्वारा यथाअपेक्षित उन परिस्थितियों को उपवर्णित करने वाला विवरण जिनके अधीन यह आवेदन किया गया है, उसकी प्रति/प्रतियों सहित संलग्न है।

भारत में तामील के लिए मेरा/हमारा पता निम्नलिखित है:—

3. आवेदन करने वाले सभी व्यक्तियों या प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

————————————

————————————

तारीख आज 19————के/की ————के————दिन

(हस्ताक्षर) 3————————

सेवा में,

पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय।

जो लागू नहीं होता, उसे काट दीजिए।

प्ररूप 21 — पेटेन्ट अधिनियम, 1970

फीस 5 रुपये — भारत से बाहर पेटेन्ट के लिए आवेदन करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन (धारा 39 देखिए)

1. आविष्कार का नाम लिखिए।

1———————— के लिए एक आविष्कार मेरे/हमारा कब्जे में है। मैंने/हमने उक्त आविष्कार के लिए पेटेन्ट-अनुदत्त करने के लिए पेटेन्ट का आवेदन सं० ———— का ————ता———— किया है।

मैं/हम निम्नलिखित देश/देशों में पेटेन्टों के लिए आवेदन करने की प्रस्थापना करता हूं/करते हैं :—

————————————

————————————

मैं/हम निवेदन करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें उक्त देशों में उक्त आविष्कार के लिए आवेदन करने की अनुज्ञा दी जाए। अधिनियम की धारा 39(1) में विनिर्दिष्ट शर्तों के पूर्व इस आवेदन को करने के निम्नलिखित कारण हैं :—

मैं/हम एतद्द्वारा घोषित करता हूं/करते हैं कि इसमें कथित तथ्य और बातें मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास में सत्य है।

तारीख आज 19————के/की ————के ————दिन

2 आवेदक (कों) या प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

(हस्ताक्षर) 2————————

सेवा में,

पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय।

जो लागू नहीं होता, उसे काट दीजिए।

प्ररूप 22 — पेटेन्ट अधिनियम, 1970

फीस 60 रुपये — धारा 43 के अधीन पेटेन्ट के मुद्रांकन के लिए प्रार्थना [नियम 56(1) देखिए]

1. आवेदक या आवेदकों का नाम लिखिए।

मैं/हम ————————प्रार्थना करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे आवेदन सं० ————का ————

2. दोनों आवेदन और क्रम संख्याओं को लिखिए।

तारीख———— के आधार पर पेटेन्ट को मुद्रांकित किया जाए और निम्नलिखित पते को भारत में तामील करने के मेरे/हमारे पते के रूप में रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए————————

————————————

तारीख आज 19————के/की———— के————दिन

3. आवेदक(कों) द्वारा या प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।

(हस्ताक्षर) 3————————

सेवा में,

पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय।

जो लागू नहीं होता, उसे काट दीजिए।

प्ररूप 23 पेटेन्ट अधिनियम, 1970

फीस 25 रु० प्रतिमास

पेटेन्ट के मुद्रांकनार्थ प्रार्थना करने की अवधि को बढ़ाने के लिए धारा 43(3) के अधीन आवेदन

(नियम 56 (3) देखिए)

1. पूरा नाम पता और राष्ट्रिकता लिखिए।

मैं / हम 1————————तारीख ———— के———आवेदन सं० ————पर पेटेन्ट के मुद्रांकनार्थ प्रर्थना करने के लिए ———— मास की अवधि को बढ़ाने के लिए एतदद्द्वारा आवेदन करता हूं । करते हैं।

यह प्रर्थना करने के कारण निम्न प्रकार प्रकार हैं:—

2. आवेदक(कों) या प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।

तारीख आज 19————के/की ———— के————दिन

(हस्ताक्षर) 2————

सेवा में,

पेटेन्ट नियंत्रक,

पेटेन्ट कार्यालय ।

जो लागू नहीं होता, उसे काट दीजिए ।

प्ररुप 24 पेन्टेट अधिनियम, 1970

फीस 50 रुपये

पेटेन्ट के संशोधन के लिए धारा 44 के अधीन आवेदन

(नियम 58 देखिए)

(इस आवेदन में किए गए कथनों को सत्यापित करने वाला साक्ष्य और अनुदत्त पेटेन्ट के साथ दो प्रतियों में भेजा जाए)

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता बताइए ।

मैं । हम 1———————— ———————— एतद्द्वारा प्रार्थना करता हूं /करते हैं

2. उस व्यक्ति का नाम, पता और राष्ट्रिकता बताइए जिस को पेटेन्ट अनुदत्त किया जाना चाहिए था।

कि पेटेन्ट सं०———— को जो———————— ———————— ————————

को अनुदत्त किया गया है, प्राप्तिकर्ता के नाम के स्थान पर————2 का नाम प्रतिस्थापित करके संशोधित किया जाए। भारत में तामील के लिए मेरा / हमारा पता निम्नलिखित है:—

3. आवेदक (कों) या प्रधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए ।

———————— ————————

तारीख आज 19————के / की ————के————दिन

(हस्ताक्षर) 3————

सेवा में,

पेटेन्ट नियंत्रक,

पेटेन्ट कार्यालय ।

प्ररूप 25 पेटेन्ट अधिनियम, 1970

फीस 25 रुपये

धारा 51(1) के अधीन निदेशार्थ आवेदन

(नियम 59 देखिये)

जिन तथ्यों में पर आवेदन निर्भर करता है उनके विवरण के साथ दो प्रतियों में दाखिल किया जाए)

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए।

मैं/हम 1———————— पेटेन्ट सं० ————का———— तारीख————————की बाबत निम्नलिखित निदेशों के लिए एतद्द्वारा आवेदन करता हूं / करते हैं:— भारत में तामील के लिए मेरा / हमारा पता निम्नलिखित हैं:—

————————————————

————————————————

2. आवेदक (कों) या प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।

तारीख आज 19————के/ की ———— के———— —दिन

(हस्ताक्षर) 2————

सेवा में

पेटेन्ट नियंत्रक

पेटेन्ट कार्यालय ।

जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए।

प्ररुप 26 पेटेन्ट अधिनियम 1970

फीस 25 रुपये

धारा 51(2) के अधीन निदेशों के लिए आवेदन

(नियम 60 देखिए)

(जिन तथ्यों पर आवेदक निर्भर करता है उन के विवरण के साथ दो प्रतियों में दाखिला किया जाए)

1. पेटेन्टधारी का पूरा नाम पता और राष्ट्रिकता लिखिए

2. अन्य पेटेन्टधारियों का नाम पता और राष्ट्रिकता लिखिए ।

मैं या हम 1———————— निम्नलिखित विषय में धारा 55(1) के अधीन दिए गए नियंत्रक के निदेशों का पालन करने के लिए ————2 की असफलता की बाबत निदेशों के लिए एतद्द्वारा आवेदन करता हूं / करते हैं ———————— ————————

भारत में तामील के लिए मेरा / हमारा पता निम्नलिखित है :—

3. आवेदक (कों) या प्रधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

———————— तारीख आज ————के / की ———— के————दिन ।

(हस्ताक्षर) 3————

सेवा में

पेटेन्ट नियंत्रक

पेटेन्ट कार्यालय

जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए ।

प्ररूप 27

फीस 50 रुपये ।

पेटेन्ट अधिनियम, 1970

धारा 52(2) के अधीन पेटेन्ट अनुदत्त करने के लिए प्रार्थना ।

(जिन तथ्यों पर आवेदक निर्भर करता है उन्हें उपवर्णित करते हुए विवरण और आदेश की प्रमाणित की गई प्रति के साथ)

1. आवेदक का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीता लिखिए ।
2. उच्च न्यायालय का नाम लिखिए ।
3. वह स्थान बताइए जहां उच्च न्यायालय या उसकी न्यायपीठ स्थित है ।
4. पेटेन्टधारी का नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए ।
5. वादाअर्जी की सं० और वर्ष लिखिए ।
6. असली और प्रथम आविष्कारक का नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए ।
7. आवेदक (कों) या उसके उनके प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता(ओं) द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं ।

मैं [1]हम———————
एतद्द्वारा घोषणा करता हूं करते हैं:-

(i) कि मैंने/हमने ————[4] द्वारा अनुदत्त के स्वामित्वाधीन पेटेन्ट सं० ———————— के प्रतिसंहरण के लिए[3] —— [2]उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 64 के अधीन अर्जी दी थी जिसकी वाद सं० ———————— है ।

(ii) कि मैंने/हमने उस आविष्कार के, जिसके लिए उक्त पेटेन्ट अनुदत्त किया गया था, असली और प्रथम आविष्कार का ———— /असली और प्रथम आविष्कारक का / के समनुदेशिती / विधिक प्रतिनिधि होने का दावा किया है ।

(iii) कि उक्त वाद में आदेश द्वारा (उक्त न्यायालय द्वारा प्रमाणित की गई प्रति इससे संलग्न है) उक्त न्यायालय ने उक्त पेटेन्ट को प्रतिसंहृत कर दिया है । उसकेदावों को अपवर्जित करके पेटेन्ट के पूर्ण-विनिर्देश में संशोधन निर्दिष्ट किया है और मुझे / हमें उक्त पेटेन्ट के बदले में संशोधन द्वारा अपवर्जित किए गए आविष्कार के भाग के स्थान पर पेटन्ट अनुदत्त करना अनुज्ञात किया है।

(iv) इसमें कथित तथ्य और बातें मेरे / हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास में सत्य है । मैं/हम निवेदन करता हूं / करते है कि मुझे / हमें उक्त प्रतिसंहृत पेन्टटे के बदले में / उक्त पेटेन्ट के पूर्ण संपूर्ण विनिर्देश में से अपवर्जित आविष्कार के भाग के स्थान पर पेटेन्ट अनुदत्त किया जाए ।

तारीख मास 19——को / की ————के ————दिन ।

(हस्ताक्षर)[7]————

सेवा में,
पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय

जो लागू नहीं होता, उसे काट दीजिए ।

प्ररूप 28

पेटेन्ट अधिनियम, 1970

धारा 55 की उप-धारा (1) के परन्तुक के अधीन अतरिक्त के पेटेन्ट को स्वतंत्रम पेटेन्ट में संपरिवर्तित करने के लिए प्रार्थना ।

(नियम 64 देखिए)

1. पूरा विवरण, आवेदकों का पता और राष्ट्रिकता लिखिए ।
2. वह स्थान जहां उच्च न्यायालय या उसकी शाखा स्थित है, लिखिए ।
3. सुसंगत कार्यवाहियों का ब्यौरा लिखिए ।
4. आवेदक/आवेदकों द्वारा या प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं ।

मैं/हमें ————————एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि:-

(i) मुझे/हमें, मेरे/हमारे ———————————नामक मुख्य आविष्कार के लिए पेटेन्ट सं०—— तारीख——— और मुख्य अविष्कार पर सुधार या उपान्तर के लिए पेटेन्ट सं०———————— तारीख ————अनुदत्त किया गया था ।

(ii). मुख्य आविष्कार के लिए पेटेन्ट————————[2] के उच्च न्यायलय द्वारा अपने निर्णय और डिक्री द्वारा ———————— में/नियंत्रक द्वारा अपने ———————— तारीख के विनिश्चय/आदेश द्वारा प्रति संहृत कर दिया गया है ।

मैं/हम निवेदन करता हूं/करते हैं कि नियंत्रक आदेश पारित करें कि उक्त अतिरिक्त पेटेन्ट, मुख्य आविष्कार के लिए उक्त पेटेन्ट की शेष कालावधि के लिए स्वतंत्र पेटेन्ट बन जाएगा ।

तारीख मास 19————के/ की ———— के————दिन ।

हस्ताक्षर[4]————————

जो लागू नहीं होता, उसे काट दीजिए ।

प्ररूप 29

फीस—नीचे टिप्पणी देखिए

पेटेन्ट अधिनियम, 1970

धारा 57 के अधीन पेटेन्ट के लिए आवेदन या संपूर्ण विनिर्देश के संशोधन के लिए आवेदन

(नियम 65(1) देखिए)

1. आवेदक या आवेदकों का पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए।	मैं/हम[1]————————— इससे उपाबन्ध प्रति 3 में लाल स्याही में दर्शित ————रूप में पेटेन्ट सं०——————
2. बताइए कि आवेदन या पूर्ण विनिर्देश का संशोधन करना है।	———तारीख ———— के लिए आवेदन के ———[2] में संशोधन करने की इजाजत चाहता हूं/चाहते हैं।
3. प्ररूप का पाद टिप्ट टिप्पण देखिए।	मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि प्रश्नगत पेटेन्ट के प्रतिलंघन के लिए या प्रतिसंहरण के लिए न्यायलय के समक्ष कोई कार्यवाही लम्बित नहीं है।[4]
4. इस पेरा को काट दीजिए यदि पेटेन्ट अनुदत्त नहीं किया गया है।	
5. आवेदक (कों) या पेटेन्टधारी (पेटेन्टधारियों) या यदि आवेदक/पेटेन्टधारी भारत से अनुपस्थित है तो प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।	इस संशोधन के करने के लिए मेरे/हमारे कारण निम्न प्रकार हैं:— ———————— ———————— मैं/हम घोषणा करता हूं/करता हैं कि इसमें कथित तथ्य और बातें मेरे/हमारे ज्ञान, जानकारी और विश्वास में सत्य हैं। भारत में तामील के लिए मेरा/हमारा पता निम्नलिखित हैं :— ————————

तारीख आज 19————के/की ———— के————दिन।

हस्ताक्षर[5]——————

सेवा में,
पेटेन्ट नियंत्रक
पेटेन्ट कार्यालय

जो लागू नहीं होता, उसे काट दीजिए

टिप्पण :—यदि विनिर्देश मुद्रित हो गया हो तो शासकीय रूप से मुद्रित प्रति युक्त होगी।

स्वीकृति सेपूर्व	30.00 रु०
स्वीकृति के पश्चात्	60.00 रु०
मुद्रांकन के पश्चात्	100.00 रु०

प्ररूप 30 पेटेन्ट अधिनियम, 1970
फीस 50 रु०

संशोधन के लिए धारा 57 के अधीन वाले आवेदन के प्रति विरोध की सूचना

(नियम 65 (3) देखिए)
(दो प्रतियों में भेजा जाए)

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए।	मैं[1] हमें——————आवेदन में या पेटेंट सं०——————में संशोधन के आवेदन का, धारा 57 के अधीन, निम्नलिखित कारणों से विरोध करने की एतद्द्वारा सूचना देता हूं। देतें हैं————
2. बताइए कि आवेदन या विनिर्देश का संशोधन करना है।	————————
3. विरोधी पक्षकार या प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।	———— ————————

तारीख आज 19 ————के/की ———— के———— दिन।

सेवा में,
पेटेन्ट नियंत्रक
पेटेन्ट कार्यालय

जो लागू नहीं होता, उसे काट दीजिए।

प्ररूप 31 पेटेन्ट अधिनियम, 1970
फीस पाद टिप्पण देखिए।

धारा 60 के अधीन पेटेन्ट के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन
(नियम 68 देखिए)

1. आवेदक या आवेदकों का पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए।	मैं / हम[1]—————————————— को अनुदत्त पेटेन्ट सं० ——————— के प्रत्यावर्तन के लिए नियंत्रक के आदेश के लिए एतद्द्वारा आवेदन करता हूं करते हैं।
2. पिछली वह तारीख लिखिए जब फीस देय थी।	
3. आवेदक या आवेदकों द्वारा या यदि आवेदक भारत से अनुपस्थित है / हैं तो प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।	वे परिस्थितियों, जिनके कारण ———————— के / की ———————— के———— दिन को या से पूर्व 2———— रु० नवीकरण फीस देने में लोप हुआ, निम्न प्रकार हैं———— ————————

तारीख आज 19 ————के/के ————के————दिन

(हस्ताक्षर)[3] ————

सेवा में,
पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय।

जो लागू नहीं होता, उसे काट दीजिए।

टिप्पणी :—फीस:—

(क) आवेदनके साथ	50.00 रु०
(ख) प्रत्यवर्तन पर अतिरिक्त फीस	150.00 रु०

प्ररूप 32 पेटेन्ट अधिनियम, 1970
फीस 50 रु०

पेटेन्ट के प्रत्यावर्तन के लिए धारा 60 के अधीन आवेदन के प्रति विरोध की सूचना

(नियम 69 देखिए)
(विवरण की दो प्रतियों के साथ दो प्रतियों में भेजी जाएं)

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए।	मैं / हम[1] ———————— ———————— एतद्द्वारा पेटेन्ट संख्या ————

के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन के प्रति विरोध की सूचना निम्नलिखित कारणों से देता हूं (देते हैं) :—

———————————

———————————

——————— विरोधी पक्षकार (रों)

भारत में तामील के लिए मेरा / हमारा पता निम्नलिखित है :—

———————————

———————————

2. विरोधी पक्षकार या प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

तारीख आज ————19———— के / की ———— के ————दिन

———————— (हस्ताक्षर)[2]

सेवा में,
पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय।

जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए।

प्ररूप 33 पेटेन्ट अधिनियम, 1970

फीस 50 रुपये

धारा 63 के अधीन पेटेन्ट का अभ्यर्पण करने के लिए प्रस्थापना की सूचना

1. (पूरा) नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए।

मैं / हम[1] ————————

———————————

———————————

पेटेन्ट संख्या ————————

तारीख ———— जो ———— को अनुदत्त किया गया है, एतद्द्वारा अभ्यर्पित करने की प्रस्थापना करता हूं (करते हैं) मैं / हम घोषित करता हूं (करते हैं) कि प्रश्नगत पेटेन्ट के अतिलंघन के लिए या प्रतिसंहरण के लिए न्यायालय के समक्ष कार्यवाही लम्बित है।

यह प्रस्थापना करने के मेरे / हमारे कारण निम्नलिखित हैं :—

———————————

———————————

मैं/हम घोषित करता हूं (करते हैं) कि इसमें कथित तथ्य और बातें मेरे / हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

मेरा / हमारा भारत में तामील का पता निम्नलिखित है:—

———————————

———————————

2. पेटेन्टधारी द्वारा या यदि पेटेन्टधारी भारत से अनुपस्थित है / हैं तो प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

तारीख आज ————19———— के / की ———— के ————दिन

(हस्ताक्षर)[2]————————

सेवा में,
पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय।

जो लागू नहीं होता, उसे काट दीजिए।

प्ररूप 34 पेटेन्ट अधिनियम, 1970

फीस 50 रुपये

पेटेन्ट के अभ्यर्पण की प्रस्थापना करने के लिए धारा 63 के अधीन विरोध की सूचना
(नियम 71(3) देखिए)
(दो प्रतियों में भेजी जाए)

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए।

मैं/हम हम[1]————————

———————————

एतद्द्वारा पेटेन्ट संख्या ———— के अभ्यर्पण की प्रस्थापना को विरोध की सूचना निम्नलिखित कारणों से देता हूं / देते हैं :—

———————————

———————————

भारत में तामील के लिए मेरा/हमारा पता निम्नलिखित है :—

———————————

———————————

2. विरोधी पक्षकार या प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाए।

तारीख आज ————19———— के / की———— के————दिन

(हस्ताक्षर)[2]————————

सेवा में,
पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय।

जो लागू नहीं होता, उसे काट दीजिए।

प्ररूप 35 पेटेन्ट अधिनियम, 1970

फीस—पाद टिप्पणी देखिए।

धारा 68 के अधीन पेटेन्टों के रजिस्टर में दस्तावेजों के रजिस्ट्रकरण के लिए आवेदन
(नियम 73 देखिए)

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए।

2. दस्तावेज की प्रकृति उसके पक्षकार और उसके निष्पादन की तारीख बताइए।

3. आवेदक को या प्राधिकृत पेटेन्टों अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।

मैं / हम [1]पेटेन्टों सं०* ———————— तारीख ———— को अनुदत्त ———————— जिसका पेटेन्टधारी है* ———————— के विषय में दस्तावेज जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है, पेटेन्टों के रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूं / करते हैं:—भारत में[2] तामील के लिए मेरा / हमारा पता निम्नलिखित है :—

———————————

———————————

तारीख आज 19 ———— के/की ———— के ———— दिन

(हस्ताक्षर) [3]————

सेवा में,
पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय।

*यदि आवेदन एक से अधिक पेटेन्ट की बाबत हो तो उनकी सं० और अन्य अपेक्षित विशिष्टियां प्रथम अनुसूची में दी जानी चाहिए, जो इस प्ररूप के साथ संलग्न की जाए।

टिप्पण:— फीस

एक पेटेन्ट की बाबत 25 रु०

प्रत्येक अतिरिक्त पेटेन्ट के लिए 10 रु०

प्ररूप 36

फीस—पाद टिप्पणी देखिए

पेटेन्ट अधिनियम, 1970

पेटेन्टों के रजिस्टर में हकदार या आंशिक हकदार के नाम की प्रविष्टि के लिए आवेदन, धारा 69 (1) के अधीन

(नियम 74 (1) (क) देखिए)

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए।	मैं / हम [1]———————— ———————————— एतद्द्वारा आवेदन करता हूं / करते हैं कि आप मेरा / हमारे नाम पेटेन्टों के रजिस्टर में पेटेन्ट संख्या ——————— के जो [2]—————— ——— को अनुदत्त किया गया
2. उस / उन व्यक्तियों का (के) नाम और पता (पते) दीजिए जिसे / जिन्हें पेटेन्ट अनुदत्त किया गया था और जो अब इस पर स्वामित्व रखता / रखते हैं।	
3. आविष्कार का नाम लिखिए।	था जिसका [3] ———————— हकदार (या आंशिक हकदार) के रूप में प्रविष्ट करेंगे।
4. ऐसी वस्तावेज की विशिष्टियां तारीख और उसके पक्षकारों का उल्लेख करते हुए और यह दर्शित करते हुए विनिर्दिष्ट करें कि यहां किया गया दावा किस प्रकार सिद्ध किया गया है।	मैं / हम इस प्रकार होने का दावा ———————— के आधार पर [4] करता हूं (करते हैं) और जिसके सबूत में मैं/हम संलग्न [5] ———————— ———————— को उसकी अनुप्रमाणित प्रति सहित पारेषित करता हूं (करते हैं)
5. दस्तावेज की प्रकृति लिखिए।	भारत में तामील के लिए मेरा / हमारा पता निम्नलिखित है :— ———————— ————————
	तारीख आज ——19——के/की ———— के———— दिन ————————
6. आवेदक (कों) या प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।	हस्ताक्षर [6]————————

सेवा में,

पेटेन्ट नियंत्रक

पेटेन्ट कार्यालय।

टिप्पणी :—यदि आवेदन एक से अधिक पेटेन्टों के बारे में है तो उनकी संख्या तथा अन्य अपेक्षित विशिष्टियों अलग अनुसूची में दी जा सकती हैं जो इस प्ररूप के साथ संलग्न होनी चाहिए।

फीस:—

एक पेटेन्ट के विषय में . . .	25.00 रु०
प्रत्येक अतिरिक्त पेटेन्टों के लिए . .	10.00 रु०

प्ररूप 37

फीस—पाद टिप्पण देखिये।

पेटेन्ट अधिनियम, 1970

धारा 69(1) के अधीन पेटेन्टों के रजिस्टर में बन्धक या अनुज्ञप्ति या अन्यथा हकदार व्यक्ति के हित की सूचना के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन।

(नियम 74(1)(ख) देखिये)

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिये।	मैं/हम [1] ———————— ———————— एतदद्वारा आवेदन करता हूं (करते हैं) कि मेरा/हमारा नाम पेटेन्टों के रजिस्टर में बन्धक/अनुज्ञप्ति/अन्यथा के आधार पर पेटेन्ट में हित के हकदार व्यक्ति के आधार पर रजिस्टर कर लिया जाय। पेटेन्ट/पेटेन्टों का ब्यौरा नीचे विनिर्दिष्ट है:—
2. उस व्यक्ति का नाम और पता दें जिसको पेटेन्ट अनुदत्त किया गया था।	मैं/हम ————————
3. आविष्कार का नाम लिखिए।	————को अनुदत्त [2] ————
4. ऐसी दस्तावेज की विशिष्टियां, तारीख और उसके पक्षकारों का उल्लेख करते हुये और यह दर्शित करते हुये विनिर्दिष्ट करें कि यहां किया गया दावा किस प्रकार सिद्ध किया गया है।	————के पेटेन्ट संख्या ——— ————में जिसका नाम [3] ——— ————है ———— ———————— के आधार पर [4] हित का (के) हकदार होने का दावा करता हूं (करते हैं)।
5. दस्तावेज की प्रकृति लिखिये	और जिसके सबूत में मैं / हम संलग्न [5] ———————— को उसकी अनुप्रमाणित प्रति सहित, पारेषित करता हूं (करते हैं)। भारत में तामील के लिये मेरा/हमारा पता निम्नलिखित है:— ———————— ————————
	तारीख———के/की———— के————दिन
6. आवेदक (कों) या प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किये जाये।	(हस्ताक्षर) [6]————————

सेवा में,

पेटेन्ट नियंत्रक,

पेटेन्ट कार्यालय।

टिप्पण :—यदि आवेदन एक से अधिक पेटेन्टों के बारे में है तो उनकी संख्यायें तथा अन्य अपेक्षित विशिष्टियां अलग अनुसूची में दी जा सकती है जो इस प्ररूप के साथ संलग्न होनी चाहिये।

फीस

एक पेटेन्ट की बाबत 25 रुपये, प्रत्येक अतिरिक्त पेटेन्ट के लिये 10 रुपये।

जो लागू नहीं होता, उसे काट दीजिये।

प्ररूप 38 — पेटेन्ट अधिनियम, 1970

फीस—पाद टिप्पण देखिये।

धारा 69(2) के अधीन पेटेन्ट या उसके अंश के हकदार व्यक्ति का नाम पेटेंटों के रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण करने के समनुदेशक द्वारा आवेदन

[नियम 74 (2) देखिये]

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिये।
2. रजिस्ट्रीकृत किये जाने वाले व्यक्तियों का नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिये।
3. ऐसी दस्तावेज की विशिष्टियां तारीख, उसके पक्षकारों के नाम देते हुये और यह दर्शित करते हुये कि किये गये दावे को किस प्रकार सिद्ध किया गया है, निर्दिष्ट कीजिये।
4. दस्तावेज की प्रकृति लिखिये।
5. आवेदक (कों) या प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता (ओं) द्वारा हस्ताक्षर किये जायें।

मैं/हम [1] ————————————

एतद्द्वारा आवेदन करता हूं (करते हैं) कि ———————— (के) नाम [2] पेटेंटों के रजिस्टर में पेटेन्ट या पेटेंटों के अंश के हकदार के रूप में, जिनका ब्यौरा नीचे विनिर्दिष्ट है। रजिस्ट्रीकरण किया जाये। पेटेन्ट सं० † ———————— जिसके मैं/हम पेटेन्टधारी हैं———— ————और जिस ———— का नाम ———————— है।

वह/वे [3] ———————— के फलस्वरूप उक्त पेटेन्ट या उसके शेयर का/के हकदार है/हैं और उसके सबूत में मैं/हम इसकी प्रमाणित प्रति सहित संलग्न [4] ———————— को पारेषित करता हूं/करते हैं।

भारत में तामील के लिये उसका/उनका पता निम्नलिखित है :—

————————————

————————————

तारीख आज 19————के/की———— ————के————दिन

(हस्ताक्षर) [5]

सेवा में,

पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय।

†यदि आवेदन एक से अधिक पेटेंटों के लिये हो तो उनकी संख्या एवं यथाअपेक्षित विशिष्टियां एक पृथक अनुसूची में होनी चाहियें जो इस प्ररूप के साथ संलग्न हो।

टिप्पण—

जो लागू नहीं होता, उसे काट दीजिये।

फीस— एक पेटेन्ट की बाबत—25 रुपये
प्रत्येक अतिरिक्त पेटेन्ट के लिये—10 रुपये

प्ररूप 39 — पेटेन्ट अधिनियम, 1970

फीस—पाद टिप्पण देखियें।

धारा 69 (2) के अधीन पेटेंटों के रजिस्टर में बंधक, अनुज्ञप्ति या अन्यथा के आधार पर लिखित के लिये बंधककर्ता या अनुज्ञापक या अन्य व्यक्ति द्वारा आवेदन

[नियम 74(2)(ख) देखिये]

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिये।
2. जिन व्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण करता है उनका नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिये।
3. आविष्कार का नाम लिखिये।
4. ऐसी दस्तावेज की विशिष्टियाँ उसकी तारीख और उसके पक्षकारों को बताते हुये, और यह दर्शित करते हुये कि किये गये दावे को किस प्रकार सिद्ध किया गया है, विनिर्दिष्ट कीजिये।
5. दस्तावेज की प्रकृति लिखिये।
6. आवेदक (कों) या प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये।

मैं/हम [1] ————————————

एतद्द्वारा आवेदन करता हूं/करते हैं कि [2] का/के नाम पेटेन्ट में बन्धक या अनुज्ञप्ति या अन्य लिखतों के आधार पर हित के हकदार व्यक्तियों के रूप में, जिनका ब्यौरा नीचे विनिर्दिष्ट है, पेटेन्टों के रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण किया जाए पेटेन्ट सं० †————————जिसका नाम [3]————है और जिसमें मैं/हम पटन्टधारी हैं।

वह/वे [4]————————के आधार पर उक्त पेटेन्ट में हित के हकदार हैं और उसके सबूत में मैं/हम इसकी प्रमाणित प्रति सहित संलग्न [5] ————————को पारेषित करता हूं/करते हैं।

भारत में तामील के लिये उसका/उनका निम्नलिखित पता है :—

————————————

————————————

तारीख आज 19————के/की ————के————दिन।

(हस्ताक्षर) [6]————————

सेवा में,

पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय।

†यदि आवेदन एक से अधिक पेटेन्ट की बाबत हो, तो उनकी संख्या और अन्य अपेक्षित विशिष्टियां पृथक अनुसूची में दी जानी चाहिये, जो इस प्ररूप के साथ संलग्न की जाये।

टिप्पण—

जो लागू नहीं होता, उसे काट दीजिये।

फीस—एक पेटेन्ट की बाबत 25 रुपये
प्रत्येक अतिरिक्त पेटेन्ट के लिए 10 रुपये

प्ररूप 40 — पेटेन्ट अधिनियम, 1970

फीस—पाद टिप्पण देखिये।

पेटेन्ट के स्वामित्व पर प्रभाव डालने वाले किसी अन्य दस्तावेज की अधिसूचना की पेटेंटों के रजिस्टर में प्रविष्टि के लिये आवेदन।

(नियम 34 (3) देखिये)।

1. दस्तावेज की प्रकृति का वर्णन तारीख और इसके पक्षकारों का नाम, पता और राष्ट्रिकता बताते हुये लिखिये।

मैं/हम पेटेन्ट सं०———————— तारीख ———————— की बाबत एक अनुप्रमाणित प्रतिलिपि तथा मूल दस्तावेज सत्यापन के लिये

दस्तावेज के अधीन लाभ उठाने वाले पक्षकार का पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिये।	पारेषित करता हूं/करते हैं और मैं/हम निवेदन करता हूं/करते हैं कि इसकी एक अधिसूचना पेटेन्टों के रजिस्टर में प्रविष्ट कर दी जाए।
3. आवेदक/आवेदकों या प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किये जायें।	2. ——————— तारीख आज 19———के/की ———के———दिन (हस्ताक्षर)[3] ——— सेवा में, पेटेन्ट नियंत्रक, पेटेन्ट कार्यालय।

टिप्पण—

जो लागू नहीं होता, उसे काट दीजिये।

फीस एक पेटन्ट की बाबत—25 रुपये

प्रत्येक अतिरिक्त पटेन्ट के लिये 10 रूपये

प्ररूप 41 पेटेन्ट अधिनियम, 1970

फीस 5 रुपये

पेटेन्टों के रजिस्टर में नाम, राष्ट्रिकता पता या तामील के लिये पता के परिवर्तन के लिये प्रार्थना

[नियम 78 (1) देखिये]

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिये।	पेटेन्ट सं० ———ता० ——— के मामले में मैं/हम[1]——— ——— एतद्द्वारा निवेदन करता हूं[1] करते हैं कि——— ———नाम, पता (या
2. रजिस्टर में प्रविष्ट करने के लिये, नाम, पता और तामील के लिये पता लिखिये।	———तामील के लिये पता) जो अभी पेटेन्टों के रजिस्टर में है, उसकी इस प्रकार परिवर्तित कर दिया जाये[2]——— ——— तारीख आज 19———के/की ———के———दिन
3. प्रार्थना करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों या प्राधिकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किये जायें।	(हस्ताक्षर)[3]——— सेवा में, पटेन्ट नियंत्रक, पेटेन्ट कार्यालय।

जो लागू नहीं होता, उसे काट दीजिये।

प्ररूप 42 पेटेन्ट अधिनियम, 1970

फीस 10 रुपये

पेटेन्टों के रजिस्टर में तामील के लिये एक अतिरिक्त पते की प्रविष्टि के लिये प्रार्थना।

[नियम 78(3)देखिये]

पेटेन्ट सं० ———ता० ——— के मामले में ———

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिये।	हम/मैं[1]——— ——— एतद्द्वारा निवेदन करता हूं[1] करते हैं कि तामील के लिये निम्नलिखित अतिरिक्त पेटेन्टों के रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाये।
2. तामील के लिये पूरा अतिरिक्त पता लिखिये।	2——— ——— तारीख आज 19———के/की ———के———दिन
3. प्रार्थना करने वाले आवेदक या प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किये जायें।	(हस्ताक्षर)[3] सेवा में, पेटेन्ट नियंत्रक, पेटेन्ट कार्यालय।

जो लागू नहीं होता, उसे काट दीजिये।

प्ररूप 43 पेटेन्ट अधिनियम, 1970

फीस 60 रुपये

धारा 84, 96 या 97 के अधीन अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन।

(नियम 80 देखिए)

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए।	मैं/हम[1]——— एतद्द्वारा पेटेन्ट संख्या———का——— तारीख——— के अधीन अनिवार्य अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए निम्नलिखित आधारों पर आवेदन करता हूं/करते हैं:— मेरे/हमारे हित और ऊपर कथित तथ्यों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य जिसकी प्रतियां इसके साथ संलग्न हैं:— 1.——— 2.——— 3.———
2. आवेदक (कों) द्वारा या यदि आवेदक भारत से अनुपस्थित है तो प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्त्ता द्वारा	मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि इसमें कथित तथ्य और बातें मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास में सही है।

हस्ताक्षर किए जाएं। भारत में तामील के लिए मेरा/हमारा पता निम्नलिखित है :—

तारीख आज 19------के/की------के ---------- दिन

(हस्ताक्षर)[2]-------

सेवा में,

पेटेन्ट नियंत्रक

पेटेन्ट कार्यालय

जो लागू नहीं होता, उसे काट दीजिए।

प्ररूप 14

फीस 60 रुपये

पेटेन्ट अधिनियम 1970

धारा 86 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा पेटेन्ट के पृष्ठांकन के लिए आवेदन

(नियम 80 देखिए)

केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पेटेन्ट संख्या --------की बाबत अधिकार की अनुज्ञप्ति पेटेन्ट के पृष्ठांकन के लिए निम्नलिखित आधारों से नियंत्रक के आदेश के लिए आवेदन करती है :

आवेदनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य की प्रतियां इसके साथ संलग्न हैं :—

1----------------

2----------------

3----------------

केन्द्रीय सरकार घोषणा करती है कि इसमें कथित तथ्य और बातें उसके सर्वोत्तम ज्ञान जानकारी और विश्वास में सही है। भारत में तामील के लिए पता निम्नलिखित है :—

तारीख आज 19---------के/की के ---------------- दिन

(हस्ताक्षर) ---------

सेवा में,

पेटेन्ट नियंत्रक,

पेटेन्ट कार्यालय।

प्ररूप 15

फीस 60 रुपये

पेटेन्ट अधिनियम 1970

धारा 89 के अधीन पेटेन्ट के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन।

(नियम 80 देखिए)

1. आवेदक(कों) का पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए।

2. आवेदक के हित की प्रकृति वे तथ्य जिन पर वह निर्भर करता है और वे आधार जिनपर आवेदन दिया गया है लिखिए।

3. आवेदक(कों) द्वारा या यदि आवेदक भारत से अनुपस्थित है/हैं तो प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं

मैं/हम[1]------------------------

एतद्द्वारा पेटेन्ट संख्या--------के प्रतिसंहरण के लिए निम्नलिखित कारणों से आवेदन करता हूं/करते हैं-----------------

2-----------------------

इस आवेदन के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य और उसकी प्रतियां इस के साथ संलग्न हैं :—

1.

2.

3.

भारत में तामील के लिए मेरा/हमारा पता निम्नलिखित है :—

तारीख आज 19------------के/की के---------------------- दिन

(हस्ताक्षर)[3]--------

सेवा में,

पेटेन्ट नियंत्रक,

पेटेन्ट कार्यालय।

जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए।

प्ररूप 46

फीस फीस 50 रुपये

पेटेन्ट अधिनियम 1970

धारा 92 और 93(5) के अधीन आवेदनों के प्रति विरोध की सूचना

(नियम 82 और 87(2) देखिए)

(इसकी दो प्रतियां विरोध के समर्थन के साक्ष्य सहित दाखिल की जाएं)

1. पूरा नाम पता और राष्ट्रिकता लिखिए।

मैं/हम[1]------------------------

एतद्द्वारा :

(क) धारा 92 के अधीन अनिवार्य अनुज्ञप्ति की मंजूरी पेटेन्ट के पृष्ठांकन या पेटेन्ट सं०-------- के प्रतिसंहरण

(ख) नियम 93(5) के अधीन पेटेन्ट संख्या--------की बाबत अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों का पुनरीक्षण के आवेदन के अपने विरोध की सूचना देता हूं/देते हैं। यह सूचना देने के निम्नलिखित कारण हैं :—

---

2. विरोधी पक्षकारों या प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।	------------------------ मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि इसमें कथित तथ्य और बातें मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी, और विश्वास में सही हैं।

तारीख आज 19--------के/की-- ----------के-- ---------दिन

(हस्ताक्षर)[2]--------

सेवा में,
पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय

जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए।

प्ररूप 47

फीस 25 रुपये

पेटेन्ट अधिनियम, 1970

धारा 88(2) के अधीन अनुज्ञप्ति के निबन्धनों को तय करने के लिए आवेदन।

(नियम 83 देखिए)

(परक्रामण के विवरण सहित दो प्रतियों में दिया जाए)

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए।	मैं /हम[1]--------घोषणा करता हूं/ करते हैं कि :–
2. आविष्कारक का नाम लिखिए।	(i) पेटेन्ट सं० ---------तारीख --------को[3] मुझे/हमें एक आविष्कार के लिए अनुदत्त किया गया था।
3. पेटेन्टधारी का पूरा नाम, राष्ट्रिकता और पता लिखिए।	(ii) धारा 86 के अधीन------को नियंत्रक के आदेश द्वारा उक्त पेटेन्ट "अधिकार की अनुज्ञप्तियां" शब्दों से पृष्ठांकित कर दिया गया है। शब्दों से पृष्ठांकित समझा गया है;
4. अनुज्ञप्ति की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए।	मैंने/ हमने उक्त पेटेन्ट के अधीन मुझे। हमें एक अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए उक्त---------- को प्रार्थना की है ;

------------ने उनसे । हमसे उक्त पेटेन्ट के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए प्रार्थना की है ;

(iii) मैं/हम और उक्त -------- अनुज्ञप्ति के निबन्धनों पर राजी होने में असमर्थ हैं ;

(iv) जिन परिस्थितियों में यह आवेदन किया गया है और अनुज्ञप्ति के निबन्धन जो मुझे / हमें स्वीकार्य है, इसके साथ विवरण में उपवर्णित किए गए हैं;

(v) इस में कथित और इस के साथ विवरण में उपवर्णित तथ्य और बातें मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं / हम प्रार्थना करता हूं / करते हैं कि उक्त पेटेन्ट के अधीन मुझे / हमें, उक्त-------------को अनुदत्त होने वाली अनुज्ञप्ति के निबन्धन नियंत्रक महोदय तय कर दें।

तारीख आज 19---------के /की ------के----------------दिन

(हस्ताक्षर) -------

सेवा में,
पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय।

जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए।

प्ररूप 48

फीस 25 रुपये

पेटेन्ट अधिनियम, 1970

धारा 88(4) के अधीन पेटेन्टकृत आविष्कार पर काम करने के लिए अनुज्ञा ।

(नियम 84 देखिए)

(दो प्रतियों में दिया जाए)

1. आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए।	मैं/हम[1]-----------------एतद्द्वारा ------------------ 2 से संबंधित
2. आविष्कार का नाम लिखिए।	आविष्कार के लिए-----------को अनुदत्त पेटेन्ट संख्या---------के आविष्कार पर काम करने के लिए आवेदन करता हूं / करते हैं जो धारा 86 के अधीन "अधिकार की अनुज्ञप्ति" शब्दों से पृष्ठांकित किया गया है या धारा 87 के अधीन "अधिकार की अनुज्ञप्ति" शब्दों से पृष्ठांकित किया जाना समझा गया है। मैंने/हमने धारा 88 की उपधारा (1) के अधीन पेटेन्टधारी से अध्यपेक्षा की है या-----------
3. अध्यपेक्षा की या नियंत्रक को आवेदन की तारीख लिखिए।	[3]------को निबन्धनों को तय करने के लिए नियंत्रक को आवेदन किया है।

इस आवेदन को करने के निम्नलिखित कारण हैं :–

मैं / हम एतद्द्वारा घोषित करता हूं / करते हैं कि ऊपर कथित तथ्य और बातें मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास में सही हैं। मेरा / हमारा निवेदन है कि मुझे / हमें उक्त पेटेन्ट के आविष्कार पर, पेटेन्टधारी के साथ करार/नियंत्रक

	द्वारा विनिश्चय के लम्बित रहने पर ऐसे निबन्धनों पर, काम करने की अनुज्ञा दी जाए जिन्हें अधिरोपित करना नियंत्रक ठीक समझे।
4. आवेदक(कों) या प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।	भारत में नामील के लिए मेरा/हमारा पता निम्नलिखित है :-

————————

तारीख आज 19———के/की———
———— के ————दिन

(हस्ताक्षर) 4 ————

सेवा में,

पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय।

जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए।

प्ररूप 49	पेटेन्ट अधिनियम, 1970
फीस 60 रुपये	धारा 93(5) के अधीन अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए आवेदन

(नियम 96 देखिए)
(इसकी दो प्रतियां साक्ष्य की दो प्रतियों सहित दाखिल की जाएं)

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए।	मैं/हम/ ———————— ———————— एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि :—

(i) मैं/हम——के नाम में——— की पेटेन्ट सं०———के अधीन अनुज्ञप्ति रख रहा हूं/रहे हैं;

(ii) नियंत्रक द्वारा मुझे/हमें अनुज्ञप्ति उसके आदेश तारीख——— द्वारा अनुदत्त की गई थी।

(iii) तय किए गए निबन्धन और शर्तें, आरंभ में अनुमानित से निम्नलिखित कारणों से, अधिक दुर्भर सिद्ध हैं; अर्थात् —

————————

————————

(iv) जिसके फलस्वरूप मैं/हम हम आविष्कार को हानि उठाकर करने के सिवाय नहीं कर सकता/कर सकते। मैं/हम इसलिए आवेदन करता हूं/करते हैं कि उक्त निबन्धनों और शर्तों को निम्नप्रकार पुनरीक्षित किया जाए।

2. आवेदकों द्वारा या प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।	मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि इसमें कथित तथ्य और बातें मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

तारीख आज 19————के/की
————को————दिन

2———— ————(हस्ताक्षर)

सेवा में,

पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय।

जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए।

प्ररूप 50	पेटेन्ट अधिनियम, 1970
फीस 50 रुपये	पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

(नियम 94 और 97 देखिए)
(उसकी दो प्रतियां दाखिल की जाएंगी)

मैं पेटेन्ट अधिनियम, 1970 के अधीन पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के लिए प्रार्थना करता हूं। ———— से लिया गया चरित्र का प्रमाणपत्र इसके साथ संलग्न है।

1. अभ्यर्थी के चरित्र का साक्ष्य देने वाला प्रमाण पत्र उस व्यक्ति से लिया गया होना चाहिए जिससे उसका संबंध न हो, और जहां अभ्यर्थी प्रायः रहता है वहां का जिला मजिस्ट्रेट मुख्य प्रशासन अधिकारी हो या किसी अन्य व्यक्ति से जिसे नियंत्रक ठीक समझता हो।	मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं पेट नियम 1972 के नियम 99 में उल्लिखित निर्योग्यताओं में से किसी के भी अधीन नहीं हूं और यह कि नीचे दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार में सत्य है। 1. पूरा नाम, उपनाम पहले, यदि कोई हो (स्पष्ट अक्षरों में)———— 2. निवास स्थान का पता————
2. या तो वांछित अर्हताओं के समर्थन में मूल डिप्लोमा प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज हों, या उनकी प्रतियां जो कि सम्यक्तः किसी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक द्वारा अनुप्रमाणित किए गए हों, आवेदन पत्र के साथ भेजी जाए।	3. कारबार का प्रमुख स्थान———— 4. शाखा कार्यालय, यदि कोई हो, का पता ———— 5. पिता का नाम———— 6. राष्ट्रिकता ———— 7. जन्मतिथि और स्थान———— 8. पूरी उपजीविका———— 9. पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हताओं की विशिष्टियां

10. क्या कभी पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में से निकाला गया था, यदि हो तो निकालने के कारण बताइए ——————

मैं एतद्द्वारा यह भी घोषणा करता हूं कि मैं अपने नाम में /———— के नाम के अन्तर्गत या———— के साथ————से पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं और पेटेन्टों के लिए आवेदन के संबंध में 5 से अधिक पूर्ण विनिर्देश, जिसकी सूची इसमें उपाबद्ध है, दाखिल कर दिये हैं।

तारीख आज 19————के/की ————के————दिन

हस्ताक्षर

सेवा में,

पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय।

जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए।

प्ररूप 51

फीस 50 रुपये

पेटेन्ट अधिनियम, 1970

पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन (नियम 102 देखिए)

(इसकी तीन प्रतियां दाखिल की जाएंगी)

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए।

2. आरम्भिक रजिस्ट्रीकरण की तारीख यहां लिखिए

मैं[1] अपने नाम को जो पेटेन्ट अधिनियम, 1970 की धारा 130 के अधीन ————————को निकाला गया था पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में प्रत्यावर्तन के लिए एतद्द्वारा आवेदन करता हूं मेरा नाम पेटेन्ट के रजिस्टर में आरम्भ में ————————को[2] दर्ज किया गया था।

तारीख आज 19————के/की——— के————————दिन

————————(हस्ताक्षर)[3]

सेवा में,

केन्द्रीय सरकार,
पेटेन्ट नियंत्रक की मार्फत
पेटेन्ट कार्यालय।

प्ररूप 52

फीस 10 रुपये

पेटेन्ट अधिनियम, 1970

पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर की प्रविष्टि के परिवर्तन के लिए आवेदन (नियम 103 देखिए)

(इसकी तीन प्रतियां दाखिल की जाएं)

1. पूरा नाम और पता लिखिए।

2. आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।

1. ————का मैं———— पेटेन्ट अभिकर्ता (रजिस्ट्रीकरण संख्या — ————————) एतद्द्वारा प्रार्थना करता हूं कि पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में दर्ज[2] मेरा नाम, कारबार या शाखाओं के प्रमुख स्थान का पता या अर्हताएं निम्न रूप में परिवर्तित कर दीजिए।

तारीख आज 19————के/की ————के———————दिन

————(हस्ताक्षर)

सेवा में,

पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय।

प्ररूप 53

फीस 15 रुपये

पेटेन्ट अधिनियम, 1970

धारा 78(1) के अधीन लिपिकीय गलतियों की शुद्धि के लिए आवेदन

(नियम 107 देखिए)

(दो प्रतियों में दिया जाए)

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए।

2. प्रार्थना करने वाले व्यक्ति या प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।

मैं/हम————————————
————————————
————————————
एतद्द्वारा निवेदन करता हूं/करते हैं कि पेटेन्ट सं०———— ————का———— तारीख ————————जिस के साथ विनिर्देश दाखिल किया गया या जिसके अनुसरण में दस्तावेज दाखिल किया गया या पेटेन्ट सं० ————का———— तारीख————के लिए आवेदन में पेटेन्ट संख्या————का ————तारीख के विषय में पेटेन्टों के रजिस्टर में प्रविष्टियों को ————उपाबद्ध मूल———— ————की प्रति में लाल स्याही में दर्शित रीति में शुद्ध कर ली जाएं।

भारत में तामील के लिए मेरा/हमारा पता निम्नलिखित है :—

————————————
————————————

तारीख आज 19————के/की
————————————
के————————दिन

(हस्ताक्षर)[2]

सेवा में

पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय।

जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिये।

प्ररूप 54 पेटेन्ट अधिनियम, 1970

फीस 10 रुपये धारा 78(5) के अधीन लिपिकीय गलती की शुद्धि के लिए प्रार्थना के प्रति विरोध की सूचना

(नियम 109 देखिए)

(दो प्रतियों में भेजा जाए और साथ में विवरण की दो प्रतियां भेजी जाएंगी)

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए।

मैं/हम[1] पेटेन्ट सं० ..... का ..... तारीख जिस के साथ विनिर्देश दाखिल किया गया था जिसके अनुसरण में दस्तावेज दाखिल किए या पेटेन्ट सं० ..... का ..... तारीख ..... के लिए आवेदन में पेटेन्ट सं० ..... का ..... तारीख ..... के विषय में पेटेन्टों के रजिस्टर में प्रविष्टियों को मैं शुद्धिकरण लिपिकीय गलती की शुद्धि के प्रति जिस शुद्धि के लिए ..... द्वारा आवेदन किया गया है, विरोध की एतद्द्वारा सूचना देता हूं/देते हैं।

वे आधार जिनपर उक्त शुद्धि की प्रार्थना का विरोध किया गया है, निम्न प्रकार हैं ..... भारत में तामील के लिए मेरा/हमारा पता निम्नलिखित है :—

.....

2. विरोधी पक्षकारों या प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।

तारीख आज, 19..... के/की ..... के ..... दिन

(हस्ताक्षर)[2] .....

सेवा में,

पेटेन्ट नियंत्रक,

पेटेन्ट कार्यालय।

जो लागू नहीं होता, उसे काट दीजिए।

प्ररूप 55 पेटेन्ट अधिनियम, 1970

फीस 30 रुपये धारा 77(1)(च) के अधीन नियंत्रक के विनिश्चय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन

(नियम 115(1) देखिए)

(विवरण की दो/तीन प्रतियों सहित इसकी दो/तीन प्रतियां दाखिल की जाएंगी)

1. पेटेन्ट के आवेदन की संख्या या पेटेन्ट और सुसंगत कार्यवाही लिखिए।

..... [1] ..... के विषय में मैं/हम[2] .....

.....

उपरोक्त विषय में आवेदक/विपक्षी पक्षकार होने के कारण एतद्द्वारा आवेदन करता हूं/करते हैं कि उपरोक्त विषय में तारीख ....के निर्णायक के विनिश्चय पुनर्विलोकित किया जाए।

2. आवेदक(गण) का नाम पता और राष्ट्रिकता लिखिए।

यह आवेदन करने के आधार संलग्न विवरण में उपवर्णित है।

3. आवेदक(गण) या प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

तारीख आज 19..... के/की ..... के ..... दिन।

(हस्ताक्षर)[3]

सेवा में,

पेटेन्ट नियंत्रक,

पेटेन्ट कार्यालय।

प्ररूप 56 पेटेन्ट अधिनियम, 1970

फीस 30 रुपये धारा 77(1)(छ) के अधीन नियंत्रक के आदेश को अपास्त करने के लिए आवेदन

(नियम 115(2) देखिए)

(विवरण की दो/तीन प्रतियां सहित दो/तीन प्रतियों में दाखिल किया जाएगा)

1. पेटेन्ट के लिए आवेदन या पेटेन्ट की संख्या और सुसंगत कार्यवाही लिखिए।

2. नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए,।

..... के विषय में मैं/हम[2] ....

उपरोक्त विषय में आवेदक (विपक्षी/पक्षकार) होने के कारण नियंत्रक के उपरोक्त विषय में ..... तारीख को ..... पारित एक पक्षीय आदेश को अपास्त करने के लिए एतद्द्वारा आवेदन करता हूं/करते हैं। यह आवेदन करने के आधार संलग्न विवरण में उपवर्णित हैं।

3. आवेदक(गण) या प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

तारीख आज 19..... के/की ..... के ..... दिन

(हस्ताक्षर)[3] .....

सेवा में,

पेटेन्ट नियंत्रक,

पेटेन्ट कार्यालय।

जो लागू नहीं होता, उसे काट दीजिए।

प्ररूप 57 पेटेन्ट अधिनियम, 1970

फीस 25 रुपये समय बढ़ाने के लिए प्रार्थना

(नियम 115 देखिए)

..... के विषय में

1. पेटेन्ट या पेटेन्ट के लिए आवेदन की संख्या और सुसंगत कार्यवाही लिखिए।

मैं/हम[2] .....

2. नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए। जो सुसंगत न हो उसे काट दीजिए।	एक मास का समय बढ़ाने के लिए एतद्द्वारा आवेदन करता हूं/करते हैं। (i) नियम 115(1) के अधीन नियंत्रक के विनिश्चय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए। (ii) नियम 115(2) के अधीन नियंत्रक के आदेश को उपास्त करने के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए।
3. आवेदक(कों) या प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।	यह प्रार्थना करने के निम्नलिखित कारण हैं ....

तारीख आज 19 ....के/की
के .... दिन

(हस्ताक्षर)[3] ....

सेवा में,
पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय।

जो लागू नहीं होता, उसे काट दीजिए।

प्ररूप 58 — पेटेन्ट अधिनियम, 1970

कोई फीस नहीं

धारा 146(2) के अधीन भारत में वाणिज्यिक मापमान पर पेटेन्टकृत आविष्कार संबंधी विवरण

(नियम 117 देखिए)

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए।	[1].............. के पेटेन्ट सं० .... के विषय में पेटेन्ट सं०....... का/के अधीन पेटेन्टधारी या अनुज्ञप्तिधारी मैं/हम ....
2. जिस से विवरण सम्बन्धित है, वह वर्ष लिखिए।	उक्त पेटेन्टकृत आविष्कार या भारत में वाणिज्यिक मापमान पर[2]..... वर्ष के लिए कार्यकरण संबंधी निम्नलिखित विवरण एतद्द्वारा देते हैं :—
3. उपलभ्य ब्यौरे दीजिए।	3(i) वह रीति और सीमा जिस में और जिस तक मेरे/हमारे पेटेन्ट पर काम किया गया है; (ii) वर्ष के दौरान अनुदत्त अनुज्ञप्तियां और उप-अनुज्ञप्तियां; (iii) उस उपक्रम के संबंध में ब्यौरे जिसके माध्यम से मेरे/हमारे पेटेन्ट पर काम किया गया है; (i) उपरि-वर्णित आविष्कार के कार्यकरण में उठाई गई कठिनाइयां :
4. विवरण देनेवाले व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।	इसमें कथित तथ्य और बातें मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

तारीख आज 19... के/की
....
के .... दिन

(हस्ताक्षर)[4] ....

सेवा में,
पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय।

जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए।

प्ररूप 59 — पेटेन्ट अधिनियम, 1970

फीस 50 रुपये

धारा 154 के अधीन पेटेन्ट की दूसरी प्रति के लिए आवेदन

(नियम 118 देखिए)

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए। 2. मूलकर्ता का नाम लिखिए। 3. यथास्थिति "खो गया" या "नष्ट हो गया" शब्द लिखिए और परिस्थितियों का सम्पूर्ण रूप से उल्लेख कीजिए। यदि पेटेन्ट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता तो इसके न प्रस्तुत किए जा सकने के कारण भी देने चाहिए। आवेदक या आवेदकों का पेटेन्ट में जो हित है उसका भी उल्लेख कीजिए।	मैं/हम[1] .... खेदपूर्वक आपको यह सूचित करता हूं/करते हैं कि [2]........... को अनुदत्त पेटेन्ट सं०......... तारीख.................. मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि इसमें कथित तथ्य और बातें मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास में सत्य हैं। अतः मैं/हम प्रार्थना करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें उसे पेटेन्ट की दूसरी प्रति जारी की जाए।

तारीख आज 19........के/की..
के ....दिन

(हस्ताक्षर)...........

सेवा में,
पेटेन्ट नियंत्रक,
पेटेन्ट कार्यालय।

प्ररूप 60 — पेटेन्ट अधिनियम, 1970

फीस 25 रुपये

धारा 72 के अधीन पेटेन्ट के रजिस्टर में प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतियों के लिए तथा 147 के अधीन प्रमाणपत्र के लिए प्रार्थना।

(नियम 119 देखिए)

1. नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए। 2. उनविनिष्टियों को जिनके प्रमाणित करने की नियंत्रक से प्रार्थना की गई है और उन दस्तावेजों की किन्हीं प्रतियों की विशिष्टियों को जो प्रमाण पत्र के साथ उपाबद्ध की जानी है, उपवर्णित कीजिए।	[1]..........के पेटेन्ट सं०...... .... के विषय में मैं/हम........... आपसे एतद्द्वारा प्रार्थना करता हूं/करते हैं कि आप इस आशय का/कि[2]..................... एक प्रमाणपत्र मुझे/हमें दें और.... की प्रमाणित प्रतिलिपि/प्रमाणपत्र भेजें। जिस प्रयोजन के लिए प्रमाण-पत्र अपेक्षित

है वह निम्न प्रकार है.....

.....

.....

.....

3. प्रार्थना करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा या प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।

तारीख आज 19.....के/की .....के..... दिन

(हस्ताक्षर)3 .....

सेवा में,

पेटेन्ट नियंत्रक,

पेटेन्ट कार्यालय।

जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए।

प्ररूप 61

फीस 10 रुपये

पेटेन्ट अधिनियम, 1970

धारा 153 के अधीन पेटेन्ट को या उसके संबंध में आवेदन को प्रमाणित करने वाले मामले के बारे में जानकारी के लिए प्रार्थना।

(नियम 120 देखिए)

1. पूरा नाम और पता लिखिए।

2. यहां उस मामले के बारे में विशिष्टियां उपवर्णित कीजिए जिसकी बाबत जानकारी ईप्सित है।

पेटेन्ट (पेटेन्ट आवेदन) सं०.....

के विषय में .....

.....के[2]

मैं/हम1.....

पूर्वोक्त पेटेन्ट/पेटेन्ट आवेदन को प्रमाणित करने वाली निम्नलिखित जानकारी मुझे/हमें भेजने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं/करते हैं :—

.....

.....

.....

.....

3. जानकारी चाहने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा या प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाए।

तारीख आज 19.....के/की .....के..... दिन

(हस्ताक्षर)3 .....

सेवा में,

पेटेन्ट नियंत्रक,

पेटेन्ट कार्यालय।

जो लागू नहीं होता, उसे काट दीजिए।

प्ररूप 62

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) के अधीन स्टाम्पित किया जाना है।

पेटेन्ट अधिनियम, 1970

(नियम 10 देखिए)

अधिनियम (धारा 127/132) के अधीन कार्यवाही या मामले में पेटेन्ट अभिकर्ता या किसी व्यक्ति के प्राधिकरण का प्ररूप

(नियम 127 देखिए)

मैं/हम 1 .....

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए।

2. पेटेन्ट अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति का पूरा नाम, पता और राष्ट्रिकता लिखिए।

3. संदर्भ संख्या का हवाला देते हुए, यदि ज्ञात हो, उस विशिष्ट मामले या कार्यवाही को लिखें जिसके लिए पेटेन्ट अभिकर्ता या व्यक्ति नियुक्त किया गया है।

4. अभिकर्ता को नियुक्त करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है।

.....

.....

.....

.....

को.....के[3] संबंध में मेरी/हमारी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत[2] करता हूं/करते हैं और प्रार्थना करता हूं/करते हैं कि इससे संबंधित सभी सूचनाएं, अभ्यपेक्षाएं और संसूचनाएं उसे अभिकर्ता को उपरोक्त पते पर भेजी जाएं।

मैं/हम एतद्द्वारा इसी मामले या कार्यवाही की बाबत इस के पूर्व सभी प्राधिकरणों को, यदि कोई हों, प्रतिसंहृत करता हूं/करते हैं।

तारीख आज 19.....के/की .....के..... दिन

(हस्ताक्षर)4 .....

सेवा में,

पेटेन्ट नियंत्रक,

पेटेन्ट कार्यालय।

जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए।

तृतीय अनुसूची

पेटेन्ट का प्ररूप (नियम 57 देखिए)

भारत सरकार

पेटेन्ट कार्यालय .....

19.....को.....की सं०.....

यतः..... ने घोषणा की है कि .....का आविष्कार उसके कब्जे में है और यह कि वह .....उसका वास्तविक और प्रथम आविष्कारक है (या वास्तविक या प्रथम आविष्कारक का विधिक प्रतिनिधि या समनुदेशिती है) और यह कि वह, पेटेन्ट अधिनियम, 1970 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, उक्त आविष्कार के पेटेन्ट के लिए हकदार है और यह कि उसे पेटेन्ट अनुदत्त करने के लिए कोई आक्षेप नहीं है;

और यतः उसने आवेदन द्वारा निवेदन किया है कि उसे उक्त आविष्कार के लिए पेटेन्ट अनुदत्त किया जाए;

और यतः उसने पूर्ण विनिर्देश द्वारा या उस में उस आविष्कार का स्वरूप और उसे क्रियान्वित करने की रीति विशिष्ट रूप से वर्णित और अभिनिश्चित की गई है;

अतः यह प्रतीत करते हैं कि ऊपर वर्णित आवेदक को (जिसमें उसका विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशिती या उनमें से कोई भी सम्मिलित है) पेटेन्ट अधिनियम, 1970 के उपबन्धों के और उक्त अधिनियम की धारा 47 में विनिर्दिष्ट शर्तों के तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों और उपबन्धों के अधीन रहते हुए, भारत में वस्तु या

पदार्थ को बनाने, उपयोग या प्रयोग करने, विक्रय करने या वितरण करने का/करने में पद्धति या प्रक्रिया का उपयोग या प्रयोग करने का और किसी अन्य व्यक्ति को, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि इस पेटेन्ट की विधिमान्यता गारन्टीकृत नहीं है और यह कि उस पेटेन्ट के बने रहने के लिए विहित फीस समयकृत संदत्त कर दी गई है ऐसे करने के लिए प्राधिकृत करने का अनन्य विशेषाधिकार 19.....के/की .....के.....दिन से पांच वर्ष/सात वर्ष/चौदह वर्ष तक रहेगा।

उसके साक्ष्य के रूप में नियंत्रक ने इस पेटेन्ट को 19.....के/की .....के..... दिन के रूप में मुद्रांकित कराया है।

पेटेन्ट नियंत्रक

मुद्रांकन की तारीख.....

टिप्पण—पेटेन्ट को यदि बनाए रखना है तो इसके नवीकरण की फीस 19.....के/की..... दिन और तत्पश्चात् प्रति वर्ष उसी दिन देय होगी।

चतुर्थ अनुसूची

नियंत्रक के समक्ष कार्यवाहियों में अनुज्ञेय खर्च का मापमान

(नियम 126 का परन्तुक देखिए)

प्रविष्टि सं०	वह विषय जिसकी बाबत खर्चा दिया जाना है	रकम
		रु०
1	धारा 25, 57, 60, 63 और 78 के अधीन विरोध की सूचना के लिए	50.00
2	धारा 84(1), 86(1), 89(1), 93(5), 96(1) और 97(1) के अधीन अनिवार्य अनुज्ञप्ति या पेटेन्टों के पृष्ठांकन के आवेदन के लिए	60.00
3	धारा 92(2) 93(5) के अधीन विरोध की सूचना के लिए	50.00
4	सुनवाई के समय हाजिर होने के आशय की सूचना के लिए	50.00
5	जहां पेटेन्ट अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति नियुक्त किया गया हो, वहां मुख्तारनामा के लिए स्टाम्प	वास्तव में संदत्त रकम
6	सुसंगत शपथपत्रों की बाबत स्टाम्प फीस	वास्तव में संदत्त रकम
7	नियम 36 के अधीन लिखित कथन के लिए	50.00
8	नियम 37 के अधीन उत्तर कथन के लिए	50.00
9	प्रत्येक शपथ-पत्र के लिए, यदि सुसंगत हो	25.00
10	किसी कार्यवाही में पेश की गई प्रत्येक	25.00
11	प्रत्येक अनावश्यक या असंगत शपथपत्र या प्रोद्धरण के लिए	25.00

पांचवीं अनुसूची

(नियम 127 देखिए)

भारतीय पेटेंट और डिजाइन नियम, 1933 में संशोधन

1. **नियम 1**—उपनियम (1) में "भारतीय पेटेन्ट और" को लुप्त कीजिए।

2. **नियम 2**—(i) खण्ड (क) में "भारतीय पेटेन्ट और" को लुप्त कीजिए।

(ii) खण्ड (ख) में "आविष्कार या" और "यथास्थिति" को लुप्त कीजिए।

(iii) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा -

"(ग)" "नियंत्रक" से व्यापार और वाणिज्य चिह्न अधिनियम, 1958 (1958 का 43) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त पेटेन्ट, डिजाइन और व्यापार चिह्न का महानियंत्रक अभिप्रेत है ;"

(i) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा—

"(घ) 'कार्यालय' से पेटेन्ट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 74 में निर्दिष्ट पेटेन्ट कार्यालय अभिप्रेत है।"

3. **नियम 3**—उपनियम (2) में "पेटेन्टधारी को या" और "पेटेन्ट रजिस्टर या" और "यथास्थिति" को लुप्त कीजिए।

4. **नियम 4**—"पेटेन्टधारी या", "पेटेन्ट या" और "पेटेन्टधारी" को लुप्त कीजिए।

5. **नियम 5**—उपनियम (1) में "पेटेन्टों के अनुदान और", "पेटेन्ट और" तथा परन्तुक को लुप्त कीजिए।

6. **नियम 6**—परन्तुक को लुप्त कीजिए।

8. **अध्याय 2** को लुप्त कीजिए।

8. **नियम 48**—उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा,—

"(4) आवेदक, रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के प्रतिकथन की एक प्रति अपने को प्रतिदत्त किए जाने के पश्चात् अपने मामले के समर्थन में शपथ-पत्र के रूप में साक्ष्य कार्यालय पर दे सकेगा और उसकी एक प्रति रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को भी परिदत्त करेगा।

(5) रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी, आवेदक का साक्ष्य अपने को परिदत्त किये जाने के पश्चात्, अपने मामले के समर्थन में शपथ-पत्र के रूप में साक्ष्य कार्यालय पर दे सकेगा और उसकी एक प्रति आवेदक को भी परिदत्त करेगा।

(6) आवेदक, रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के साक्ष्य की एक प्रति अपने को परिदत्त किए जाने के पश्चात् शपथ-पत्र के रूप में उत्तर साक्ष्य कार्यालय में दे सकेगा और ऐसे साक्ष्य की एक प्रति रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को भी परिदत्त करेगा।

(7) किसी भी पक्षकार द्वारा कोई भी अतिरिक्त कथन या साक्ष्य नियंत्रक की इजाजत या उसकी अपेक्षा पर के सिवाय नहीं दिया जाएगा।

(8) जहां धारा 51 के अधीन किसी आवेदन या उसके विरोध के संबंध में दाखिल किए गए किसी कथन या शपथपत्र में अंग्रेजी भाषा से भिन्न भाषा में की कोई दस्तावेज निर्दिष्ट की गई हो वहां उस दस्तावेज का अनुप्रमाणित अनुवाद दो प्रतियों में दिया जाएगा ।

(9) प्रतिकथन दाखिल करने के लिए या शपथपत्रों के रूप में साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात किया गया समय मामूली तौर से एक मास होगा जो समय को बढ़ाने की इच्छा करने वाले पक्षकार द्वारा दी गई अर्जी पर किए गए नियंत्रक के विशेष आदेश द्वारा ही बढ़ाया जा सकेगा ।

परन्तु इस प्रकार मंजूर किया गया समय का बढ़ाया जाना किसी भी दशा में कुल तीन मास से अधिक नहीं होगा ।

(10) उपनियम (3) से लेकर (8) तक में निर्दिष्ट कथन और साक्ष्य के दाखिल किए जाने पर ही या ऐसे अन्य समय पर जिसे वह विनिश्चित करे, नियंत्रक आवेदन की सुनवाई के लिए समय नियत करेगा और पक्षकारों को ऐसी सुनवाई की दिन से अन्यून की सूचना देगा ।

(11) यदि कोई भी पक्षकार सुने जाने की इच्छा करता होता तो वह सुनवाई में हाजिर रहने की अपने आशय की प्ररूप 7 में सूचना नियंत्रक को देगा ।

(12) यदि सुनवाई के समय किसी भी पक्षकार का किसी प्रकाशन को निर्दिष्ट करने का आशय है तो वह नियंत्रक और अन्य पक्षकार को ऐसे आशय की पांच दिन से अन्यून की सूचना देगा तथा उसके साथ जिस प्रकाशन को निर्दिष्ट करने का उसका आशय है उसके ब्योरे भी देगा ।

(13) सुने जाने की इच्छा करने वाले पक्षकार या पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् या, यदि कोई भी पक्षकार सुने जाने की इच्छा नहीं करता है या सुनवाई के समय हाजिर नहीं रहता है तो बिना सुनवाई के नियंत्रक आवेदन और विरोध पर, यदि कोई हो, विनिश्चय करेगा तथा अपना विनिश्चय पक्षकारों को अधिसूचित करेगा"।

9. **अध्याय 4** के शीर्षक में पेटेन्ट **और** " को लुप्त कीजिए ।

10. **नियम 49** से लेकर 51 तक लुप्त कीजिए ।

11. **नियम 53**— "पेटेन्टधारी या" को लुप्त कीजिए ।

12. **नियम 54**— "पेटेन्ट को या, "पेटेन्ट, या" और "यथास्थिति" को लुप्त कीजिए ।

13. **नियम 56**— "पेटेन्ट का या" को लुप्त कीजिए ।

14. **नियम 58**— "रजिस्टर" के स्थान पर "डिजाइन रजिस्टर" रखा जाएगा और "पेटेन्ट या" को लुप्त कीजिये ।

15. **नियम 59**—"पेटेन्ट और डिजाइन रजिस्टर" के स्थान पर डिजाइन रजिस्टर रखा जाएगा ।

16. **नियम 60**— "पेटेन्टों या" और "पेटेन्ट या" को लुप्त कीजिए ।

17. **नियम 61**—(i) विद्यमान नियम को उसके उपनियम (1) के रूप में पुनः संख्यांकित कीजिए और इस प्रकार पुनः संख्यांकित किए गए उपनियम (1) में "पेटेन्ट रजिस्टर या" और "और ऐसे विरोध को निपटाने की प्रक्रिया नियम 20, 21 और 22 के उपबंधों द्वारा विनियमित की जाएगी" को लुप्त कीजिए ।

(ii) इस प्रकार पुनः संख्यांकित किए गए उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा—

"(2) विरोधी, विरोध की सूचना देने के चौदह दिन के भीतर दो प्रतियों में अपना लिखित कथन कार्यालय में देगा जिसमें वह अपने हित की प्रकृति, जिन तथ्यों पर वह अपना विरोध आधारित करता है उनको तथा जिस अनुतोष को वह चाहता है, उसको उपवर्णित करेगा ।

(3) नियंत्रक विरोध की सूचना की और लिखित कथन की एक एक प्रति आवेदक को भेजेगा ।

(4) नियम 48 के उपनियम (4) से लेकर (13) तक में विनिर्दिष्ट साक्ष्य देने और सुनवाई से संबंधित प्रक्रिया, यावत्शक्य धारा 64 के अधीन आवेदन की सुनवाई को इस प्रकार लागू होगी जैसे कि वे धारा 51क के अधीन किसी आवेदन की सुनवाई को लागू होती है ।"

18. **नियम 62**— उपनियम (3) के खंड (क) में, "अधिनियम की धारा 9, 10 (1क), 16 और 17 के अधीन अपीलों में," को लुप्त कीजिए ।

19. **नियम 63**—"रजिस्टर" के स्थान पर "डिजाइन रजिस्टर" रखा जाएगा । और "पेटेन्टों, विनिर्देशों" को लुप्त कीजिए ।

20. **नियम 63**—क को लुप्त कीजिए ।

21. **नियम 63**— ध को लुप्त कीजिए ।

22. **नियम 64**—"पेटेन्ट के लिए या" तथा "यथास्थिति अस्वीकृत या" को लुप्त कीजिए ।

23. **प्रथम अनुसूची**—

(i) प्रविष्टि संख्या 1 से लेकर 24 तक लुप्त कीजिए ;

(ii) प्रविष्टि संख्या 25 में, "पेटेन्ट न कराए गए किसी आविष्कार या" और "40 या" को लुप्त कीजिए;

(iii) प्रविष्टि संख्या 34 में "विनिर्देश आदि के (या का)" लुप्त कीजिए और "रेखाचित्र" के स्थान पर डिजाइनों के रूपणों की प्रतियां" रखा जाएगा

(iv) प्रविष्टि संख्या 37क को लुप्त कीजिए ;

(v) प्रविष्टि संख्या 41 और 43 में "पेटेन्ट का या", या इन नियमों के प्रवृत्त होने के" और "पेटेन्ट या" को लुप्त कीजिए ;

(vi) प्रविष्टि संख्या 42 और 44 में "पेटेन्ट का या", "और इन नियमों का प्रवृत्त होने" और "पेटेन्ट या" को लुप्त कीजिए ;

(vii) प्रविष्टि संख्या 45 में, "पेटेन्ट का या", "पेटेन्ट का अनुदान", "या इन नियमों के प्रवृत्त होके" और" पेटेन्ट या" को लुप्त कीजिए;

(viii) प्रविष्टि संख्या 46 में, "पेटेन्ट का या", "पेटेन्ट का अनुदान", "और इन नियमों का प्रवृत्त होना" और "पेटेन्ट या" को लुप्त कीजिए ;

(ix) प्रविष्टि संख्या 48 में, "20 या" को लुप्त कीजिए ;

(x) प्रविष्टि संख्या 52 में, "5, 9, 10 (1क), 16, 17" को लुप्त कीजिए ।

24. द्वितीय अनुसूची में—

(i) प्ररूपों की सूची के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूपों की सूची रखी जाएगी:—

"प्ररूपों की सूची"

प्ररूप	अधिनियम की धारा या नियम	नाम
4	नियम 38क	समय बढ़ाने के लिए आवेदन ।
5	43, 69	अपील ।
6	नियम 61	विरोध की सूचना ।
7	नियम 48 या 61	सुनवाई के समय हाजिर रहने के आशय की सूचना ।
14	40, 32	किसी अरजिस्ट्रीकृत डिजाइन के आशयित प्रदर्शन या प्रकाशन की सूचना ।
15	43	डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ।
16	78क	व्यतिकारी व्यवस्थाओं के अधीन डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ।
17	43	किसी संवर्ग को लागू डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ।
18	नियम 41	विनिश्चय के आधारों के लिए निवेदन ।
19	47	कापीराइट (प्रतिलिप्यधिकार) को बढ़ाने के लिए आवेदन ।
20	51	जब रजिस्ट्रीकरण संख्यांक दे दिया जाए तब जानकारी के लिए आवेदन ।
21	51	जब रजिस्ट्रीकरण संख्यांक न दिया जाए तब जानकारी के लिए आवेदन ।
22	51क	डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए नियंत्रक को आवेदन ।
23	नियम 53	नाम या रजिस्टर में तामील के लिए दिए गए पते या पतों में परिवर्तन करने के लिए निवेदन ।
24	20, 46	रजिस्टर में दो पतों की प्रविष्टियों के लिए निवेदन ।
25	63	रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए आवेदन ।
26	63	रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए आवेदन ।
27	नियम 58	रजिस्टर में दस्तावेजों की अधिसूचना की प्रविष्टि के लिए आवेदन ।
28	52	शुद्धि के लिए निवेदन ।
29	59 (नियम 63)	प्रमाणपत्र के लिए निवेदन ।
30	64	रजिस्टर की परिशुद्धि के लिए आवेदन ।
31	76	अभिकर्ता को प्राधिकार की शक्ति ।

(ii) सभी प्ररूपों के शीर्षक में—
भारतीय पेटेन्ट और को लुप्त कीजिए ;

(iii) प्ररूप 1, 1क, 1ख, 1ग, 1कग, 1गग, 1खग2, 2क, 2ग, 2कग, 3, 3क, 8, 9, 10, 11, 11क, 11ख, 11ख, 11ग, 12, 13 और 29क को लुप्त कीजिए ;

(iv) प्ररूप 4 में—

(क) "धारा 4क, 5, 10, 14 या नियम 11 या 38क" के स्थान पर "(नियम 38क देखिए)" रखा जाएगा ;

(ख) (क) से लेकर (घ) तक की मदें लुप्त कीजिए ;

(v) प्ररूप 5 में "धारा 5,9,10, (1क), 16, 17," और (क) से लेकर (झ) तक की मदें लुप्त कीजिए ;

(vi) प्ररूप 6 में—

(क) "धारा 9,15, 16 या 17 या नियम 25, 33 या 61" के स्थान पर "(नियम 61 देखिए)" रखा जाएगा ;

(ख) (क) से लेकर (ज) तक की मदों को लुप्त कीजिए ;

(ग) "पेटेन्टों" और "पेटेन्टों" को लुप्त कीजिए ;

(vii) प्ररूप 7 में, "धारा 9, 10(1क), 16, 17, 23घ(5), 24 या नियम 48 या 61" के स्थान पर "नियम 48 (ii) और 61 देखिए" रखा जाएगा ;

(viii) प्ररूप 14 में—

(क) "पेटेन्ट न कराये गए प्राधिकार या" को लुप्त कीजिए ।

(ख) "धारा 40 से 52" के स्थान पर "धारा 52" रखी जाएगी ;

(ग) मद (घ) में "भारतीय पेटेन्ट और" को लुप्त कीजिए ;

(ix) प्ररूप 23 में—

(क) "पेटेन्ट का या" और "————————की पेटेन्ट संख्या————————" को लुप्त कीजिए ;

(ख) "पेटेन्ट डिजाइन रजिस्टर" के स्थान पर "डिजाइन रजिस्टर" रखा जाएगा ;

(ग) टिप्पण में "पेटेन्ट या 6" को लुप्त कीजिए ;

(x) प्ररूप 24 में—

(क) जिन दो स्थानों पर "पेटेन्ट डिजाइन रजिस्टर" आया है उनके स्थान पर "डिजाइन रजिस्टर" रखा जाएगा ;

(ख) "20 या" और "————————की पेटेन्ट संख्या————————" को लुप्त कीजिए ;

(xi) प्ररूप 25 में,—

(क) जिन दो स्थानों पर "पेटेन्ट/डिजाइन रजिस्टर" आया है उनके स्थान पर "डिजाइन रजिस्टर" रखा जाएगा ;

(ख) "————————को जिसका नाम———————— है अनुदत्त————————के पेटेन्टों (पेन्टेट) की संख्या————————का" को लुप्त कीजिए ;

(ग) हाशिए में के टिप्पण 2 और 3 को लुप्त कीजिए ;

(घ) पादटिप्पण में—

(क) "या भारतीय पेटेन्ट और डिजाइन नियम, 1933 का प्रवृत्त होना" को लुप्त कीजिए ;

(ख) "पेटेन्ट या" जहां कहीं भी आएं उन्हें लुप्त कीजिए ;

(xii) प्ररूप 26 में—

(क) जिन दो स्थानों पर "पेटेन्ट/डिजाइन रजिस्टर" आया है उनके स्थान पर "डिजाइन रजिस्टर" रखा जाएगा ;

(ख) "————————को जिसका नाम————————है अनुदत्त————————के पेटेन्ट (पेटेन्टों) की संख्या————————का" को लुप्त कीजिए ;

(ग) हाशिए में के टिप्पण 3 और 4 लुप्त कीजिए ;

(घ) पादटिप्पण में—

(क) "या भारतीय पेटेन्ट और डिजाइन नियम, 1933 का प्रवृत्त होना" को लुप्त कीजिए ;

(ख) "पेटेन्ट या" जहां कहीं भी आएं उन्हें लुप्त कीजिए ।

(xiii) प्ररूप 27 में,—

(क) "पेटेन्ट/डिजाइन रजिस्टर" के स्थान पर "डिजाइन रजिस्टर" रखा जाएगा ;

(ख) "29 या" और "पेटेन्ट (पेटेन्टों)" को लुप्त कीजिए ;

(ग) पादटिप्पण में,—

(क) "पेटेन्ट का अनुदान या" और "या भारतीय पेटेन्ट और डिजाइन नियम, 1933 का प्रवृत्त होना" को लुप्त कीजिए ;

(ख) "पेटेन्ट या" जहां कहीं भी आए उन्हें लुप्त कीजिए ।

(xiv) प्ररूप 29 में—

(क) "————————की पेटेन्ट संख्या————————" को लुप्त कीजिए ;

(ख) हाशिए के शीर्षक संख्या पर "1 डिजाइन का संख्यांक और वर्ग अन्तःस्थापित कीजिए" रखा जाएगा ।

(xv) प्ररूप 30 में,—

(क) "पेटेन्ट/डिजाइन रजिस्टर" के स्थान पर "डिजाइन रजिस्टर" रखा जाएगा ;

(ख) "पेटेन्ट/डिजाइन" के स्थान पर "डिजाइन" रखा जाएगा ;

(ग) हाशिए के शीर्षक संख्या 2 में "पेटेन्ट या का" को लुप्त कीजिए ।

25. तृतीय अनुसूची को लुप्त कीजिए ।

26. पांचवी अनुसूची में,—

(i) प्रविष्टि संख्या 1 में, "धारा 9, 16 और 17 तथा नियम 33 और 61" के स्थान पर "नियम 48 और नियम 61" रखा जाएगा ;

(ii) प्रविष्टि संख्या 2 और 3 को लुप्त कीजिए ;

(iii) प्रविष्टि संख्या 8 में "नियम 21 (1) या" को लुप्त कीजिए ।

(iv) प्रविष्टि संख्या 9 में "नियम 21 (2) या" को लुप्त कीजिए ।

[सं० फा० 33(1)—पी०पी० एण्ड डी०/71]

आर० के० तलवार, संयुक्त सचिव

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1973

का. आ. 166.—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 जनवरी, 1961, की अधिसूचना सं. 17-43/59-एम.-1 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजनों के लिए यूनिवर्सिटी आफ इल्लिनोइस, संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा प्रदत्त एम. डी. चिकित्सा अर्हता मान्य चिकित्सा अर्हता होगी ;

और यतः डा. लोइस हेलीना विस्सचर को जिनके पास उक्त अर्हता है शिक्षण एवं धर्मार्थ कार्य के प्रयोजनों के लिए फिलहाल कासगंज, उत्तर प्रदेश स्थित क्रिश्चियन अस्पताल के साथ सम्बद्ध है ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के परन्तुक के भाग (ग) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा—

(1) पहली जुलाई, 1974 को समाप्त होने वाली दो वर्ष की और अवधि

अथवा

(2) उस अवधि की जब तक डा. लोइस हेलीना विस्सचर जो कासगंज, उत्तर प्रदेश स्थित क्रिश्चियन अस्पताल के साथ सम्बद्ध रहते हैं, जो भी कम हो, वह अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसमें पूर्वोक्त डा. मेडिकल प्रैक्टिस कर सकेंगे ।

[प. सं. वी. 11016/21/72-एम.पी.टी.]

प्रकाश चन्द्र अरोरा, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

New Delhi, the 2nd January, 1973

ORDER

S.O. 166.—WHEREAS by the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. 17-43/59 MI, dated the 9th January, 1961, the Central Government has directed that the Medical qualification, M.D. (University of Illinois, U.S.A.) shall be recognised medical qualification for the purposes of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956);

AND WHEREAS Dr. Lois Helena Visscher who possesses the said qualification is for the time being attached to the Christian Hospital, Kasganj, Uttar Pradesh for the purposes of teaching and charitable work;

NOW, THEREFORE, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies—

(i) a further period of two years ending on the 1st July, 1974, or

(ii) the period during which Dr. Lois Helena Visscher is attached to the said christian Hospital, Kasganj, Uttar Pradesh, whichever is shorter, as the period of which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. V. 11016/21/72-MPT]

P. C. ARORA, Under Secy.

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1972

का. आ. 167.—पूर्त-अक्षय निधि अधिनियम, 1890 के मामले में और पुस्तकालय विज्ञान के लिए शारदा रंगानाथन अक्षय निधि के मामले में केन्द्रीय सरकार को, इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति को पूर्त-अक्षय निधि के खजांची में निहित करने के लिए एक आवेदन पत्र भेजा गया है, जो भूतपूर्व शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस. ओ. 3371 दिनांक 27 नवम्बर, 1963 (जो इसके बाद उक्त योजना कहलायेगी) के साथ प्रकाशित योजना के अनुसार अनुप्रयुक्त होगी ।

अतः अब, पूर्त-अक्षय निधि अधिनियम, 1890 (1890 के 6) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्वोक्त आवेदन-पत्र पर, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निर्देश करती है कि उक्त सम्पत्ति भारत के पूर्त-अक्षय निधि के खजांची, जो कार्यालय में उसके द्वारा तथा उसके उत्तराधिकारी द्वारा धार्य होगा, में निहित होगा और यह भी निदेश देता है कि उक्त सम्पत्ति और उसकी आय का उपयोग उपरोक्त योजना में निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

अनुसूची

पुस्तकालय विज्ञान के लिए शारदा रंगानाथन अक्षय निधि की ओर से आवधिक जमा में तमिल नाडु औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड मद्रास में उनके आवधिक खाते की रसीद संख्या 19022 दिनांक 22 अगस्त, 1972 द्वारा 50,000/- रुपये की पूंजी लगाई गई ।

[सं. एफ. 4-1/71-सी. ए. 1(3)]

ए. एस. तलवार, अवर सचिव

MINISTRY OF EDUCATION SOCIAL WELFARE

(Department of Culture)

New Delhi, the 29th December, 1972

S.O. 167.—*In the matter of the Charitable Endowments Act, 1890 and*

In the matter of the Sarda Ranganathan Endowment for Library Science.

WHEREAS an application has been made to the Central Government for vesting the property specified in the Schedule appended hereto in the Treasurer of Charitable Endowments for India, to be applied in accordance with the Scheme, published with the notification of the Government of India in the late Ministry of Education No. S.O. 3371, dated the 27th November, 1963 (hereinafter referred to as the said scheme);

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890), and upon the applications as aforesaid, the Central Government hereby directs that the said property shall vest in the Treasurer of Charitable Endowments for India to be held by him and his successor in office and directs that the said property and the income thereof shall be applied in accordance with the terms set out in the said scheme.

THE SCHEDULE

A sum of Rs. 50,000/- invested on behalf of the Sarada Ranganathan Endowment for Library Science in Fixed Deposit with the Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Limited Madras *vide* their Fixed Deposit Receipt No. 19022, dated 22nd August, 1972.

[No F. 4-1/71-CAI(3)]

A. S. TALWAR, Under Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1973

का. आ. 168.—सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950, (1950 का 64) की धारा 44 की उप-धारा (2) के खंड (एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम

(1) इन नियमों का नाम दिल्ली परिवहन निगम (सलाहकार परिषद्) नियम, 1973 होगा ।

(2) उक्त नियम, शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन होने की तारीख को लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "अधिनियम" से सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 क 64) अभिप्रेत है,

(ख) "अध्यक्ष" से परिषद का अध्यक्ष अभिप्रेत है,

(ग) "निगम" से दिल्ली परिवहन निगम अभिप्रेत है,

(घ) "परिषद्" से अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत संगठित सलाहकार परिषद् अभिप्रेत है,

(ङ) "उपाध्यक्ष" से परिषद् का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है,

(च) "अवर उपाध्यक्ष" से परिषद् का अवर उपाध्यक्ष अभिप्रेत है,

(छ) "सचिव" से परिषद् का सचिव अभिप्रेत है ।

3. परिषद् का संगठन

(1) परिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(क) निगम का अध्यक्ष, जो कि पदेन परिषद् का अध्यक्ष होगा ।

(ख) निगम का उपाध्यक्ष, जो कि परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा ।

(ग) निगम का महाप्रबंधक, जो कि परिषद् का पदेन अवर उपाध्यक्ष होगा ।

(घ) निगम के यातायात विभाग का प्रधान ।

(ङ) निगम के यान्त्रिक इंजीनियरी विभाग का प्रधान ।

(च) दिल्ली महानगर परिषद् का एक प्रतिनिधि ।

(छ) दिल्ली नगर निगम का एक प्रतिनिधि ।

(ज) दो संसद सदस्य ।

(झ) दिल्ली परिवहन निगम कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि ।

(ञ) जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली का एक विद्यार्थी प्रतिनिधि ।

(ट) दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के दो प्रतिनिधि ।

(ठ) दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति द्वारा नामित उक्त विश्वविद्यालय की छात्राओं की ओर से एक प्रतिनिधि ।

(ड) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि ।

(ढ) श्रमिकों के दो प्रतिनिधि ।

(ण) मुख्य कल्याण अधिकारी, कर्मी विभाग, मंत्री मंडल सचिवालय, भारत सरकार ।

(त) दिल्ली कैंटोन्मेंट बोर्ड का एक प्रतिनिधि ।

(थ) दिल्ली पुलिस का एक प्रतिनिधि ।

(द) दिल्ली सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि ।

(ध) दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली का एक प्रतिनिधि ।

(न) परिवहन निदेशालय का एक प्रतिनिधि ।

(प) नई दिल्ली नगर पालिका का एक प्रतिनिधि ।

(फ) उपभोक्ताओं या किसी अन्य आवश्यक समझे गये हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा चार व्यक्तियों का नामांकन किया जाना है ।

(ब) दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी कल्याण विभाग के डीन ।

(2) परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अवर उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जायेगी ।

4. **परिषद् के सचिव**

निगम एक सचिव की नियुक्ति करेगा जोकि, परिषद् के निमंत्रण और निदेशन के अंतर्गत, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कर्तव्य निभाएगा जोकि उसे परिषद् या उसके अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये जायेंगे ।

5. **परिषद् का सदस्य चुने जाने या बनाए जाने के संबंध में अयोग्यताएं :**

कोई व्यक्ति परिषद् का सदस्य चुने जाने या बनाए जाने के संबंध में अयोग्य होगा :—

(क) यदि वह विकृत चित्त है और इस बात की घोषणा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा की जाती है ।

(ख) यदि उसे दिवालिया घोषित किया गया है, या

(ग) यदि नैतिक भ्रष्टता संबंधी किसी अपराध के कारण उसकी गिरफ्तारी की गई है, या

(घ) यदि प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः समाविष्ट कंपनी में निगम के साथ किसी वर्तमान करार या उसके लिये किये जा रहे किसी कार्य में उसका कोई हित हो (सिवाय हिस्सेदार के रूप में, न कि निदेशक के तौर पर), बशर्ते कि जहां वह हिस्सेदार है, वहां पर केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त कंपनी में उसके द्वारा धारित शेयरों की प्रकृति और सीमा के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सूचना देगा, या

(ङ) यदि उसका किसी अन्य सड़क परिवहन उपक्रम या निगम में कोई वित्तीय हित है ।

6. **परिषद् के सदस्य, अवैतनिक हैसियत में काम करेंगे ।**

7. **कार्यावधि**

नियम 22 के उपबन्धों के अनुसार परिषद् का एक सदस्य उस अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिये पद पर रहेगा जिसके द्वारा उसे परिषद् का सदस्य नियुक्त किया गया है और वह पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होगा, बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, दो वर्ष की उक्त अवधि के दौरान किसी सदस्य की सदस्यता को समाप्त कर देती है और उत्तराधिकारी की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना के प्रकाशन तक सेवा निवृत होने वाला कोई सदस्य कार्य करता रहेगा ।

8. **अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अवर उपाध्यक्ष या सदस्य द्वारा अपने पद से त्यागपत्र**

(1) केन्द्रीय सरकार को लिखित नोटिस देकर परिषद् का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अवर उपाध्यक्ष या सदस्य अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है ।

(2) परिषद् के सदस्य का पद उस तारीख से रिक्त हो जायेगा जबकि उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाता है या केन्द्रीय सरकार द्वारा त्यागपत्र की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की समाप्ति पर उक्त पद रिक्त हो जायेगा, दोनों में से जो भी पहले हो ।

9. **अस्थायी रिक्त स्थान**

परिषद् में आकस्मिक रिक्त स्थान केन्द्रीय सरकार द्वारा नई नियुक्ति द्वारा भरा जायेगा, बशर्ते कि इस प्रकार नियुक्त किया गया सदस्य उस अवधि के लिये पद धारण करेगा जिसके संबंध में वह सदस्य जिसका स्थान वह भरता है, यदि रिक्त स्थान न होता तो भी वह उस पद को धारण करता ।

10. **सदस्यों संबंधी रिक्त स्थान, जोकि परिषद् के अधिनियमों या कार्यवाहियों को अमान्य नहीं करते**

अपने सदस्यों के किसी रिक्त स्थान के होने के कारण ही, परिषद् का कोई भी अधिनियम या कार्यवाई अमान्य नहीं होगी ।

11. **परिषद् के कार्य**

परिषद् का कार्य सभी अथवा निम्नलिखित मामलों में से किसी पर निगम को सलाह देना होगा :—

(1) उन मार्गों से संबंधित प्रश्न जिन पर सेवाएं चलाई जाएंगी ।

(2) सेवाओं की आवृत्ति से संबंधित प्रश्न ।

(3) समय सारणियां ।

(4) यात्रियों के लिये सुविधाएं ।

(5) यात्रियों और माल के लिये स्टैन्डों, शेडों आदि का निर्माण और डिपुओं, उप-डिपुओं और बस स्टेशनों की स्थापना ।

(6) खंड (5) में निर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिये उपयुक्त स्थानों और भूमि की खरीद या अधिप्राप्ति ।

(7) निगम द्वारा चलाई जा रही सेवाओं से संबंधित कोई अन्य मामला जोकि निगम, परिषद् के सामने रख सकता है ।

12—परिषद् की बैठक के संचालन करने की प्रक्रिया

(1) परिषद् दो महीनों में कम से कम एक बार बैठक करेगी, और उपर्युक्त को छोड़कर परिषद् ऐसे समय और ऐसे स्थानों पर बैठक करेगी जिनका निर्धारण अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा ।

(2) परिषद् के सदस्यों के साथ परामर्श करके अध्यक्ष परिषद् की बैठकों के लिये तिथियों का निर्णय करेगा ।

(3) बैठक के लिये निर्धारित तारीख से कम से कम तीन दिन पहले सचिव, परिषद् के सभी सदस्यों को बैठकों की तारीख, समय और स्थान के बारे में सूचना भेजेगा,

बशर्ते कि उन बैठकों के विषय में कोई सूचना भेजना आवश्यक नहीं होगा जिनके लिये निर्दिष्ट तारीखें नियत की गई हैं ।

13—विशेष बैठक

(1) अध्यक्ष, लिखित मांग पर जोकि सात सदस्यों से कम द्वारा नहीं पेश की जायेगी, परिषद् की एक विशेष बैठक बुलाएगा बशर्ते कि किसी वर्ष में ऐसी तीन से अधिक विशेष बैठकें नहीं होंगी ।

(2) एक विशेष बैठक के लिये लिखित मांग के साथ उन विषयों की एक सूची भी संलग्न की जायेगी जोकि बैठक में चर्चा के लिये प्रस्तावित हैं और उसके साथ प्रत्येक विषय पर टिप्पणियां भी प्रेषित की जायें ।

(3) बैठक के लिये निर्धारित तारीख से कम से कम तीन दिन पहले सचिव, सदस्यों को विशेष बैठक की सूचना भेजेगा और उसके साथ कार्य सूची और टिप्पणियों की एक प्रति भेजेगा ।

14—कार्यसूची :

सचिव, द्वारा सदस्यों में बैठक की सूचना के साथ साथ साधारण तथा टिप्पणियों सहित कार्यसूची की प्रति, यदि हो, परिचालित की जायेगी ।

15—विशेष विषय :

नियम 12 में दर्ज सामग्री के बावजूद अध्यक्ष स्वयं या किसी सदस्य को परिषद् के विचारार्थ कोई ऐसा मामला रखने की अनुमति दे सकता है जो कि कार्यसूची में शामिल नहीं है और जिसके संबंध में परिषद् की सिफारिशों की तुरन्त आवश्यकता है तथा परिषद् ऐसी बैठक में इस विषय पर विचार करेगी ।

16—प्रस्ताव की सूचना :

कोई भी सदस्य जो कि किसी साधारण बैठक में कोई प्रस्ताव रखना चाहता है, एक संक्षिप्त टिप्पणी सहित ऐसे प्रस्ताव की सूचना तथा उसके समर्थन में कारणों का विवरण बैठक के लिये निर्धारित तारीख से कम से कम 15 दिन पहले सचिव को भेजेगा । उसकी प्राप्ति के यथाशीघ्र टिप्पणी सहित ऐसी सूचना की एक प्रति साधारणतया सदस्यों में परिचालित की जायेगी ।

17—सभापति के रूप में अध्यक्ष :

परिषद् की प्रत्येक बैठक का सभापतित्व अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और उन दोनों की गैर हाजिरी में बैठक का सभापतित्व अवर उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में मौजूद सदस्यों में कोई एक उस बैठक का अध्यक्ष होगा जोकि सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जायेगा ।

18—कोरम :

अध्यक्ष सहित दस सदस्यों का कोरम होगा ।

19—कोरम के अभाव में बैठक का स्थगन :

(1) यदि बैठक के लिये निश्चित समय के आधे घंटे के अन्दर कोरम मौजूद न हो तो बैठक उस तारीख तक स्थगित कर दी जायेगी जिसका निर्धारण अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा ।

(2) यदि स्थगित बैठक में नियत समय से आधे घंटे के अन्दर कोरम मौजूद न हो तो उपस्थित सदस्य कोरम की अनुपस्थिति के बावजूद परिषद् के सामने कार्रवाई शुरू कर देंगे ।

20—बहुमत द्वारा प्रश्नों का फैसला किया जायेगा :

(1) बैठक में रखे गये सभी प्रश्नों पर, उपस्थित सदस्यों द्वारा बहुमत से फैसला किया जायेगा ।

(2) एक समान मतदान प्राप्त होने की हालत में अध्यक्ष को दूसरा या निर्णयात्मक मतदान प्राप्त होगा ।

(3) सचिव को परिषद् की चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार होगा परन्तु उसे किसी बैठक में मतदान देने का अधिकार नहीं होगा ।

21—कार्यवृत्त :

(1) प्रत्येक बैठक की कार्रवाइयों का कार्यवृत्त सचिव द्वारा तैयार किया जायेगा और यथाशीघ्र उसे परिषद् के सदस्यों में परिचालित किया जायेगा तथा तत्पश्चात् उसे कार्यवृत्त पुस्तक में दर्ज किया जायेगा और उसे स्थायी रिकार्ड के रूप में रखा जायेगा ।

(2) प्रत्येक बैठक की कार्यवाही संबंधी कार्यवृत्त पर आगामी बैठक में अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे, जब तक कि पिछली बैठक में मौजूद कोई सदस्य कार्यवृत्त के संबंध में इसलिये आपत्ति उठाता है कि उसे गलत ढंग से या अपूर्ण रूप से लिखा गया है और उस हालात में अध्यक्ष, बैठक में उपस्थित सदस्यों के मत से कार्यवृत्त में ऐसे संशोधन करेगा जिसे वह उचित समझेगा और फिर अध्यक्ष द्वारा संशोधित कार्यवृत्त की पुष्टि और उस पर हस्ताक्षर किये जायेंगे ।

22—पद की समाप्ति :

पदेन सदस्य के अतिरिक्त यदि कोई सदस्य अध्यक्ष की अनुमति बिना निरन्तर तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसकी परिषद् की सदस्यता समाप्त हो जायेगी ।

23—निःशुल्क बस पास :

परिषद् का प्रत्येक सदस्य दिल्ली के संघराज्य क्षेत्र में निगम द्वारा चलाई जा रही सेवाओं में यात्रा करने के लिये एक सर्व-मार्गीय निशुल्क बस पास प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।

[सं. 15-टी. ए. जी. (15)/72]

एन. आर. रेड्डी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 6th January, 1973

S.O. 168.—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of section 44 of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short Title:**

(1) These rules may be called the Delhi Transport Corporation (Advisory Council) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Definitions:**

In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) 'Act' means the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950);

(b) 'Chairman' means the Chairman of the Council;

(c) 'Corporation' means the Delhi Transport Corporation

(d) 'Council' means the Advisory Council constituted under section 17 of the Act;

(e) 'Junior Vice Chairman' means the Junior Vice Chairman of the Council;

(f) 'Secretary' means the Secretary of the Council;

(g) 'Vice Chairman' means the Vice Chairman of the Council.

3. **Constitution of the Council:**

The Council shall consist of the following members, namely:

(a) The Chairman of the Corporation, who shall be ex-officio Chairman of the Council.

(b) Vice-Chairman of the Corporation who shall be ex-officio Vice Chairman of the Council.

(c) General Manager of the Corporation, who shall be ex-officio Junior Vice Chairman of the Council.

(d) Head of the Traffic Department of the Corporation.

(e) Head of the Mechanical Engineering Department of the Corporation.

(f) One representative of the Delhi Metropolitan Council.

(g) One representative of the Delhi Municipal Corporation.

(h) Two Members of Parliament.

(i) Two representatives of the Delhi Transport Corporation workers.

(j) One student representative of the Jamia Milia Islamia, Delhi.

(k) Two representatives of boys students of Delhi University.

(l) One representative of the girl students of the Delhi University to be nominated by the Vice Chancellor of that University.

(m) One representative of Central Government employees.

(n) Two representatives of labour.

(o) Chief Welfare Officer, Department of Personnel, Cabinet Secretariat, Government of India.

(p) One representative of the Delhi Cantonment Board.

(q) One representative of the Delhi Police.

(r) One representative of the Delhi Public Works Department.

(s) One representative of the Delhi Development Authority.

(t) One representative of the Directorate of Transport, Delhi.

(u) One representative of the New Delhi Municipal Committee.

(v) Four persons to be nominated by the Central Government to represent users or any other interests considered necessary.

(w) Dean of Students Welfare, University of Delhi.

(2) The Chairman, the Vice Chairman, junior Vice-Chairman and other members of the Council shall be appointed by the Central Government.

4. **Secretary of the Council:**

The Corporation shall appoint a Secretary who shall, under the control and direction of the Council, exercise such powers and perform such duties as may be delegated to him by the Council or the Chairman.

5. Disqualifications for being chosen as or for being a member of the Council:

A person shall be disqualified for being chosen as, or for being, a member of the Council:—

(a) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent Court; or

(b) if he has been adjudged an insolvent; or

(c) if he has been convicted of an offence involving moral turpitude; or

(d) if he has directly or indirectly, any interest in any subsisting contract made with, or in any work being done for, the Corporation (except as a shareholder not being a director) in an incorporated company, provided that where he is a share-holder he shall disclose to the Central Government the nature and extent of shares held by him in such company; or

(e) if he has any financial interest in any other road transport undertaking or corporation.

6. The members of the Council shall serve in an honorary capacity.

7. **Term of Office:**

Subject to the provisions of rule 22 a member of the Council, shall hold office for a period of two years from the date of the notification appointing him a member of the Council and shall be eligible for re-appointment, provided that the Central Government may, by order, terminate the membership of any member during the said term of two years and any out-going member shall continue in office until the notification of the appointment of his successor.

8. Resignation of office by the Chairman, the Vice-Chairman, the Junior Vice-Chairman or by a member

(1) The Chairman, the Vice-Chairman, the Junior Vice-Chairman or a member of the Council may resign his office by giving notice in writing to the Central Government.

(2) The office of a member of the Council shall fall vacant from the date on which his resignation is accepted or on the expiry of thirty days from the date of receipt of resignation by the Central Government, whichever is earlier.

9. **Temporary vacancies:**

A casual vacancy in the Council shall be filled by a fresh appointment made by the Central Government provided that

a member so appointed shall hold office for the period for which the member whose place he fills would have held office if the vacancy had not occurred.

10. Vacancies amongst members not to invalidate acts or proceedings of the Council.

No act or proceeding of the Council shall be invalid by reason only of the existence of any vacancy amongst its members.

11. **Functions of the Council:**

The functions of the Council shall be to advise the Corporation on all or any of the following matters:—

(i) questions relating to routes on which the services will be operated;

(ii) questions relating to frequencies of services:

(iii) time tables;

(iv) amenities for the passengers;

(v) the erection of stands, sheds for passengers and goods and the setting up of depots, sub-depots and bus stations;

(vi) the purchase or acquisition of sites and lands suitable for any of the purposes specified in clause (v);

(vii) Any other matter relating to the services operated by the Corporation, which the Corporation may place before the Council.

12. **Procedure for the conduct of the meeting of the Council.**

(1) The Council shall meet at least once in two months and save as aforesaid the Council shall meet at such times and at such places as the Chairman may fix.

(2) The Chairman may, in consultation with the members of the Council, decide on any specified dates for the meetings of the Council.

(3) The Secretary shall send intimation of the date, time and place of the meetings to all the members of the Council at least three days before the date fixed for the meeting:

Provided that it shall not be necessary to send intimation for meetings in respect of which specified dates have been fixed.

13. **Special Meeting:**

(1) The Chairman shall, on the written requisition of not less than seven members, call a special meeting of the Council provided however that there shall not be more than three such special meetings in any year.

(2) The written requisition for a special meeting shall be accompanied by a list of the subjects which are proposed to be discussed at the meeting with notes on each subject.

(3) The Secretary shall send intimation of a special meeting to the members at least three days before the date fixed for the meeting together with a copy of the agenda and of the notes.

14. **Agenda:**

A copy of the agenda with the notes, if any, shall ordinarily be circulated by the Secretary to the members alongwith the notice of the meeting.

15. **Special Subjects:**

Notwithstanding anything contained in rule 12, the Chairman may himself place or allow any member to place for the consideration of the Council any matter not included in the agenda on which advice or recommendations of the Council are urgently required and the Council shall consider the matter at such meeting.

16. **Notice of the proposition:**

Any member who desires to move any proposition at any ordinary meeting shall send notice of such proposition together with a brief note, setting out the reason in support of the proposition to the Secretary at least 15 days in advance of the date fixed for the meeting. A copy of such notice with the note shall ordinarily be circulated to the members as soon as possible after the receipt thereof.

17. **Chairman to preside:**

Every meeting of the Council shall be presided over by the Chairman and in his absence by the Vice Chairman and in the absence of both the Chairman and Vice-Chairman, by the Junior Vice-Chairman. In the absence of the Chairman, the Vice-Chairman and the Junior Vice-Chairman such one of the members present and chosen by them from amongst themselves shall be the Chairman for that meeting.

18. **Quorum:**

Ten members including the Chairman shall form a quorum.

19. **Adjourned Meeting for want of Quorum:**

(1) If, within half an hour from the time appointed for the meeting, the quorum is not present, the meeting shall be adjourned, to a date to be fixed by the Chairman.

(2) If at the adjourned meeting, the quorum is not present within half an hour from the time appointed for that meeting, the members present shall proceed to transact the business before the Council notwithstanding the absence of the quorum.

20. **Questions to be decided by majority:**

(1) All questions coming before a meeting shall be decided by the majority of the votes of the members present and voting.

(2) In the case of an equality of votes, the Chairman shall have a second or casting vote.

(3) The Secretary shall have the right of taking part in the discussions of the Council but shall not have the right to vote at any meeting.

21. **Minutes:**

(1) The minutes of the proceedings of every meeting shall be drawn by the Secretary and circulated to the members of the Council as early as possible and thereafter recorded in a minute book which shall be kept for permanent record.

(2) The minutes of the proceedings of each meeting shall be signed by the Chairman at a succeeding meeting, unless any member present at the previous meeting objects to the minutes as having been incorrectly or incompletely recorded, in which case, the Chairman after taking the sense of the members present at the meeting may make such amendments in the minutes as he thinks proper and the amended minutes shall then be confirmed and signed by the Chairman.

22. **Vacation of office:**

If any member, other than an *ex-officio member*, absents himself from three consecutive meetings, without the permission of the Chairman, he shall cease to be a member of the Council.

23. **Free bus pass:**

Every member of the Council shall be entitled to receive one all route free bus pass for travel by the services operated by the Corporation in the Union Territory of Delhi.

[No. 15-TAG(15)/72]

N. R. REDDY, Joint Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1972

आदेश

का. आ. 169.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स श्री श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ट्रस्ट की ईस्ट कुमारडुभी कौलियरी डाकघर चिरकुण्डा, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (संख्या 3) धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या मैसर्स श्री श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ट्रस्ट की ईस्ट कुमारडुभी कौलियरी, डाकघर चिरकुन्डा (धनबाद) के प्रबन्धतंत्र की श्री देवशरण सिंह, चपरासी एवं नाईट गार्ड को 20 अगस्त, 1972 से काम से रोकने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?"

[संख्या एल/2012/131/72-एस.आर.-2]

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 25th November, 1972

S.O. 169.—WHEREAS the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of East Kumardhubi Colliery of Messrs. Shree Shree Lakshmi Narain Bhagwan Trust, Post Office Chirkunda, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

AND WHEREAS the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 3), Dhanbad, Constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of East Kumardhubi Colliery of Messrs. Shree Shree Lakshmi Narain Bhagwan Trust, Post Office Chirkunda (Dhanbad) in stopping from work Shri Deo Sharan Singh, Chaprasi-cum-Night Guard, with effect from the 20th August, 1972, is justified? If not, to what relief the workman is entitled?

[No. L/2012/131/72-LRII.]

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1972

आदेश

का. आ. 170.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में पश्चिमी रेलवे से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण (सं. 1), मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या पश्चिमी रेलवे के प्रबन्धमण्डल की, श्री अब्दुल रहीम, तार चपरासी, पश्चिमी रेलवे, कोटा को पदच्युत करने की कार्यवाही वैध और न्यायोचित थी? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[सं. एल. 41012/32/72/एल. आर.-3]

New Delhi, the 2nd December, 1972

ORDER

S.O. 170.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Western Railway and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal (No. 1), Bombay constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Western Railway, in dismissing Shri Abdul Rahim, Telegraph Peon, Western Railway, Kota was legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?

[No. L. 41012/32/72/LRIII]

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1972

आदेश

का. आ. 171.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स नेशनल कोल डेवेलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, की मोनीडीह प्रियोजना डाकघर मोनीडीह, जिला धनबाद के प्रबन्ध तन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (संख्या 2) धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मेसर्स नेशनल कोल डेवेलेपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की मोनीडीह परियोजना, डाकघर मोनीडीह, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र की श्री प्राबित कुमार पांडे को, कम्प्रेस्सर फिटर वर्ग-4 के पद से निचले ग्रेड में वेतन-मान के न्यूनतम वेतन पर कम्प्रेस्सर हेल्पर फिटर वर्ग-2 के पद पर लाने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[संख्या एल/20012/92/72-एल.आर.-2]

करनैल सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 20th December, 1972.

ORDER

S.O. 171.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Monidih Project of Messrs. National Coal Development Corporation Limited, Post Office Monidih, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Monidih Project of Messrs. National Coal Development Corporation Limited, Post Office, Monidih, District Dhanbad, in down-grading Shri Prabit Kumar Pandey from the post of Compressor Fitter Category-IV to the post of Compressor Helper Category-II, on the minimum of the pay scale, is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

[No. L/20012/92/72-LRII]

New Delhi, the 6th January, 1973

S.O. 172.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 3, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Khas Dharmaband Colliery of Messrs Khas Dharmaband Colliery Company (Private) Limited, Post Office Malkera, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 2nd January, 1973.

[No. 1/12/66-LRII.]
KARNAIL SINGH, Under Secy.

CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No. 67 of 1968

Present :

Shri B. S. Tripathi—Presiding Officer.

Parties :

Employers in relation to the Khas Dharmaband Colliery of M/s. Khas Dharmaband Colliery Company (P) Limited, P.O. Malkera, Dist. Dhanbad

AND

Their Workmen.

Appearances :

For Employers—Shri S. S. Kapoor, Advocate Shri B. Joshi, Advocate on behalf of Sethia Mining & Manufacturing Corporation Ltd.—added as a party as per Order No. 21 dated 9-4-70.

For Workmen—Shri P. K. Bose, Advocate.

Industry : Coal. **State :** Bihar.

Dhanbad, the 23rd December, 1972

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation, (Department of Labour & Employment) being of the opinion that an industrial dispute exists between the above-mentioned parties, by their Order No. 1/12/66-LRII dated the 1-12-66 referred the said dispute under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 to the Central Government Industrial Tribunal, Dhanbad for adjudication of the matters specified in the schedule of reference. The schedule is as follows :—

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Khas Dharmaband Colliery of M/s. Khas Dharamaband Colliery Company (P) Limited in refusing to treat the workmen, whose names and designations are given in the annexure, as permanent workmen, and thereby denying them the privileges available to permanent workmen of the colliery, was justified? If not, to what relief are the workmen entitled?

ANNEXURE

Sl.No	Name	Designation
1.	Shri Musafir Singh	Line Mazdoor
2.	,, Dasai Singh	Trammer
3.	,, Rampati Singh	Drilling
4.	,, Kirishan Bahadur	Night Guard
5.	,, T.S. Row	Tub Checker
6.	Shri Binon Kumar	Tub Checker
7.	,, Mukta Sirkar	Lamp Mazdoor
8.	,, Birjanandan Singh	Trammer
9.	,, Bisto Mahato	Line Mazdoor
10.	,, Karamchand Rewani	Timber Mazdoor
11.	,, Rameshwar Singh	Tub Checker
12.	,, Bhagirath Rajak	Lamp Mazdoor
13.	,, Ramain Gope	Body Searcher
14.	,, Ganpat Sah	Bailing Mazdoor
15.	,, Ramsaran Singh	Trammer
16.	,, Rambilash Mali	-Do-
17.	,, Tilak Rewani	Tub Loading Mazdoor
18.	,, Mahadeo Dusadh	Trammer
19.	,, Rameshwar Mahato	C.C.M. Helper
20.	,, Durjodhan Rewani	Line Mazdoor
21.	,, Rambilash Singh	Trammer
22.	,, Sarju Singh	C.C.M. Helper
23.	,, Suresh Ram	Dusting Mazdoor
24.	,, K.P. Mitra	Camp Lamp Repairer
25.	,, Upendar Rewani	Lamp Mazdoor
26.	,, Alkha Rajbhar	Dusting Mazdoor
27.	,, Janu Mahato	Tub unloading Mazdoor
28.	,, Ram Singhasan Singh	C.C.M. Helper
29.	,, Jogindar Modak	Pump Khalasi
30.	,, Chotu Mahato.	Drilling
31.	,, Ram Tunak Singh	Trammer
32.	,, Ch. Bhuban Rewani	-Do-
33.	,, Dhirja Mahato	Tub unloading Mazdoor
34.	,, Ramu Mahato	Onseter
35.	,, Tarachand Rewani	Drilling
36.	,, Jiban Mahato	Pump Khalasi
37.	,, Manu Rewani	Dusting Mazdoor
38.	,, Hardeo Singh	-Do-

Sl.No	Name	Designation
39.	Shri Hazai Mahato	General Mazdoor
40.	„ Gopi Gope	-Do-
41.	„ Gopichand Yadav	-Do-
42.	„ Meghu Mahato	-Do-
43.	„ Judopado Rewani	-Do-
44.	„ Akhtar Mian	-Do-
45.	„ Mahabir Rewani	-Do-
46.	„ Rameshwar Mahato	-Do-
47.	„ Shana Pandit	-Do-
48.	„ Muneshwar	-Do-
49.	„ Kalamath Gope	-Do-
50.	„ Bikarma Gope	-Do-
51.	„ Anirka Singh	-Do-
52.	„ Ramphal Mohali	-Do-
53.	„ Ram Awadhesh Singh	-Do-
54.	„ Dibnarain Yadav	-Do-
55.	Srimati Bifiya Chamain	Kamin
56.	„ Keshiya Chamain	-Do-
57.	„ Bhagiya Chamain	-Do-
58.	„ Tukri Chamain	-Do-
59.	„ Panwa Bhuiani	-Do-
60.	„ Sibiya Bhuiani	-Do-
61.	„ Dashni Bhuiani	-Do-
62.	„ Binda Kamarin	-Do-
63.	„ Mundri Kamarin	-Do-
64.	„ Santi Rewanin	-Do-
65.	„ Panwa Harin	-Do-
66.	„ Kuni Harin	Do--
67.	„ Beluna Harin	-Do-
68.	„ Sugiya Mahatwain	-Do-
69.	„ Lagni Mahatwain	-Do-
70.	„ Lilmani Rewanin	-Do-
71.	„ Wabi Majhian	-Do-
72.	„ Hazra Bibi	-Do-
73.	„ Samli Mahatwain	-Do-
74.	„ Taguni Mahatwain	-Do-
75.	„ Saroni Rewanin	-Do-
76.	„ Kanni Rewanin	-Do-
77.	„ Bijli Rewain	-Do-
78.	„ Fulmani Rewanin	-Do-
79.	„ Upasi Mahatwain	-Do-
80.	„ Jamuna Napitain	-Do-
81.	Shri Chhotan Bhuian	General Mazdoor
82.	„ Nageshwar Bhuian	-Do-

II. Whether the action of the management of the said colliery in stopping the privilege, with effect from the 1st January, 1966, of providing conveyance free of charge or paying conveyance charges in lieu thereof for transporting the dependants of the workman of the said colliery from the colliery premises to the regional or central hospital of the Coal Mines Welfare Organisation, Dhanbad and back for treatment, as and when advised by the medical officer of the management was justified ? If not, to what relief are the workmen entitled ?

2. The reference was received by the Central Government Industrial Tribunal, Dhanbad on 14-12-66 and was registered there as reference No. 161 of 1966. Later on, as per Ministry's Order No. 8/25/67-LRII dated the 8-5-67 the reference was transferred to Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad where it was received on 20-5-67 and was registered as reference No. 196 of 1967. Subsequently the reference was transferred to this Tribunal for adjudication as per Ministry's Order No. 8/71/68-LRII dated the 13-8-68. The reference was received by this Tribunal on transfer on 26-8-68 and was renumbered as reference No. 67 of 1968.

3. The industrial dispute in question was sponsored by Colliery Mazdoor Sangh, Dhanbad and in the proceeding before the Tribunal the same union represented the workmen. The union filed written statement on behalf of the workmen on 27-2-68. The written statement of the employers, namely, Khas Dharmaband Colliery Co. (P) Ltd., dated 18-11-68 was received in the Tribunal on 20-11-68. Thereafter the employers filed a petition to implead M/s. Sethia Mining & Manufacturing Corporation Ltd., in the present proceeding stating that they had transferred all their rights, title and interests in the colliery in question to M/s. Sethia Mining & Manufcturing Corporation Ltd., and that the purchasers have changed the name of the colliery from Khas Dharmaband Colliery to New Dharmaband Colliery. After hearing the parties my predecessor-in-office as per his order dated 9-4-70 accepted the submission made by the employers and added M/s. Sethia Mining & Manufacturing Corporation Ltd., as a party to the present proceeding. The transferee company filed their written statement on 13-7-70. I like to mention at this place that the colliery in question was sold to M/s. Sethia Mining & Manufacturing Corporation Ltd., as per registered sale deed Ext. M-8 dated 22-10-69. The factum of the purchase of the colliery by the Sethia Mining & Manufacturing Corporation Ltd., as per sale deed aforesaid, is no longer in dispute between the parties.

4. As per schedule of reference there are 2 items of demand of the workmen. In the first item the concerned workmen are 82 in number and it relates to the justification or otherwise of the action of M/s. Khas Dharmaband Colliery Co. (P) Ltd., in refusing to treat the said 82 workmen as permanent workmen and thereby denying them the privileges available to the permanent workmen of the colliery. So far as the second item of reference is concerned, all the workmen of the colliery are concerned in it. It relates to the justification or otherwise of the action of the management of the colliery in stopping the privilege of providing conveyance free of charge or paying conveyance charges in lieu thereof for transporting the dependants of the workmen of the colliery from the colliery premises to the Regional or Central Hospital of the Coal Mines Labour Welfare Organization, Dhanbad and back for treatment, as and when advised by the Medical Office of the management.

5. The case of the workmen in their written statement in respect of the first item of reference is that all the 82 workmen named in the schedule of reference had been working since 1960 or 1961 in time scale pay on the jobs of permanent nature in the colliery in question and as such these workmen are permanent workmen of the colliery. It is alleged that under the Standing Orders applicable to the employees of the colliery a workman engaged on a work of permanent nature has to be made permanent and treated as such after he has successfully completed service for a period of three months, but in spite of long standing service of the concerned workmen in the colliery as against the jobs of permanent nature, the management have not made them permanent and thus they have denied the previleges and benefits available to permanent workmen in regard to leave, bonus, medical assistance, train fare etc., to these workmen. The workmen further allege that the management had been indulging in the nefarious practice of not marking the attendance of the concerned workmen for more than 10 to 15 days in any register, though they used to be paid wages, for the period they worked, through vouchers. The allegation is that this payment through vouchers used to be made in order to deprive the said workmen of the benefits available to permanent workmen. With regard to the second item of reference the case of the workmen is that the management had been providing conveyance free of charge or conveyance charges in lieu thereof to the workmen for transporting the dependants of the workmen from the colliery premises to the Regional or Central Hospital of the Coal Mines Welfare Organisation, Dhanbad and back and this practice had been continuing for more than 10 years and thus by long usage the practice has become a condition of service of the workmen of the colliery. It is stated that the management in utter violation of Section 9A of Industrial Disputes Act, 1947 arbitrately withdrew or stopped this privilege without any reason with effect from 1-1-66. The prayer of the

workmen, accordingly, is to hold the actions of the management with respect to both the items of reference as unjustified. They further pray that the Tribunal should order to make the 82 workmen concerned in Item No. I of the reference permanent and to allow the benefits and privileges of permanent workmen to them with retrospective effect and that the Tribunal should direct the management to continue to grant the privileges as mentioned in Item No. II of the refrence to all the workmen of the colliery and to pay to the concerned workmen the amount they have already spent, in the meantime, on this account.

6. The case of the employers, namely, M/s. Khas Dharmaband Colliery Co. (P) Ltd., is that the workmen in the list of the item No. I of the reference were employed in the colliery as casual or **badli** workmen on temporary basis and they were not in permanent service. It is said that according to the Standing Orders applicable to the colliery, an employee becomes permanent when he has satisfactorily put in six months continued service in a permanent post and accordingly the concerned workmen cannot be treated as permanent employees. The employers' case further is that the benefits of leave, bonus, train fare etc., an employee is entitled to, does not depend upon permanent or temporary character of the service of the employee but upon the number of days an employee attends to his duty. So far as the second item of reference is concerned the case of the employers is that there was never any practice or usage of allowing conveyance to the dependants of the employees free of charge for transporting them from the colliery premises to the Regional or Central Hospital of the Coal Mines Welfare Organisation, Dhanbad when they fall ill or to pay transport charges to the employees concerned and as such the question of discontinuance of such privilege by the employers does not arise. The prayer accordingly is that the reference may be decided against the workmen.

7. The case of M/s. Sethia Mining & Manufacturing Corporation Ltd., is that this company came into picture with respect to the colliery in question for the first time on 22-10-69 when they purchased it on the basis of the deed of conveyance dated 22-10-69 from M/s. Khas Dharmaband Colliery Co. Ltd., and on the date of reference there was no relationship of employers and employee so far as this company is concerned. The submission accordingly is that the workmen are not entitled to any relief against this company.

8. On behalf of the employers, namely, M/s. Khas Dharmaband Colliery Co. (P) Ltd., the documents filed are Form B registers relating to the years 1963, 1964, 1965 & 1966 (Exts. M-1 to M-5), copy of Standing Orders of the Company Ext. M-6, copy of failure of conciliation report Ext. M-7 and Ext. M-8, the certified copy of the deed of conveyance dated 22-10-69 whereby the colliery in question was transferred to M/s. Sethia Mining & Manufacturing Corporation Ltd., by M/s. Khas Dharmaband Colliery Co. (P) Ltd. All these documents have been exhibited on the admission of the workmen. On behalf of the workmen the documents exhibited are only 2 letters marked Exts. W-1 & W-2. Both the letters have been exhibited on the admission of the employers. Ext. W-1 is the office copy of the letter of the Secretary of the Union to the Agent of Khas Dharmaband Colliery dated 18-2-66 to treat the 82 workmen concerned under Item No. I of the reference as permanent. Ext. W-2 is the office copy of the letter of the Secretary of the Union to the A.L.C. (Central), Dhanbad dated 29-4-66 requesting to take up the matter relating to the permanency of the said 82 workmen in conciliation proceedings. On behalf of the employers two witnesses namely Sri G.A.M. Murthy (MW-1) and Sri Nabagopal Chatterjee (MW-2) have been examined. The only witness examined on behalf of the workmen is Sri A. L. Sharma (WW-1), the Organizing Secretary of the Colliery Mazdoor Sangh. M/s. Sethia Mining & Manufacturing Corporation Ltd., did not examine any witness on their behalf and no document on their behalf also was exhibited.

9. I like to mention at this place that the oral evidence adduced by the parties relate only to the second item of reference, already referred to above, and the witnesses examined by them do not say anything so far as Item No. I of the reference is concerned. The workmen have not filed any document in proof of the allegation that the 82 workmen mentioned in Item No. I of the reference were permanent workmen. The employers, however, have filed Form B registers, already said above, to show the period of service of the concerned workmen during the relevant period. As to the demand of the workmen regarding the privilege of providing conveyance free of charge or paying conveyance charges in lieu thereof for transporting the dependants of the workmen to the hospitals from the colliery, the evidence of MW-1 and MW-2 is that there was never any such custom or practice in the colliery. At the time MW-1 was examined in the Tribunal he was working as Stenographer of the Custodian of the Colliery from 15-11-71 and prior to that he was working as Attendance Clerk in the colliery from 1-8-1963. Apart from the general denial of the alleged practice or custom the witness states that during the period of his service in the colliery once his mother had fallen ill and he had to bring her to Coal Mines Welfare Organization's Central Hospital at Dhanbad for treatment and he had to do this at his own expense. In the cross-examination by the workmen the witness states that in 1965 & 1966 he had occasions to take his wife and children to Katras Regional Hospital for treatment and during this occasion also he did not get transport facility from the colliery. From the evidence of MW-2 it appears that the name of the colliery was changed from Khas Dharmaband Colliery to New Dharmaband Colliery on 22-10-69 when M/s. Sethia Mining & Manufacturing Corporation Ltd., purchased the colliery in question. At present the witness is working as Bill Clerk in this colliery and before that he was working in different capacities in that colliery from 1942. The witness states that there was no practice of transport for the dependants of the workmen of the colliery to Regional or Central Hospital at the expense of the company at any time. From the evidence of WW-1 it appears that he was also in the service in the colliery for a considerable period. His statement in cross-examination is that he was working as Attendance Clerk in this colliery till 9-11-67 and his statement in examination in chief is that during the period he was in service of the company, the company was not incurring the expenses for taking the dependants of the employees of the company to Regional or Central Hospital for treatment nor the company ever paid conveyance charge for bringing the ailing dependants of the employees to the said hospitals. I have already said above that excepting WW-1 no other witness has been examined on behalf of the workmen. Thus according to the oral evidence of both the parties the employers never granted any facility for transport of the dependants of their employees in the colliery to Regional or Central Hospital for treatment nor they paid conveyance charges to the concerned employee at any time. I may mention at this place that no documentary evidence have been placed on record on the side of the workmen to show that such facility was granted to the employees by the company.

10. In view of the above evidence on record the submission on behalf of the employers is that since the employers did never grant the privilege of the transport of the dependants of the employees from the colliery to Regional or Central Hospital for treatment at any time, the question of stopping such privilege from 1-1-66 does not arise. Similarly the question of justification or otherwise for stopping the alleged privilege also does not arise for consideration. The reference under Item No. II however presupposes that there was such a privilege which was being enjoyed by the employees of the colliery in question and the management stopped this privilege with effect from the 1st January, 1966. In view of the reference made to the Tribunal, the Tribunal has to take as a fact that the employees were enjoying that privilege prior to 1-1-66 and the employers stopped that privilege from that date. The matter to be decided by the Tribunal so far as this item of reference is concerned is the justification or otherwise of the management in stopping that privilege, though as pointed out above the evidence adduced on both the parties is that there was no such privilege. In support of this position I rely upon the decision of their Lordships of the Supreme Court reported in 1967(1)LLJ 423 (Delhi Cloth and General Mills Co. Limited and workmen and others) in which it has been held that the parties to the reference cannot be allowed to contend that the foundation of the dispute mentioned in the order of reference was non-existent and that the true dispute is something else. I therefore proceed to discuss about the demand in question in the light of the above ruling.

11. The privilege claimed by the workmen is not in accordance with any legal right or any condition of service in the colliery in question. However, under certain circumstances a particular privilege can be acquired by custom or usage

by long user. There is nothing on record to show that the privilege claimed in the present case was being enjoyed by the employees in the colliery in question for a long time so that it may have the force of one of the conditions of service of the employees in that colliery. In that view of the matter the stoppage of the alleged privilege claimed by the workmen cannot be said to be unjstified on the part of the management. The workmen therefore are not entitled to any relief so far as Item No. II of the reference is concerned.

12. I have already said above that the first item of reference relates to the justification or otherwise of the action of the management in refusing to treat the 82 workmen mentioned in the list of the said item as permanent workmen and thereby denying them the privileges available to such workmen of the colliery. According to the written statement filed on behalf of the workmen the said 82 workmen had been working in Khas Dharmaband Colliery since the year 1960 or 1961 on time scale on the jobs of permanent nature with different designations as mentioned in the schedule of reference. They have alleged further that these workmen during all this period were being paid through vouchers, but in the attendance registers their attendance at one time was not shown for more than 10 to 15 days with some ulterior motive. According to the case of the management, as made out in their written statement, these workmen were employed as casual or badli workmen on temporary basis and Sl. No. 62 to 80 out of the said 82 workmen were employed on piece rated basis, whenever they were employed. Neither the management nor the workmen have adduced any oral evidence in support of their respective allegations, as said above. Not a single workmen out of the concerned workmen has been examined to say that he has been working since the year 1960 or 1961 continuously and that his attendance was not being marked for more than 10 to 15 days. There is also no documentary evidence in proof of the above allegation of the workmen. The alleged vouchers, on the basis of which the payments to the said workmen used to be made, according to the statement in the written statement of the workmen, have also not been called for by the workmen from the management in proof of their continuous service. In view of all these the case of the workmen in the written statement is that the concerned workmen had been working from 1960 or 1961 continuously and their attendance was not shown by the management for more than 10 to 15 days at one time cannot be accepted. In the same manner there is no oral evidence in proof of the case of the management that the concerned workmen had been employed as casual or badli workmen or to say that out of them Sl. No. 62 to 80 were employed on piece rated basis. There is also no document in support of the above allegation of the management. Accordingly the case of the management in this regard also cannot be accepted.

13. On behalf of the workmen it is submitted that the designations of the concerned workmen of Item No. I of the schedule of reference shown against each name go to show that these workmen were employed on the jobs of permanent nature and accordingly these workmen should have been treated as permanent workmen and the refusal of the management in this regard is unjustified. In support of this contention reliance has been placed upon the decision of their Lordships of the Supreme Court reported in 1961(1)LLJ 649 (Jaswant Sugar Mills Ltd., Meerut & Badri Prasad). In that case according to the Standing Orders applicable to the company a "permanent workman" was defined as one engaged in a permanent nature of work throughout the year who has completed his probationary period. While construing the definition of "permanent workmen" in the said Standing Orders their Lordships observed that the proper construction of the definition of permanent workmen is that he must be a workman engaged on a work of permanent nature which lasts throughout the year but has completed his probationary period, if any, not being one engaged to fill any temporary need of extra hands on permanent jobs. The submission on behalf of the workmen accordingly is that in the present case there is no evidence on the side of the management that the concerned workmen were taken in service on permanent jobs on account of a temporary need or to show that these workmen were casual or badli workers. The submission further is that there is no evidence to show that the posts which the concerned workmen were holding at the relevant time were not permanent posts and as such the designations of the workmen given in the schedule of reference must hold good and it must be held on that basis that the said workmen were employed on works of permanent nature. It is submitted that in view of all this the period of service is of no consequence to determine whether a particular employee was a permanent workman or not. Their Lordships in that ruling, while scrutintzing the definition of 'permanent workman', have held that the definition did not require that such workman should be employed throughout the year and all that was necessary to make an employee a permanent workman was that the job in which an employee was employed must be of permanent nature and it must continue to exist throughout the year, the employee in that job must have completed the probationary period, if any, and he must not have been engaged to fill any temporary need of extra hands on permanent job.

14. In my opinion, the above ruling does not support the contention of the workmen, even on the Standing Order of that case, that mere appointment against a job of permanent nature will make an employee, a permanent workman. If the standing order provides for undergoing a period of probation, the employee cannot be made permanent before the expiry of the probationary period. Ext. M-6 is the standing order relating to the present case in which a 'Permanent Employee' has been defined in Clause 1(g) as follows :—

> "A 'permanent employee' is one who is appointed for an unlimited period or who has satisfactorily put in six months continue service in a permanent post as a probationer."

In clause 1(h) of the standing order a probationer has been defined in these words :—

> "A probationer is one who is provisionally employed to fill a permanent vacancy and has not completed six months service in that post. If a permanent employee is employed as a probationer in a new post he may, at any time during the probationary period not exceeding six months, be reverted to his substantive post."

According to this definition an employee who has been appointed for an unlimited period will be considered as a permanent employee. Besides this, an employee will be a permanent employee if he is posted in a permanent post as a probationer and the employee has completed six months continued service as such and he has worked as such satisfactorily. It comes to this, therefore, that the continued satisfactory service for a period of six months in a permanent vacancy is pre-requisite for treating an employee as a permanent employee.

15. I have already said above that the workmen have not adduced oral or documentary evidence and the management have not also adduced any oral evidence on the point under consideration. The management however have filed From B registers Exts M-1 to M-5 for the years 1963 to 1966 with respect to the employees of the colliery in question for the purpose of showing that the concerned workmen were not in continued service for a period of six months at any time, so that they may be treated as permanent workmen. An extract from Form B registers relating to the year 1965 and 1966 as per entries in Exts. M-3, M-4 & M-5 has been filed by the parties duly authenticated by their representatives who submitted that the extract may be accepted as being correctly prepared from the registers concerned and they may be referred to for the purpose of giving award. From the said extract and also the connected registers it appear that at no point of time the employees of Sl. Nos. 1 to 42, 45, 46, 48, 50, 52, 53, & 54 out of 82 workmen of the schedule of reference were in service in the colliery for a continued period of six months. The workmen have not challenged the correctness of the entry in the Form B registers. On the other hand by accepting the extract aforesaid they have accepted the correctness thereof. Form B registers are statutory registers and they are maintained under Section 48 of the Mines Act, 1952 read with Rule 77 of the Mines Rules, 1955. Among others the Form B registers contain the date of commencement of employment and the date of termination or leaving of employment of an employee in the colliery. The entries in these registers must, threfore, be presumed to be correct unless shown otherwise and in the present case it has not been shown that the entries are incorrect. In any view of the case, therefore, out of the 82 workmen concerned. the workmen mentioned against Sl. Nos. 1 to 42, 45, 46, 48, 50, 53 & 54 cannot be said to have acquired the

status of a permanent workman as per Standing Order referred to above. Accordingly, the refusal of the management to treat these workmen as permanent cannot be said to be unjustified.

16. The aforesaid extract submitted by the parties and the corresponding Form B registers do not contain the names of the workmen against Sl. Nos. 43, 44, 47, 49, 51 & 55 to 82 of the schedule of reference. The management do not give any explanation as to why the names of these workmen do not appear in the Form B registers filed by them. The reference contains the names and designations of all the 82 workmen including the aforesaid workmen of the colliery. It is not the case of the management that these workmen were not working in the colliery at any time. All that the management have stated in their written statement is that these workmen did not work continuously for a period of six months in the colliery at one time. It must, accordingly, be held that the aforesaid workmen were in the employ of the management in the colliery in question. In view of the provisions of Section 48 of the Mines Act read with Rule 77 of Mines Rules in the matter of maintaining Form B register, no distinction has been made in regard to permanent or temporary or casual or Badli employees, rather Section 48 says that the names of all the employees of the mine shall be entered in Form B register with the necessary particulars. In the absence of any explanation it may reasonably be presumed that Form B register with respect to the aforesaid employees was maintained and the management has not produced the same as it will go against them, if produced. Again, according to the reference the onus is upon the management to prove that the concerned workmen were not permanent workmen. This could be proved by the production of Form B register or by any other evidence, oral or documentary, which the management has failed to prove. Considering the evidence and circumstances on record it will not be unreasonable to hold that so far as the workmen of Sl. Nos. 43, 44, 47, 49, 51 & 55 to 82 are concerned the refusal by the management to treat them as permanent was not justified and I hold accordingly.

17. In paragraph 2 of the written statement of the management it has been stated that workmen mentioned at Sl. Nos. 62 to 80 whenever employed were employed on piece rated basis. No evidence has been adduced by the management in proof of this allegation. I do not accordingly accept the above allegation of the management.

18. On behalf of M/s. Sethia Mining & Manufacturing Corporation Ltd., it is stated that the workmen are not entitled to any relief as against them in as much as their purchase of the colliery in question from M/s. Khas Dharmaband Colliery Co. (P) Ltd., is subsequent to the reference made by the Government. I am unable to accept this submission. By virtue of the purchase of right, title and interest of M/s. Khas Dharmaband Colliery Co. (P) Ltd., with respect to the colliery in question, they have become the successor-in-interest of Khas Dharmaband Colliery Co. (P) Ltd., in respect of that colliery and the liability to implement that part of the award which is against the management of that colliery must, accordingly, rest with M/s. Sethia Mining & Manufacturing Corporation Ltd. In that view of the matter I do not accept the contention on behalf of the purchaser company that the workmen are not entitled to any relief as against them in the present proceeding.

19. In view of the findings already recorded above, I answer Item No. I of the schedule of reference in the following manner :—

> Action of the management of the Khas Dharmaband Colliery of M/s. Khas Dharmaband Colliery Co. (P) Ltd., in refusing to treat the workmen under Sl. Nos. 1 to 42, 45, 46, 48, 50, 52, 53 & 54 out of the list of 82 workmen given in the Annexure of the said item, as permanent workmen and thereby denying them the privileges available to permanent workmen of the colliery was justified. In that view of the matter these workmen are not entitled to any relief in this regard.

I, however, find that the action of the management of Khas Dharmaband Colliery of M/s. Khas Dharmaband Colliery Co. (P) Ltd., in refusing to treat the remaining workmen of the said list, namely, the workmen mentioned aaginst Sl. Nos. 43, 44, 47, 49, 51 & 55 to 82 as permanent workmen and thereby denying them the privileges available to permanent workmen of the colliery was not justified. In view of this finding the question that arises for consideration is as to what relief these workmen are entitled to. These workmen shall be treated as permanent workmen of the colliery and shall get all the benefits as permanent workmen. These workmen shall further be reinstated in their post by the management of the colliery in question, if they appear and apply to be put on work within thirty days from the date this award becomes enforceable. The said workmen also will get full wages during the period of their forced unemployment. So far as Item No. II of the reference is concerned my finding is that the action of the management of Khas Dharmaband Colliery of M/s. Khas Dharmaband Colliery Co. (P) Ltd., in stopping the privileges, with effect from 1st January, 1966, of providing conveyance free of charge or paying conveyance charges in lieu thereof for transporting the dependants of the workmen of the said colliery from the colliery premises to the Regional or Central Hospital of the Coal Mines Welfare Organization, Dhanbad and back for treatment, as and when advised by the Medical Officer of the management was justified. In view of this finding the workmen are not entitled to any relief, so far as Item No. II of the reference is concerned.

20. This is my award. Let the award be submitted to the Central Government under Section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

B. S. TRIPATHI, Presiding Officer.

New Delhi, the 6th January, 1973

S.O. 173.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Balihari Colliery of Messrs. Balihari Colliery Company Private Limited, Post Office Kusunda, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 2nd January, 1973.

[No. L-2012/69/71-LRII]
KARNAIL SINGH, Under Secy.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (No. 1), DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 17 of 1971

Parties :

Employers in relation to the management of Balihari Colliery of Messrs. Balihari Colliery Company Private Limited, P.O. Kusunda, (Dhanbad).

And

Their workmen

Present :

Shri D. D. Seth, Presiding Officer.

Appearances :

For the Old employers :

Shri B. Joshi, Advocate with Shri I. P Mishra, Manager.

For the Bharat Coking Coal Ltd. :

Shri S. S. Mukherjee, Advocate with J. N. P. Sahi, Labour and Law Adviser.

For the Workmen :

Shri J. Bhattacharjee, Asstt. Secretary, Hindustan Khan Mazdoor Sangh.

State : Bihar **Industry :** Coal.

Dhanbad, dated the 27th December, 1972

AWARD

The present reference arises out of Order No. L/2012/69/71-LR.II, dated New Delhi, the 28th June, 1971 passed by the Central Government in respect of an industrial dispute between the parties mentioned above. The subject matter of the dispute has been specified in the schedule to the said order and the said schedule runs as follows :

"Whether the action of the management of Balihari Colliery of Messrs. Balihari Colliery Company Private Limited, Post Office Kusunda, District Dhanbad, in dismissing Shri Prabhu Ram, Night Guard, from service with effect from the 29th July, 1967, is justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. The dispute has been settled out of Court. A joint petition of compromise dated 1st December, 1972, has been filed in the office of the Tribunal. The petition has been signed by Shri I. P. Mishra, Manager on behalf of the old management, Shri J. N. P. Sahi, Labour and Law Adviser on behalf of the Bharat Coking Coal Ltd., and by Shri J. Bhattacharjee, Asstt. Secretary, Hindustan Khan Mazdoor Sangh on behalf of the workmen. I have gone through the terms of settlement contained in the said petition. They are fair and reasonable and, therefore, I make an award on the basis of the terms of settlement. The joint petition of compromise shall form part of the award.

3. Let a copy of this award be forwarded to the Central Government under section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

D. D. SETH, Presiding Officer.

BEFORE THE HON'BLE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (No. I) AT DHANBAD.

In the matter of :—

Reference No. 17 of 1971

Parties :

Employers in relation to Balihari Colliery.

And

Their workmen

MEMORANDUM OF SETTLEMENT

All the parties in the present proceedings have amicably settled the dispute involved in the present Reference on the terms hereinafter stated :—

(1) That Shri Prabhu Ram (Night Guard) the workman concerned in the present Reference, who was already since some time past employed in Gazlitand Colliery with slightly changed name as "Prabhu-Nath Saw", will be allowed to continue his present work at Gazlitand Colliery and his correct name (Prabhu-Ram) will be put on the said Colliery records henceforth. He will not be entitled to any back wages.

(2) That the period intervening from the date of dismissal (which gave rise to the present Reference) till the date of resumption of duty at Gazlitand Colliery shall, for the purposes of continuity of services, be treated as leave without pay.

(3) The above terms finally resolve the dispute between the parties and, therefore, there is no subsisting dispute for adjudication in the present Reference.

(4) The parties shall bear their own cost of proceedings.

It, is therefore, prayed that the Hon'ble Tribunal may be pleased to accept this Settlement and to give the Award in terms thereof.

FOR THE EMPLOYERS :— FOR THE WORKMEN:—
Manager, Secretary,
Balihari Colliery. Hindustan Khan Mazdoor Sangh.
Sig. (Illigible) For Bharat Coking Coal Ltd. :—
Advocate

Dated the 1st December, 1972. J. N. P. SAHI,
Labour and Law Adviser,
Bharat Coking Coal Ltd.
Sig Illigible
Advocate

New Delhi, the 6th January, 1973

S.O. 174.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the Agent, South Bulliari Kendwadih Group of Collieries of Messrs. East Indian Coal Company Limited, Post Office Mohuda, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 2nd January, 1973.

AWARD

[No. L-2012/101/71-LRII]

KARNAIL SINGH, Under Secy.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (No. 1), DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 23 of 1972

Parties :

Employers in relation to the Bhatdee Colliery of Messrs. Bengal Bhatdee Coal Company Limited, Post Office Mohuda, Distt. Dhanbad.

And

Their workmen

Present :

Shri D. D. Seth, Presiding Officer.

Appearances :

For the Old employers :

Shri H. R. Choudhury, Manager.

For the Bharat Coking Coal Ltd. :

Shri S. S. Mukherjee, Advocate with Shri J. N. P. Sahi, Labour and Law Adviser.

For the Workmen :

Shri S. V. Acharior, General Secretary, Hindustan Khan Mazdoor Sangh.

State : Bihar **Industry :** Coal.

Dhanbad, dated the 28th December, 1972

AWARD

The present reference arises out of Order No. L/2012/101/71-LRII, dated New Delhi, the 29th June, 1972, passed by the Central Government in respect of an industrial dispute between the parties mentioned above. The subject matter of the dispute has been specified in the schedule to the said order and the said schedule runs as follows :

"Whether the demands that the management of Bhatdee Colliery of Messrs. Bengal Bhatdee Coal Company Limited, Post Office Mohuda, District Dhanbad, should pay to Sarvashri Mutuk Ram, Sudarshan Singh, Prahalad Thakur, Ram Chandra Dusadh, Car/Truck Drivers and Sarvashri Jogindra Ram, Prankisto Turi, Titan Thakur and Ram Chandra Helpers/Cleaners, wages as per recommendations of the Central Wage Board for Coal Mining Industry and that they are entitled to be employed as permanent workmen are justified? If so, to what relief the workmen are entitled and from which date?"

2. The dispute has been settled out of Court. A joint petition of compromise dated 20th December, 1972, has been filed in the office of the Tribunal. The petition has been signed by Shri H. R. Choudhury, Manager on behalf of the old management, Shri J. N. P. Sahi, Labour and Law Adviser on behalf of the Bharat Coking Coal Ltd., and by Shri S. V. Acharior, General Secretary, Hindustan Khan Mazdoor Sangh on behalf of the workmen. I have gone

through the terms of settlement contained in the said petition. They are fair and reasonable and, therefore, I make an award on the basis of the terms of settlement. The joint petition of compromise shall form part of the award.

3. Let a copy of this award be forwarded to the Central Government under section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

D. D. SETH, Presiding Officer.

BEFORE THE HON'BLE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (No. I) AT DHANBAD.

In the matter of :—

Reference No. 23 of 1972

Parties :

Employers in relation to Bhatdee Colliery.

And

Their workmen

MEMORANDUM OF SETTLEMENT

All the parties to the present proceedings have amicably settled the dispute involved in the present Reference on the terms hereinafter stated :—

(1) That Sarvashri Mutuk Ram, Sudershan Singh, Prahalad Thakur, and Ram Chandra Dusadh (Car/Truck Drivers) workmen concerned in the present Reference have been already employed as permanent workmen and placed in Category-V (Five) (under Recommendations of the Central Wage Board) (Coal Mining Industry).

(2) That out of remaining four workmen concerned in this reference, three workmen viz. S/Shri Prankisto Turi, Titan Thakur and Ram Chandra, Helper/Cleaners have also been employed as permanent workmen and they will be placed in Category-II (Two) (under the said Wage Board's Recommendations) with effect from the 15th August, 1972 and will be allowed basic wage rate of Rs. 5.47 p. (Rupees Five and Paise forty-seven only) per day with effect from the said date (15/8/72).

(3) That Shri Jogindra Ram, Helper/Cleaner, one of the concerned workman, had left the employment of the said colliery of his own accord about eight months back and his disputes does not survive.

(4) The General Secretary, Hindustan Khan Mazdoor Sangh will be paid a sum of Rs. 50 (Rupees fifty only) as the cost of proceedings.

(5) The above terms finally resolve the dispute between the parties and, therefore, there is no subsisting dispute for adjudication in the present Reference.

It is, therefore, prayed that the Hon'ble Tribunal may be pleased to accept this settlement and to give the Award in terms thereof.

FOR THE EMPLOYERS :— FOR THE WORKMEN :—

Manager, General Secretary,

Bhatdee Colliery. Hindustan Khan Mazdoor Sangh.

For Bharat Coking Coal Ltd :—

Dated the 20th December, 1972. J. N. P. SAHI,
Labour and Law Adviser,
Sig. Illigible
Bharat Coking Coal Ltd.

New Delhi, the 6th January, 1973

S.O. 175.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Nimcha Colliery of Messers Nimcha Coal Company Limited, Post Office Raniganj, District Burdwan and their workmen, which was received by the Central Government on the 3rd January, 1973.

AWARD

(No. L-19012|44|71-LRII.)

KARNAIL SINGH, Under Secy.

Reference No. 95 of 1971

AND

Reference No. 103 of 1971

Parties :

Employers in relation to the management of Nimcha Colliery of Messers Nimcha Coal Company Limited, Their Workmen

(In both the references).

Present :

Sri S. N. Bagchi...Presiding Officer.

Appearances :

On behalf of the Employers—Sri K. P. Mukherjee, Bar-at-Law, with Sri J. D. Mukherjee, Advocate.

On behalf of Workmen—Sri B. Malkhandy, Bar-at-Law.

State : West Bengal ..**Industry :** Coal Mine

AWARD

By Orders No. L1912/44/71-LRII, dated 23rd July, 1971 No.L/1912/66/71-LRII, dated 13th September, 1971, the Government of India, in the Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour and Employment, referred the dispute existing between the employers in relation to the management of Nimcha Colliery of Messers Nimcha Coal Company Limited and their workmen, to this Tribunal, for adjudication. The matter referred to for adjudication are stated in the Schedule of the respective references and they are as follows:

SCHEDULE

In reference No. 95 of 1971 :

"Whether the management of Nimcha Colliery of Messers Nimcha Coal Company Limited, Post Office Raniganj, District Burdwan, having regard to their financial capacity, are justified in not paying the arrears of Variable Dearness Allowance at the rate of Rs. 1.53 to the workmen from 1st April, 1970 to 31st May, 1970 and at the rate of Rs. 1.62 from 1st October, 1970 to 31st December, 1970 to the monthly paid staff and from 1st October, 1970 to 17th January, 1971 to weekly paid staff and in not paying arrears of annual-increment to all the workmen with effect from 15th August, 1970 to 31st September, 1970? If not, to what relief are the workmen entitled?"

In Reference No. 103 of 1971 :

"Whether the stoppage of work in Nimcha Colliery of Messers Nimcha Coal Company Limited, Post Office Raniganj, District Burdwan with effect from the 26th April, 1971, is a closure or lockout? In the either case to what relief the workmen concerned are entitled?"

2. With the consent of the learned Counsels appearing for the respective parties both the references were heard on the common issues hereafter to be stated and both the references shall be governed by this decision (Award).

3. Reference No. 95 of 1971 is dated 23rd July, 1971 whereas Reference No. 103 of 1971 is dated 13th September, 1971. In both the references some preliminary issues have been raised for determination by the management. Notices in

Reference No. 95 of 1971 were issued on 2-8-71 and in Reference No. 103 of 1971 on 24-9-71, both to the management and to the Secretary, Colliery Mazdoor Sabha, CITU, Raniganj. Dist. Burdwan. In Reference No. 95 of 1971 the management filed its statement of case on 24-2-72. In paragraph 3 of the said statement of the case the management states:

"The Company states that colliery Mazdoor Sabha Raniganj District Burdwan whose name has been stated in the said Government Order dated 23rd July, 1971 is not competent in law to represent the workmen employed by the company and/or to raise any Industrial Disputes within the meaning of the Industrial Disputes Act 1947 on behalf of the workmen employed at the said Nimcha Colliery. The Company has been furnished with a copy of a written statement dt. Nil November'71 signed by Sri Robin Chatterjee, General Secretary of the above mentioned trade union (hereinafter referred to as the said statement) purported to be written statement on behalf of the workmen employed at the said Nimcha Colliery."

The Colliery Mazdoor Sabha, CITU, Raniganj filed its statement of case on 1-12-71. The management filed the statement on 24-2-72 with a copy to Colliery Mazdoor Sabha, CITU, Raniganj which however was not traversed by any rejoinder filed by the Colliery Mazdoor Sabha, CITU, Raniganj. On 31-5-72 the General Secretary for and on behalf of the Colliery Mazdoor Sabha, CITU, Raniganj, Sri Robin Chatterjee, by a petition dated 27th May, 1972 referred to Reference No. 103 of 1971 pending for final hearing before this tribunal and mentioned therein that both the matters are in connection with the same management and that the issues involved in Reference No. 95 of 1971 are very much involved in the issues in Reference No. 103 of 1971. The penultimate paragraph of the petition reads as, "Under the circumstances the petitioner humbly prays that the hearing of the Ref. No. 103 of 1971 be taken first before the hearing of the Ref. No. 95 of 1971." It will appear from the Order dated 21-11-72 in both the reference that the Order passed in Reference No. 103 of 1971 and other relevant orders passed in the record of Reference No. 103 of 1971 shall also govern Reference No. 95 of 1971 in which the parties and the preliminary points raised in the issues in the proceedings settled on that date are the same. In reference No. 103 of 1971 the Colliery Mazdoor Sabha, CITU, through its General Secretary Shri Robin Chatterjee filed its statement of case on 23-11-71. The management of Nimcha Colliery filed its statement of case on 1-3-1972. In paragraph 3 of the said statement of case the company states:

"The Company states that Colliery Mazdoor Sabha Raniganj District Burdwan whose name has been stated in the said Government Order dt. 13th September, 1971 is not competent in law to represent the workmen employed by the company as its said Nimcha Colliery and/or to raise any industrial disputes on their behalf within the meaning of the Industrial Disputes Act, 1947."

In paragraph 5(f) the management states:

"That the Colliery Mazdoor Sabha, Raniganj is not competent in law to represent the workmen employed at Nimcha Colliery at the time of effecting the complete closure on 26th April, 1971 and the period subsequent thereto and in any event was and is not competent to raise "industrial dispute" in terms of the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 as such the said Govt. order dated the 13th September, 1971 is not maintainable in law".

4. The workmen filed a rejoinder through Colliery Mazdoor Sabha, Raniganj, CITU. This rejoinder is dated 27th May, 1972 signed by Robin Chatterjee, General Secretary for and on behalf of the Colliery Mazdoor Sabha, CITU, Raniganj. In paragraph 2 of the rejoinder it is stated as follows:

"The contention raised in paragraph 2,3,4,5 and the grounds thereof are denied and disputed. It is specifically denied that there is no distinct trade union exclusively meant for the workmen employed at the Nimcha Colliery. It is further denied that there was ever complete closure of Nimcha Colliery as alleged or at all. The Union states that the closure was *malafide* and in fact it was lock out."

The material assertion in paragraphs 3 and 5(f) of the managements statement of case had not been specifically and pointedly controverted in the rejoinder filed by the Colliery Mazdoor Sabha, CITU, Raniganj, on 27th May, 1972. On 13th June, 1972 the Colliery Mazdoor Sabha, CITU Raniganj, Registration No. 3449 filed a petition before this tribunal in Reference No. 103 of 1971 calling for certain documents and for presence of Assistant Labour Commissioner (C), Asansol as a witness on behalf of the workmen represented by the union concerned. On 17th August, 1972 the management of the Nimcha Colliery filed a petition. In paragraphs 2 and 3 of the said petition the management states as follows:

"2.... The Company states that neither the said Colliery Mazdoor Sabha nor the said Colliery Mazdoor Sabha of India is a Trade Union of workmen and therefore is incompetent in law to represent or raise industrial dispute on behalf of the workmen employed by the petitioner at the Nimcha Colliery.

"3.... The Company further states that neither the said Colliery Mazdoor Sabha nor the said Colliery Mazdoor Sabha of India is legally registered under the provisions of Indian Trade Unions Act and in any event is not legally competent to function as a trade Union in accordance with the provisions of law."

5. On 10th July, 1972 Mr. Malkhandy, learned Counsel and Mr. Sudhendu Mukherjee, Advocate, Calcutta High Court, were authorised to represent the workmen whose cause is being espoused by Robin Chatterjee for and on behalf of CITU, Raniganj. This is the only memorandum of representation dated 10th July 1972. On 13th September, 1972 the management in paragraph 2 of its petition referred to paragraph 5(f) of its statement of case dated 24-2-72 filed on 1st March, 1972 before this Tribunal reading as follows:

"That the Colliery Mazdoor Sabha, Raniganj, is not competent in law to represent the workmen employed at the Nimcha Colliery at the time of effecting complete closure on 26-4-71 and the period subsequent thereto, and in any event was and is not competent to raise "industrial dispute" in terms of the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, and as such the said Government Order dated 13-9-71, is not maintainable in law."

In paragraphs 3 and 4 of that petition the management states as follows:

"3. The petitioner states that the Colliery Mazdoor Sabha, Raniganj, is not a registered trade union in terms of the provisions of the Indian Trade Unions Act and as such is not competent in law to represent the workmen employed by your petitioner at the Nimcha Colliery, inasmuch as the said Colliery Mazdoor Sabha, Raniganj, is using Registration No. 3449 under the Indian Trade Unions Act along with another organisation known as the Colliery Mazdoor Sabha, Asansol which organisation is also using the same Registration No. 3449 under the Trade Unions Act. Further, both the organisations, Colliery Mazdoor Sabha, Raniganj, and Colliery Mazdoor Sabha, Asansol, are wrongly contending that each one of them is entitled to use the identical registration No. 3449 and further alleging that each one of them is registered under the Indian Trade Unions Act and the Registrar of Trade Unions, West Bengal, has granted such registration number in terms of the provisions of the Indian Trade Unions Act. That the said two organisations, viz., Colliery Mazdoor Sabha, Raniganj, and Colliery Mazdoor Sabha, Asansol, are using the same registration number 3449 would appear from the following undisputed records:

(i) Attested copy of the minutes, dated 12-8-71, made by Shri K. Sharan, Regional Labour Commissioner (Central), Asansol, signed by Shri Robin Chatterjee, General Secretary, and Shri Samir Dhar, Secretary, Colliery Mazdoor Sabha, Raniganj.

(ii) Letter, dated 7-12-70, from the Colliery Mazdoor Sabha, Raniganj, (Registration No. 3449) to the Director, Nimcha Colliery, Calcutta-20.

(iii) Letter No. E.2/3(239)/70, dated 22-8-70, from Shri B. S. Sachdevn, Labour Commissioner (Central) Asansol to General Manager, Nimcha Coal Co., Ltd., Calcutta-20 and the Organising Secretary, Colliery Mazdoor Sabha (A.I.T.U.C.), G. T. Road, Asansol, and enclosing a copy of a letter, dated 18-8-70, addressed by Shri Sunil Sen, Organising Secretary, Colliery Mazdoor Sabha (A.I.T.U.C.), G. T. Road, Asansol, addressed to the Assistant abour Commissioner (Central), Asansol, and bearing the seal of Colliery Mazdoor Sabha, G.T. Road, Asansol (Registration No. 3449).

4. Your petitioner further states that the documents referred to above are merely illustrative and not exhaustive as would appear from the records of this Hon'ble Tribunal relating to various awards made by this Hon'ble Tribunal that the said Colliery Mazdoor Sabha, Raniganj, and the Colliery Mazdoor Sabha, Asansol, are both using the same Registration No. 3449 under the Indian Trade Unions Act.'

In paragraph 8 of the said petition the management prayed for a decision on the preliminary issues raised in paragraph 5 of the written statement of the management.

5. On 19-9-72 Sri Dinesh Singh, for and on behalf of the Colliery Mazdoor Sabha of India, Raniganj, filed a petition dated 17-9-72. In paragraph 5, 6, 7, 8 and 9 of that petition the Secretary, Colliery Mazdoor Sabha of India, Raniganj District Burdwan, states:

"5. Your petitioner states Colliery Mazdoor Sabha is a registered Union and with had two Offices one at Asansol and one at Raniganj. The said Union was affiliated to All India Trade Union Congress

6. The said Colliery Mazdoor Sabha was also recognised by the management of the said Colliery and the said Sabha took up many disputes on behalf of the workmen of the said Colliery who were all members of the said Sabha. Therefore, political differences arose amongst the members of the said Sabha and there was a move to form a separate Union and eventually a Union under the name and style "Colliery Mazdoor Sabha of India" was formed and registered according to Trade Union Act.

7. Mr. Robin Chatterjee who was the Vice-President of the Colliery Mazdoor Sabha became the General Secretary of the said new Union.

8. Workmen of Nimcha Colliery who were all members of Colliery Mazdoor Sabha declared their allegience to the new Union *i.e.* Colliery Mazdoor Sabha of India in a meeting of the workers. Your petitioner states that though the dispute was raised on behalf of the Colliery Mazdoor Sabha the workers authorised the new Union of which Sri Robin Chatterjee is General Secretary to take up the dispute and to take all necessary action.

9. Being so authorised by the workmen of the said Colliery who were all members of the Colliery Mazdoor Sabha and afterwards became the members of the new Union, your petitioner is representing the case before the Hon'ble Tribunal."

The penaltimate paragraph in the said petition is that the preliminary objections raised by the management should be rejected.

6. On 20-9-72 the management filed another petition. In paragraph 6 of that petition the management states as follows:

"6. That in terms of the directions given by this Hon'ble Tribunal on the 13th September' 72 your petitioner submits this reply with reference to the said petition dt.17.9.72 made on behalf of the Colliery Mazdoor Sabha of India Raniganj, without prejudice to the contention of your petitioner that the said Colliery Mazdoor Sabha of India, Raniganj being not a Trade Union to whom the said Govt. order of reference dated the 13th September 1971 was forwarded by the Central Govt. and for the reasen stated in the said two petitions dated 17.8.72 and 13.9.72 the said Colliery Mazdoor Sabha of India Raniganj being incompetent in law or represent and/or raise any dispute on behalf of the workmen employed at the said colliery is not competent in law to submit the said petition of objection dated 17th September, 1972 before this Hon'ble Tribnual".

In paragraphs 11 and 12 of the said petition it is stated as follows:

"11. The petitioner reiterates its contentions made in its earlier petitions dated 17.8.72 and 13.9.72 that Colliery Mazdoor Sabha, Raniganj and Colliery Mazdoor Sabha, Asansol are separate and distinct organisations using in unauthorised and illegal manner the same registration No. 3449 under the Indian Trade Unions Act and in the circumstances in accordance with the provisions of Indian Trade Unions Act as well as the Award made by this Hon'ble Tribunal in Reference No. 93 of 1971 (Ranipur Colliery *Vs.* Workmen) none of the said organisation *viz.* Colliery Mazdoor Sabha, Raniganj and/or Colliery Mazdoor Sabha, Asansol is competent in law to represent the workmen employed at Nimcha Colliery either before the management of Nimcha Colliery or before the conciliation officer appointed in terms of the provisions of the Industrial Disputes Act or before this Hon'ble Tribunal.

12. Your petitioner states that Colliery Mazdoor Sabha of India having registration No. 9703 under Indian Trade Unions Act at no point of time raised any dispute on behalf of the workmen employed at Nimcha Colliery either before the management of Nimcha Colliery or before the conciliation officer nor your petitioner reiterates that the workmen employed at the Nimcha Colliery made no demand or raised any dispute either before the Management of the Nimcha Colliery or before the Conciliation Officer relating to the issue of the said Govt. order of reference dated the 13th September '71 purported to be under section 10(1) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947 and in any event the said Colliery Mazdoor Sabha, Raniganj was not competent in law to raise the said disputes referred to in the said Govt. order of reference dated the 13th September 1971."

In paragraph 19 of the petition it is stated, "Your petitioner denies the contentions that Colliery Mazdoor Sabha Raniganj raised any alleged disputes referred to in the said Govt. order of reference dated 13.9.71 either before the Management of Nimcha Colliery or before the conciliation officer relating to the subject matter of the said Govt. order of reference dated 13.9.71. Your petitioner denies and disputes the allegations made in the said petition of objection dated 17.9.72 that the workmen employed at Nimcha Colliery at any point of time authorised Colliery Mazdoor Sabha of India Raniganj to take up their matter and/or declare their allegience to the said Colliery Mazdoor Sabha of India Raniganj and left the Colliery Mazdoor Sabha, Raniganj as wrongly alleged....." On 21st November 1972, the management filed another petition and referred to the issues raised being Issue Nos. (i), (ii) and (iii) and prayed for hearing of those issues as preliminary issues.

7. On 21.11.72 upon hearing the learned Counsel of both the parties, the management and Colliery Mazdoor Sabha of India, three preliminary issues were framed and the relevant order after framing up of the issues runs as follows:

"ISSUES

(i) Is the Colliery Mazdoor Sabha, having the office at Raniganj, bearing Registration No.3449 mentioned as being represented through its General Secretary in response to the notice issued in this proceeding by this tribunal as well as by the Government, representing the workmen parties to the dispute has been a duly registered Trade Union under the Trade Unions Act, and has, therefore, the right to represent the workmen involved in the dispute through any of its officers within the scope of Section 36(1) (a) of the Industrial Disputes Act ?

(ii) Is the Colliery Mazdoor Sabha of India, Registration No. 9703, aniganj, Burdwan a duly registered

trade Union under the Trade Union Act? If so, can it represent the workmen involved in this dispute within the scope of Section 36(1) (a) of the Industrial Dispute Act when, upto 13.7.72, the workmen involved in this dispute had been represented in this proceeding as well as before the Conciliation officer by the Colliery Mazdoor Sabha, Raniganj, being Registration No.3449 claiming to be a duly registered union functioning through its officer *i.e.* the General Secretary Sri Robin Chatterjee who filed the written statement in this proceeding on behalf of the workmen involved in this dispute and represented by the workmen upto 13th July, 1972 ?

(iii) Did the Colliery Mazdoor Sabha bearing Registration No.3449, Raniganj, Asansol, raised any demand relating to the subject matter of the dispute under reference before any authority of the management prior to its approach with the demand relating to the dispute under reference to the Conciliatory authority? If not, is the dispute under reference an industrial dispute within Section 2(k) of the Industrial Disputes Act so as to make the reference entertainable and adjudication by this Tribunal ?

Those above are the preliminary issues raised on the contentions put forward by Mr. Mukherjee, the learned Counsel for the management and Mr. Malkhandy the learned Counsel who is now representing the Colliery Mazdoor Sabha of India, Raniganj. This order should be read as supplementary to the orders dated 30.6.72, 17.8.62 and 13.9.72, arising out of the same subject matter now contended before me by the learned Counsels. Mr. Malkhandy now representing the Colliery Mazdoor Sabha of India, Registration No. 9703, Raniganj, had through the General Secretary of the said union caused a statement to be submitted before this tribunal with a copy to the management. The management also by its two petitions dated 17.8.72 and 13.9.72 through the learned Counsel, raised several preliminary questions regarding representation of the workmen in this proceeding. So, on the last date of hearing on those petitions Mr. Malkhandy who was then appearing for the Colliery Mazdoor Sabha, Raniganj, Burdwan submitted that the workmen involved in the dispute have since transferred their allegience to a newly registered trade union, Colliery Mazdoor Sabha of India, Registration No. 9703, and that Colliery Mazdoor Sabha of India has been authorised by the workmen represent the workmen in this proceeding. Such statement was asked to be embodied in a petition. The result was the petition that was caused to be filed on 17.9.72 in this proceeding through Sri Dinesh Singh who describes himself as Secretary of the Colliery Mazdoor Sabha of India, Raniganj, Burdwan. Mr. Malkhandy now represents that body. He submits that he is also representing the Colliery Mazdoor Sabha, Raniganj, Burdwan. In this circumstance, upon hearing the learned Counsels and reading the petitions the preliminary issues have been framed. The other issue that was raised as a preliminary issue by Mr. Mukherjee in his submission based on a petition will appear from the order dated 30.6.72 relating to the competency on merit of the reference on the allegation that the dispute in fact was arising out of closure. That aspect of the case shall have to be considered upon hearing and deciding the fundamental issues settled to-day which go to the very root of the jurisdication of this tribunal and the competency of the reference as constituted on the questions settled under the issues.

To December 11 for hearing the preliminary issues framed to-day and for orders. All documents necessary for hearing in the preliminary issues must be produced according to law and all steps for production of documents must be taken as early as possible but before the date fixed for hearing by the parties concerned.

This order and the relevant orders referred to would govern the Reference No. 95 of 1971 in which the parties and the preliminary points raised in the issues in this proceeding settled to-day are the same."

Issue No. 1-In Issue No. (i) there is a slip. In place of the 'is' the word 'has' is to be read and the word 'has' in the 7th line of the issue is to be deleted.

8. The Failure reportes that came with each of the reference would show that Secretary, Colliery Mazdoor Sabha, CITU, Raniganj, Dist. Burdwan, raised the relevant industrial disputes before the Assistant Labour Commissioner. The Central Government under Rule 10B(1) of the Central Rules forwarded a copy of the order of reference to the Secretary, Colliery Mazdoor Sabha, CITU. P.O.Raniganj Distric Burdwan, in both the refernnces. This tribunal in both the references issued notice to Secretary Colliery Mazdoor Sabha, CITU, Raniganj, Dist. Burdwan. One Robin Chatterjee Secretary. CMS, P. O. Raniganj received the notice on 23-10-71 In Reference No. 103 of 1971. In Reference No. 95 of 1971 the notice was received by somebody on 9-8-71 writing in Hindi a rubber stamp impression of Colliery Mazdoor Sabha. In Reference No. 103 of 1971 on 29th August, Colliery Mazdoor Sabha, affiliated to CITU, Registration No. 3449 filed a petition before the Tribunal signed by Robin Chatterjee, General Secretary, Colliery Mazdoor Sabha, P.O. Raniganj, Distt. Burdwan. On 22-11-71 the workmen represented by Colliery Mazdoor Sabha, CITU, through its General Secretary, Robin Chatterjee filed a petition. On 5th November, 1971 Robin Chatterjee, General Secretary, Colliery Mazdoor Sabha Registration No. 3449 affiliated to CITU, filed another petition. Colliery Mazdoor Sabha, CITU, filed its statement of case on 23.11.71 signed by Robin Chatterjee, General Secretary, Colliery Mazdoor Sabha, CITU. On 19.5.72 Robin Chatterjee the General Secretary for and on behalf of the Colliery Mazdoor Sabha, Raniganj, filed another petition. Robin Chatterjee, for and on behalf of the Colliery Mazdoor Sabha, CITU, Raniganj, filed on 27th May a petition for leave to file rejoinder to the management's statement of case. On 27th May, 1971 Robin Chatterjee, General Secretary, for and on behalf of the CMS, Raniganj, filed the Rejoinder on that very date he filed another petition. On 26th June, 1972 one Moni Bose, Secretary, for and on behalf of the Colliery Mazdoor Sabha, Raniganj, (CITU) filed a petition. In both the references on 10th July, 1972, Robin Chatterjee, for and on behalf of the CITU, Raniganj, filed an authorisation letter appointing Sri B. Malkhandy, Bar-at-law and Sri Sudhendu Mukherjee, Advocate, to act and plead in Reference No. 95 & 103 of 1971 for the said union. So, upto July the record of Reference No.103 of 1971 would show that the workmen were being represented by Colliery Mazdoor Sabha, CITU, Raniganj. On 19th September, 1972 for the first time a petition was filed by Dinesh Singh, Secretary, Colliery Mazdoor Sabha of India, Raniganj. in which certain statements of fact were made and the prayer made in such petition would show that the contentions raised by the management in its statement of case and several petitions referred to above should be rejected. On 27.9.72 a joint petition was filed by the management and the workmen represented by the Colliery Mazdoor Sabha of India praying for adjournment of the hearing of the matter but Colliery Mazdoor Sabha of India has neither prayed for being joined as a party nor was made a party but was allowed to raise the contentions to which I have already referred. On 21st November, 1972 the Colliery Mazdoor Sabha of India. Raniganj for the first time filed an authority letter, signed by Robin Chatterjee, General Secretary Colliery Mazdoor Sabha CITU, Raniganj, appointing Mr. Malkhandy, Bar-at-Law, to represent such union in the reference No.103 of 1971. In reference No.95 of 1971 the Colliery Mazdoor Sabha of India did not appear nor did engage Mr. Malkhandy to represent the workmen involved in the dispute in Reference No. 95 of 1971 for and on behalf of the Colliery Mazdoor Sabha of India.

9. Section 36(1) of the Industrial Disputes Act reads as follows:

"36(1) A workman who is a party to a dispute shall be entitled to be represented in any proceeding under this Act by—

(a) an officer of a registered trade union of which he is a member;

(b) an officer of a federation of trade unions to which the trade union referred to in clause (a) is affiliated;

(c) where the worker is not a member of any trade union, by an officer of any trade union connected with, or by any other workmen employed in, the

industry in which the worker is employed and authorised in such manner as may be prescribed."

A workman is a party to the dispute. He shall be entitled to be represented in any proceeding under the Industrial Disputes Act, firstly by an officer of a registered trade union of which he is a member, secondly by an officer of a federation of trade unions to which the trade union referred to in clause (a) is affiliated, and thirdly, where the workman is not a member of a trade union by an officer of any trade union connected with, or by any other workman employed in the industry in which the worker is employed and authorised in such manner as may be prescribed. Section 36(1) is to be read with Rules 36 and Form F of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957. Rule 36 of the Central Rules reads as follows:

"36. Form of authority under section 36—The authority in favour of a person or persons to represent a workman or group of workman or an employer in any proceeding under the Act shall be in Form F."

The form F reads as follows:

FORM F

(See Rule 36)

Before (here mention the authority concerned).
Reference No. of Workmen
versus

.....Employer.

In the matter of ..... I/We hereby authorise Shri/Sarvashree.....to represent me/us in the above matter.

Dated this.....day of 19

Signature of person(s) nominating the representative(s).

Address

Accepted.

Signature of representative(s)
Address."

In neither of the references, the letters of authority filed have been made according to Rule 36 Form F. A workman who is a party to a dispute shall be entitled to be represented in any proceeding under the Industrial Disputes Act. The party is the workman not the Union. The workman is to authorise the union in view of Rule 36 Form F to represent the workmen or workman concerned in the relative dispute in any proceeding under the Industrial Disputes Act. In the record of the two proceedings none of the letters or authority has been signed by any of the workmen involved in the relative disputes authorising any officer of the Colliery Mazdoor Sabha, Raniganj or Colliery Mazdoor Sabha of India to represent in conformity with Section 36(1)(a) read with rule 36. Section 36(1) says that the workman who is a party to a dispute shall be entitled to be represented in any proceeding under the Industrial Disputes Act clause (a) by an officer of a registered trade union of which he is a member. Rule 36 speaks of the authority in favour of a person or persons. A union which is a registered trade union is a person under Section 13 of the Trade Union Act since it is a corporate body having perpetual succession and common seal. Section 13 of the Trade Union Act, 1926 reads as follows:

"13. Incorporation of registered Trade Unions. Every registered Trade Union shall be a body corporate by the name under which it is registered, and shall have perpetual succession and a common seal with power to acquire and hold both moveable and immoveable property and to contract, and shall by the said name sue and be sued."

So, the workman or a group of workmen in any proceeding under the Industrial Disputes Act is to sign the letter of authority in favour of a person or persons i.e. in case of a registered trade union to such union enabling an officer of such registered trade union to represent the workman or workmen in any proceeding under the Industrial Disputes Act, in accordance with Rule 36 Form F of the Industrial Dispute (Central) Rules, 1957. Such letter of authority is then to be filed before the authority concerned in the proceeding under the Industrial Disputes Act. The rules are part of the law i.e. the Industrial Disputes Act. It has been decided by the Supreme Court in the case reported in 1972 I LLJ p. 99, Workmen of Delhi Cloth and General Mills Ltd. *vs.* Delhi Cloth and General Mills Ltd. that the rules and the forms prescribed under the Industrial Disputes Act, I mean the Central Rules and forms, are parts of the Industrial Disputes Act. Any act in violation of any rule and the form prescribed by the Rules for doing any act under the Industrial Disputes Act by a party to the dispute in any proceeding under Industrial Disputes Act would be no act according to law and must have to be held illegal and unwarranted by law. The letters of authority filed in both the proceedings would not show that the workmen who are parties to the relevant disputes by signing the letter of authority according to Rule 36 and Form F of the Central Rules authorised either the Colliery Mazdoor Sabha, Raniganj, CITU or the Colliery Mazdoor Sabha of India said to be registered rade unions to represent the party i.e. workmen involved in the dispute in both the references in any proceedings under the Industrial Disputes Act. In none of the letters of authority none of the workmen involved in either of the disputes under either of the references signed any letter of authority as prescribed by Rule 36 of the Central Rules and Form F thereto authorising either the General Secretary or the Organising Secretary or any Secretary of any of the unions either the Colliery Mazdoor Sabha, Raniganj, CITU or the Colliery Mazdoor Sabha of India to represent the workmen involved in the proceedings of both the references. The Form F read with Rule 36 and Section 36(1)(a) of the Industrial Disputes Act makes it abundantly clear, in view of the decision of the Supreme Court reported in 1959 II LLJ p. 553 Hotel Imperial's case that the party to a dispute is on onside the employer and on other side its workmen but not any union. A registered trade union can act only to represent the workmen provided the workmen by making a letter of authority as prescribed by Rule 36 and Form F authorise a registered trade union of which they are members to represent the workmen involved in the dispute under reference in any proceeding under the Industrial Disputes Act. But no union whether registered or unregistered can appear as of right to represent any workman or workmen involved in any dispute referred to for adjudication before the industrial tribunal or a labour court or a National tribunal under the Industrial Disputes Act, 1947 Unless workmen complying with rule 36 and form F authorise a registered union to represent them in any proceeding under the Act, no union of which such workmen are members can have any right to represent the workmen under Section 36(1)(a) of the Industrial Disputes Act in any proceeding under the Act. I have gone through the letters of authority filed in both the references. I have noted the character of those letters of authority. In the proceedings of both the references the provisions of Section 36(1)(a) of the Industrial Disputes Act and Rule 36 Form F of the Industrial Disputes (Central) Rules have been blattantly violated. Rule 37 of the Central Rules reads as follows:

"37. Parties bound by acts of representative—A party appearing by a representative shall be bound by the acts of that representative."

As a party appearing by a representative shall be bound by the acts of that representative, the party is the workmen, involved in the dispute under reference, in both the proceedings and if the party i.e. the workmen have lawfully authorised any registered Trade Union of which they are members by making a letter of authority, any officer of the said authorised registered trade union has then the authority to represent the workmen involved in the dispute in any proceeding under the Industrial Disputes Act, in view of the provisions of Section 36(1)(a) read with Rule 36 Form F of the Central Rules. If the registered union working through any of its officers has accepted on the workmen's letter of authority to represent the workmen involved in the proceedings under reference, as prescribed by Rule 36 Form F, the representative of the workmen i.e. any of the officers of such registered Trade Union so appointed by the workmen can bind by his act done in the proceedings as reprsentative of workmen, but no otherwise, in view of Rule 37 of the Central Rules. So, Rule 36 and 37 of the Central Rules must be read with Section 36(1)(a) of the Industrial Disputes Act. I have already observed that the letters of authority filed in both the proceedings do not comply in the least with the provisions of Section 36(1)(a) read with Rule 36 Form F of the Industrial

Disputes Act. So, the union Colliery Mazdoor Sabha of India, P. O. Raniganj, Dist. Burdwan that claims to represent the workmen involved in both the dispute in both the proceedings under both the references have no legal authority to represent through any of its officer the workmen involved in the dispute under both the references in both the proceedings.

10. The failure report in both the references would show that before the Conciliation Officer in both the cases Secretary, Colliery Mazdoor Sabha, CITU, P.O. Raniganj, Dist. Burdwan raised the relative dispute under both the references. Conciliation proceedings appear in Chapter IV Section 11 Subsections (2) and (4) of Industrial Disputes Act. So, the conciliation proceeding is a proceeding under the Industrial Disputes Act. If the workmen themselves approach the management i.e. the authority of the management that may accede to or reject the charter of demand of the workmen and place the charter of demand for and on behalf of themselves, the first limb of the industrial dispute is then in the making. If the management does not accede to the charter of demand served on it, the workmen may approach the conciliation officer. If the cause of the workmen is taken up by a registered trade union of which the workmen are members, any officer of such union, if the union is authorised by the workmen under provisions of Section 36(1)(a) read with Rule 36 Form F may represent the workmen, firstly before the management when the first limb of the industrial dispute is in the making. If the management does not accede to the charter of demand placed on behalf of the workmen by an officer of such registered Trade union duly authorised by the workmen to act on behalf of the workmen in placing the charter of demand before the management, the workmen may authorise under Section 36(1)(a) read with rule 36 the registered trade union to raise the demand relating to the dispute before the Conciliation Officer. In the conciliation proceeding any officer of such registered trade union may represent the workmen. So, if an officer of a registered trade union is to represent the workmen involved in a dispute in any proceedings under Industrial Disputes Act, the workmen, who are parties to the dispute are required, in view of Section 36(1)(a) of the Industrial Disputes Act. read with Rules 36 Form F of the Industrial Disputes (Central) Rules to authorise in writing according to Form F a registered trade union of which they are member to represent the workmen involved in the dispute before the Conciliation officer since the conciliation proceeding is within the expression "in any proceeding under the Act" as mentioned in Section 36(1) of the Industrial Disputes Act. In such a case an officer of the said registered trade union if authorised by workmen who are party to the dispute in the manner mentioned above shall have the right to represent the workmen involved in the dispute before the conciliatory authority but not otherwise since conciliation proceeding is a proceeding under the Act, when the second limb of industrial dispute before the conciliation authority is in the making. Section 36(1)(a) and (b) relate respectively to an officer of a registered trade union of which the workmen are members, and to an officer of a Federation of a trade unions which must be registered to which the trade union referred to in clause (a) is affiliated. Clause (c) of Section 36(1) relates to a workman who is not a member of any trade union. In such a case an officer of any trade union connected with or by another workmen employed in the industry in which the workman is employed and authorised in such manner as may be prescribed can represent. So, before the Conciliation Officer an officer of any trade union meaning registered trade union in the circumstances enumerated in clause (c) may represent under Section 36(1)(c) provided such officer of a registered trade union is authorised by the workmen in accordance with Rule 36 Form F of the Central Rules, as a workman can also authorise a registered trade union or a federation of registered trade unions, as clause (a) and (b) of Section 36(1) enjoins. By clause (c) of Section 36(1) of the Industrial Disputes Act, a workman in the circumstances prescribed in that clause may even authorise in conformity with Rules 36 Form F any officer of a registered trade union to represent the workman involved in the dispute in any proceedings under the Industrial Disputes Act.

11. Now, the question first to be decided is whether the Colliery Mazdoor Sabha, CITU, Raniganj as appearing in the two failure reports in the two proceedings is a registered trade union under the Trade Unions Act, 1926. Section 8 of the Trade Union Act reads as follows:

> "8. Registration. The Registrar, on being satisfied that the Trade Union has complied with all the requirements of this Act in regard to registration, shall register the Trade Union by entering in a register, to be maintained in such form as may be prescribed, the particulars relating to the Trade Union contained in the statement accompanying the application for registration."

Section 9 of the Trade Unions Act reads as follows:

> "9. Certificate of registration. The Registrar, on registering a Trade Union under section 8, shall issue a certificate of registration in the prescribed form which shall be conclusive evidence that the Trade Union has been duly registered under this Act."

Certificate of registration shall be the conclusive evidence that the trade union has been duly registered under the Act. No certificate of registration of Colliery Mazdoor Sabha, CITU, Raniganj or Colliery Mazdoor Sabha of India has been filed in either of the two references. Section 8 of the Trade Union Act has to be read with Regulation 4 of the Bengal Trade Union Regulations, 1927. The Register of Trade Union was called for by the management, Ext. M 14. Colliery Mazdoor Sabha was registered on 15th July, 1955 bearing Sl. No. 3449. Its registered head office is P.O. Jamuria, Distt. Burdwan. Section 5 sub-section (1) of the Trade Unions Act speaks of application for registration. Clause (b) of sub-section (1) of Section 5 says, "the name of the Trade Union and the address of its head office." Section 12 of the Trade Union Act—Registered office—reads as follows:

> "12. Registered office. All communications and notices to a registered Trade Union may be address to its registered office. Notice of any change in the address of the head office shall be given within fourteenth days of such change to the Registrar in writing, and the changed address shall be recorded in the register referred to in section 8."

Section 8 of the Act, already quoted, is inextricably linked with Sections 5, 6 and 12 of the Act and the relative Bengal Regulations, 1927, viz. rule 4 and 5A.

12. Section 12 of the Trade Unions Act amongst other things says that notice of any change in the address of the Head office shall be given within 14 days of such change to the Registrar in writing and the changed address shall be recorded in the Register referred to in Section 8. The Bengal Trade Union Regulation 1927, Rule 4 says that the register of Trade unions referred to in Section 8 shall be maintained in Form B. Rule 5(A) of the Regulation says, every notice of change of address of Head office or change of name or amalgamation or desolution of a trade union shall be made in Forms C1, C2, C3 or C4 as the case may be. Regulation 5A(1) and (2) says that the Registrar on receiving any such notice may take such step as he thinks fit to verify the facts stated therein and to satisfy himself that the notice is genuine and may if he is not satisfied refuse to give effect to the notice. It is abundantly clear from those Sections 8 and 12 and Bengal Regulations 4 and 5A(1) and (2) that a registered trade union which had its head office registered at the time of registration shall have to notify the change of its address of the registered head office and such change of address of the registered head office of the registered trade union shall be recorded in the register of trade unions maintained in form B of the Bengal Regulation Rule 4 by the Registrar of Trade Unions in conformity with Regulation 5A(1) and (2). If we look to Ext. M 14 the Register of Trade Unions in Bengal now West Bengal, it would be found that a trade union of the name of Colliery Mazdoor Sabha was registered on 15th July, 1955 with Registration Sl. No. 3449 with its registered head office at Jamuria, P.O. Jamuria, Distt. Burdwan. There is no registered trade union bearing registration Sl. No. 3449 with its registered head office either at Raniganj or at Asansol with the name of Colliery Mazdoor Sabha. There is even uptil to-day a registered trade union bearing Reg. Sl. No. 3449 with its registered head office at Jamuria, P.O. Jamuria, Distt. Burdwan having its name Colliery Mazdoor Sabha. So, Secretary, Colliery Mazdoor Sabaha, CITU, Raniganj that raised the dispute in both the references in both the proceedings before the conciliatory authority is not a registered trade union under the Trade Unions Act, 1926 since there is no registered trade union of the name of Colliery Mazdoor Sabha bearing Regd. Sl. No. 3449 having any head office either at Raniganj or at Asansol. A registered trade union, with a registered Sl. number with its registered name and registered head office is as such a corporate entity under Section 13 of the Trade

Union Act, 1926 which has already been quoted. So, Colliery Mazdoor Sabha was registered as a registered trade union bearing Regd. Sl. No. 3449 having its registered head office at Jamuria, P.O. Jamuria, Distt. Burdwan in 1955. The Colliery Mazdoor Sabha bearing Sl. No. 3449 was not registered as a registered trade union having its head office at any place other than at Jamuria. So, the Colliery Mazdoor Sabha CITU claiming to bear Regd. Sl. No. 3449 and claiming to have its office at Raniganj and Asansol is not identical with the registered trade union Colliery Mazdoor Sabha bearing Regd. Sl. No. 3449 having its registered, head office at Jamuria, P.O. Jamuria, Distt. Burdwan. The Register of trade unions maintained under Section 8 of the Trade Union Act in which any change of the head office of a registered trade union is to be recorded by the Registrar of Trade Unions in the manner already discussed is a statutory register maintained under the provisions of the Trade Unions law, and as such, is a public document entries wherein are conclusive unless the contrary is proved by any party controverting the same. Looking into the register of trade unions, Ext. M. 14, I hold that it has been maintained upto date according to law by the Registrar of trade unions. Therefore, there is no registered trade union of the name Colliery Mazdoor Sabha bearing Reg. Sl. No. 3449 having its any office, not to speak of its head office, either at Asansol or at Raniganj. The Colliery Mazdoor Sabha, bearing Regd. Sl. No. 3449 having its office at Asansol and Raniganj Distt. Burdwan is not, therefore, a registered trade union under Section 8 of the Trade Unions Act head with Section 13 of that Act. Moreover as there cannot be in law two organisations of registered Trade unions bearing the same name and the same registration serial number, one of such organisations must be a spurious one, having no legal existence as a registered trade union under Trade Unions Act.

13. What is the position then? The first limb that constitute an industrial dispute under Sec. 2(k) of the Industrial Disputes Act, 1947 is rested in the raising of a dispute, either by workmen involved in such dispute relating to their demand or by a registered trade union of which the workmen are members authorised by the workmen involved in the dispute to raise the dispute for and on behalf of the workmen so authorised relating to the demand of the workmen before an authority of the management that may accede to or reject the demand so raised. When the demand relating to the dispute of the workmen is laid before an authority of the management that may accede to or reject the demand relating to the dispute it may be raised by either by a body of workmen or by a registered trade union, authorised by the workmen in that behalf. The authority of the management before whom the demand relating to the dispute is so raised may either accede to or reject the demand relating to the dispute. The first limb is then in the making relating to the industrial dispute under Section 2(k) of the Industrial Disputes Act in view of the decisions in Raju's Cafe, Coimbatore and Others vs. Industrial Tribunal Coimbatore and another, 1951 I LLJ, p. 219 (Madras High Court), Sindhu Resettlement Corporation Ltd. and Industrial Tribunal, Gujarat & Ors. 1968 I LLJ p. 834 (Supreme Court) and Fedders Lylord Corporation Private Ltd. and Lt. Governor, Delhi and Ors. F.L.R. 1970(2) p. 343 (Delhi High Court). If the management rejects the demand relating to the dispute raised either by a body of workmen or by a registered trade union of which the workmen are members, authorised in that behalf by the workmen, through one of its officers, the workmen or the registered trade union acting through its Officer may approach the conciliatory authority with the demand relating to the dispute which must be identical to the demand relating to the dispute as laid before the management. The Conciliation proceeding then begins. In the conciliation proceeding the workmen themselves may represent or they may authorise a registered trade union of which they are members to represent their cause when any officer of the authorised registered trade union may represent the cause of the workmen in the conciliation proceeding in view of Section 36(1)(a) read with Rule 36 Form F. The conciliation proceedings fails. The second limb in the making of the industrial dispute is then complete. The failure report sent to the appropriate Government is considered by the Government and the Government may refer the dispute relating to the demand of the workmen raised in the manner already discussed to either a labour court or an industrial tribunal or a National tribunal as the case may be for adjudication of the demand relating to the dispute. Then begins the proceedings in the reference before either of those authorities commonly known as reference proceeding as the case may be. There the workmen themselves can represent as of right in the proceeding before either of the authorities named above or the workmen may authorise a registered trade union of which they are members in the manner and to the extent prescribed by Rule 36 Form F read with Section 36(1)(a) of the Industrial Disputes Act to represent their cause before either of those authorities in the proceeding. Then any of the officers of such registered trade union so authorised may appear before any of those authorities in the proceeding to represent the workmen involved in the dispute under reference. Then comes rule 37. The demand relating to the dispute as raised before the management, as raised before the conciliatory authority and as raised before either of the authorities mentioned above, i.e. the labour court, industrial tribunal or National Tribunal, must be identical. The third limb in the making of the industrial dispute under Sec. 2(k) of the Industrial Disputes Act is then fully made up. So, a dispute to become an industrial dispute under Section 2(k) of the Industrial Disputes Act in view of the decisions already quoted above relating to the demand of the workmen must first be raised before an authority of the management that may accede to or reject the demand relating to the dispute which may be raised either by the workmen in a body involved in the dispute or by a registered trade union of which the workmen are members, authorised in that behalf by the workmen in the manner and to the extent prescribed by rule 36 Form F of the Central Rules read with Section 36(1)(a) of the Industrial Disputes Act. The first limb that enters into the making up of the industrial dispute under Section 2(k) of the Act is the laying of the demand of the workmen relating to the dispute before the authority of the management. The second limb in the making of the industrial dispute under Section 2(k) of the Act is the laying of the demand of the workmen relating to the dispute before the conciliatory authority. The third limb that make up a dispute a full fledged industrial dispute under Section 2(k) of the Industrial Disputes Act is the statement of case which the workmen are required to file in response to the order of reference before either of the authorities already mentioned to whom the reference is made for adjudication by the Govt. The demand relating to the dispute first laid before the management, then laid before the concilliatory authority and then laid in the statement of case filed for and on behalf of the workmen as mentioned above must not only be identical but must be raised seriatim *i.e.* first before the management, then before the conciliatory authority and then before either of those authorities to which the reference is made by the Government, in the statement of case filed for and on behalf of the workmen. Having regard to the principles laid down in the three cases mentioned above, "any proceeding under Section 36(1) of the Industrial Disputes Act" includes, the proceedings that starts when the workmen or a registered trade union as the case may be, as already discussed, lay their charter of demand before the management, and next before the conciliatory authority and lastly in the statement of case filed in the proceeding before the adjudicating authorities. Now, in each of the three stages mentioned above, the workmen themselves in a body may submit their charter of demand relating to the dispute before the authority of the management or they may authorise a registered trade union in the manner prescribed by Rule 36 and Form F to lay the charter of demand relating to the dispute on behalf of the workmen successively before the authority of the management and before the conciliatory and adjudicating authorities as already mentioned. In such a situation, any officer of such a registered trade union has the right under Section 36(1)(a) of the Industrial Disputes Act read with Rule 36 Form F of the Central Rules to represent the workmen before the management, the conciliatory and adjudicating authority and by his acts the workmen, as rule 37 of the Central Rule prescribes, are to be bound but not otherwise. Now, it must be made clear that this is not a case in either of the proceedings before me in which any unregistered trade union is involved. In both the proceedings the case stands on the footing that the demand relating to the dispute in both the proceedings was laid by a registered trade union i.e., Colliery Mazdoor Sabha bearing No. 3449, P.O. Raniganj, CITU, particularly before the conciliatory authority as the failure reports show. The workmen themselves have the right to represent them in any proceeding under the industrial Disputes Act. Conciliation proceeding is indisputably one of such proceedings under the Act. Impliedly by the decisions in the three cases quoted above, the laying of the charter of demand relating to a dispute either by the workmen in a body or by a registered trade union authorised in that behalf by the workmen who are members thereof before an authority of the

management is none the less a proceeding under the Industrial Disputes Act since if the charter of demand is not first laid, either by the workmen or by an authorised registered trade union through its any officer before the authority of the management, the first of the three limbs that make up a dispute into an industrial dispute under Section 2(k) of the Industrial Disputes Act would be wanting. If the workmen or the registered trade union as the case may be, approach the conciliatory authority with the charter of demand straight off before approaching an authority of the management with such charter of demand, the dispute relating to that charter of demand would not be an industrial dispute under Section 2(k) of the Act in view of the decisions in the three cases referred to above. By the implication of those decisions as well as by Sec. 18(1) of Industrial Disputes Act, 1947 the right to represent the workmen by an officer of a registered trade union before the management by laying the charter of demand for and on behalf of the workmen may be created in favour of registered trade union by the workmen themselves, who are members of such a registered trade unions, provided the workmen members of the said registered trade unions authorise such trade union in the manner prescribed by rule 36 and Form F to lay the charter of demand relating to their dispute before the authority of the management. Only an officer of such an authorised registered trade union authorised in the manner prescribed by law may represent the workmen by laying the charter of demand for and on behalf of the workmen before the authority of the management. If neither the workmen nor any officer of a registered trade union which is duly authorised by the workmen members of such trade union lay the charter of demand before the authority of the management and the workmen or the registered trade union takes the dispute straight off to the conciliatory authority the dispute may be a dispute but would not be an industrial dispute under Section 2(k) of the Industrial Disputes Act. So, right from the stage of laying the charter of demand before the authority of the management upto the conclusion of the proceeding before the Conciliatory authority and/or before the industrial tribunal or the labour court or the National tribunal as the case may be, the proceedings under Industrial Disputes Act within the meaning of Sec. 36(1) of I.D. Act start and continue at three such stages and in such proceedings the workmen themselves may represent or if the workmen are members of the registered trade union, they may authorise such registered trade union to represent the workmen at all these three stages of the proceedings, and in that event the officer of such an authorised registered trade union, can under Section 36(1)(a) of the I.D. Act represent the workmen from the stage of laying the demand relating to the dispute of the workmen before the authority of the management right upto the conclusion of the proceedings before any of the adjudicating authorities mentioned above when the award is rendered.

13. Now, such authorisation by the workmen, as I have already discussed, must be effected in writing by the workmen involved in the dispute in the manner prescribed Rule 36 Form F of the Central Rules whenever the workmen desire that in any of the three stages of the proceedings, beginning from the laying down of the charter of demand before an authority of the management right upto the making of the award, they should be represented by a registered trade union and then only the representation of the workmen by authorised trade union may be effective under Section 36(1)(a) by any officer of such registered trade union so duly authorised by the workmen involved in the proceedings at the three stages under the Industrial Disputes Act. Therefore, in Sec. 36(1)(a) of the Act the emphasis lies on the words "registered trade union" as appearing in Section 36(1)(a) of the Act which must be read with Rule 36 Form F of the Central Rules. In place of an officer of a registered Trade union it should not be read "any member of the Executive or other office bearer" in view of the recent amendment. But the words thus replacing "an officer" have no importance in this case. Before the conciliatory authority Secretary, Colliery Mazdoor Sabha, CITU, Raniganj raised the dispute relating to the demand of the workmen in both the proceedings that resulted in the two failure reports. Colliery Mazdoor Sabha, CITU. Raniganj, which claims to bear Regd. Sl. No. 3449 with its office, but not head office at Raniganj, is not a registered trade union. The Secretary of that trade union committed fraud upon the statute when he posed himself before the conciliatory authority that he is the Secretary of a Registered trade union of the name Colliery Mazdoor Sabha, CITU, Raniganj, when, however, there has been no existence of any trade union registered as Colliery Mazdoor Sabha, P.O. Raniganj, District Burdwan bearing Reg. Sl. No. 3449 anywhere in West Bengal. There is one registered trade union, vide Ext. M14, bearing the name Colliery Mazdoor Sabha, Regn. Sl. No. 3449, having its registered head office at Jamuria, P.O. Jamuria, Dist. Burdwan which is even now existing as a corporate body under Section 13 of the Trade Union Act, being registered as such under Section 8 of the Trade Union Act. Therefore, the Colliery Mazdoor Sabha, CITU, P.O. Raniganj, Dist. Burdwan is not a registered trade union under the Trade Union Act and its Secretary who claims to have raised the dispute relating to the demand of the workmen involved in both the proceedings before this tribunal was not a Secretary of a registered trade union and as such was not an officer of a registered trade union. There he had no legal authority under Section 36(1)(a) of the Industrial Disputes Act to represent the workmen involved in the dispute in both these proceedings before the conciliation authority involved in both the references in both the proceedings. So, the conciliation proceeding relating to both the references, now involved in both the proceedings before this tribunal suffered from inherent infirmity of law and were wholly vitiated since fraud vitiates every transaction. The Colliery Mazdoor Sabha, CITU, P.O. Raniganj, is not a registered trade union. So, the Colliery Mazdoor Sabha, CITU, being not a registered trade union, its Secretary being not an officer of a registered trade nion had no authority to represent in the conciliation proceedings relating to both the references before the conciliation officer for and on behalf of the workmen involved in the dispute under both the references in both the proceedings. The conciliation officer was likely to have the impression that Colliery Mazdoor Sabha, CITU P.O. Raniganj was a registered trade union, and that its Secretary was an officer of such a registered trade union. Whether the Colliery Mazdoor Sabha, CITU, Raniganj, if the Conciliation authority took it for granted that it was a registered trade union, was authorised by the workmen involved in the dispute under both the references in the manner prescribed by Rule 36 Form F remains in darkness In these two proceedings before this tribunal. Apparently the failure reports show that the conciliation officer took it for granted that the Colliery Mazdoor Sabha, CITU, P.O. Raniganj was registered trade union and that the registered trade union was authorised by the workmen to raise the dispute before the conciliation officer relating to both the references in both the proceedings now before this tribunal. He was thoroughly misled, if he had the impression, as the records show, that he had. The fraud was committed on the Statutes patently by the Secretary of Colliery Mazdoor Sabha P.O. Raniganj when that Secretary raised the dispute involved in those two proceedings, now before the Tribunal and before the Conciliation officer leading him to believe that the Colliery Mazdoor Sabha, CITU P.O. Raniganj was a registered trade union and the Secretary thereof was an officer of such a registered trade union authorised by the workmen to represent them in the conciliation proceedings before the Conciliation officer. But it is now revealed in these two proceedings, that Colliery Mazdoor Sabha bearing Regd. Sl. No. 3449, P.O. Raniganj, Dist. Burdwan is not a registered trade union vide Ex. M14, and that its Secretary who raised the dispute relating to the demand of the workmen before the conciliation authority involved in the two references in both the proceedings before this tribunal was not an officer of a registered trade union. He, therefore, committed a fraud on the Statutes i.e. Trade Union Act and the Industrial Disputes Act and caused the entire conciliation proceedings involved in the two references to be vitiated before the Conciliation officer. So, there was no representation before conciliatory authority under Section 36(1)(a) Industrial Disputes Act, read with Rule 36 Form F of the Industrial Disputes Act and Central rules valid in law. On the conclusion of the two conciliation proceedings which were vitiated by fraud of the Secretary of the so called trade union, the conciliation officer submitted a failure report in both the Conciliation proceedings before him upon which the Central Government acted in referring the dispute relating to the demand of the workmen under two separate orders of reference for adjudication by this tribunal. I have already observed that a fraud vitiates every proceedings, either legal, or administrative. Upon the failure reports based on proceedings before the conciliation officer vitiated by fraud, the Central Government can acquire no jurisdiction to refer the dispute relating to the demand of the workmen, involved in both the orders of reference in both the proceedings before this tribunal, for adjudication by the tribunal, since the respective dispute relating to the demand of the workmen in-

volved in both the proceedings lost its character of an industrial dispute, under Section 2(k) of the Industrial Disputes Act when the failure reports were based upon conciliation proceedings before the conciliation officer that were vitiated by the fraud, committed by the self-styled Secretary of the Colliery Mazdoor Sabha, CITU, Raniganj which had never been a registered trade union under the Trade Union Act.

14. The Central Government under Rule 10B(1) of the Industrial Disputes (Central) Rules had sent the order of reference in both the proceedings to the Secretary, Colliery Mazdoor Sabha, P.O. Raniganj, District Burdwan. I have already observed that in both the proceedings upto July 1972 Colliery Mazdoor Sabha, registered No. 3449 affiliated to CITU, P.O. Raniganj, Dist. Burdwan appeared before the tribunal to represent the workmen involved in the dispute under reference in both the proceedings. The Colliery Mazdoor Sabha registered No. 3449 affiliated to CITU, P.O. Raniganj, Dist. Burdwan, as I have already held, is not a registered trade union. So neither Secretary nor General Secretary Robin Chatterjee, is an officer of a registered trade union. In both the proceedings before this tribunal one Robin Chatterjee as General Secretary, Colliery Mazdoor Sabha, Registered No. 3449 affiliated to CITU, P.O. Raniganj, at Burdwan filed a statement of case and himself claimed to represent the workmen involved in the dispute under reference in both the proceedings without having any legal authority of the workmen, involved in the dispute in both the proceedings before this tribunal. The letters of authority filed in both proceedings by Colliery Mazdoor Sabha, Registered No. 3449, affiliated to CITU, P.O. Raniganj, Dist Burdwan, as I have already discussed, would not show that the workmen involved in the dispute under reference in both the proceedings issued those letters of authority in favour of a registered trade union, Colliery Mazdoor Sabha, registered No. 3449, affiliated to CITU, P.O. Raniganj, Dist. Burdwan, by signing such letters of authority, to such registered trade union, in the manner and to the extent as prescribed by Rule 36 Form F of the Central Rules under the Industrial Disputes Act. I have already discussed that in any proceedings under the Industrial Disputes Act the workmen are required by Rule 36 read ith Form F of the Central Rules framed under the Industrial Disputes Act to make and subscribe a letter of authority in favour of a registered trade union of which the workmen are members. Such authorised registered Trade Union, then through officer (now a member of the executive or an office bearer) shall have to accept such authority letter for representing the workmen involved in the dispute under reference in the proceedings before the Tribunal, and such letter of authority is to be filed before the tribunal. On the basis of such letter of authority an officer of the authorised registered trade union can represent the workmen in the proceedings before the tribunal under the Industrial Disputes Act under Section 36(1)(a) read with Rule 36 Form F of the Central Rules. But, in both the proceedings before this tribunal, the letters of authority that have been filed by the Colliery Mazdoor Sabha had not been made and signed by any of the workmen involved in the dispute under reference in both the proceedings, authorising any trade union, be it registered or unregistered, to represent the workmen involved in the dispute under reference in both the proceedings. So no officer of any trade union be it registered or unregistered shall have any right to represent workmen in the two proceedings before this tribunal. Colliery Mazdoor Sabha, registered No. 3449 affiliated to CITU, P.O. Raniganj, Dist. Burdwan, which I have already held is not a registered trade union, but it filed a statement of case signed by Robin Chatterjee, General Secretary on 22-1-71 in Reference No. 103 of 1971. This statement is dated 18th November, 1971. On 29th August, 1972 Robin Chatterjee, General Secretary, Colliery Mazdoor Sabha, P.O. Raniganj, Dist. Burdwan filed an application. On 27-6-72 Moni Bose Secretary for and on behalf of Colliery Mazdoor Sabha, CITU, Raniganj, filed a petition. On 30-6-72 before this tribunal Moni Bose filed a letter which reads as follows:

"Ref. No. 103 of 1971

Sir,

I have been authorised by the Union to appear and place the submission to day that is 30-6-72 before the Hon'ble Tribunal.

Yours faithfully,
Moni Bose, Secretary,
for and on behalf of Colliery
Mazdoor Sabha (CITU), Raniganj".

The letter will show that it is not a letter of authority made and signed by the workmen as required by Rule 36 Form F of the Central rules read with Section 36(1)(a) of the Industrial Disputes Act. On 10th July, 1972 in Reference No. 103 of 1971 Robin Chatterjee for and on behalf of the CITU, Raniganj filed a letter of authority which reads as follows:

"I hereby authorised Sri B. Malkhandy (Barrister-at-Law), and Sri Sudhendu Mukherjee (Advocate), Calcutta High Court to act and lead the above matter."

Who authorised Robin Chatterjee to represent the workmen involved in the dispute either in Reference No. 103 of 1971 of in Reference No. 95 of 1971? There is no letter of authority made and signed by any workman involved in both the references in both the proceedings, authorising Colliery Mazdoor Sabha, CITU, P.O. Raniganj, to represent the workmen involved in both the references in both the proceedings before the tribunal. There is a limit to such fragrant violation of law that can possibly be indulged by any sensible man of affairs of the world. I have pointedly referred to Rule 36 Form F of the Central Rules as well as to Section 36(1)(a) of the Industrial Disputes Act. In Reference No. 95 of 1971 Samir Kumar Dhar, Secretary, Colliery Mazdoor Sabha, CITU, but not Moni Bose, filed a petition dated 13-8-71 before this tribunal praying for time. On 13th August, 1971 Samir Dhar claims to be the Secretary of Colliery Mazdoor Sabha, Sl. No. 3449, CITU, P.O. Raniganj, in Reference No. 95 of 1971 whereas, Moni Bose claims in Reference No. 103 to be the Secretary of the same union on 30-6-72. On 14-10-71 the same Samir Kumar Dhar filed a petition for extension of time for filing statement of case. Colliery Mazdoor Sabha, Registered No. 3449, affiliated to CITU, Raniganj, filed a statement of case in case No. 95 of 1971 on 22-11-71 signed by Robin Chatterjee, General Secretary. On 10th July, 1972 in Case No. 95 of1 971 for and on behalf of the Colliery Mazdoor Sabha, Robin Chattarjee, *Secretary* but not General Secretary filed a letter which is quoted below :

"The Colliery Mazdoor Sabha do hereby authorise Shri Bishnu Malkhandy, Bar-at-Law, to represent the workmen."

Who authorised Colliery Mazdoor Sabha, P.O. Raniganj to represent the workmen in the two proceedings before this tribunal? Robin Chatterjee cannot authorise either himself or anybody else to represent workmen in any proceedings before this tribunal. I have already observed that the workmen are to make and subscribe the letter of authority in favour of a registered trade union in conformity with Rule 36 Form F. Such registered trade union shall then have to accept it and then an officer of the registered trade union or now member of the Executive or an office bearer under Sec. 36(1)(a) can come and represent the workmen in the two proceedings before this tribunal. There is no letter of authority in Reference No. 95 of 1971 and in Reference No. 103 of 1971 made and subscribed by the workmen under Rule 36 Form F of the Central Rules, involved in both the references in both the roceedings authorising any registered or unregistered trade union to represent the workmen in both the proceedings before this tribunal. So, there is no question of acceptance of any such letter of authority for representation of the workmen by anybody be it a registered trade union or an unregistered trade union. Colliery Mazdoor Sabha, affiliated to CITU, P.O. Raniganj, Regd. No. 3449 if it was at all a registered trade union, which it has never been, was required to be authorised by the workmen involved in both the proceedings before this tribunal by a letter made and subscribed by the workmen in the Form F read with Rule 36 of the Central Rules. The registered trade union, if so authorised (as in this case we are not concerned with any unregistered trade union) shall have to accept such authority for representation. That letter of authority made and subscribed by the workmen involved in these two proceedings accepted by the registered trade union were to have been filed before the tribunal in both the proceedings. If such a letter of authority would have been filed, then any office bearer of such a registered trade union or any member of its executive was to be considered as authorised by the workmen to represent them in this proceedings and could have acquired a

right to represent the workmen involved in these two proceedings under Section 36(1)(a) of the Industrial Disputes Act read with Rule 36 Form F of the Central Rules. But I have found that in neither of the wo proceedings, Reference No. 95 of 1971, and Reference No. 103, of 1971 any such letter of authority was filed, made and subscribed by the workmen involved in the dispute under reference in both the proceedings. So, the Colliery Mazdoor Sabha Raniganj, bearing No. 3449 hos no right to represent any of the workmen involved in both the proceedings before this tribunal through any of its officers, firstly because it is not a registered trade union, and secondly because, even if the Colliery, Mazdoor Sabha, P.O. Raniganj. Dist. Burdwan would have been a registered trade union, no letter of authority made and subscribed by the workmen involved in the dispute under reference in both the proceedings, according to Central rule 36 Form F, was filed in either of these proceedings.

15. To sum up, the conciliation proceedings were vitiated by fraud of a person who claimed to be the Secretary of Colliery Mazdoor Sabha, CITU, Raniganj, representing such trade union to be a registered trade union before the Conciliation officer in the proceedings thus vitiated by fraud of the said Secretary aforsaid. The Central Government acted on the failure reports that emanated from the result of the conciliation proceedings, vitiated by the fraud committed on the Statutes by a person who posed himself as Secretary of Colliery Mazdoor Sabha, CITU, P.O. Raniganj, before the conciliatory authority, as if a registered trade union of the name Colliery Mazdoor Sabha, CITU, Raniganj, which has never been a registered trade union. The Secretary, Colliery Mazdoor Sabha, CITU, Raniganj got the two orders of reference straight from the Central Government in both the proceedings and notices were also issued to that Secretary by this Tribunal relating to the two orders of reference. Then, as I have already observed, there had been fragrant violation of the law relating to representation of the workmen in both the proceedings before this tribunal by the Secretaries and General Secretary of the so called registered trade union, Colliery Mazdoor Sabha, CITU, Raniganj, as none of the workmen involved in the dispute under reference in both the proceedings had ever authorised any union, be it a registered or a unregistered trade union, to represent the workmen by a letter of authority, made and subscribed by the workmen in accordance with rule 36 Form F of the Central Rules read with Section 36(1)(a) of the Industrial Disputes Act. But Secretaries and General Secretary of the Colliery Mazdoor Sabha, CITU, Raniganj, claimed to represent the workmen bv filing several papers signed by them respectively in both the proceedings before this tribunal. I have already pointed out the nature of all those relevant documents. They had no authority in the law, as I have already discussed, to represent the workmen involved in the dispute under reference in both the proceedings before this tribunal.

16. It would be proper to note another as taunding feature. Form H is the Annual return for the year ending 31st December 1969, Ext. W1. Colliery Mazdoor Sabha, G. T. Road, Asansol, bearing No. 3449 filed the return. It is not a registered trade union vide Ext. M14. Another annual return for the year ending 31st December, 1970 was filed by the Colliery Mazdoor Sabha, G. T. Road, Asansol, at present Raniganj, Dist. Burdwan, bearing Sl. No. 3449, Ext. W 2. It is not a registered trade union. There is Ext. M 1, M 2 and M 3. M 1 is dated 22-8-70, a letter issued by R. L. C. (C), Asansol to the General Manager, Nimcha Coal Company Limited and to the Organising Secretary, Colliery Mazdoor Sabha, AITUC, G. T. Road, Asansol. There is thus another Colliery Mazdoor Sabha, AITUC at G. T. Road, Asansol. On 18-8-1970, **vide** Ext. M 2 Sunil Sen. Organising Secretary of the Colliery Mazdoor Sabha, G. T. Road, Asansol, AITUC, wrote a letter to the Assistant Labour Commissioner (C), Asansol, Ext. M 3 is a letter to the Manager, Nimcha Colliery signed by Sunil Sen, Organising Secretary of Colliery Mazdoor Sabha, AITUC, G. T. Road, Asansol and it is dated 26-4-72. In 1970 to 1972 there is one Colliery Mazdoor Sabha, AITUC, G. T. Road, Asansol Dist. Burdwan that is operating in the area of Nimcha Coal Company, Limited i.e. in Nimcha Colliery. In 1969 and 1970 **vide** Ext. W 1and W 2 a Colliery Mazdoor Sabha, G. T. Road, Asansol and a Colliery Mazdoor Sabha, P. O. Raniganj bearing Sl. No. 3449 did operate as they are now operating. Colliery Mazdoor Sabha, Raniganj, amliated to CITU bearing Registration No. 3449, P.O. Raniganj, Dist. Burdwan, West Bengal, **vide** Ext. M 4 wrote a letter on 7th December, 1970 to the Director, Nimcha Colliery signed by Robin Chatterjee, General Secretary, copy to Regional Labour Commissioner, Asansol and Assistant Labour Commissioner, Asansol. Ex. M 6 is a letter by the Regional Labour Commissioner (C), Asansol to the Manager Nimcha Colliery relating to a strike notice dated 24-4-72 served on the Manager of the Nimcha Colliery by the General Secretary, Colliery Mazdoor Sabha of India, CITU, Raniganj. Ext. M 13 is an award of this tribunal dated 12th January, 1971 In paragraph 5 of that award it is stated, "The trade union of the name of Colliery Mazdoor Sabha espoused the cause of the workmen and filed written statement". In paragraph 9 of the award it is stated, "The version as given in the notice was disputed by the sole witness examined by the workmen namely Sunil Sen in the following language.....". SunilSen is the author of Ext. M 2 dated 18-8-70 and Ext. M 3 dated 26- 4-72. Sunil Sen is the Organising Secretary of Colliery Mazdoor Sabha, AITUC, G. T. Road, Asansol which is not a registered trade union. Robin Chatterjee claims to be the General Secretary of the Colliery Mazdoor Sabha, CITU, G. T. Road, Asansol and Raniganj, Dist. Burdwan **vide** Ext. W 1 and W 2 and represent the said organisation to be a registered trade union bearing registration No. 3449 but it had never been a registered trade union. There is in existence only one registered trade union of the name Colliery Mazdoor Sabha, Regd. No. 3449 with its registered head office at Jamura, P. O. Jamuria, Dist Burdwan, as will appear from the Register of Trade Unions maintained upto date, (Ext. M 14), produced by the Registrar of Trade Unions West Bengal on being summoned by the management in both the proceedings. This is how fraud is being perpetrated upon the Statutes, vitiating all transactions by so called Secretaries, General Secretary and Organising Secretary of so called unions which are not registered trade union, but pass themselves to be registered trade union through those so called office bearer. So, in answer to Issue No. (i) I conclude as follows :

Colliery Mazdoor Sabha, CITU, bearing Registration No. 3449, P. O. Raniganj has never been a registered trade union under the Trade Union Act. Its Secretary had no authority to raise a dispute for and on behalf of the workmen involved in both the roceedings according to law as I have already The so called General Secretary of Colliery Mazdoor Sabha, CITU, P. O. Raniganj, or the Secretaries of that Body, being not a registered trade union, and having had not been authorised by the workmen involved in the dispute under reference in both the proceedings according to law as I have already discussed, have no right to represent the workmen in these two proceedings before this tribunal under Section 36(1)(a) of the Industrial Disputes Act and had no authority for representing the workmen in any proceedings under the Industrial Disputes Act, including the stages of the proceedings commencing from the laying of the charter of demand before the authority of the management, before the conciliatory authority and in filing the statement of case for and on behalf of the workmen and doing any other act in both the proceedings before this tribunal. Moreover, as I have already found, the conciliation proceedings before the conciliation authority had been vitiated by fraud of the so called Secretary of the Colliery Mazdoor Sabha, CITU, Raniganj that tainted the two failure reports with legal infirmity. So, upon the failure reports, vitiated by fraud committed by the so called General Secretary of Colliery Mazdoor Sabha, CITU, Raniganj, in the conciliation proceedings before the conciliation authority relating to the demand, involved in the two references in these two proceedings, the Central Government acquired no jurisdiction to refer the dispute under both the references in both the proceedings for adjudication by this tribunal since those disputes may be disputes, but are not industrial disputes under Section 2(k) of the Industrial Disputes Act. The Colliery Mazdoor Sabha, CITU, Raniganj, has no right nor any authority to represent the workmen involved in the dispute under reference in both the proceedings before this tribunal nor had it any authority to represent the workmen in the roceedings from the stage of laying of the charter of demand relating to the dispute in both the references before the authority of the management right upto the stage of conciliatiion proceedings before the Conciliation Officer.

17. **Issue No. (ii)** : In the two proceedings the workmen had not been legally represented by any trade union worth the name. The Colliery Mazdoor Sabha, CITU, had no legal authority to represent the workmen involved in both the reference in both the proceedings before this tribunal, though

the General Secretary or the Secretary of the said ogrnisation claimed to represent the workmen upto certain stage in both the proceedings, say, upto 13th July, 1972. Such representation was thoroughly illegal.

18. During the pendeny of the proceedings in both the references came the Colliery Mazdoor Sabha of India, P. O. Raniganj, District Burdwan affiliated to CITU. This Colliery Mazdoor Sabha of India was never authorised by any of the workmen, involved in both the references in both the proceedings, to represent the workmen in the two proceedings before this tribunal in the manner and to the extent as required by Rule 36 Form F of the Central Rules read with Section 36(1)(a) of the Industrial Disputes Act. Mr. Malkhandy who had no legal authority to represent the Colliery Mazdoor Sabha of India placed before me a decision reported in 1959 II LLJ, Hotel Imperial *vs.* Chief Commissioner, Delhi and Ors., page 553. He submitted that although the Colliery Mazdoor Sabha, CITU, P. O. Raniganj, was mentioned in the orders of the two references and the orders of the two references were sent to the Secretary of that organisation, the Colliery Mazdoor Sabha of India, a registered trade union has a right to represent the workmen involved in both the reference in both the proceedings. In Hotel Imperial's case, in the order of reference it was stated amongst other things, "that an industrial dispute exists between the management of Hotel Imperial, India and its workmen as represented by Hotel Workers Union, Katra, Chandni Chawk, Delhi". The contention in that case was that the order of reference was bad in law as the party involved in the dispute on the side of the workmen were the workmen themeselves but not the union. That contention was over-ruled by their Lordships of the Supreme Court. At page 554 their Lordships observed, "The addition of the words as representative of Hotel Workers Union, Katra, Chandni Chowk, Delhi was merely for the sake of convenience so that the tribunal may know to whom it should give notice when proceeding to deal with the reference. That however did not preclude the workmen. If they wanted to be represented by any other union, to apply to the tribunal for such representation or even to apply for being made parties individually". (Underlined by me for emphasis). Then their Lordships elucidated Section 36 of the Industrial Act. I rely on the observations of their Lordships underlined above. None of the workmen applied under rule 36 Form F before this Tribunal authorising any union, not to speak, of Colliery Mazdoor Sabha of India, to represent the workmen involved in the two proceedings before this tribunal. The General ecretary of the Colliery Mazdoor Sabha of India, as I have already observed, constituted himself an authority to appoint Mr. Malkhandy a counsel to represent the workmen in these two proceedings for and on behalf of the Colliery Mazdoor Sabha of India. None of the workmen, if they are members of that organisation, has made and subscribed any letter of authority according to rule 36 Form F of the Central Rules authorising Colliery Mazdoor Sabha of India, if it is a registered trade union, to represent the workmen involved in the dispute under the two reference in these two proceedings before this tribunal. As no such letter of authority was made and subscribed in favour of the said Colliery Mazdoor Sabha of India by the workmen, so no such letter was filed before this tribunal by the Colliery Mazdoor Sabha of India, accepting the responsibility of representing the workmen involved in both the reference in both the proceedings, signing the column of accentance in such letter so as to bind by the acts of an officer of such organisation in the two proceedings before this tribunal, the workmen involved in the dispute in both the references in both the proceedings. So, Colliery Mazdoor Sabha of India has no right to represent any workman in either of the proceedings before this tribunal under Section 36(1) (a) of the Industrial Disputes Act. Colliery Mazdoor Sabha of India may be registered trade union. But the point is, whether the workmen involved in the dispute under the two references in the two proceedings before this tribunal by making and subscribing a letter of authority in terms of rule 36 Form F, authorised the Colliery Mazdoor Sabha of India to represent the workmen in these two proceedings before this tribunal. The Colliery Mazdoor Sabha of India did not, through its General Secretary, Robin Chatterjee, or its Secretaries, as the case may be, file any such letter of authority to show that the workmen involved in the two references in these two proceedings did authorise as required by law the Colliery Mazdoor abha of India to represent the workmen in the two proceedings before this tribunal so as to entitle either the General Secretary or the Secretary of that organisation to appear before this tribunal in these two proceedings to represent the workmen involved in the two references in the two proceedings before this tribunal. Therefore, from the start right upto this date the workmen had not been represented by any trade union according to law neither by the Colliery Mazdoor Sabha, CITU, Raniganj nor by the Colliery Mazdoor Sabha of India. I cannot allow either of the two organisations to represent the workmen involved in the dispute in both the references in both the proceedings since neither Colliery Mazdoor Sabha, CITU Raniganj nor the Colliery Mazdoor Sabha of India has ever produced any letter of authority of the nature I have already discussed to entitle any of the office bearers of that organisation, be it registered or unregistered trade union, to represent the workmen involved in both the proceedings in both the references before this tribunal under Section 36(1) (a) of the Industrial Disputes Act read with Rule 36 Form F of the Central rules. So, in both the proceedings no action taken at the instance of the Secretary or the General Secretary either of Colliery Mazdoor Sabha, CITU, Raniganj or Colliery Mazdoor Sabha of India has been effective to bind the workmen involved in the dispute in both the references in both the proceedings within the scope of Rule 37 of the Central rules. Moreover the dispute referred to for adjudication in these two proceedings, as I have already observed, is not an industrial dispute within Sec. 2(k) of the Industrial Disputes Act for the reasons I have elaborately discussed. Accordingly, the Centra Government acquired no jurisdiction on the failure reports the character of which I have already discussed to make a reference of the dispute which is not an industrial dispute under Section 2(k) of the I.D. Act, in the two references involved in both the proceedings before this tribunal. So, the Colliery Mazdoor Sabha, CITU Raniganj and Colliery Mazdoor Sabha of India have no legal status to represent the workers in both the proceedings before this tribunal under Section 36(1) (a) read with Rule 36 Form F of the Central Rules nor any of its officer can by any of its act done in both the proceedings bind the workmen in view of Rule 37 of the Central Rules. So, upto this date the workmen have not been represented in either of the proceedings before this tribunal by any legally authorised representative.

19. Issue No. (iii): I have already found that the Secretary Colliery Mazdoor Sabha, CITU, Raniganj, when raised the dispute relating to the demand of workmen involved in the two reference in both the proceedings committed a fraud upon the Statutes. Therefore, the entire conciliation proceedings were vitiated by fraud at the instance of the Secretary, Colliery Mazdoor Sabha, CITU, Raniganj. The failure reports emanated from such conciliation proceedings vitiated by fraud were not a failure reports according to law in both the proceedings before the conciliation authority. The Central Government acted on such failure reports and made references of the disputes relating to the demands of the workmen involved in both the proceedings before this tribunal for adjudication by this tribunal. The Central Government's order in the two references thus suffers from the legal infirmity based on the failure reports vitiated by fraud of the so called Secretary of a so called trade union which is not a registered trade union. I have elaborately discussed this aspect already in Issue No. (i). Now, who authorised the Colliery Mazdoor Sabha, CITU, Raniganj to lay the charter of demand for the workmen relating to the two disputes in the two references in both the proceedings? Did the workmen authorise the Colliery Mazdoor Sabha, CITU, Raniganj? There is no evidence. The authorisation should be also at that stage as I have already observed, by the workmen in confirmity with rule 36 Form F of the Central rules framed under the industrial Disputes Act of 1947 and that authorisation must be to a registered trade union. But Colliery Mazdoor Sabha, CITU, Raniganj is not a registered trade union. I have already obsereved that the first limb in making of the dispute starts when the workmen or the union authorised by the workmen who are members thereof approach the management with the charter of demand. If a registered trade union was not lawfully authorised by the workmen who are members thereof, that means in terms of rule 36 Form F of the Central Rules to lay the charter of demand relating to the dispute before the authority of the management, there was the absence of the first limb in the making up a dispute into an industrial dispute under Section 2(k) of the Industrial Disputes Act. In view of the principles inunciated in the three decisions referred to above, the next limb is the raising of the dispute before the conciliation officer. There also the registered trade union shall have to be authorised by the workmen in the manner as I have already observed. If there

is no such workmen's authorisation, no officer of any registered trade union can raise a dispute before the conciliation officer if he did so, the second limb in the making of a dispute into an industrial dispute under Sec. 2(k) of the Act would be wanting. Next the third stage-filing of the statement of case on behalf of the workmen. There also the workmen must in terms of rule 36 form F of the Central rules make and subscribe a letter of authority in favour of the registered trade union and the registered Trade Union shall have to accept that letter of authority and shall have to file that letter of authority before the tribunal. In that event any officer of a registered trade union shall be entitled to represent the workmen involved in the proceedings before the tribunal but not otherwise. Now, these three limbs constituting the demand relating to the dispute of the workmen makes up a dispute into an industrial dispute under Section 2(k) of the Industrial Disputes Act but not otherwise. This crux of the principle has been enunciated firstly by the Madras High Court in Raju's Cafe's case, secondly by their Lordships of the Supreme Court in the case of Sindhu Resettlement Corporation, etc., and thirdly by the Delhi High Court in the case Fedder Lloyds, etc. Judging from the said principle the dispute that has been referred to for adjudication in these two proceedings is not an industrial dispute under Section 2(k) of the Industrial Disputes Act. Therefore, irrespective of the question whether before the management any union raised the demand relating to the dispute in both the reference becomes irrelevant. Next, the conciliation proceedings in both the reference were vitiated by the fraud purpetrated by a person who posed himself as a Secretary of a seemingly registered trade union but which has never been a registered trade union. This was a fraud upon the Statutes and any fraud on the Statutes vitiates any proceeding be it administrative, judicial or quasi-judicial. Therefore, the failure reports thus vitiated by the fraud in the manner and to the extent I have already discussed created no jurisdiction in the Central Government to act upon such failure reports to exercise its jurisdiction to make a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, the dispute in both the references to this tribunal for adjudication. So, the dispute under the reference in both the proceedings referred to for adjudication by this tribunal is not an industrial dispute within Section 2(k) of the Industrial Disputes Act in view of the law that I have discussed and the facts that I have found in these two proceedings.

20. Accordingly, I answer the issue No.(iii) that the dispute referred to for adjudication in both the references in both the proceedings is not an industrial dispute under Section 2(k) of the Industrial Disputes Act, and that the Central Government acquired no jurisdiction on the failure reports vitiated by fraud to exercise its jurisdiction under Section 10 (1) (d) of the Industrial Disputes Act to refer the dispute in both the references for adjudication by this tribunal since such disputes may be disputes, but not industrial disputes under Section 2(k) of the Industrial Disputes Act.

21. Therefore, this tribunal has acquired no jurisdiction on the two orders of reference in both the proceedings to entertain either of the references and to adjudicate thereon. Accordingly, I reject both the references.

This is my award.

S. N. BAGCHI, Presiding Officer.

December 19, 1972.

New Delhi, the 11th January, 1973

S.O. 176.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Murulidih 20/21 Pits Colliery of Messrs Bengal Coal Company Limited, Post Office Mohuda, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th January, 1973.

[No. 2/115/70-I.RII.]
KARNAIL SINGH, Under Secy.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Present :

Shri Nandagiri Venkata Rao, Presiding Officer.

Reference No. 5 of 1971

In the matter of an industrial dispute under S. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Parties :

Employers in relation to the management of Murulidih 20/21 Pits Colliery of Messrs Bengal Coal Company Limited, Post office Mohuda, District Dhanbad

AND

Their workmen.

Appearances :

On behalf of the employers in relation to the management of Murulidih 20/21 Pits Colliery.	: Shri D. Narsing, Advocate.
On behalf of Bharat Coking Coal Ltd.	: Shri S. S. Mukherjee, Advocate.
On behalf of the workmen.	: Shri S. V. Acharior, General Secretary, Hindustan Khan Mazdoor Sangh.

State: Bihar. **Industry:** Coal.

Dhanbad, 1st January, 1973

AWARD

The Central Government, being of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Murulidih 20/21 Pits colliery of Messrs Bengal Coal Company Limited, Post office Mohuda, District Dhanbad and their workmen, by its order No. 2/115/70-I.RII dated 10 December, 1972 referred to this Tribunal under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication the dispute in respect of the matters specified in the schedule annexed thereto. The Schedule is extracted below :—

SCHEDULE

"Whether the undermentioned workmen were locked-out on the dates mentioned against each by the management of Murulidih 20/21 Pits Colliery of Messrs Bengal Coal Company Limited, Post office Mohuda, District Dhanbad ? If so, to what relief are the workmen concerned entitled ?

S. No.	Name of the workmen	Designation	Date of stoppage of work
1.	Bhimraj[Mahato	C.C. Machine Driver	10.4.1970 and 11.4.1970
2.	Dhuma Mahato	do	11.4.1970
3.	Ch. Rezak Mia	do	do
4.	Topi Roy	C.C.M. Driver-cum-Helper	do
5.	Rasik Mahato	C.C.M. Driver	do
6.	Muslim Ansari	do	do
7.	Ramadhani[Turi	do	do
8.	Sitaram Bouri	do	do

2. On 20 December 1972 Shri S. V. Acharior, General Secretary, Hindusthan Khan Mazdoor Sangh on behalf of the workmen, Shri D. Narsingh, Advocate on behalf of the employers and Shri S. S. Mukherjee, Advocate on behalf

of the Bharat Coking Coal Ltd. have filed a compromise memo and verified the contents as correct. Having gone through the terms of compromise I find them beneficial to the workmen in general and the affected workmen in particular. The compromise memo is, therefore, accepted and the award is made in terms of the compromise and submitted under S. 15 of the Industrial Disputes Act, 1947. The compromise memo is annexed herewith and made part of the award.

N. VENKATA RAO, Presiding Officer.

BEFORE THE HON'BLE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. II) AT DHANBAD

In the matter of :—

Reference No. 5 of 1971

Parties :

Employers in relation to Murulidih 20/21 Pits Colliery

AND

Their Workmen.

MEMORANDUM OF SETTLEMENT

All the parties in the present proceedings have amicably settled the dispute involved in the present Reference on the terms hereinafter stated :—

(1) That since the dispute related to a very short period of stoppage of work (*i.e.* for one day only for 7 workmen (S. No. 2 to 8 of the Schedule to Order of Reference and for two days in respect of workman at Sr. No. 1 of the said Schedule) and the matter had been settled soon after the dispute and the concerned all eight workmen were carrying on their normal work, no dispute survives at present, and the concerned workmen do not claim any wages for the said period of stoppage of work.

(2) The General Secretary, Hindustan Khan Mazdoor Sangh will be paid a sum of Rs. 150/- (Rupees one hundred fifty only) as the cost of proceedings.

(3) The above terms finally resolve the dispute between the parties and, therefore, there is no subsisting dispute for adjudication in the present Reference.

It is, therefore, prayed that the Hon'ble Tribunal may be pleased to accept this Settlement and to give the Award in terms thereof.

FOR THE EMPLOYERS

Manager,
Murulidih 20/21 Pits
Colliery.

FOR THE WORKMEN

General Secretary,
Hindustan Khan Mazdoor Sangh.

For Bharat Coking Coal Ltd.
J. N. P. SAHI,
Labour & Law Adviser
Bharat Coking Coal Ltd.

Dated 20 December, 1972.

New Delhi, the 11th January, 1973

S.O. 177.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Pootkee Colliery of Messrs Oriental Coal Company Limited, Post Office Kusunda, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th January, 1973.

[No. 2/128/70-LRII]
KARNAIL SINGH, Under Secy.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Present :

Shri Nandagiri Venkata Rao, Presiding Officer.

Reference No. 21 of 1971

In the matter of an industrial dispute under S. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Parties :

Employers in relation to the management of Pootkee colliery of Messrs Oriental Coal Company Limited, Post Office Kusunda, District Dhanbad

AND

Their Workmen.

Appearances :

On behalf of the workmen : Shri S. Dasgupta, Advocate.

On behalf of the employers in relation to the Management of Pootkee Colliery, and Bharat Coking Coal Ltd. : Shri S. S. Mukherjee, Advocate.

State: Bihar. **Industry:** Coal.

Dhanbad, 1st January 1973

AWARD

The Central Government, being of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Pootkee colliery of Messrs Oriental Coal Company Limited, Post office Kusunda, District Dhanbad and their workmen, by its order No. 2/128/70-L.R.II dated 18th January, 1971 referred to this Tribunal under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication the dispute in respect of the matters specified in the schedule annexed thereto. The schedule is extracted below :

SCHEDULE

'Whether the action of the management of Pootkee Colliery of Messrs Oriental Coal Company Limited, Post office Kusunda, District Dhanbad, in not placing Shri Shanti Prakash, Latheman, in Category VI as recommended by the Coal Wage Board is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

2. On 23rd December, 1972 Shri S. Dasgupta, Advocate on behalf of the workmen and Shri S. S. Mukherjee, Advocate on behalf of the employers and Bharat Coking Coal Ltd. have filed a compromise memo and verified the contents as correct. Having gone through the terms of compromise I find them beneficial to the workmen in general and the affected workman in particular. The compromise memo is, therefore, accepted and the award is made in terms of the compromise and submitted under S. 15 of the Industrial Disputes Act, 1947. The compromise memo is annexed herewith and made part of the award.

N. VENKATA RAO, Presiding Officer.

BEFORE THE HON'BLE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (No. II) AT DHANBAD

In the matter of :—

Reference No. 21 of 1971

Parties :

Employers in relation to Pootkee Colliery,

AND

Their Workmen.

MEMORANDUM OF SETTLEMENT

All the parties in the present proceedings have amicably settled the dispute involved in the present Reference on the terms hereinafter stated :—

(1) That Sri Shanti Prakash (Latheman) the workman concerned in the present Reference shall be placed in Category-VI (Six) (under the Recommendations of the Central Wage Board (Coal Mining Industry) with effect from the 15th August, 1972 with starting basic wage rate of Rs. 11.30 P. (Rupees eleven and Paise thirty only) per day with effect from the said date (15/8/72). His next increment will be allowed from the 15th February, 1973.

(2) The Joint-General Secretary, Colliery Mazdoor Sangh, will be paid a sum of Rs. 200/- (Rupees two hundred only) as cost of the proceedings.

(3) The above terms finally resolve the dispute between the parties and, therefore, there is no subsisting dispute for adjudication in the present Reference.

It is, therefore, prayed that the Hon'ble Tribunal may be pleased to accept this Settlement and to give the Award in terms thereof.

FOR THE EMPLOYERS

Manager,
Pootkee Colliery.

FOR THE WORKMEN

S. DAS GUPTA,
Joint-General Secy.
Colliery Mazdoor Sangh.

For Bharat Coking Coal Ltd.
J. N. P. SAHI,
Labour & Law Adviser,
Bharat Coking Coal Ltd.

Dated, 23rd December, 1973.

New Delhi, the 11th January, 1973

S.O. 178.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby published the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 3, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of 1/12 & 2/12 Inclines of Kendwadih Colliery of Messrs G. S. Atwal & Company (Asansol), Raising & Selling Agents at Kendwadih Colliery of M/s. East Indian Coal Company Limited, Post Office Kusunda, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th January, 1973.

[No. 2/140/68-LRII.]
KARNAIL SINGH, Under Secy.

CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No. 55 of 1969

Present:

Shri B. S. Tripathi, Presiding Officer.

Parties:

Employers in relation to the management of 1/12 & 2/12 Inclines of Kendwadih Colliery represented by M/s. G. S. Atwal & Co. (Asansol), Raising & Selling Agents at Kendwadih Colliery of M/s. East Indian Coal Co. Ltd., P.O. Kusunda, Dist. Dhanbad.

AND

Their workmen.

Appearances:

For Employers—Shri Jagir Singh, Advocate representing M/s. G. S. Atwal & Co., Dhanbad,

Shri S. S. Mukherjee, Advocate representing Bharat Coking Coal Ltd.

For Workmen—Shri Lalit Burman, General Secretary, Bihar Koyla Mazdoor Sabha.

Industry: Coal. **State:** Bihar.

Dhanbad, the 30th December, 1972

AWARD

This is a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 made by the Central Government in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), as per their Order No. 2/140/68-LRII dated the 14th August, 1969, to this Tribunal for adjudication of an industrial dispute, mentioned in the schedule of reference existing between the parties named above. The schedule is extracted below:—

SCHEDULE

"Whether the action of the management of 1/12 & 2/12 inclines of Kendwadih Colliery, P.O. Kusunda, Dt. Dhanbad of M/s. G. S. Atwal & Co. (Asansol), Raising and Selling Agents at Kendwadih Colliery of M/s. East Indian Coal Co. Ltd., in dismissing from services the following workmen vide management's letter dated the 31st January, 1966 was justified? If not, to what relief are the workmen entitled?

Sl. No.	Name	Designation
1.	Sri Lallu Lodh	M.C.Loader
2.	Sri Kishun Passi	P. Minner
3.	Sri Hanuman Passi	Trammer
4.	Sri Prahalad Passi	Drillman
5.	Sri Parmeshwar Yadava	P. Miner
6.	Sri Seoprasad Lodh	M.C.Loader
7.	Sri Janeshar Mahato	Trammer
8.	Sri Maharanidin Lodh	R. Dresser."

2. The reference was received in this Tribunal on 28-8-1969 and was registered as reference No. 55 of 1969. The Industrial dispute in question was sponsored by Bihar Koyla Mazdoor Sabha, Dhanbad. This Union represented the workmen in the present proceeding as well. The Union filed written statement in the reference on 17-12-1969. On behalf of M/s. G. S. Atwal & Company written statement was filed on 6-4-1970. During the pendency of the present reference the management of the concerned colliery vested in the Central Government under the provisions of the Coking Coal Mines (Emergency Provision) Act, 1971 with effect from 17-10-1971 and thereafter the management of the concerned colliery was handed over to Bharat Coking Coal Limited, a Government Company, with effect from 18-1-1972. Thereafter notice was given to the Chairman of Bharat Coking Coal Limited to show cause as to why the said company shall not be impleaded as a party to the reference. On 23-3-1972 the B. C. C. Limited filed a petition stating that the campany had no objection to be added as a party to the reference. After hearing the parties and the Advocate of B. C. C. Limited the B. C. C. Limited was impleaded as a party to the present reference as per Order No. 22 dated the 23rd March, 1972. The B. C. C. Limited filed written statement on 29-4-1972 adopting the written statement filed by the outgoing employers namely M/s. G. S. Atwal & Company on merits. It is however stated in the written statement of the B. C. C. Limited that the B. C. C. Limited is in no way liable or responsible for any act of the past management prior to the date of taking over of the colliery by the Central Government under the Coking Coal Mines (Emergency Provision) Act, 1971.

3. The concerned workmen in the present reference, mentioned in the schedule of reference, are eight in number, working in different capacities in 1/12 & 2/12 Inclines of Kendwadih Colliery. They were dismissed from services by the management's letter dated the 31st January, 1966. The reference is for a decision as to the justification or otherwise of the action of the management in this regard and if not justified, what relief the concerned workmen are

entitled to. Ext. W-5 series are some of the letters of dismissal issued to the concerned workmen by the management, namely, M/s. G. S. Atwal & Co. (Asansol). The said dismissal letters purport to show that in a departmental enquiry held for the misconduct of the concerned workmen, for which chargesheet was issued to them, had been satisfactorily established and accordingly they were dismissed from service. Ext. W-1 series are the chargesheets issued to the concerned workmen. It appears that the charges levelled against all the eight workmen are the same. The charges are that the said workmen had assaulted the Asstt. Labour Officer of the Company on 3-9-1964 and that on account of this assault there was a criminal case in which the said workmen were convicted by a First Class Magistrate, Dhanbad for offences involving moral turpitude. All the workmen were thus charged with the aforesaid misconduct. Ext. W-2 series are the explanations submitted by the concerned workmen to the chargesheet issued to them. The explanation of all the eight workmen is the same. The concerned workmen denied to have assaulted the Asstt. Labour Officer and stated further that they were falsely implicated in the criminal case in question by the Asstt. Labour Officer and as against the judgment of conviction an appeal was pending before the Court of District & Sessions Judge, Dhanbad. Ext. W-3 series are the letters of the management dated the 24th December, 1965 to the concerned workmen intimating that a departmental enquiry would be held on the 29th December, 1965 at 10 A.M., at the Office of 1/12 Incline and the concerned workmen were asked to be present at the relevant time with their witnesses, if any. On receipt of the said letters, it appears, the concerned workmen wrote to the Manager of the Company that as the appeal was pending for hearing before the Court of the District & Sessions Judge, Dhanbad the management had no jurisdiction to hold the departmental enquiry into the matter. Ext. W-4 series dated 25-12-1965 are the letters in question. According to the case of the workmen the concerned workmen and others went to the colliery office to enquire about the position regarding the payment of quarterly bonus for the quarter ending the 30th June 1964, which was not paid to them within the stipulated period i.e. on or before 31-8-1964. The workmen state that instead of listening to them the management got them implicated in a false criminal case on the basis of a concorted report of the Asstt. Labour Officer. In that case the Trying Magistrate convicted the concerned workmen for offences under Section 147 & 448 of Indian Panel Code and sentenced each of them to undergo rigorous imprisonment for a period of two months under each of the sections as per Judgment and Order dated 15-12-1965. The workmen thereafter filed an appeal against the order of conviction and sentence awarded to them before the Learned District & Sessions Judge, Dhanbad who by his judgment dated the 31st July, 1967 set aside the order of the conviction of the workmen and acquitted them of the charges levelled against them. The workmen state that immediately after the order of conviction was passed by the Learned Magistrate, the management framed and issued chargesheet dated 17-12-1965, referred to above, without waiting for the result of the appeal preferred by the workmen before the District & Sessions Judge, inspite of the fact that the workmen in their show cause to the chargesheet brought the fact of filing of the appeal to the notice of the management, and the management proceeded with the departmental proceeding. The case of the workmen is that in fact no enquiry was held respect to the chargesheet issued to them, that the workmen did not assault the Asstt. Labour Officer, that the conviction of the workmen in the criminal case under Section 147 & 448 of I.P.C., does not amount to their conviction for offences involving moral turpitude, that the conviction of the workmen by the Trying Magistrate was not aside by the Appeallate Court which found the workmen not guilty of the charges levelled against them and that the workmen were not guilty of any misconduct under the provisions of the Standing Orders for Coal Mining Industry. It is, accordingly, alleged that the order of dismissal of the workmen by the management is not at all justified and it amounts to unfair labour practice. The prayers was accordingly is to reinstate the concerned workmen in their respective posts with continuity of service and full back wages and other benefits accruing to them.

4. The case of the management is that the concerned workmen were dismissed from service after holding proper departmental enquiry for assaulting the Asstt. Labour Officer and on account of the fact that they were convicted by the criminal court of offences of serious nature involving moral turpitude. It is submitted that the assault by the workmen and their conviction by the criminal court for offences involving moral turpitude amount to misconduct under the provisions of the Standing Orders of the Company and as the misconduct alleged against the workmen was satisfactorily established in the departmental enquiry they were rightly dismissed by the management from service.

5. I may mention at this place that neither the management nor the workmen have examined any witness in support of their respective allegations. The only document filed by the management is the Standing Orders for the Coal Mining Industry and it is marked as Ext. M-1 on admission by the workmen. Out of the documents filed on behalf of workmen I have already referred to the documents, Ext. W-1 series to W-5 series while stating the facts of the case of the workmen. Besides the above documents, the only other document filed by the workmen is the certified copy of the judgment of the Learned Sessions Judge, Dhanbad dated 31-7-1967 in criminal appeal No. 231 of 1965 (Ext. W-6). This appeal was filed by the concerned workmen and another against their conviction under Sections 147 & 448 of I.P.C., by J. P. Singh, Munsif Magistrate, First Class, Dhanbad by his order dated the 15th December, 1965. On perusal of the judgment of the Learned Sessions Judge it appears that according to the prosecution case the concerned workmen and some others went into the office room of the Asstt. Labour Officer of M/s. G. S. Atwal & Company, Shri Uma Shankar Singh, and asked as to why bonus had not been paid to some of the labourers, whereupon Sri Uma Shankar Singh replied that it was because they had taken part in the strike. Thereupon, it is stated, one Chhotu Lal Lodh, not a concerned workman, gave a push to the Asstt. Labour Officer and others dragged him out of the office room. Thus the concerned workmen were charged under Section 147 of I.P.C. for being members of an unlawful assembly, the common object of which was to assault the said Asstt. Labour Officer, and under Section 448 of I.P.C. for committing house trespass with intent to assault the said Asstt. Labour Officer. The Trial Court convicted the concerned workmen under both the aforesaid sections and sentenced each of them to undergo rigorous imprisonment for two months under each section, with a direction that the sentences awarded to them shall run concurrently. The Learned Appellate Court after scrutinizing the evidence adduced in the case came to the conclusion that the ingredients of the offences for which the concerned workmen were charged were not established at all and accordingly he set aside the order of conviction of the concerned workmen and acquitted them of the charges.

6. The management have not produced any document relating to the enquiry proceeding in the alleged domestic enquiry held in pursuance of the chargsheets issued to the concerned workmen. There is no evidence as to who had held the departmental enquiry or to show that fair opportunity was afforded to the concerned workment to defend themselves in the said proceeding. Even the enquiry report has not been filed by the management. According to the case of the management the concerned workmen were dismissed from service since the charges levelled against the workmen were found established in a domestic enquiry. In the absence of any evidence oral or documentary relating to the alleged departmental enquiry, the dismissal of the workmen by the management in consequence of the alleged enquiry cannot be allowed to stand.

7. Of course, in case of defective enquiry or no enquiry before the order of dismissal was passed, the management could have proved the charges levelled against the workmen before the Tribunal by adducing evidence independent of the domestic enquiry. As pointed out above, the management have not adduced any evidence whatsoever in proof of the alleged charges against the concerned workmen. Thus there is no evidence before the Tribunal to come to the conclusion that the concerned workmen had assaulted the Asstt. Labour Officer of M/s. G. S. Atwal & Co. Therefore, it must be held that the charge of alleged assault on the Asstt. Labour Officer by the concerned workmen has not been proved at all, either during the domestic enquiry or before the Tribunal after reference, independent of the domestic enquiry.

8. So far as the other charge is concerned, namely, the charge that the concerned workmen were convicted of offences under Sections 147 & 448 of I.P.C. there is admission of the workmen in their written statement that they were convicted of the said charges by a Criminal Court. It is not the conviction in any Court of Law by itself amounts to misconduct justifying punishment of fine or suspension or dismissal of concerned workman, but in order that the said conviction may amount to a misconduct it must be for any criminal offence involving moral turpitude. In this connection reference may be made to Clause 27(15) of the Standing Orders Ext. W-6. It is true that at the time when the chargesheet was issued to the concerned workmen and they were dismissed from service there was the order of conviction of the said workmen by a criminal court for offences under Sections 147 & 448 of I.P.C. On behalf of the workmen it is submitted that the said conviction does not amount to conviction for offences involving moral turpitude. I fully agree with the above submission. The management has not produced the certified copy of the judgment of conviction of the concerned workmen by the Trying Magistrate, but with reference to the judgment of the Appellate Court I have already stated above what the case of the prosecution was and how the concerned workmen was charged for offences under Sections 147 & 448 of I.P.C. In consideration of the same, it becomes abundantly clear that the offences alleged to have been committed by the workmen do not involve any moral turpitude so as to attract the provisions of Clause 27(15) of the Standing Orders. There is another aspect which requires consideration. At the time the chargesheet was issued an appeal had been preferred before the Learned Sessions Judge of Dhanbad against their conviction by the Trying Magistrate and the appeal was pending. The concerned workmen moved the management not to proceed with the departmental enquiry till the result of the appeal. The management did not listen to it and proceeded with the domestic enquiry. However, subsequently the conviction of the concerned workmen was set aside as per judgment dated 31-7-1967 in which the said workmen were found not guilty of the charges. Thus, the order of conviction does not stand against the workmen. In other words, it must be held that there was no conviction of the concerned workmen. It comes to this therefore that the other charge, namely, the charge that the concerned workmen were convicted of criminal offences involving moral turpitude must fail.

9. In view of what I have held above the order of dismissal of the concerned workmen as per management's letter dated the 31st January, 1966 must be set aside as being unjustified and I order accordingly. I find that the action of the management of 1/12 & 2/12 Inclines of Kendwadih Colliery, P.O. Kusunda, Dist. Dhanbad of M/s. G. S. Atwal & Co. (Asansol), Raising & Selling Agents at Kendwadih Colliery of M/s. East Indian Coal Co. Limited in dismissing from service the workmen mentioned in the schedule of the reference was unjustified. The question that now arises for consideration is what relief the concerned workmen are entitled to. It appears from Ext. W-1 series, which contain the chargesheets issued to the workmen, that the concerned workmen were placed under suspension simultaneously with the issue of chargesheets. The chargesheets appear to have been received by four of the workmen, namely, Sarvashree Lallu Lodh, Hanuman Passi, Prahalad Passi and Seoprasad Lodh, on 21-12-1965 and the remaining four workmen received the chargesheets on 20-12-1965 and all the concerned workmen were placed under suspension from the dates of receipt of the chargesheet. Subsequently they were dismissed from service as per letter of the management dated 31-1-1966. In view of the findings already given above, the order of suspension of the workmen must be set aside. The concerned workmen will, therefore, be deemed to be in service from the dates of their suspension without the stigma of suspension and they are entitled to be reinstated to their respective posts with effect from 31-1-1966 when the order for dismissal was passed by the management. All the concerned workmen will have continuity of their service during all this period and will get full back wages with benefits that might have accrued to them during all this time.

10. I have already said above that by virtue of the provisions of the Coking Coal Mines (Emergency Provisions) Act, 1971 (Central Act No. 64 of 1971) the management of the colliery in question vested in the Central Government with effect from 17-10-1971 and the management of the same was then handed over to B.C.C. Limited, a Government Company. Subsequently the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972 (Act No. 36 of 1972) was passed by the Parliament and it received the assent of the President on 17-8-1972. According to the provisions of this Act the right, title and interest of the owners in the colliery stood transferred to, and vested absolutely in, the Central Government, free from all incumbrances with effect from the appointed day i.e. from 1-5-1972. Thereafter by virtue of the order of the Central Government as per the provisions of Section 7 of the Act, the right, title and interest in the colliery vested in B.C.C. Limited, the Government Company. On behalf of B.C.C. Limited the submission is that B.C.C. Limited are not liable for the acts and omission of the outgoing employers, namely, M/s. G. S. Atwal & Company the Raising & Selling Agents of the colliery in question, in view of the provisions of Section 9 of the Nationalisation Act (Act 36 of 1972) and an order may be passed accordingly. Section 9(1) of the said Act provides—

> "Every liability of the owner, agent, manager, or managing contractor of a coking coal mine or coke oven plant, in relation to any period prior to the appointed day, shall be the liability of such owner, agent, manager or managing contractor, as the case may be, and shall be enforceable against him and not against the Central Government or the Government Company".

It is clear from this that it is the liability of M/s. G. S. Atwal & Company for the period to 1-5-1972 so far as the dues of the concerned workmen of the present proceeding is concerned. In this connection reference may be made to the provisions of Section 17(1) of the said Act which runs as follows:—

> "Every person who is a workman within the meaning of the Industrial Disputes Act, 1947, and has been, immediately before the appointed day, in the employment of a coking coal mine or coke oven plant, shall become on and from the appointed day, an employee of the Central Government, or, as the case may be, of the Government company in which the right, title and interest of such mine or plant have vested under this Act, and shall hold office or service in the coking coal mine or coke oven plant, as the case may be, on the same terms and conditions and with the same rights to pension, gratuity and other matters as would have been admissible to him if the rights in relation to such coking coal mine or coke oven plant had not been transferred to, and vested in, the Central Government or Government company, as the case may be, and continue to do so unless and until his employment in such coking coal mine or coke oven plant is duly terminated or until his remuneration, terms and conditions of employment are duly altered, by the Central Government or the Government company".

In view of the finding recorded above and in view of the said provisions in law, the concerned workmen will be deemed to be in service of the colliery in question from the date were dismissed from service and they will be deemed still to continue in service of B.C.C. Limited from 1-5-1972 on the same terms and conditions and with the same rights to pension etc. as would have *been transferred to, and vested* in, the Central Government or Government Company as the case may be. Thus it is the liability of the B.C.C. Limited to pay the wages *and other emoluments* to the concerned workmen *with effect from* 1-5-1972 *and* it is their liability to reinstate them in the service of the colliery, for which the concerned workmen shall apply to the B.C.C. Limited within 30 days from the date when the award becomes enforceable. If the concerned workmen do not apply for reinstatement within the period allowed, the liability of B.C.C. Limited to reinstate them will cease and the concerned workmen will not be entitled to wages etc. from B.C.C. Limited since after the expiry of the said period. The outgoing employer, namely, M/s G. S. Atwal & Company, however, will be liable to pay wages etc. for the period prior to 1-5-1972.

11. This is my award. Let the award be submitted to the Central Government under Section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

B. S. TRIPATHI, Presiding Officer.
Central Govt. Industrial Tribunal *cum* Labour Court (No. 3) Dhanbad.

New Delhi, the 11th January, 1973

S.O. 179.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bhuggatdih Rise Area Colliery of Messrs Bengal Nagpur Coal Company Limited, Post Office Dhansar, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th January, 1973.

[No. L-2012/21/71-LRII.]
KARNAIL SINGH, Under Secy.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD.

Present :

Shri Nandagiri Venkata Rao, Presiding Officer.

Reference No. 48 of 1971

In the matter of an industrial dispute under S. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Parties :

Employers in relation to the Bhuggutdih Rise Area Colliery of Messrs Bengal Nagpur Coal Company Limited, Post office Dhansar, District Dhanbad.

AND

Their workman

Appearances :

On behalf of the workman—Shri S. Dasgupta, Advocate.

On behalf of the employers—Shri S. S. Mukherjee, Advocate in relation to the Bhuggutdih Rise Area Colliery

and

Bharat Coking Coal Ltd.

State : Bihar. **Industry :** Coal.

Dhanbad, 1st January, 1973.

Saka-11 Pausa, 1894.

AWARD

The Central Government, being of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Bhuggutdih Rise Area Colliery of Messrs Bengal Nagpur Coal Company Limited, Post office Dhansar, District Dhanbad and their workmen, by its order No. L-2012/21/71-LR. II dated 21-4-1971 referred to this Tribunal under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication the dispute in respect of the matters specified in the Schedule annexed thereto. The schedule is extracted below:—

SCHEDULE

"Whether the claim of Shri S. C. Das, Assistant Electrician of Bhuggutdih Rise Area Colliery of Messrs Bengal Nagpur Coal Company Limited, Post office Dhansar, District Dhanbad, for being placed as Electrician in Category IV as per Coal Wage Board Recommendations with effect from the 15th August, 1967, is justified? If not, to what relief is the workman entitled and from what date?"

"Whether the action of the management of Bhuggutdih Rise Area Colliery of Messrs Bengal Nagpur Coal Company Limited, Post office Dhansar, District Dhanbad in appointing Sarvashri B. B. Bhattacharjee, L. N. Das and M. K. Bhattacharjee Badli Mining Sirdar-*cum*-Shot-firers, on consolidated pay of Rs. 151/- per month with effect from the 8th July, 1968, the 8th July, 1968 and the 12th September, 1968 respectively is justified? If not, to what relief are the workman entitled?"

2. On, 23-12-1972 Shri S. Dasgupta, Advocate on behalf of the workmen and Shri S. S. Mukherjee, Advocate on behalf of the employers and Bharat Coking Coal Ltd. have filed a compromise memo and verified the contents as correct. Having gone through the terms of compromise I find them beneficial to the workmen in general and the affected workmen in particular. The compromise memo is, therefore, accepted and the award is made in terms of the compromise and submitted under S. 15 of the Industrial Disputes Act, 1947. The compromise memo is annexed herewith and made part of the award.

N. VENKATA RAO, Presiding Officer.

BEFORE THE HON'BLE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. II) AT DHANBAD

In the matter of:—

Reference No. 48 of 1971

Parties :

Employers in relation to Bhuggutdih Rise Area Colliery,

AND

Their workmen.

MEMORANDUM OF SETTLEMENT

All the parties in the present proceedings have amicably settled the dispute involved in the present Reference on the terms hereinafter stated in respect of the concerned workmen:—

(1) That Shri S. C. Das (Asst. Electrician) will be designated as Electrician and placed in Category-V (Five) (under the Recommendations of the Central Wage Board Coal Mining Industry) with effect from the 15th August, 72 with starting basic wage rate of Rs. 8.23 P. (Rupees eight and Paise twenty-three only) per day with effect from the said date (15/8/1972). His next increment will be allowed from 15/2/1973. He will be also paid a lump sum of Rs. 1000/- (Rupees One thousand only) as an Ex-gratia amount.

(2) That S/Shri B. B. Bhattacharjee and L. N. Das (who were no longer in employment of the said Colliery) will be paid lump sum of Rs. 450/- (Rupees Four hundred fifty only) each as Ex-gratia amounts.

(3) Shri M. K. Bhattacharjee (who had been placed in proper grade in September, 1969) will be paid a lump sum of Rs. 100/- (Rupees One hundred only) as an Ex-gratia amount.

(4) That a sum of Rs. 200/- (Rupees Two hundred only) will be paid to the Joint-General Secretary, Colliery Mazdoor Sangh, as cost of the proceedings.

(5) The aforesaid payments will be made latest by the 31st January, 1973.

(6) The above terms finally resolve the dispute between the parties and, therefore, there is no subsisting dispute for adjudication in the present Reference.

It is, therefore, prayed that the Hon'ble Tribunal may be pleased to accept this Settlement and to give its Award in terms thereof.

For Employers:—
Manager,
Bhuggutdih Rise Area
Colliery.

For the Workmen:—
S. DAS GUPTA, Joint-General Secy.,
Colliery Mazdoor Sangh.

For Bharat Coking Coal Ltd.:—
J. N. P. SAHI, Labour & Law Adviser,
Bharat Coking Coal Ltd.

Dated 23rd December, 1972.

New Delhi, the 11th January, 1973

S.O. 180.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Balihari Colliery of Messrs Balihari Colliery Company (Private) Limited, Post Office Kusunda, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 2nd January, 1973.

[No. L-2012/57/71-LR II.]
KARNAIL SINGH, Under Secy.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 1), DHANBAD.

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 27 of 1971

Parties :

Employers in relation to the management of Balihari Colliery of Messrs Balihari Colliery Company (Private) Limited, Post Office Kusunda, Dist. Dhanbad.

AND

Their Workmen

Present :

Shri D. D. Seth, Presiding Officer.

Appearance :

For the old management:

Shri B. Joshi, Advocate with Shri I. P. Mishra, Manager.

For the Bharat Coking Coal Limited:

Shri S. S. Mukherjee, Advocate with Shri J. N. P. Sahi, Labour and Law Adviser.

For the Workmen:

Shri J. Bhattacharjee, Asstt., Secretary, Hindustan Khan Mazdoor Sangh.

State : Bihar. **Industry :** Coal.

Dhanbad, dated the 28th February, 1972.

AWARD

The present reference arises out of Order No. L/2012/57/71-LR II, dated New Delhi, the 21st July, 1971 passed by the Central Government in respect of an industrial dispute between the parties mentioned above. The subject matter of the dispute has been specified in the schedule to the said order and the said schedule runs as follows:—

"Whether the action of the management of Balihari Colliery of Messrs Balihari Colliery Company (Private) Limited, Post Office Kusunda, District Dhanbad, in dismissing Shri Ramsaran Mali, Guard/Wagon Shunter with effect from the 29th July, 1967 was justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The dispute has been settled out of Court. A joint petition of compromise dated 1-12-1972 has been filed in the office of the Tribunal. The petition has been signed by Shri I. P. Mishra, Manager on behalf of the old management, Shri J. N. P. Sahi, Labour and Law Adviser on behalf of the Bharat Coking Coal Ltd., and by Shri J. Bhattacharjee, Asstt. Secretary, Hindustan Khan Mazdoor Sangh on behalf of the workmen. I have gone through the terms of settlement contained in the said petition. They are fair and reasonable and, therefore, I make an award on the basis of the terms of settlement. The joint petition of compromise shall form part of the award.

3. Let a copy of this award be forwarded to the Central Government under section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

D. D. SETH, Presiding Officer.

BEFORE THE HON'BLE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 1) AT DHANBAD.

In the matter of:—

Reference No. 27 of 1971

Parties :

Employers in relation to Balihari Colliery
And
Their Workmen

MEMORANDUM OF SETTLEMENT

All the parties in the present proceedings have amicably settled the dispute involved in the present Reference on the terms hereinafter stated:—

(1) That Shri Ramsaran Mali (Guard) the workman concerned in the present Reference shall be reinstated as a Watchman and posted at Kendwadih Colliery with effect from the 11th December, 1972 without any back wages. He will be placed in Grade-II (under Recommendations of the Central Wage Board (Coal Mining Industry) with starting basic salary of Rs. 46/- (Rupees One hundred forty-six only) per month with effect from the said dated (11/12/72).

(2) That the period intervening from the date of dismissal (which gave rise to the present Reference) till the date of resumption of duty shall, for the purposes of continuity of services, be treated as leave without pay, but the workman concerned will be eligible to proportionate leave or quarterly bonus provided he puts in proportionate qualifying attendance during the remaining period of current year or current quarter, as the case may be.

(3) In the event of the failure of the concerned workman to report for work within a fortnight from 11-12-72 the workman concerned shall have no right for re-employment etc. under this agreement.

(4) The above terms finally resolve the dispute between the parties and, therefore, there is no subsisting dispute for adjudication in the present Reference.

(5) The parties shall bear their own cost of proceedings.

It is, therefore, prayed that the Hon'ble Tribunal may be pleased to accept this Settlement and to give the Award in terms thereof.

For the employers:—
I. P. MISHRA
Manager,
Balihari Colliery.

For the workmen:—
J. BHATTACHARJEE,
Asstt. Secretary,
Hindustan Kham Mazdoor Sangh.

For Bharat Coking Coal Ltd.:—
J. N. P. SAHI, Labour and Law Adviser.

Dated 1st December, 1972.

New Delhi, the 11th January, 1973

S.O. 181.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Balihari Colliery of Messrs Balihari Colliery Company (Private) Limited, Post Office Kusunda, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th January, 1973.

[No. L-2012/60/71-LRII.]
KARNAIL SINGH, Under Secy.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD.

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 64 of 1971

Parties:

Employers in relation to the management of Balihari Colliery of Messrs Balihari Colliery Company (Private) Limited, P.O. Kusunda, (Dhanbad).

AND

Their Workmen

Present:

Shri D. D. Seth—Presiding Officer.

Appearances:

For the old employers: Shri B. Joshi, Advocate.

For the Bharat Coking Coal Ltd.: Shri J. N. P. Sahi, Labour and Law Adviser.

For the Workmen: Shri J. Bhattacharjee, Asstt., Secretary, Hindustan Khan Mazdoor Sangh.

State: Bihar. **Industry:** Coal.

Dhanbad, dated the 27th December, 1972.

AWARD

The present reference arises out of Order No. L/201z/60/71-LRII, dated New Delhi, the 5th October, 1971 passed by the Central Government in respect of an industrial dispute between the parties mentioned above. The subject matter of the dispute has been specified in the schedule to the said order and the said schedule runs as follows:

"Whether the action of the management of Balihari Colliery of Messrs. Balihari Company (Private) Limited, Post Office Kusunda, District Dhanbad, in dismissing Shri Jagu Hazam, General Mazdoor/Night Guard with effect from the 29th July, 1967, is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The dispute has been settled out of Court. A joint petition of compromise dated 6-12-1972 has been filed in the office of the Tribunal. The petition has been signed by Shri I. P. Mishra, Manager on behalf of the old management, Shri J. N. P. Sahi, Labour and Law Adviser on behalf of the Bharat Coking Coal Limited and by Shri J. Bhattacharjee, Asstt. Secretary, Hindustan Khan Mazdoor Sangh on behalf of the workmen. I have gone through the terms of settlement contained in the said petition. They are fair and reasonable and, therefore, I make an award on the basis of the terms of settlement. The joint petition of compromise shall form part of the award.

3. Let a copy of this award be forwarded to the Central Government under section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

D. D. SETH, Presiding Officer.

BEFORE THE HON'BLE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 1) AT DHANBAD.

In the matter of:—

Reference No. 64 of 1971

Parties:—

Employers in relation to Balihari Colliery

AND

Their Workmen

MEMORANDUM OF SETTLEMENT

All the parties in the present proceedings have amicably settled the dispute involved in the present Reference on the terms hereinafter stated:—

(1) That Shri Jagu Hazam (General Mazdoor/Night guard) the workman concerned in the present Reference shall be re-instated as a Watchman and posted at Bhagaband Colliery with effect from the 18th December, 1972 without any back wages. He will be placed in Grade-II (under Recommendations of the Central Wage Board Coal Mining Industry) with starting basic salary of Rs. 146/- (Rupees One hundred forty six only) per month with effect from the said date (18/12/72).

(2) That the period intervening from the date of dismissal (which gave rise to the present Reference) till the date of resumption of duty shall, for the purposes of continuity of service, be treated as leave without pay, but the workman concerned will be eligible to proportionate leave or quarterly bonus provided he puts in proportionate qualifying attendances during the remaining period of current year or current quarter, as the case may be.

(3) In the event of the failure of the concerned workman to report for work within a fortnight from 18/12/72 the workman concerned shall have no right for re-employment etc. under this agreement.

(4) The above terms finally resolve the dispute between the parties and, therefore, there is no subsisting dispute for adjudication in the present Reference.

(5) The parties shall bear their own cost of proceedings.

It is, therefore, prayed that the Hon'ble Tribunal may be pleased to accept this Settlement and to give the Award in terms thereof.

For the employers:—
I. P. MISHRA
Manager,
Balihari Colliery.

For the workmen:—
J. BHATTACHARJEE,
Asstt. Secretary,
Hindustan Kham Mazdoor Sangh.

For Bharat Coking Coal Ltd.:—
J. N. P. SAHI, Labour and Law Adviser,

Dated 6/12/72.

New Delhi, the 12th January, 1973

S.O. 182.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad, in a petition filed under Section 33A of the Act by Shri Matturi Mallaiah and 41 other Sanitary Mazdoors (Hospital) of Singareni Collieries Company Limited, Post Office, Belampalli (Andhra Pradesh) against the management of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem (Andhra Pradesh) which was received by the Central Government on the 3rd January, 1973.

[No. 7/21/67-LRII(i)]

KARNAIL SINGH, Under Secy.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

Present:

Sri P. S. Ananth, B.Sc., B.L., Presiding Officer, Industrial Tribunal, Hyderabad.

Miscellaneous Petition No. 295 of 1968

In

Industrial Dispute No. 30 of 1967

BETWEEN

Matturi Mallaiah and 41 other sanitary Mazdoors (Hospital) Singareni Collieries Company Limited, P.O. Bellampalli. Petitioners

AND

The Management, Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem. Respondent.

Appearances :

Sri M. Komariah, General Secretary, Singareni Collieries Workers Union, for Petitioners. Sri K. Srinivasa Murthy, Hony. Secretary, Federation of A. P. Chambers of Commerce and Industry and Sri V. Gopala Sastry, Assistant Personnel Officer, for Respondent.

AWARD

This is a petition filed under Section 33-A of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter referred to as the said Act) by the petitioners for directing the respondent to restore the normal wages quantum by restoration of work on such play days as has been usual all these years and for payment of wages for such play-days from 17-10-1968.

2. The petitioners are employed as Sanitary Mazdoor in the Medical and Health Department of the Hospital of the Singareni Collieries Company Limited, at Bellampalli filed the petition contending as follows : The petitioners are time rated (daily rated) workmen and the wage period of petitioners is a calendar month. The petitioners work on all days of a Wage period and though they work for 2/3 of their shift period on weekly play days, they are paid full wages of a day for that day. The respondent denied employment to the petitioners on such weekly play days from 17-10-1968. During the past wage period namely in October, 1968 the respondent denied employment to the petitioners on such play days. As a consequence to such a denial of employment to the petitioners, they had lost 3 days wages from their total normal emoluments for the said wage period which they would have otherwise received on the pay day i.e. on 6-11-1968. The petitioners were informed by the respondent that they would not be employed to work on such weekly play days in future too. The petitioners will therefore get lesser amount as their total emoluments for the future wage periods too. As the loss in their total emoluments will be equal to the number of such weekly play days during a wage period multiplied by their wage rate. This alteration in the number of working days in a wage period has altered the service conditions in respect of wages quantum in a wage period of the petitioners. I.D. No. 30 of 1967 is pending. The petitioners are also covered by the said reference. The action of the respondent in denial of work on play days to the petitioners has altered matters connected with the dispute in I.D. No. 30 of 1967. So the petitioners had to file the present petition for the reliefs asked for.

3. The respondent is the Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli and it filed a counter contending as follows :—The petitioners numbering 42 are employed as Sweeping Mazdoors in the Health Department of the Colliery Hospital at Bellampalli and their correct names are shown in the counter. The petitioners are daily rated workmen and the wage period is now refixed by an agreement and they are paid at the end of the month with effect from February, 1968. The petitioners used to be booked for work on a weekly play day for five hours. As this is against the universal practice of observing weekly day of rest and as all other employees including sweepers recruited recently at Bellampalli, Mandamari and Ramagundam avail weekly day of rest in accordance with any other labour legislation the management felt it desirable to apply the weekly day of rest for the said workers also. The workmen were paid wages for work done including weekly day of rest but no extra payment was made. A notice under Section 9A of the said Act was given with effect from 11-10-1968 in the interest of workmen and management. The petition is misconceived as the matter is not connected with the dispute referred for adjudication in I. D. No. 30 of 1967. A change in regard to the matter not connected with the dispute is in accordance with the labour legislation and the Standing Orders which lay down a weekly day of rest. The compensatory day of rest is imperative and it is not left to the employer or employee otherwise as is laid down. So the averments made that the petitioners are denied employment on weekly play days is illegal and unjustified. The claim for wages for all the days in a calendar month is speculative and can not be deemed to be a right or privilage or condition of service. The allegation that there is a change in the conditions of service due to less number of working days and claiming that the rest day should be a compulsory working day is erroneous. The reference in I.D. No. 30 of 1967 is in respect of modifications and changes in categorisation and wage structure that is applicable to the workmen. As per the Wage Board Recommendations and as laid own in Chapter VII of Wage Board Recommendations the rates for daily rated workers have been arrived at taking into consideration the weekly day of rest. So there is no violation of Section 33 of the said Act and the petition is not maintainable.

4. This is a petition filed before the reference, which was taken on file as Industrial Disputes No. 2 of 1970, was received by this Tribunal contending that there had been violation of provisions of Section 33 of the said Act, in view of the pendency of I.D. No. 30 of 1967. This petition is filed on the ground that the respondent had affected alteration in the conditions of service since the respondent had introduced weekly day of rest though all along they had been working on all the 7 days of the week and getting wages for all the 7 days of work. The reference which is the subject matter of I.D. No. 2 of 1970 is whether the action of the Management in introducing the weekly day of rest without wages was justified. Since the subject matter of this petition is in a way connected with I.D. No. 2 of 1970, both parties agreed that this petition would abide by the result of the Award passed in I.D. No. 2 of 1970 and so this petition was being called along with I.D. No. 2 of 1970 and no separate evidence had been let in so far as this petition is concerned.

5. So far as I.D. No. 2 of 1970 is concerned award had been passed on 2-12-1972 holding that the action of the management in introducing the weekly day of rest without wages was justified. In as much as the parties had agreed that this petition would abide by the award passed in I.D. No. 2 of 1970 and in as much as award had been passed in I.D. No. 2 of 1970 holding that the action of the management was justified in introducing weekly holiday without wages this petition is dismissed.

Award is passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 2nd day of December, 1972.

P. S. ANANTH, Presiding Officer.

APPENDIX OF EVIDENCE

NIL.

INDUSTRIAL TRIBUNAL.

New Delhi, the 12th January, 1973

S.O. 183.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad, in a petition filed under Section 33A by Shri Matangi Rangiah and 279 workmen of Medical and Sanitary Department of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem (Andhra Pradesh) against the management of Singareni Collieries Company Limited, Kothgudem (Andhra Pradesh) which was received by the Central Government on the 3rd January, 1973.

[No. 7/21/67-LRII(ii)]

KARNAIL SINGH, Under Secy.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

Present :

Sri P. S. Ananth, B.Sc., B.L., Presiding Officer, Industrial Tribunal (Central), Hyderabad.

Miscellaneous Petition No. 280 of 1968

IN

Industrial Dispute No. 30 of 1967

BETWEEN

Matangi Rangiah and 279 workmen of Medical and Sanitary Department, Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem. **Petitioners.**

AND

Management of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem. **Respondent.**

Appearances :

Sri M. Komariah, General Secretary, Singareni Collieries Workers Union, for Petitioners. Sri K. Srinivasamurthy, Hony. Secretary, Federation of A. P. Chambers of Commerce and Industry and Sri V. Gopal Sastry, Assistant Personnel Officer, for Respondent.

AWARD

This is a petition filed under Section 33A of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter referred to as the said Act) by the workmen of the Medical and Sanitary Department, Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem for directing the management not to effect alteration in the service conditions contrary to the provisions of Section 33 of the said Act.

2. In the petition it is contended as follows : The workmen employed in the Medical and Sanitary Department of Singareni Collieries Company Limited at its collieries at Kothagudem, Bellampalli, Yellandu numbering approximately 400 have been since long period working 7 days in a week and were paid wages for all the 7 days. This system of work had been necessitated due to the very nature of work and civic amenities. These workmen were paid wages for 7 days a week unlike the other daily rated workers who are paid wages for 6 days a week. They were enjoying the benefits of full wages in the entire period of a week and month. These workmen whose services were considered of essential nature have been granted exemption from the provisions of the Mines Act and other Acts regarding holidays and rest days. Contrary to age long practice of the payment of the wages and emoluments granted to them, the Management with an intention to introduce and effect change in the service conditions of the workmen of the Medical and Sanitary Department, issued notice that weekly holidays and rest would be given to these workmen also. This sinister move of the management was strongly opposed by the workmen and also their representative Union. The Central Industrial relations Machinery intervened. Discussions were held in the presence of the Assistant Labour Commissioner (C) Vijayawada on 6-10-1968 wherein failure report was submitted to the Government as the issue could not be settled by mutual discussions. Since all the petitioners efforts to settle the dispute amicably have failed and as the management had been insisting to enforce compulsory holiday in a week the workmen were forced to seek redress of their legitimate demand by filing the present application. Had the management introduced weekly holidays of rest, to these workmen they would actually suffer wage cut in their earnings earned by them. Not only that they will suffer cut in weekly wages but also in statutory bonus which is paid quarterly and the Annual Bonus. Leave with pay granted to them will be adversely effected. In short granting of weekly day of rest would reduce the earnings, the number of attendances and the emoluments in wages and Bonus and leave wages. The workmen would be prejudiced if the Management is allowed to introduce weekly day of rest. As the management has contravened the provisions during the pendency of I.D. No. 30 of 1967 the petitioner had to file the present petition under Section 33A for directing the management not to effect alterations in the service conditions.

3. The respondent which is the Management of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem filed a reply statement contending, as follows : The Management is not guilty of contravention of the provisions of Section 33 of the said Act. It is true that the daily rated Medical and Sanitary workers of Singareni Collieries except those in the new Divisions were working on all the days in a week and getting wages for 7 days. Since this is against the universal practice of observing weekly day of rest and as all the employees numbering about 35,000 working in the Collieries including Sanitary and Medical Department in new divisions, have been availing weekly day of rest, the management felt it desirable to introduce weekly day of rest for these Sanitary and Medical workers also and gave notice under Section 9A on 2-9-1968 proposing to introduce weekly day of rest from 30-9-1968 in the interests of workmen as well as industry. These workmen were paid the wages for the work done on weekly day of rest and no extra payment was ever made for the rest days. On receipt of the notice under Section 9A of the said Act, Singareni Collieries worker's Union representing the workmen in the present application and also Andhra Pradesh Singareni Collieries Mazdoor Sangh raised a dispute opposing the introduction of weekly day of rest and the matter was taken up in conciliation by the Assistant Labour Commissioner (C) Vijayawada on 5-10-1968. On the advice of the Assistant Labour Commissioner the proposed change was kept in abeyance pending conclusion of conciliation proceedings, concluded on 15-10-1968 the date on which the report of the Conciliation Officer was recieved by the Government of India and the management introduced the weekly day of rest from 27-10-1968. The Union has also issued a strike notice under Section 22 of the said Act which was received by the Conciliation Officer on 28-10-1968 and the Regional Labour Commissioner (Central) Hyderabad initiated formal conciliation proceedings as required under Section 20 of the said Act. Thus it would be seen that the dispute raised by the Union is pending with the Government and decision of the Government is awaited. The subject matter of the dispute referred to in I.D. No. 30 of 1967 is about further modifications if any required in the categorisation and wage structure to be made applicable. The Singareni Collieries and the introduction of weekly day of rest is in no way connected with that issue. If the workmen are aggrieved, the proper remedy is to raise a dispute and this they did and conciliation proceedings were also held under Section 12 of the said Act. Under Section 33A of the said Act an employer may alter, in regard to any matter not connected with the dispute, the condition of service applicable to that workmen immediately before the commencement of the proceedings. As the Conciliation proceedings were not pending at the time of introducing this weekly day of rest and as this is in no way connected with the proceedings in I.D. No. 30 of 1967 it does not attract the provisions of Section 33 of the said Act and so complaint is not maintainable under law.

4. This is a petition filed before the reference, which was taken on file as Industrial Dispute No. 2 of 1970, was received by this Tribunal contending that there had been violation of provisions of Section 33 of the said Act, in view of the pendency of I.D. No. 30 of 1967. This petition is filed on the ground that the respondent had effected the alteration in the conditions of service since the respondent had introduced weekly day of rest, though all along they had been working on all the 7 days of the week and getting wages for all the 7 days of work. The reference, which is the subject matter of the I.D. No. 2 of 1970, is whether the action of the Management in introducing the weekly day of rest without wages was justified. Since the subject matter of this petition is in a way connected with I.D. No. 2 of 1970, both parties agreed that this petition would abide by the result of the award passed in I.D. No. 2 of 1970 and so this petition was being called along with I.D. No. 2 of 1970 and no separate evidence had been let in so far as this petition is concerned.

5. So far as I.D. No. 2 of 1970 is concerned award had been passed on 2-12-1972 holding that the action of the management in introducing the weekly day of rest without wages was justified. In as much as the parties had agreed that this petition would abide by the award passed in I. D. No. 2 of 1970 and in as much as an award had been passed in I.D. No. 2 of 1970 holding that the action of the management was justified in introducing weekly holiday without wages this petition is dismissed.

Award is passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 2nd day of December, 1972.

P. S. ANAND, Presiding Officer.

APPENDIX OF EVIDENCE

N I L

INDUSTRIAL TRIBUNAL.

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1972

आदेश

का. आ. 184.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में, मैसर्स ईस्टर्न मैंगनीज, एण्ड मिनरल्स लि. की बन्दर चुहा अभ्रक खान, डाकघर डोमचांच, जिला हजारीबाग के प्रबन्ध क्षेत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है :

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (संख्या 1) धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या मैसर्स ईस्टर्न मैंगनीज एण्ड मिनरल्स लिमिटेड की बन्दर चुहा अभ्रक खान, डाकघर डोमचांच, जिला हजारीबाग के प्रबन्धतंत्र द्वारा इस खान में एक कुशल कर्मकार के रूप में नियोजित श्री महावीर कुम्हार को 6 फरवरी, 1972 से काम देने से इन्कार करना न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?"

[सं. एल/28012/4/72-एस. आर. 4]

New Delhi, the 29th December, 1972

OREDR

S.O. 184.—WHEREAS the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Banderchuha Mica Mine of Messrs Eastern Maganese and Minerals Limited, Post Office Domchanch, District Hazaribagh and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

AND WHEREAS the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal (No. 1), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the management of Banderchuha Mica Mine of Messrs Eastern Maganese and Minerals Limited, Post Office Domchanch, District Hazaribagh was justified in refusing work from 6th February, 1972 to Shri Mahavir Kumar employed as skilled worker at the mine? If not, to what relief is the workman entitled?

[No. L-28012/4/72-LR. IV]

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1972

आदेश

का. आ. 185.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स सतना सीमेन्ट वर्क्स की सग्मानिया लाईम स्टोन क्वारी, सतना के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स सतना सीमेन्ट वर्क्स की सग्मानिया लाईम स्टोन क्वारी मुकाम और डाकघर सतना, जिला सतना के प्रबन्धतंत्र की, श्री शंकरलाल पाण्डे, स्कूल अध्यापक, की 29 अप्रैल, 1971 से छंटनी करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[सं. एल/29011/42/72-एस. आर.-4]

New Delhi, the 30th December, 1972

ORDER

S.O. 185.—WHEREAS the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Sagmania Lime Stone Quarry of Messrs. Satna Cement Works, Satna, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

AND WHEREAS the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (4 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, Constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Sagmania Lime Stone Quarry of Messrs. Satna Cement Works at and Post Office Satna, District Satna, in retrenching Shri Shankerlal Pandey, School Master, with effect from the 29th April, 1971, is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?

[No. L-29011/42/72-LRIV.]

आदेश

का. आ. 186.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में श्री कन्हैया धाटीवाला, कृष्णा भवन, चौड़ा रास्ता, जयपुर तापुकरा और धनेश्वर रेत पत्थर खानों से सम्बद्ध नियोजकों और उन के कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री उपदेश नारायण माथुर होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या पत्थर खान मजदूर संघ, कोटा की, ऐसी दरों पर मजदूरी के भुगतान की मांग, जो राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या एफ-3(7)/लेब-63, तारीख 9 अक्तूबर, 1971 के अधीन श्री कन्हैयालाल धाटीवाला, जयपुर की तापुकरा और धनेश्वर रेत पत्थर खानों में नियोजित कर्मकारों को निर्धारित की गई मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम न हों, न्यायोचित है? यदि हां, तो मजदूरी की दरें क्या होनी चाहिएं और वे किस तारीख से देय होंगी?

[सं. एल.-29011/56/72-एल. आर.-4]

ORDER

S.O. 186.—WHEREAS the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Tapukra and Dhaneshwar Sand Stone Mines of Shri Kanhyalal Ghatiwala, Krishna Bhawan, Choura Rasta, Jaipur and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

AND WHEREAS the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri Updesh Narain Mathur, as Presiding Officer, with headquarters at Jaipur, and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

Whether the demand of the Pathar Khan Mazdoor Sangh, Kota for payment of wages at rates not less than minimum rates of wages fixed under the Notification No. F. 3(7)/LAB-63, dated the 9th October, 1971, issued by the Government of Rajasthan, to the workmen employed in the mines of Tapukra and Dhaneshwar Sand Stone Mines of Shri Kanhyalal Ghatiwala, Jaipur, is justified? If so, what should be the rates of wages and from what date would it be payable?

[No. L-29011/56/72-LRIV.]

आदेश

का. आ. 187.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में वेस्ट सूकेत लेबर कंट्रेक्टर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की कुकरा लाइम स्टोन क्वारी, डाकघर सूकेत, जिला कोटा के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री उपदेश नारायण माथुर होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स वेस्ट सूकेत लेबर, कंट्रेक्टर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, की कुकरा लाइम स्टोन क्वारी, डाकघर सूकेत, जिला कोटा में नियोजित कर्मकारों की लेखा वर्ष 1968-69, 1969-70 और 1970-71 के लिए उनके द्वारा उपार्जित मजदूरियों की 20 प्रतिशत की दर से बोनस की मांग न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार इनमें से प्रत्येक वर्ष के लिए बोनस की किस मात्रा के हकदार हैं?

[सं. एल/29011/60/72-एल.आर.-4]

S.O. 187.—WHEREAS the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Kukra Lime Stone Quarry of West Suket Labour Contractors Cooperative Society Limited, Post Office Suket, District Kota, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

AND WHEREAS the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri Updesh Narain Mathur, as Presiding Officer with headquarters at Jaipur, and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

Whether the demand of the workmen employed in Kukra Lime Stone Quarry of Messrs West Suket Labour Contractors Co-operative Society Limited, Post Office Suket, District Kota, for payment of bonus at the rate of 20 per cent the wages earned by them for the accounting years 1968-69, 1969-70 and 1970-71 is justified? If not, to what quantum of bonus are the workmen entitled for each of these years?

[No. L-29011/60/72-LR. IV]

आदेश

का. आ. 188.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स ईस्टर्न मैंगनीज एण्ड मिनरल्स लिमिटेड की बन्दर चूहा अभ्रक खान, डाकघर डोमचांच, जिला हजारीबाग के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (संख्या 1) धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या मैसर्स ईस्टर्न मैंगनीज एण्ड मिनरल्स लिमिटेड की बन्दर चूहा अभ्रक खान, डाकघर डोमचांच, जिला हजारीबाग के प्रबन्धतंत्र का श्री बन्धन हजाम को, जो खान में पम्प खलासी के रूप में नियोजित थे, 31 मार्च, 1972 से काम से मना करना न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?"

[संख्या एल-28012/3/72-एल. आर.-4]

ORDER

S.O. 188.—WHEREAS the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Banderchuha Mica Mine of Messrs Eastern Maganese and Minerals Limited, Post Office Domchanch, District Hazaribagh and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

AND WHEREAS the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Governmtnt hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal (No. 1), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the management of Banderchuha Mica Mine of Messrs Eastern Maganese & Minerals Limited, Post Office Domchanch, District Hazaribagh, was justified in refusing work from 31st March, 1972, to Shri Bandhan Hazam employed as Pump Khalasi at the mine? If not, to what relief is the workman entitled?

[No. L-28012/3/72-LR. IV]

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1973

का. आ. 189.—औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20) की धारा 2 के खण्ड (ग) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 662, तारीख 7 मार्च, 1963 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में मद (1) और उससे संबंधित स्तंभ 1 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :—

"सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) मुख्यालय, धनबाद ।"

[फा. सं. एस. 12025/12/72-एल. आर-1]

एस. एस. सहस्त्रनामन, अवर सचिव

New Delhi, the 6th January, 1973

S.O. 189.—In pursuance of clause (c) of section 2 of the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (20 of 1946), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment No. S.O. 662, dated the 7th March, 1963, namely—

In the Schedule annexed to the said notification, for item (1) and the entry in column I relating thereto, the following entry shall be substituted, namely:—

"(1) Assistant Labour Commissioner (Central), Headquarters, Dhanbad."

[File No. S.-12025/22/72-LR. I]

New Delhi, the 8th January, 1973

S.O. 190.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Chowgule and Company Private Limited, Mormugao Harbour, Goa and their workmen, which was received by the Central Government on the 1st January, 1973.

[No. L-29012/22/71-LR. IV]

S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

AWARD

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY.

Reference No. CGIT-2/1 of 1972

Employers in relation to the management of Messrs. Chowgule and Company Private Limited, Mormugao Harbour, Goa.

AND

Their Workman

Present :

Shri N. K. Vani, Presiding Officer.

Appearances :

For the Employers :—Shri A. S. Devasthali, Labour Adviser.

For the workman :—(i) Shri Anand S. Vernekar, Workman.

(ii) Shri George Vaz, General Secretary, Goa Mining Labour Welfare Union, Goa.

Industry : Iron Ore Mines. **State :** Goa, Daman and Diu.

Bombay, the 16th December, 1972.

AWARD

By Order No. L-29012/22/71-LRIV dated 13th January, 1972 Central Government in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute existing between the employers in relation to the management of Messrs Chowgule and Company Private

Limited, Mormugao-Harbour, Goa and their workman in respect of the matters specified in the schedule as mentioned below:—

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Messrs. Chowgule and Company Private Limited, Mormugao Harbour, in terminating the services of the workman Shri Anand S. Vernekar, trainee in Electrical department Palletisation Plant, Pale Mines in their letter No. STAFF/TL/53, dated the 27th June, 1969 and consequently not offering him the post of Charge-hand in the grade of Rs. 300—15—390—20—510 after the completion of the training period was justifiable? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The facts giving rise to this reference are as follows:—

The workman Shri Vernekar first raised an industrial dispute by his letter dated 28th September, 1970 with the Asstt. Labour Commissioner, Govt. of Goa, Daman and Diu, Panaji regarding his termination of services. On account of management's objection regarding the State Government's jurisdiction over the dispute, the Asstt. Labour Commissioner, Panaji advised the workman to approach the Assistant Labour Commissioner (C) Vasco-de-Gama because he was satisfied that the establishment in question fell in the Central Sphere and because the Central Government was the appropriate authority in this respect.

(ii) On account of this the workman Shri Vernekar raisd an industrial dispute before the Asstt. Labour Commissioner (C) Vasco-de-Gama. Asstt. Labour Commissioner (C) Vasco-de-Gama tried to bring about conciliation but in vain. He therefore made failure of conciliation report to the Government, who in its turn referred this reference to this Tribunal for adjudication.

3. Messrs. Chowgule and Company Private Limited, Goa (hereinafter referred to as 'the Company' have filed written statement at Ex. 2/E and rejoinder at Ex. 4/E.

4. According to the company,

(i) This reference is not maintainable as the cause of Shri Vernekar has not been espoused by any workmen employed by the company or by the union.

(ii) Section 2A under which this reference has been made is bad in law. Section 2A of the Act is void and illegal as it offends the provisions of Article 14 of the Constitution.

(iii) This Court has no jurisdiction to entertain this reference as it is not an industrial dispute and because Section 2A is void and bad in law.

(iv) The workman Shri Vernekar was holding a diploma in Electrical Engineer. He had no previous experience. He applied for the post of Electrical Engineer. He was informed that the management was willing to take him up as a trainee on the following, amongst other, conditions.

"(1) He will be on trial for a period of 6 months and would be paid a stipend of Rs. 150/- per month,

(2) On satisfactory completion of trial, he would be taken for training for a period of 2 years and his stipend would be increased from time to time upto Rs. 250/- per month,

(3) On completion of training, he might be absorbed as Charge-hand provided a vacancy arose then. If in principle, he agreed to join as trainee, he was required to inform the company within 7 days to enable the company to issue a letter of appointment in his favour."

(v) As Shri Vernekar accepted the conditions mentioned in its letter dated 21st October, 1966, a letter offering him an appointment in the company as a trainee was issued.

(vi) By its letter dated 29th May, 1967 it informed the workman concerned that it was pleased to take him up as a trainee and increase the stipend to Rs. 200/- per month.

(vii) Shri C.F. Jaffries was the Superintendent of the Plant where Shri Vernakar was undergoing training. He reported that Shri Vernekar had not come upto the required standard and was not proficient as he believed himself to be. He also recommended that Shri Vernekar's appointment be terminated. In pursuance of this report Shri Vernekar was informed by its letter dated 27th June, 1969, that his training would be discontinued with effect from 1-7-1969. His appointment was terminated strictly in accordance with the letter of appointment dated 1st November, 1966. His services were terminated bonafide.

5. The affected workman Shri Vernekar has filed written statement at Ex. 1/W and rejoinder at Ex. 3/W. He has examined himself as a witness at Ex. 17/W.

6. According to Shri Vernekar:—

(i) After completion of six months trial period he was taken up as a trinee for a period of two years on a stipend of Rs. 200/- per month. His stipend was increased to Rs. 250/- with effect from 1st July, 1968. He completed the period of training on 30th June, 1969. After the completion of this period he was not absorbed as Charge-hand. During the period of probation and training he was never informed at any time by the company that his work was unsatisfactory and not upto the mark. His stipendary training was discontinued with effect from 1st July, 1969 as he had completed training period as mentioned in Company's letter dated 27th June, 1969. Ex. 9/E.

(ii) Shri Raghuvir Joined the company as a probationer after him. His training period was over after completion of his training period. He was given the job of Charge-hand though he was junior to him.

(iii) As he was discontinued after the training period was completed and not prior to that, the company's action in not giving him the post of Charge-hand, though there was a vacancy, is illegal.

(iv) During the period of training the company found his work satisfactory. The company issued certificates to him from time to time, *vide* Ex. 10/W to 12/W and 14/W to 15/W. As his work was found satisfactory throughout there was no justification for the company to discontinue him without giving the post of Charge-hand.

(v) On these grounds he claims that he should be reinstated with continuity of service and back wages.

7. Shri Vernekar, the affected workman has produced documents as mentioned below:—

(i) Copy of letter dated 8th May, 1967 from the Superintendent to the Principal, Government Polytechnic, Belgaum—Ex. 10/W.

(ii) Copy of Certificate dated 28th October, 1967 issued by the Superintendent to Shri Vernekar—Ex. 11/W.

(iii) Copy of Certificate dated 20th September, 1968 issued by the Superintendent to Shri Vernekar—Ex. 12/W.

(iv) Copy of letter dated 27th June, 1969 from the Director to Shri Vernekar—Ex. 13/W.

(v) Copy of certificate dated 2nd July, 1969 from the Superintendent to Shri Vernekar—Ex. 14/W.

(vi) Copy of Certificate dated 2nd July, 1969 from the Superintendent to Shri Vernekar—Ex. 15/W.

(vii) Copy of Training Certificate dated 27th June, 1969 from the Director—Ex. 16/W.

(viii) Increment in stipend letter from the Company Ex. 18/W.

(ix) Copy of letter dated 14th August, 1969 from Shri A. S. Vernekar to Mr. V. D. Chogule—Ex. 19/W.

(x) Copy of letter dated nil from Shri Vernekar to Shri V. S. Chowgule Ex. 20/W.

(xi) Copy of letter dated nil from Shri Vernekar to the Director Ex. 21/W.

(xii) Copy of letter dated 2nd July, 1970 from Shri Vernekar to the Director—Ex. 22/W.

(xiii) Copy of letter dated 13th July, 1970 from Shri Vernekar to the Director—Ex. 23/W.

(xiv) Letter dated 13/15th June, 1970 from the Company addressed to Shri Vernekar—Ex. 24/W.

(xv) Copy of confidential report Ex. 28/W.

8. The company has examined two witnesses on its behalf. They are S/Shri B. P. Manoji and Yeshwant Govind Prabhu Ex. 25/E and 29/E respectively. The company has produced annexures with the written statement Ex. 2/E. They are as follows:—

(i) Copy of letter dated 21st October, 1966 addressed to Shri A. S. Vernekar—Ex. 5/E.

(ii) Copy of letter dated 1st November, 1966 addressed to Shri A. S. Vernekar Ex. 6/E.

(iii) Copy of letter dated 9th November, 1966 from Shri A. S. Vernekar to the Director of the company—Ex. 7/E.

(iv) Copy of letter dated 29th May, 1967 addressed to Shri A. S. Vernekar—Ex. 8/E.

(v) Copy of letter dated 27th June, 1969 addressed to Shri A. S. Vernekar—Ex. 9/E.

The company has also produced some documents as mentioned below:—

(i) Original confidential report at x. 26/E.

(ii) Letter dated 26th June, 1969 from Shri C. F. Saffries at Ex. 27/E.

(iii) Extract of report on Shri A. S. Vernekar by Shri C. F. Jeffries, at Ex. 30/E.

(iv) Form of Service agreement Ex. 31/E.

(v) Copy of certified Standing orders at Ex. 32/E.

9. From the pleadings and documents on record the following points arise for decision.

(i) Whether dispute between the company and the employee Shri A. S. Vernekar is an industrial dispute within the meaning of Section 2(k) read with Section 2A of the Industrial Disputes Act, 1947?

(ii) Whether this Tribunal has jurisdiction to entertain the reference?

(iii) Whether the action of the management of Messrs Chowgule and company Private Limited, Mormugao-Harbour, in terminating the services of the workman Shri Anand S. Vernekar, trainee in Electrical department Palletisation Plant, Pale Mines in their letter No. STAFF/TI/63 dated the 27th June, 1969 and consequently not offering him the post of charge hand in the grade of Rs. 300—15—390—20—510 after the completion of the training period was justifiable?

(iv) If not, to what relief is the workman entitled?

(v) What order?

10. My findings are as follows:—

(i) Yes.

(ii) Yes.

(iii) Yes.

(iv) Not entitled to any relief.

(v) As per order.

33 G of I—15.

REASONS

Point No. i and ii.

11. Shri Devasthali, Labour Adviser of the company contends that the dispute between the company and Shri Vernekar is not an industrial dispute because this is a dispute between the employer and a single individual and because the same is not raised by a body of employees or by the union.

In support of this contention he relies on Section 2(k) of the I. D. Act, 1947.

12. Section 2(k) of the I. D. Act, 1947 is as follows.—

"(k) 'industrial dispute' means any dispute or difference between employers and employers or between employers and workmen or between workmen and workmen, which is connected with the employment or non-employment or the terms of employment or with the condition of labour, of any person"

13. A perusal of the above Section shows that *prima facie* the present dispute between the company and Shri Vernekar is not an industrial dispute within the meanings of Section 2(k) of the I.D. Act 1947 because it is not a dispute between the employer and a body of workmen and because it is a dispute between the employer and a single workman.

14. Section 2A of the I. D. Act, 1947 has been inserted by Act 35 of 1965. This Section 2A is as follows:—

"2. A DISMISSAL ETC. OF AN INDIVIDUAL WORKMAN TO BE DEEMED TO BE AN INDUSTRIAL DISPUTE—Where any employer discharges, dismisses, retrenches or otherwise terminates the services of an individual workman, any dispute or difference between that workman and his employer connected with, or arising out of, such discharge, dismissal, retrenchment or termination shall be deemed to be an industrial dispute notwithstanding that no other workman nor any union of workmen is a party to the dispute."

15. In view of the introduction of Section 2. A referred to above there cannot be any doubt that the dispute between an employer and a single workman becomes an industrial dispute though no other workman or any union or workmen is a party to the dispute.

16. Shri Devasthali, Labour Adviser for the company contends that though the present dispute is an industrial dispute within the meaning of Section 2-A of the I.D. Act, 1947, yet the reference made to this Tribunal is bad in law because Section 2A is void and illegal, as it offends the provisions of Article 14 of the Constitution. In support of this, he relies on the ruling of the Calcutta High Court in the case between Jute and Jute Goods Buffer Stock Association *Vs.* The Second Industrial Tribunal of West Bengal and others, reported in 1972 Lab. I. C. 503. This ruling is as follows:—

"Section 2-A is void since the power of Government under Section 10 is un-principled as applied to cases of individual disputes deemed to be industrial disputes under Section 2-A. AIR 1957 SC 329 and AIR 1957 SC 532 Rel. on AIR 1970 Mys. 171 and AIR 1970 Delhi 60 and AIR 1970 Mad 82 Distinguished. AIR 1971 Punj and Har 60 Doubted. (Para. 30).

The Supreme Court laid down criteria for the exercise of discretion under Section 10 for collective disputes do not apply to Section 10 references of individual disputes under Section 2-A because there can be no threat of interruption of production or of industrial strikes or breach of industrial peace in cases of individual disputes.

Section 10 discretion of the Government is rendered unguided on account of its being free to make a reference in the case of one workman and refuse a reference in the case of another although both of them may be situated in exactly similar circumstances. (Para. 16)

The Act was enacted for settlement of collective disputes between employers and workmen. The enactment of Section 2-A destroys the concept of an industrial dispute as a collective dispute. The provisions of Section 2-A do not fit into the general texture of the Act. (Para. 18).

A right to form Trade Union Association even by employers is guaranteed by Article 19(1) (c) of the Constitution. Any law which is inconsistent (as Section 2-A is) with that fundamental right is to that extent rendered void by Article 13. Thus so far as collective disputes are concerned the power under Section 10 are valid: but those powers are invalid in relation to an industrial dispute deemed to be an industrial dispute within Section 2-A. Consequently Section 2-A which is severable from Section 10 is void and as such inoperative in law, in spite of Section 10 being valid for collective disputes being refered to adjudication under Section 10. (Para. 18)."

17. The above mentioned ruling supports the contention of Shri Devasthali that Section 2A of the I.D. Act, 1947 is void and bad in law as it offends the provisions of Article 14 of the Constitution. There is however, ruling of High Court of Mysore in the case between P. Janardhana Shetty and Union of India and others, reported in 1970, II, LLJ, page 738, which has taken a contrary view. This ruling is as follows:—

"In the instant case the employees whose services were terminated preferred appeals to the Commissioner of Labour under S. 39 of the Mysore Shops and Establishment Act. After S. 2A of the Industrial Disputes Act, 1947 came into force on 1st December, 1965 the Labour Commissioner directed the employees to have recourse to the remedy provided under the Industrial Disputes Act.

The employees filed petition before the Commissioner for Labour withdrawing the appeals, pursuant to which the Commissioner for Labour directed the Labour Officer to conciliate the dispute relating to such employee's termination. The Labour Officer consequently initiated conciliation proceedings by issuing notices to the employer and the employee.

In the instant writ petition preferred by the employee against such notices issued by the Conciliation Officer, it was contended on his behalf that S. 2A should be struck down as being violative of Art. 14 of the Constitution of India and its enactment was beyond the powers of the legislature. It was further contended that as the dispute relating to discharge, dismissal, retrenchment or termination having taken place in the instance case prior to 1st December, 1965 S. 2A had no application and the Commissioner of Labour had no jurisdiction to direct the Labour Officer to conciliate the dispute and the Labour Commissioner should have disposed of the appeals under S. 39 of the Shops and Establishments Act.

Negativing the contention that S. 2A was *ultra vires* of the Act and it was violative of Art. 14 of the Constitution of India, it was held that S. 2A could not be said to be inconsistent and repugnant to the object of the Act. When a subsequent Act amends the earlier Act in such a way as to incorporate itself or as part of itself, into the earlier Act, then the earlier Act must thereafter be read and construed as if the altered words had been written into the earlier Act with pen and the old words scored out so that thereafter there is no need to refer the amending Act at all. The words 'industrial dispute' occurring in the preamble of the Act, are vide enough to cover dispute between an employer and single employee and as such individual [illegible] relating to discharge, dismissal or retrenchment could not be construed to be outside the scope of the Industrial Disputes Act, as the legislature was competent to introduce S. 2A under Entry 22 in list III to Schedule 7 of the Constitution of India. The said entry is vide enough to include industrial and labour disputes between an individual employee and his employer.

It was further held that the said S. 2A did not offend, Art. 14 of the Constitution of India, as there is an intelligible differentia which distinguishes an individual workman who is discharged, dismissed, retrenched or whose services have been terminated and individual workman who has some other grievance in regard to his employment or conditions thereof, and as the discharge, dismissal or retrenchment or termination of services of a workman is of graver consequence to a workman than any other terms of conditions of employment. By enabling the individual workman to raise a dispute in regard to his discharge, dismissal or retrenchment, his cause need not bank upon the support of fellow workers as it was prior to the coming into force of S. 2A and thus the object for which S. 2A was introduced has been achieved. So long as discharge, dismissal, retrenchment or termination of services is of greater degree of grevious consequence to an individual workman than any other grievance in regard to his employment or conditions thereof, it is open to the Legislature to provide for a special remedy in regard to a workman who is discharged, dismissed, retrenched or whose services are terminated, while such remedy may not be provided for a workman whose grievance is of lesser gravity."

18. In the present case Shri Devasthali has not pointed out any ruling of the Bombay High Court or of Supreme Court in support of his contention that Section 2A is void and illegal as it offends the provision of Article 14 of the Constitution. In the absence of specific ruling by the Supreme Court or by the Bombay High Court, I rely on the ruling of the High Court of Mysore, which has taken a view that Section 2-A is not void. If Section 2-A is not void and illegal the dispute raised by Shri Vernekar would be deemed to be an industrial dispute though it is not espoused by other workmen or any union of workmen. Hence the Central Government was competent to refer this dispute to this Tribunal and this Tribunal has got jurisdiction to entertain this reference. Hence my finding on point Nos. (i) and (ii) are as above.

Point Nos. (iii) and (iv)

19. Admittedly Shri Vernekar joined the company as a Trainee. He was neither a temporary or permanent employee of the company.

20. Shri Vernekar was holding a diploma in Electrical Engineering but he had no previous experience. He applied for the post of Electrical Engineer, but the company wrote to him that the management was willing to take him up as a trainee on the conditions mentioned below:—

"(1) He will be on trial for a period of 6 months and would be paid a stipend of Rs. 150/- per month.

(2) On satisfactory completion of trial, he would be taken for training for a period of 2 years and his stipend would be increased from time to time upto Rs. 250/- per month.

(3) On completion of training, he might be absorbed as chargehand provided a vacancy arose then. If in principle, he agreed to join as trainee, he was required to inform the company within 7 days to enable the company to issue a letter of appointment in his favour."

21. As Shri Vernekar accepted the conditions mentioned above, he was appointed as a trainee.

22. After the completion of 6 months trial period the company informed him that it was prepared to take him as a trainee and increased the stipend to Rs. 200/- per month by its letter dated 29th May, 1967 produced at Ex. 8/E.

23. The company's contention is that during the training period Shri Vernekar's work was not found satisfactory, that Shri C. F. Jefferies who was the Superintendent, under whom Shri Vernekar was undergoing training made a report that Shri Vernekar had not come upto the required standard and he is not as proficient as he believes to be. He also recommended that Shri Vernekar's appointment be terminated, and that in pursuance of this report Shri Vernekar's training period was discontinued with effect from 1st July, 1969 by letter dated 27th June, 1969 produced at Ex. 9/E. The company however contends that his discontinuance of training period was strictly in accordance with the letter of appointment dated 1st November, 1966 and that it was not *malafide*.

24. At the outset it may be noted that the company has not examined Shri C. F. Jefferies, Superintendent of the Plant where Shri Vernekar was undergoing training. The company has however examined two witnesses viz. S/shri B. P. Manoji and Yeswant Govind Prabhu at Ex. 25/E and Ex. 29/E respectively and produced confidential report at Ex. 26/E and Extract of report on Shri A. S. Vernekar by Shri C. F. Jefferies at Ex. 30/E.

25. Shri B. P. Manoji, Ex. 25/E says in his evidence that he has mentioned in his confidential report dated 26th June, 1969 Ex. 26/E that the performance of Shri Vernekar was between average and below average in respect of 4 items out of 6, that he was found sleeping while on duty, that in that respect he was charge-sheeted and found guilty for misconduct. He further says in his evidence that he has mentioned in his confidential report that Shri Vernekar should not be confirmed.

26. Messrs Crawford Bayley and Company is the Solicitor of the Company. Written statement in this case was filed by Messrs Crawford Bayley and Company on behalf of the company and copy of the same was given to Shri Vernekar. Copy supplied to Shri Vernekar has got Annexure 'C' which purports to be a copy of confidential report dated 26th June, 1969.

27. On comparing the copy supplied to him with the original confidential report produced at Ex. 26/E, it will be clear that there are no tick marks in column 2 and column 1 of the copy of the confidential report Ex. 28/W regarding average and below average, which will be found in the original confidential report Ex. 26/E. In the absence of these tick marks in the copy Ex. 28/W supplied to Shri Vernekar, no weight can be attached to the tick marks shown in the original confidential report Ex. 26/E for showing that the performance of Shri Vernekar was average and below average in respect of 4 items out of 6. On the admission of Shri Manoji, Ex. 25/E, adverse remarks made against Shri Vernekar were not communicated to him because he was not supposed to convey the same.

28. Company's other witness Shri Prabhu, Ex. 29/E on the other hand says in his evidence that it was Shri Manoji's duty to communicate the adverse remarks to Shri Vernekar. He says that the existing practice in respect of adverse remarks is that the head office will not communicate the adverse remarks to the individuals concerned directly, but various In-Charges of the establishment communicate the adverse remarks to the persons concerned verbaliy.

29. Shri Vernekar, emphatically states in his evidence that during the period of probation and training he was never informed at any time by the Company that his work was unsatisfactory and not upto the mark.

30. Considering his evidence and having regard to the admission given by Shri Manoji, Ex. 25/E that adverse remarks made against Shri Vernekar were not communicated to him in writing, because he was not supposed to convey the same, I am of the view that no weight can be attached to the original confidential report Ex. 26/E produced on record.

31. Shri Manoji, Ex. 25/E says in his evidence that Shri Vernekar was found sleeping on duty, that on account of this he was charge-sheeted and found guilty of the mis-conduct. He further says that this fact has been mentioned in his report.

32. It appears from the cross-examination of Shri Manoji, Ex. 25/E that if anybody was found sleeping on duty this was to be reported to the Superintendent and to the departmental head and that Shri Vernekar was informed in writing that he was found sleeping. He further says that Shri Vernekar's signature was not taken on the duplicate in token of warning served on him. He however denies the suggestion that Shri Vernekar was never found sleeping while on duty and that he was not telling the truth when he says that he was warned twice for misconduct on this account.

33. In the present case the company has not produced any satisfactory and convincing evidence to show that Shri Vernekar was found sleeping while on duty and that in that respect he was charge-sheeted and found guilty of his misconduct. In the absence of documents bearing signature of Shri Vernekar in token of his having received warning for sleeping while on duty suspicion about this allegation arises.

34. Shri Prabhu, Ex. 29/E has produced the extract of report on Shri A. S. Vernekar by Shri C. F. Jefferies for the year 1967-68 at Ex. 30/E. It is as follows:—

> "Extract of report on Mr. A. S. Vernekar, by Mr. C.F. Jefferies.
>
> 67-68
>
> ---
>
> Mr. Vernekar, transferred to Palc from MOHD is now working on shift electrical maintenance side. Unfortunately he is not as proficient as he believes himself to be. In his attendance he is regular but in his ability he is only 'average'."

35. On the evidence of Shri Prabhu, Ex. 29/E, document Ex. 30/E is the original record. This extract does not bear the signature of Shri C. F. Jefferies, it does not bear any date. If such is the condition of the original record, it cannot be given any weight. It was the original report given by Shri Jefferies one would expect his signature and date on it in ordinary course. In the absence of his signature on it and date, it is difficult to hold that Ex. 30/E is the original report made by Shri Jefferies.

36. Shri Vernekar has produced number of certificates at Ex. 10/W to 12/W, 14/W to 15/W. These certificates were issued by the Superintendent. These certificates show that his work was found satisfactory. These certificates are contrary to the confidential report made by Shri Jefferies, Superintendent,. As these certificates are contrary to the confidential report made by Shri Jefferies, no weight can be attached to the confidential reports made by him.

37. It is contended that these certificates were given for particular purpose *i.e.* to enable Shri Vernekar to seek employment elsewhere, though his work was not found satisfactory. If that be so the company was keeping him in darkness. It was the duty of the Officer to convey the adverse remarks to Shri Vernekar to enable him to show improvement in his work. By not conveying the adverse remarks, he has been deprived of the opportunity to show improvement in the work. By the certificates, given to him, stating that his work was found satisfactory, Shri Vernekar must have been misled.

38. Shri Vernekar emphatically states in his evidence Ex. 17/W that during the period of probation and training the company found his work satisfactory and issued certificates to him from time to time *vide* Ex. 10/W to 12/W, 14/W and 15/W. From the evidence of Shri Vernekar coupled with other circumstances regarding confidential reports referred to above and the certificates given to Shri Vernekar, Shri Vernekar's work must not have been unsatisfactory.

39. If Shri Vernekar's work was not unsatisfactory whether there was obligation on the company to give the post of charge-hand to him on completion of his training period, on the basis of item 3 in Ex. 5/E. Item 3 in Ex. 5/E is as follows:—

> "(3) On completion of training you may be absorbed as chargehand, provided a vacancy arises then."

40. In the present case Shri Vernekar's evidence Ex. 17/W shows that Shri Raghuvir joined the company as probationer after him and that his training period was over after his training period. He was given the post of Chargehand though he was junior to him. In view of this evidence, there cannot be any doubt that there was vacancy of chargehand and that the same could have been given to Shri Vernekar instead of his junior Shri Raghuvir.

41. In this case the training period of Shri Vernekar was completed on 30th June, 1969 but after the completion of this period he was not absorbed as charge Hand though there was a vacancy. Instead of absorbing him as Chargehand, his stipendary training period was discontinued with effect from

1st July, 1969 by letter dated 27th June, 1969, though the same was completed.

42. From item 3 in Ex. 5/E, it appears to me that there was no obligation on the company to absorb Shri Vernekar as Charge Hand though there would be vacancy and though his work would be found to be satisfactory. It was in the discretion of the company (as per Ex. 5/E) whether to absorg Shri Vernekar as Charge Hand or not. As it was not obligatory on the company to absorb Shri Vernekar as Charge Hand on the basis of the appointment letter Ex. 5/E, accepted by Shri Vernekar, Shri Vernekar cannot make any grievance about the company's exercise of the discretion in not absorbing him as Chargehand. It cannot be said that the company's action in discontinuing Shri Vernekar's training period by letter dated 27th June, 1969, Ex. 9/E on completion of his training period and not absorbing him as Charge Hand is illegal and unjust. Hence Shri Vernekar is not entitled to any relief. Hence my finding on point Nos. (iii) and (iv) are as above.

Point No. (v)

43. In view of the above findings I pass the following order:—

ORDER

(i) It is hereby declared that the action of the management of Messrs Chowgule and Company Private Limited, Mormugao Harbour, in terminating the services of the workman Shri Anand S. Vernekar, trainee in electrical department Palletisation Plant, Pale Mines in their letter No. STAF/TL/53 dated the 27th June, 1969 and consequently not offering him the post of Charge Hand in the grade of Rs. 300—15—390—20—510 after the completion of the training period was justifiable and that he is not entitled to any relief.

(ii) Award is made accordingly.

(iii) No order as to costs.

N. K. VANI, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1973

आदेश

का० आ० 191—यतः मैसर्स गोग्गागुरू सन्थाआइयाह एण्ड ब्रदर्स खान मालिक, सन्दुर के प्रबन्धतंत्र से संबंध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व जम्बुनाथा लौह अयस्क और लाल आक्साइड खान श्रमिक यूनियन, पापीनायाकानाहाल्ली करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः उक्त, कम्पनी और यूनियन ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें वर्णित व्यक्तियों के माध्यस्थम् के लिए निदेशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम् करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम् करार को, जो उसे 28 दिसम्बर, 1972 को मिला था, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, (करार) 1947 की धारा 10-क के अधीन बीच

नियोजकों के प्रतिनिधी	श्रमिकों के प्रतिनिधी
1. श्री जी० बासाइआह भागीदार। मैसर्स गोग्गागुरुसन्थाइयाह एण्ड ब्रदर्स, सन्दुर।	श्री ए० एस० मालेबेन्नुर, अध्यक्ष। जम्बुनाथा लौह अयस्क और लाल आक्साइड् खान श्रमिक यूनियन, पापिनायाकानाहाल्ली।
2. श्री जी. सारभाइआह्, भागीदार, मैसर्स गोग्गागुरुसन्थाइयाह् एण्ड ब्रदर्स, सन्दुर।	

पक्षकारों के बीच एतद्द्वारा निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को डी० बी० रामचन्द्रन, सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) हैदराबाद के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है।

I. विनिर्दिष्ट विवाद ग्रस्त विषय : "क्या सर्वश्री हनुमानथाप्पा और टकाप्पा, जिन्हें ड्रिलर्स के रूप में नियोजित किया गया था, ने स्वैच्छिक रूप से त्याग-पत्र दिया, यदि हां तो क्या वे किसी अनुतोष, जिसमें पुननियुक्ति और पुनर्नियोजन शामिल है, के हकदार हैं।'

II. विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिसमें अन्तर्वलित स्थापन का उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है।

1. श्री जी० बासाइआह्, भागीदार, मैसर्स गोग्गागुरुसन्थाइयाह एण्ड ब्रदर्स, सन्दुर। — श्री ए० एस० मालेबेन्नुर, अध्यक्ष, जम्बुनाथा लौह अयस्क और लाल आक्साइड खान श्रमिक यूनियन, पापिननायाकनाहाल्ली।

2. श्री जी० सारभाइआह्, भागीदार, मैसर्स गोग्गागुरुसन्थाईयाह, एण्ड ब्रदर्स, सन्दुर।

III. यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता है तो उसका नाम।
जम्बुनाथा लौह अयस्क और लाल आक्साइड खान श्रमिक यूनियन, पापिनायाकानाहाल्ली, हास्पेट ताल्लुक, बेल्लारी जिला, मैसूर राज्य।

IV. प्रभावित उपक्रमों में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या 150 है।

V. विवाद द्वारा प्रभावित या सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्याः दो है।

हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर आबद्ध कर होगा।

मध्यस्थ अपना पंचाट तीन मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ावा जाय, देगा। यदि पूर्ववर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता है तो माध्यस्थम् के लिए निदेश स्वतः रद्द हो जायगा, और हम नए माध्यस्थम के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे।

दिनांक 21 दिसम्बर, 1972

पक्षकारों के हस्ताक्षर

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले	कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले
1. ह०/-जी० बासिआह्, भागीदार, मैसर्स गोग्गागुरुसान्थाइआह् एण्ड ब्रदर्स ।	1. ह०/-ए० एस० मालेबेन्नुर, अध्यक्ष, जम्बुनाथा लौह अयस्क और लाल आक्साइड् खान श्रमिक यूनियन ।
2. ह०/-जी० सारभाइआह्, भागीदार, मैसर्स गोग्गागुरुसानथाइआह् एण्ड ब्रदर्स ।	

साक्षी

1. ह०/जी नारायणस्वामी, सहायक श्रमायुक्त, (केन्द्रीय) बेल्लारी ।	2. पी० राघावन, उच्च श्रेणी लिपिक सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय, बेल्लारी ।

[संख्या एल-29013/5/72-एल०आर० 4]

एस० एस० सहास्रानामन,

New Delhi, the 9th January, 1972

ORDER

S.O.191—Whereas an industrial dispute exists between the management of Messrs. Goggagurusanthaiah and Brothers, Mine Owners, Sandur and their workmen represented by the Jambunatha Iron Ore & Red Oxide Mines Workers, Union, Papinayakanahalli.

AND WHEREAS the said company and the Union have by a written agreement in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) agreed to refer the said dispute to arbitration of the persons mentioned therein and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government;

NOW THEREFORE, in pursuance of the provision of sub-section (3) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement which was received by it on the 28th December, 1972.

(Agreement)

AGREEMENT UNDER SECTION 10A OF THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947 BETWEEN

Representatives of Employers	Representative of workmen
1. Shri G. Basaiah, Partner, M/s. Goggagurusanthaiah & Bros. Sandur.	Shri A. S. Malebennur, President, Jambunatha Iron Ore & Red Oxide Mines Workers Union, Papinayakanahalli.
2. Shri G. Sarbhaiah, Partner, M/s. Goggagurusanthaiah & Bros. Sandur.	

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Shri D. V. Ramachandran, Assistant Labour Commissioner (Central), Hyderabad.

Specific matters in dispute :—

"WHETHER S/SHRI HANUMANTHAPPA AND TAKAPPA EMPLOYED AS DRILLERS VOLUNTARILY RESIGNED, IF SO, WHETHER THEY ARE ENTITLED FOR ANY RELIEF INCLUSIVE OF RE-INSTATEMENT OR RE-EMPLOYMENT"

(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking.

1. Shri G. Basaiah, Partner, M/s. Goggagurusanthaiah & Bros, Sandur.	Shri A. S. Malebennur, President, Jambunatha Iron Ore & Red Oxide Mines Workers Union, Papinayakanahalli.
2. Shri G. Sarbhaiah, Partner, M/s. Goggagurusanthaiah & Bros, Sandur.	

(iii) Name of the Union if any represented the workmen in question.

Jambunatha Iron Ore & Red Oxide Mines workers, Union, Papinayakanahalli, Hospet Taluk, Bellary Disstt. Mysore State.

(iv) Total number of workmen employed in the undertakings is 150.

(v) Estimated number of workmen affected are likely to be affected by the dipsute is 2.

We further agree that the decision of the Arbitrator shall be binding on us.

The Arbitrator shall make his Award within a period of three months or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the Award is not within the period aforementioned the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Dated, the 21st December, 1972.

Signature of the parties

Representatives of Employers	*Representative of the workmen*
1. Sd/- G. BASIAH Partenr, M/s. Goggagurusanthaiah & Bros.	1. Sd/- A.S. MALEBENNUR President, Jambunatha Iron Ore & Red Oxide Mines Workers Union.
2. Sd/- G. SARBHIAH Partner, M/s. Goggagurusanthaiah & Bros.	
Witnesses	
Sd/-	Sd/-
1. G. NARAYANASWAMY Assistant Labour Commissioner, (Central) Bellary.	2. P. RAGHAVAN UDC, Office of the A.L.C.(C), Bellary

[No. L-29013/5/72-LR. IV]

S.S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1973

का. आ. 192.—कर्मचारी भविष्य निधि तथा कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5-घ की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 3011, तारीख 29 अगस्त, 1968 में आंशिक उपांतरण करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री आर. के. रस्तोगी को केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता देने के लिए, समस्त, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैण्ड और मेघालय राज्यों तथा मिजोराम और अरूणाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एतद्द्वारा प्रादेशिक भविष्य निधि नियुक्त करती है।

[संख्या 33(2)/68-भ. नि.-1(1)]

New Delhi, the 9th January, 1973

S.O. 192.—In exercise of the power sconferred by sub-section (2) of section 5D of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952) and in partial modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 3011 dated the 29th August, 1968, the Central Government hereby appoints Shri R. K. Rastogi as the Regional Provident Fund Commissioner for the whole of the States of Assam, Manipur, Tripura, Nagaland and Meghalaya and the Union Territories of Mizoram and Arunachal Pradesh to assist the Central Provident Fund Commissioner in the discharge of his duties.

[No. 33(2)/68-PF.I(i)]

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1973

का. आ. 193.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 3012 तारीख 29 अगस्त, 1968 में आंशिक उपांतरण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री आर. के. रस्तोगी को उक्त अधिनियम और उसके अधीन विरचित स्कीमों के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के सम्बन्ध में या किसी रेल कम्पनी, महापत्तन, खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से सम्बन्धित किसी स्थापन के सम्बन्ध में सम्पूर्ण असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैण्ड और मेघालय राज्यों तथा मिजोराम और अरुणाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है।

[सं. 33(2)/68-भ. नि. (1)(2)]

New Delhi, 10th January, 1973

S.O. 193.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), and in partial modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 3012 dated the 29th August, 1968, the Central Government hereby appoints Shri R. K. Rastogi, to be an Inspector for the whole of the States of Assam, Manipur, Tripura, Nagaland and Meghalaya and the Union Territories of Mizoram and Arunachal Pradesh for the purposes of the said Act and the Schemes framed thereunder, in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government, or in relation to any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oilfield or a controlled industry.

[No. 33/2/68-PF-I(ii)]

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1973

का. आ. 194.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सर्वश्री एम. सी. हिरूथानाथन और एन. केशवन को उक्त अधिनियम और उसके अधीन विरचित स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियन्त्रणाधीन किसी स्थापन के सम्बन्ध में या किसी रेल कम्पनी, महापत्तन खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से सम्बन्धित किसी स्थापन के सम्बन्ध में या ऐसे स्थापन के सम्बन्ध में जिसकी एक से अधिक राज्य में शाखाएं या विभाग हों, सम्पूर्ण तमिल नाडु राज्य के लिए निरीक्षक नियुक्त है।

[संख्या ए-12015(5)/71-पी. एफ.-1]

दलजीत सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 11th January, 1973

S.O. 194.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints Sarvashri M. C. Hiruthayanathan and N. Kesavan to be Inspectors for the whole of the State of Tamil Nadu for the purposes of the said Act and of any Scheme framed thereunder in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oilfield or a controlled industry and in relation to establishments having departments or branches in more than one State.

[No. A-12015/5/71-PF. I]

DALJIT SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1973

आदेश

का. आ. 195—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स यूनिवर्सल क्लीयरिंग एण्ड फारवर्डिंग एजेंसी, कलकत्ता के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स यूनिवर्सल क्लीयरिंग एण्ड फारवर्डिंग एजेंसी, 5, आचार्य जगदीश बोस रोड, कलकत्ता-20 के प्रबन्धतंत्र की श्री गौरेज तामांग और श्री के. बी. मोकलान, चौकीदारों को क्रमशः 21 जून, 1972 और 23 जून, 1972 से नियोजन देने से इन्कार करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं?

[सं. एल.-32012/5/72-पी. एण्ड डी.]

पी. शंकरालिंगम, अवर सचिव

New Delhi, 11th January, 1973

ORDER

S.O. 195.—WHEREAS the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Universal Clearing and Forwarding Agency, Calcutta, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

AND, WHEREAS, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Messrs Universal Clearing and Forwarding Agency, 5, Acharya Jagadish Bose Road, Calcutta-20, in refusing to employ Shri Gorej Tamang and Shri K. B. Mocktan, Watchman with effect from 21st June, 1972 and 23rd June, 1972 respectively is justified? If not, to what relief are the workmen entitled?

[No. L-32012/5/72-P&D]

V. SANKARALINGAM, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1973

का. आ. 196.—कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 (1947 का 32) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3025, तारीख 9 दिसम्बर, 1960 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार, 17 जनवरी, 1973 से पचहत्तर पैसे प्रति टन ऐसी दर के रूप में एतद्द्वारा नियत करती है, जिस पर उक्त उपधारा में निर्दिष्ट उत्पाद शुल्क, कोयला खानों से भेजे गए सभी कोयले और कोक पर उद्ग्रहणीय होगा ।

[सं. 1/8/70-एम-II]

New Delhi, the 11th January, 1973

S.O. 196.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947 (32 of 1947), and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S.O. 3025 dated the 9th December, 1960, the Central Government hereby fixes, with effect from the 17th January, 1973, seventy five paise per tonne as the rate at which the duty of excise referred to in the said sub-section shall be leviable on all coal and coke despatched from collieries.

[No. 1/8/70-MII]

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1973

का. आ. 197.—कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 (1947 का 32) की धारा 5 की उपधारा (5) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोयला खान श्रम आवास और साधारण कल्याण निधि की 1972-73 के दौरान साधारण कल्याण लेखा में प्राप्तियों और उसमें से व्यय का निम्नलिखित प्राक्कलन, 1971-72 के लेखा-विवरण और उस वर्ष के दौरान उक्त निधि के साधारण कल्याण लेखा से वित्त-पोषित कार्यकलाप की रिपोर्ट के साथ प्रकाशित करती है, अर्थात् :—

भाग — 1

1972-73 के दौरान प्राप्तियों और व्ययों का प्राक्कलन

साधारण कल्याण लेखा

प्राप्तियां	व्यय
2,35,97,000 रु.	2,95,71,000 रु.

भाग — 2

1971-72 वर्ष के लिए लेखा — विवरण

साधारण कल्याण लेखा

	प्राप्तियां	व्यय
1. 1अप्रैल 1971 को अथशेष रू0	(—) 17,93,396*	
2. वर्ष के दौरान साधारण कल्याण लेखे में से व्यय		2,91,80,370 रू0
3. वर्ष के दौरान प्राप्तियां	रू0 2,54,91,869	
4. 31 मार्च 1972 को इतिशेष		(—) 64,81,897 रू०
	2,06,98,373 रू०	,26,98,473 रू०

*टिप्पण :— 1 अप्रैल, 1972 के अर्थशेष में 59,30,700 रू. की वह राशि शामिल नहीं है जो आवास लेखे में से 1970-71 वर्ष का घाटा पूरा करने के लिए साधारण कल्याण लेखे को ऋण के रूप में मंजूर की गई थी । यह मंजूरी अभी तक महालेखा पाल, बिहार, रांची द्वारा स्वीकार नहीं की गई है ।

भाग — 3

1. चिकित्सा प्रसुविधाएं

(क) **अस्पताल** :—तीन केन्द्रीय अस्पताल, धनबाद, आसनसोल और मनेन्द्रगढ़ में, प्रत्येक में एक-एक और कोयला क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर बारह प्रादेशिक अस्पताल बराबर काम करते रहे । धनबाद, आसनसोल, और मनेन्द्रगढ़ के केन्द्रीय अस्पतालों की शैय्या संख्या क्रमशः 300, 350 और 50 है ।

(ख) **औषधालय** :—झुरमा कोयला क्षेत्र में एलोपैथिक स्थैतिक औषधालय, आसाम कोयला क्षेत्र में एक चल-चिकित्सा-एकक और विभिन्न कोयला क्षेत्रों में 29 आयुर्वेदिक औषधालय कार्य करते रहे । निधि के आयुर्वेदिक औषधालयों के प्रयोग के लिए अपेक्षित शुद्ध दवाओं की विनिर्मिती के लिए झरिया कोयला क्षेत्र में पर्थौडीह पर स्थापित आयुर्वेदिक फार्मेसी बराबर कार्य करती रही ।

(ग) **प्रसूति, परिवार और शिशु-कल्याण केन्द्र** :—प्रत्येक प्रादेशिक अस्पताल से सम्बद्ध परिवार-कल्याण-केन्द्र काम करता रहा । इसके अतिरिक्त विभिन्न कोयला क्षेत्रों में पहले ही स्थापित 8 केन्द्र भी प्रत्येक स्वतंत्र एकक के रूप में, अर्हताप्राप्त महिला स्वास्थ्य-चर के भारसाधन में, काम करते रहे । इसके अतिरिक्त आसनसोल, झरिया और हजारीबाग खान, स्वास्थ्य-बोर्ड द्वारा 58 प्रसूति और शिशु-कल्याण केन्द्र, जिनके अनुरक्षण के लिए कोयला खान-श्रम-कल्याण केन्द्र, जिनके अनुरक्षण के लिए कोयला खान-श्रम-कल्याण संगठन बराबर सहायक अनुदान देता रहा, चलते रहे । चंदा कोयला क्षेत्र के कोयला खान कर्मकारों के

फायदे के लिए सरकारी अस्पताल चंदा से संलग्न ब्लॉक बराबर काम करता रहा।

(घ) **औषधालय-सेवाओं में सुधार के लिए वित्तीय सहायता :—** कोयला खान प्रबन्धकों को कोयला खान के कर्मकारों और उनके आश्रितों के फायदे के लिए कोयला खानों पर औषधालय-सेवाओं के स्तर में सुधार के लिए बढ़ावा देने की दृष्टि से, सहायक अनुदान संदत्त करने की स्कीम बराबर चलती रही तथा 14,00,000 रूपये की रकम वर्ष के दौरान दिये जाने के लिए मंजूर की गई। इसके अलावा कोयला खान प्रबन्धकों को उन के द्वारा नियोजित कर्मकारों के फायदे के लिए नये औषधालय बनाने और वर्तमान औषधालय-सेवा के सुधार के लिए प्रोत्साहन देने की कोयला खान-श्रम-कल्याण संगठन, निर्माण की वास्तविक लागत के बराबर, बिना ब्याज के उधारों के संदाय के रूप औषधालयों के विद्यमान भवन में सुधार, जिसमें उपस्कर का क्रय भी है, की वास्तविक लागत के समतुल्य संदाय के रूप में वित्तीय सहायता, जो अधिक से अधिक, वार्षिक सहायता अनुदान से 16 गुनी हो सकती है, की एक स्कीम चलाता रहा। वर्ष के दौरान 4,81,000 रूपये की रकम देने के लिए अलग रख दी गई थी।

(ङ) **क्षय-रोधी उपाय :—**क्षय से पीड़ित कोयला खान कर्मकारों और उनके आश्रितों के उपचार के लिए संगठन के क्षय-रोधी अस्पताल में 262 शैय्याओं का प्रबन्ध किया गया है। इससे अतिरिक्त कोयला खान कर्मकारों और उनके आश्रितों के उपचार के लिए विभिन्न क्षय-रोधी सैनेटोरियमों में 61 शैय्याएं आरक्षित रही। गृह-क्षय-रोधी उपचार की स्कीम बराबर चलती रही और जो क्षय-रोगी इस स्कीम के अन्तर्गत इलाज करा रहे थे उनको निर्वाह भत्तों का संदाय भी कार्यक्रम के अनुसार किया जाता रहा। इस अवधि के दौरान इस स्कीम पर 7,93,000 रुपये की रकम खर्च की गई। विभिन्न सैनिटोरियम-प्राधिकरणों को वर्ष के दौरान 1,75,100 रूपये की रकम 61 शैय्याओं के आरक्षण के लिए दी गई।

(च) **परिवार नियोजन सेवाएं :—**कोयला खान श्रम आवास और साधारण कल्याण निधि अस्पतालों में, तथा उस प्रयोजन के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में खोली गई क्लीनिकों में, परिवार नियोजन के बारे में मुफ्त सलाह दी जाती रही और मुफ्त निरोधक वितरण बराबर चलता रहा। कोयला खान स्वामियों को परिवार नियोजन के लिए, सहायक अनुदान की स्कीम बराबर प्रवृत्त रही। 5 स्थैतिक परिवार नियोजन-एकक तथा 3 चल-परिवार नियोजन-एकक बराबर काम करते रहे। इसके अतिरिक्त भरिया, आसनसोल और हजारी-बाग खान, स्वास्थ्य बोर्ड द्वारा अपने-अपने कोयला क्षेत्रों के विभिन्न भागों में चलाए जा रहे 58 प्रसूति और शिशु-कल्याण केन्द्रों, में भी परिवार नियोजन की सेवाएं उपलब्ध थीं।

(छ) **पुनर्वास:—**धनबाद और आसनसोल में केन्द्रीय अस्पतालों से संलग्न पुनर्वास एवं भौतिक चिकित्सा केन्द्र बराबर कार्य करता रहा। छिंदवाड़ा के पुनर्वास केन्द्र का निर्माण कार्य पूरा हो गया और आगे की कार्यवाही की जा रही है। पश्चिम बंगाल कोयला क्षेत्र में सिद्धवाड़ी में पुनर्वास एवं स्वास्थ्य लाभगृह को बिजली का कनेक्शन दे दिया गया था और आगे की कार्यवाही की गई है।

(ज) **अन्य कार्यकलाप:—**कोयला खान श्रम-कल्याण संगठन की चिकित्सा और जन-साधारण स्वास्थ्य की दिशा में अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलाप थे — — कैन्सर, कोढ़, मानसिक रोगों के उपचार के लिए सुविधाएं देना, धनबाद तथा आसनसोल के केन्द्रीय अस्पतालों में रक्त बैंक चलाना, चश्मे और नकली दांतों का मुफ्त देना तथा और फाइलेरिया का नियंत्रण कार्य।

2. शैक्षिक और मनोरंजन की प्रसुविधाएं

(क) इस मद में महत्वपूर्ण कार्यकलापों को बताने वाले कुछ सुसंगत आंकड़े निम्नलिखित हैं:—

i	बहु प्रयोजनीय संस्थान	60
ii	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	60
iii	महिला-कल्याण केन्द्र	61
iv	पोषिक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	150
v	कोयला खान के कर्मकारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां	547 गत वर्ष में दी गई छात्रवृत्तियों का नवीकरण
vi	बच्चों के लिए बोर्डिंगहाउस	2 के अतिरिक्त औद्योगिक संस्था के प्रशिक्षार्थियों को
vii	अवकाश गृह	2 500 साधारण 22 तकनीकी छात्रवृत्तियां और 25 वृत्तिक दी गईं।

(ख) **खेल और क्रीड़ा.—**कोयला खान के कर्मकारों के मनोरंजन के लिए प्रत्येक वर्ष खेल और क्रीड़ाओं का आयोजन किया जाता है। वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों और क्रीड़ाओं के आयोजन के लिए 1,86,200 रूपये की रकम मंजूर की गई थी।

(ग) **अन्य कार्यकलाप:—**इस सम्बन्ध में दी गई अन्य महत्वपूर्ण प्रसुविधाएं हैं—(1) विभिन्न कोयला क्षेत्रों में शिक्षा-संस्थानों को सहायक अनुदान, (2) कोयला खनिकों के बीच में खेल और क्रिड़ाओं की व्यवस्था, (3) सिनेमा दिखाना, (4) ट्यूशन फीस और बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ते की मंजूरी, (5) कोयला खान के कर्मकारों की, जो खान में दुर्घटना से मर गए हैं, पत्नियों और स्कूल जाने वाले बच्चों की सहायता के लिए वित्तीय सहायता।

3. जल प्रदाय

वर्ष के दौरान जल प्रदाय की स्कीम पर 18,03,500 रूपये की रकम खर्च की गई। जल प्रदाय स्कीम की मद में वर्ष के दौरान प्रगति का संक्षिप्त पुनर्विलोकन निम्नलिखित है :—

मध्य प्रदेश कोयला क्षेत्र में, हजारीबाग कोयला क्षेत्र में नयी चुनी गई धोरी कोयला खान तथा विश्रामपुर कुण्ड कोयला खान में जल प्रदाय स्कीम वर्ष के दौरान पूरी की गई। हजारीबाग कोयला क्षेत्र में सुदमडीह, खास करनपुरा, सुरंगेरा और आरा कोयला खानों में तथा मध्य प्रदेश कोयला क्षेत्र में सीलवाडा, अम्लाई, बीरसिंगपुर, चिरीमिरी और बरहार संख्या क्षेत्र ।, कोयला खानों में जल प्रदाय स्कीम काम करती रही।

कुओं का गलाना:—50 प्रतिशत सहायिकी की स्कीम के अधीन 20 कुएं गलाए गए जिससे अब तक पूरे किये गये कुओं की कुल संख्या 279 होगी। सहायिकी के रूप में 20,000 रूपये की रकम वर्ष के दौरान विभिन्न कोयला क्षेत्रों में कुएं खोदने के लिए खर्च की गई।

4. सहकारिता आन्दोलन

कोयला खान कर्मकारों के प्राथमिक सहकारिता भण्डारों और ऋण संस्थाओं की कुल संख्या 569 ही रही। 12 थोक या केन्द्रीय सहकारिता भण्डार भी थे जो संगठन द्वारा चलाये जा रहे थे।

[सं. जैड.-16016/3/72-एम-2]

पी. आर. नैय्यर, अवर सचिव।

New Delhi, the 12th January, 1973

S.O. 197.—In pursuance of sub-section (5) of section 5 of the Coal Mines Labour Welfare Fund Act 1947 (32 of 1947), the Central Government hereby publishes the following estimates of receipts into and expenditure from the General Welfare Account of the Coal Mines Labour Welfare Housing and General Welfare Fund for the year 1972-73 together with a statement of Account for the year 1971-72 and a report on the activities financed during that year from the General Welfare Account of the said Fund, namely:—

PART-I

Estimates of receipts and expenditure during 1972-73

General Welfare Account

Receipt	*Expenditure*
Rs. 2,35,97,000/-	Rs. 2,95,71,000/-

PART-II

Statement of Account for the year 1971-72

General Welfare Account

	Receipt	Expenditure
1. Opening balance on Ist April, 1971.	Rs. (—)*27,93,396	
2. Expenditure on General Welfare Account during the year.		Rs. 2,91,80,370
3. Receipt during the year	Rs. 2,54,91,869	
4. Closing balance on 31st March 1972.		Rs. (—)64,81,897
	Rs. 2,26,98,473	Rs. 2,26,98,473

*Note :—The opening balance as on Ist April 1971 does not include an amount of Rs. 59,30,700/—sanctioned from the Housing Account as *Loan* to the General Welfare Account to wipe out the deficit for the year 1970-71. The sanction has not so far been accepted by the Accountant General Bihar, Ranchi.

PART-III

1. MEDICAL FACILITIES

(a) *Hospitals*:—The three Central Hospitals one each at Dhanbad, Asansol and Manendragarh and twelve Regional Hospitals situated in different Coalfields continued to function. The bed-strength of the Central Hospitals at Dhanbad, Asansol and Manendragarh is 300,350 and 50 respectively.

(b) *Dispensaries*:—One allopathic Static Dispensary in Mugma Coalfield, one Mobile Medical Unit in Assam Coalfield and 29 Ayurvedic Dispensaries in various coalfields continued to function. For the manufacture of the genuine medicines required for the use at the Ayurvedic dispensaries of the Fund, the Ayurvedic Pharmacy set up at Patherdih in the Jharia Coalfield, continued to render service.

(c) *Maternity, Family and Child Welfare Centres*:—A Family Welfare Centre attached to each of the Regional Hospitals continued to function. Besides 8 centres already established in the various coalfields were also functioning as independent units, each under the charge of a qualified Lady Health Visitor. In addition 58 Maternity and Child Welfare Centres were being run by the Asansol, Jharia and Hazaribagh Mines Boards of Health for which the Coal Mines Labour Welfare Organisation continued to pay grant-in-aid towards their maintenance. For the benefit of the colliery workers in the Chanda Coalfield, the block attached to the Government Hospital, Chanda, continued to function.

(d) *Financial assistance for improving dispensary services*:—With a view to encouraging the colliery managements for improving the standard of dispensary services at the collieries for the benefit of the colliery workers and their dependents, the scheme for the payment of grant-in-aid was continued and a sum of Rs. 14,00,000 was sanctioned for payment during the year. Further, in order to give incentive to colliery managements to provide new dispensaries or to improve the existing dispensary services for the benefit of the workers employed by them, the Coal Mines Labour Welfare Organisation operated a scheme of financial assistance in the form of payment of interest free loans equivalent to actual cost of construction or improvement of existing building for the dispensaries including purchase of equipment subject to the maximum of 16 times of the annual grant-in-aid. A sum of Rs. 4,81,000 was earmarked for payment during the year.

(e) *Anti T. B. Measures*:—For the treatment of colliery workers and their dependents suffering from T.B., provision of 262 beds in the T.B. Hospitals of the Organisation has been made. Besides 61 beds remained reserved in the various T.B. Sanatoria for the treatment of colliery workers and their dependents. The scheme of domiciliary T.B. treatment continued to function and payment of subsistence allowance to the T. B. patients who were undergoing treatment under this scheme also continued to be made according to schedule. A sum of Rs. 7,93,000 was incurred on this scheme during the period. For the reservation of 61 beds, a sum of Rs. 1,73,100 was paid during the year to the various sanatorium authorities.

(f) *Family Planning Services*:—Free advice on family planning continued to be given and contraceptive supplied free of cost at the Coal Mines Labour Welfare Fund's Hospitals and at the clinics opened for the purpose in various coalfields. The scheme for the payment of grant-in-aid to the colliery owner for the family planning work continued to be in force. The 5 Static Family Planning Units and the 3 Mobile Family Planning Units remained in operation. In addition, the Maternity and Child Welfare Centres numbering 58 run by the Jharia, Asansol and Hazaribagh Mines Boards of Health in different part of respective coalfields also provided family planning services.

(g) *Rehabilitation*:—A Rehabilitation-*cum*-Physiotherapy Centre attached to each of the Central Hospitals at Dhanbad and Asansol continued to function. The work of construction of the Rehabilitation Centre at Chhindwara was completed and further action was in hand. Electric connection to the Rehabilitation-*cum*-Convalacent Home at Sidhabari in West Bengal Coal field was given and further action remained in progress.

(h) *Other activities*:—Other important activities of the Coal Mines Welfare Organisation on the medical and public health side were provision of facilities for the treatment of Cancer, Leprosy and Mental Cases, running of blood bank at the Central Hospital, Dhanbad and Asansol, free supply of spectacles and dentures and Malaria and Filaria control operations etc., etc.

2. Educational and Recreational Facilities

(a) Some relevant statistics on the important activities on this account are given below:—

(i) Multipurpose Institutes	... 60	
(ii) Adult Education Centres	... 60	
(iii) Women Welfare Centres	... 61	
(iv) Feeder Adult Education Centres	... 150	
(v) Scholarship to the children of colliery workers	... 547	(500 general, 22 technical scholarships and 25 stipends for Industrial Institute trainees are awarded every year in addition to renewal of scholarships awarded during the previous year).
(vi) Boarding Houses for children	...	
(vii) Holiday Homes	... 2	

(b) *Games and Sports*:—Games and sports are held every year to provide recreation to colliery workers. During the year, for organising various games and sports a sum of Rs. 1,86,200/- was sanctioned.

(c) *Other activities*:—Other important facilities provided in this connection comprises (1) grant-in-aid to the educational institutions in the different coalfields, (2) provision for games and sports amongst coal miners, (3) exhibition of films, (4) grant of tuition fees and children education allowances, (5) provision for financial assistance to the wives and school going children of colliery workers who die of accident in mines.

3 WATER SUPPLY

During the year a sum of Rs. 18,03,500 has been spent on water supply schemes. A brief review of the progress made in respect of water supply scheme during the year is furnished below:—

The water supply schemes at New Selected Dhori Collieries in Hazaribagh Coalfield and Bisrampur Kunda Colliery in M.P. Coalfield were completed during the year. The water supply schemes at Sudamdih, Khas Karanpura, Surabera and Ara Collieries in Hazaribagh Coalfield and Silwara, Amlai, Birshingpur, Chirimiri and Burhar No. 1 collieries in Madhya Pradesh Coalfield were under execution.

Sinking of Wells:—20 wells, under the scheme of 50 per cent subsidy, were sunk bringing the total number of wells so far completed to 279. A sum of Rs. 20,000/- was spent on digging of wells in different coalfields during the year.

4. COOPERATIVE MOVEMENT

The total number of primary Co-operative stores and Credit Societies of colliery workers remained at 569. There were also 12 wholesale or Central Cooperative Stores sponsored by the Organisation.

[No. Z-16016/3/72-M. II]

P. R. NAYAR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, RING ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973